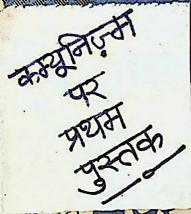
gitized by Arya Samai Foun





लेखक जार्ज डबल्यू क्रोनिन

अनुवादक जगदीश चन्द्र

नेशनल एकाइमी दिल्ली

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



कम्यानिज्म पर प्रथम पुस्तक

दो सौ प्रश्न तथा उत्तर

लेखक जार्ज डब्ल्यू. क्रोनिन

> भ्रमुवादक जगवीश चन्द्र

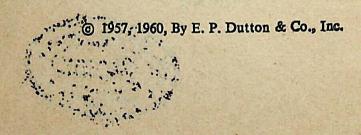


प्रकाशक

नेशनल एकाडमी हे, ग्रंसारी मार्केट, दरियागंज, CC-0.Panini Kany विकासी Veyvalaya Collection. प्रकाशक नेशनल एकाडमी, ६, ग्रंसारी मार्केट, दरियागंज, दिल्ली-६

प्रथम संस्करण : जून १६६४

मूल्य: एक रुपया



मुद्रक नया हिन्दुस्तान प्रेस, चांदनी चौक, दिल्ली-६

Digitized by Arya Samaj क्रिक्कू स्निर्धान जुरु गमुश्चिम् अपुरस्तक



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परिचय



इस वात का निर्णय तो विश्व-जनमत से ही होगा कि मानवता अन्त में अपने लिए स्वतन्त्रता का मार्ग चुनती है या कम्यूनिष्म का। परन्तु एक बात स्पष्ट है कि यदि यह निर्णय तथ्यों के आधार पर हुआ तो हमें परिणाम के बारे में कोई संदेह नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य से जनमत और निर्णय का आधार कम्यूनिष्म द्वारा फैलाई हुई मिथ्याएं भी हो सकती हैं। कम्यूनिष्म का प्रचार आशाजनक परन्तु गलत धारणाओं के कारण होता है। कम्यूनिष्म का स्वर्ण-जाल बहुत चतुरता से उन भोले-भाले लोगों को फांसने के लिये बिछाया जाता है जो उज्ज्वल भविष्य के स्वप्न देखते हैं। यह पुस्तक कम्यूनिष्म के असली उद्देश्यों पर कोरा सैदान्तिक तर्क करने की बजाय इसके व्यावहारिक पहलुओं का सिहावलोकन करती है।

अन्तर्राष्ट्रीयता, कम्यूनिषम के बहु लक्षणों में से एक लक्षण है। इसकी हम सहज ही उपेक्षा कर जाते हैं। सोवियत यूनियन एक राष्ट्र या राज्य नहीं है। इसके स्वार्थ और लालसा की सीमाएं बहुत दूर तक फैली हुई हैं यह उस अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट आन्दोलन का केन्द्र भी है जो धार्मिक उन्माद के साथ स्वतंत्र संसार को गुलामी की वेड़ियाँ पहनाना चाहता है। कम्यूनिषम का खतरा युद्ध या इसकी धमकी से भी बड़ा है और हर समय सर पर सवार रहता है। पर परम्परागत कूटनीति का काम यह है कि विभिन्न देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पैदा करे और इसके फलस्वरूप जब मैत्री, शान्ति, न्याय तथा समृद्धि के संचार का विश्वास हो जाए तो प्रतीयमान संरक्षण का अनुभव स्वाभाविक है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिषम इस प्रतीयमान शान्ति के वाता-वरण से लाभ उठाता है। युद्धकाल हो या शान्तिकाल, उसे यही धुन रहती है कि स्वार्थ-सिद्धि का कोई अवसर हाथ से न जाने पाए। मानव की स्वतंत्रता तथा प्रगति का जहाँ कहीं आभास मिले, उसे सत्म कर दिया जाए।

जोड़-तोड़ तथा घातपूर्ण चालें सोचने में कम्यूनिस्ट बल के प्रयोग को

न्यायसंगत तथी प्रिपिरिहार्य ती भीनते हिण्हें व्याप्त जिनकी बक्त शिक्ष प्रियो रहती है कि कूटनीति से प्रपनी विरोधी शक्ति को कमजोर और शिथिल कर दिया जाए। उनकी मुस्कानों से स्वतन्त्र जगत् की सुरक्षा की व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। उनकी ग्रोर से सांस्कृतिक तथा प्रोपेगण्डा ग्राक्रमण की ग्राशा की जा सकती है वह उत्पादन में उन्नति की नुमाइश करके उसे कम्यूनिज्म का चमत्कार वताते हैं। यदि ग्रसन्त्रीय ग्रीर गड़वड़ से लाभ होने की ग्राशा हो तो ग्राधिक सहायता भी देते हैं। यदि वल प्रयोग ग्रधिक लाभकारी जान पड़े तो वह इससे भी नहीं चूकते।

श्रान्दोलन शक्ति तथा विस्तार के दृष्टिकोण से कम्यूनिषम दिरव-इतिहास में बहुत श्रजीब लेकिन सबसे श्रधिक साम्राज्यवादी शक्ति वन चुका है। श्राज भी करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो इसकी वर्बरता तथा श्रत्याचार से पूरी तरह परि-चित नहीं, और इसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं।

यह पुस्तक इसी सूभ-वूभ को फैलाने का सशक्त शस्त्र है।

फ्रैंकलिन एल० बैंडटे प्रोफेसर तथा डायरेक्टर, सरकारी अनुसंधान व्यूरो, मेरीलैण्ड विश्वविद्यालय।

AND WILLIAM	
विषय-सन्दर्भ	· No.
The (John Comments)	er
परिचय	9 11 0
प्राक्कथन	3
१. कम्यूनिज्म की रूपरेखा	११
२. कम्यूनिस्ट शासन-प्रणाली	38
३. कम्यूनिज्म श्रीर मजदूर	30
४. कम्यूनिज्म के अन्तर्गत जमीन तथा जायदाद की मिल्कियत	३=
५. कम्यूनिषम में समता	४६
६. कम्यूनिचम के ग्रधीन न्यायालय तथा न्याय	५०
७. साम्यवाद का लीह ग्रावरण	২ ७
कम्यूनिज्म श्रीर धर्म	६२
 कम्यूनिज्म के ग्रधीन शिक्षा-प्रणाली 	७१
१०. कम्यूनिएम के ग्रधीन खाद्य वस्तुश्रों तथा माल का उत्पादन	53
११. कम्यूनिज्म के घधीन पारिवारिक जीवन स्त्रियां ग्रीर बच्चे	83
१२. कम्यूनिज्म में व्यापार	१०२
१३. कम्यूनिष्म का विस्तार	११३
१४. शांतिपूर्ण सहम्रस्तित्व भीर सैन्यवाद	१२५
१५. कम्यूनिज्म ग्रोर स्वतन्त्र संसार	१३६
१६. कम्यूनियम का मुक़ाविला कैसे किया जाए	188
ग्रमरीका के राष्ट्रपति का यूनियन की दशा के विषय पर भाषण	१५८

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्राक्कथन

"कम्यूनिज्म पर प्रथम पुस्तक" में अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिज्म पर दो सौ से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्यों कि कम्यूनिज्म के विषय पर प्राय: यही पूछे जाते हैं। उत्तर सरल भाषा में दिए गए हैं और इनका अभिप्राय यह है कि कम्यूनिज्म के सिद्धान्त पर विचारात्मक तर्क-वितर्क में न पड़ते हुए इस सम्बन्ध में पाठकों को प्रारम्भिक जानकारी दी जाए। सोल-हवें अध्याय में, जिसका शीर्षक है, "कम्यूनिज्म का मुकाबिला कैसे किया जाए" कम्यूनिज्म का मुकाबिला करने के कुछ स्पष्ट तथा ठोस सुभाव देने का प्रयास किया गया है। यद्यपि इस प्रथम पुस्तक को कम्यूनिज्म सम्बन्धी प्रश्नों का अन्तिम तथा पूर्ण उत्तर नहीं कहा जा सकता तथापि इतना अवश्य है कि इस विषय पर प्रारम्भिक जानकारी के लिए यह एक उद्धरण पुस्तक अवश्य है जिससे तुरन्त ही लाम उठाया जा सकता है।

श्रायुनिक कम्यूनिक्म के श्राच्ययन में जिन मूल सूत्रों से फायदा उठाया गया है उनमें संयुक्त राष्ट्रमण्डल की सरकारी रिपोटें, श्रमरीकी सरकार के प्रकाशन शौर उस देश में प्रकाशित अन्य प्रामाणिक पुस्तकें इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही कम्यूनिस्ट देशों के अनगणित प्रकाशनों से भी कुछ तथ्य उद्घृत किए गए हैं।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पहला ग्रध्याय कम्यूनिज्म की रूपरेखा

१. कन्यूनिक्म क्या है ?

श्राधुनिक कम्यूनिज्म की नींव माक्स तथा एंजल्ज ने रखी है। उन्होंने इसे वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। साधारण शब्दों में यह सिस्टम इस बात का चोतक है कि उत्पादन तथा विभाजन के सब साधनों पर जन साधारण (ग्रर्थात् राज्य-स्टेट) का सामूहिक श्राधिपत्य हो। (परन्तु यह ग्रावश्यक नहीं है कि निजी प्रयोग की वस्तुएं भी इनमें शामिल हों)। सैद्धान्तिक रूप में कम्यू-निज्म का ग्राधार नीचे लिखे नियमों पर है:

१. सारी जनता मिलकर सार्वजनिक कल्याण के लिए काम करे और कुल उत्पादन से उन्हें अपने परिश्रम का फल मिले। वितरण का नियम यह हो। "हर एक से उसकी योग्यता अनुसार काम, हर एक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उजरत।"

२. वर्गहीन समाज में हर किस्म के काम को, चाहे वह बौद्धिक हो या शारीरिक, समान मान्यता दी जाए। वर्गभेद मिटते ही स्टेट के ग्रस्तित्व का ग्रन्त हो जाएगा ग्रर्थात् केन्द्रीय सत्ता ग्रनावश्यक हो जाएगी।

कम्यूनिज्म इस रूप में वस्तुतः कहीं भी मौजूद नहों है और नहीं भविष्य में इस मंजिल को पा लेने की आशा की जा सकती है।

इस युग के कम्यूनियम में उत्पादन की सुविधाएँ, साधन तथा सामग्री स्टेट या इससे सम्बन्धित किसी संस्थापन—जैसे कारखाने ग्रथवा सामूहिक फ़ामं— के हाथ में होती हैं। सोवियत यूनियन में जमीन भी स्टेट के ग्रधिकार में है। ग्रधिकार को इतना केन्द्रित कर दिया गया है कि सोवियत यूनियन एकाधिकारी राज्य वन गया है। तमाम मानव तथा भौतिक साधनों पर एक जटिल सरकारी प्रशासन ढांचे द्वारा कम्यूनिस्ट पार्टी ग्रौर उसके ग्रान्तरिक नेतृत्व का ग्रधिकार सुदृढ़ रूप में बना रहता है। काम तथा सेवाग्रों के ग्राधार पर नए वर्गीय भेव पैदा होते हैं । Digitiz क्रांक्रियागु वर्षे क्रांक्रिकारी ज्यां होते हैं त्रामीक्षया त्रथा द्वारी क्रांक्रिया वहत वड़ा हाथ रहता है ।

रूस के ग्रांतिरिक्त ग्रन्य कम्यूनिस्ट देशों में (विशेषतया पूर्वी यूरोप, उत्तरी वियेतनाम ग्रीर उत्तरी कोरिया के तथा कथित गणराज्यों में कम्यूनिस्ट ग्राधिक प्रणाली बहुत कम प्रगति कर पाई है। उदाहरण के लिए, इन देशों में ग्रगी तक निजी सम्पत्ति तथा व्यवसाय ग्रहण करने की स्वतंत्रता है, यद्यपि प्रतिवंध कठोर हैं, ग्रीर सरकारी नियन्त्रण कड़ा है। कम्यूनिस्ट चीन में प्रचलित कम्यूनिज्म की रूपरेखा भिन्न है। (प्रश्न नम्बर दस देखिए)

पिछले दिनों रूस से वाहर के कुछ कम्यूनिस्ट नेताग्रों ने मत प्रकट किया
है कि सोशलिएम (कम्यूनिएम) तक पहुँचने के लिए ग्रलग-ग्रलग राहें हो सकती
हैं। परन्तु यह "राष्ट्रवादी" कम्यूनिस्टों का मतभेद कम्यूनिएम के वास्तविक
ग्रिभित्राय से नहीं, केवल उस तक पहुँचने के तरीकों से है।

े. आधुनिक कम्यूनिज्य के स्रोत क्या हैं ?

सांभी मिल्कियत का नियम कम्यूनिस्टों की कोई नई उपज नहीं है। हजारों वर्ष पूर्व इस नियम को मानने वाले तथा इसका पालन करने वाले लोग मौजूद थे। कुछ असम्य कवीलों में अब भी जमीन सांभी मिल्कियत समभी जाती है।

मानसं तथा एंजल्ज ने उन्नीसवीं शताब्दी के पूंजीवाद का ग्रध्ययन करके ग्रपना दृष्टिकोण पेश किया। उन्नीसवीं शताब्दी के ग्रधं तक पूंजीवाद में कुछ विशेषताएं ऐसी थीं जिनसे मानसं के ग्रन्तरवर्गीय संघर्ष के सिद्धान्त की पुष्टि हुई।

सबसे पहले मार्क्स ने पूंजीवाद के "वैज्ञानिक" विश्लेषण तथा उसके "ग्रंत-विरोध" पर जोर दिया। उनका मत था कि इन "ग्रन्तिविरोधों" के कारण श्रमजीवी वर्ग ग्रौर वुर्जुंग्रा (उत्पादन के साधनों के मालिक) वर्ग के बीच संघर्ष बढ़ता जाएगा। मार्क्स ने यह भी कहा कि इस संघर्ष के फलस्वरूप 'मजदूर या सर्वेहारा ऋन्ति' हो जाएगी जो एक नई समाजी व्यवस्था—कम्यूनिज्म को जन्म देगी।

१८४८ में मार्क्स तथा उनके सहयोगी एंजल्ज ने "कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो" प्रकाशित किया। इसमें सोशलिज्म के मूल सिद्धान्त लिखित हैं जिन्हें बाद में रूस के क्रान्तिकारी नेतायों—लेनिन तथा स्टालिन—ने कम्यूनिज्म का रूप दिया। १६१८ में रूसी बोलशेबिक पार्टी ने निकोलाई-लेनिन के नेतृत्व में

ग्रपना नाम बदल कर प्राविष्ठ Samai Foundation Chennai and e Gangotri ग्रापना नाम बदल कर प्राविष्ठ रूस कम्यूनिस्ट पार्टी रखे लिया। बाद में यह सोवियत यूनियन की कम्यूनिस्ट पार्टी (सी. पी. एस. यू.) कहलाने लगी।

३. कम्यूनियम की समाजी व्यवस्था में व्यक्ति का वया स्थान है ?

कम्यूनिस्ट समाज में व्यक्ति पर ग्रनगणित प्रतिवन्ध लगे होते हैं। उसे ग्रपने व्यवसाय तथा पारिश्रमिक के विषय में कुछ कहने का ग्रधिकार नहीं है। काम के हालात तथा शर्तों के सम्बन्ध में उसकी कोई ग्रावाज नहीं। ग्रवकाश का समय उसका ग्रपना नहीं होता। वह ग्रपने वच्चों की परविरिश, ग्रपनी तथा ग्रपनी पत्नी की इच्छानुसार, नहीं कर सकता।

कम्यूनिज्म के ग्रन्तगंत साधारण गृहणी घर से वाहर काम करने पर विवश है, ताकि उसका कुटुम्ब जीवित रह सके। सोवियत यूनियन में भारी साधारण काम प्रायः स्त्रियाँ ही करती हैं। सोवियत परिवार इस हद तक तो ग्राजाद हैं कि किसी भी धर्म के ग्रनुयायी वनें परन्तु इस स्वतन्त्रता के प्रयोग पर उन्हें काफ़ी परेशानी तथा खतरा हो सकता है।

कम्यूनिस्ट समाज में व्यक्ति को कोई श्रिषकार, मूल श्रिषकार के रूप में प्राप्त नहीं है। जो सीमित श्रिषकार उसे मिले हुए हैं वह सरकार की देन हैं और श्रपनी इच्छानुसार वह उन्हें किसी समय भी सीमित कर सकती है या उन्हें पुर्णतया खत्म कर सकती है। इसके श्रितिरिक्त व्यक्ति पर कई प्रकार के राजनीतिक दवाव डाले जाते हैं। पुलिस उसकी निगरानी करती रहती है। वह राज्य के श्रिषकारारूढ़ श्रिषकारवादी एजन्सियों की दया का पात्र वन कर ही रह सकता है। रूस में पुलिस का नियन्त्रण कुछ कम कर दिया गया है। परन्तु चीन में इसे और भी कठोर वना दिया गया है।

व्यक्ति की भ्रावश्यकताओं तथा भ्राकांक्षाओं की भ्रोर कम्यूनिषम बहुत कम ध्यान देता है, परन्तु यदि मजदूरों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी हो तो सरकार तुरन्त ही कदम उठाती है। ऐसी स्थिति में कभी-कभी यह भी भ्राव-श्यक हो जाता है कि काम करने वाले लोगों को कुछ सुविधाएँ दी जाएँ ताकि पैदावार में वृद्धि हो भ्रौर सरकार की भ्रावश्यकताएँ पूरी हों।

राज्य, कम्यूनिस्ट पार्टी का बाहरी चोला है। यही सोवियत समाज तथा ग्रन्य कम्यूनिस्ट देशों की राह है, मंजिल है। ग्रन्य कम्यूनिस्ट देशों में विभिन्न संस्थान सोवियत सिस्टम के ही प्रतिरूप हैं।

किसी सम्यूषिक्ट अनेस्प्र (जैसे मुनोस्का श्रिका) में nrय बित्र कि कि में बुनियादी बातों में रूस से मिलता-जुलता है।

४. क्या कम्यूनिस्ट पार्टी पर सदैव कम्यूनिस्ट लेवल लगा होता है ?

वहुत से कम्यूनिस्ट देशों में कम्यूनिस्ट पार्टी किसी ग्रीर नाम से काम करती है। किही यह "वर्क पार्टी" का स्वरूप घारण करती है तो कहीं "पीपुल सोशलिस्ट पार्टी" का भेष वदलती है ग्रीर कहीं कोई दूसरा ही नाम ग्रहण कर लेती है।

दूसरा नाम धारण करने के कई अभिप्राय हो सकते हैं। (१) जनता का अधिक सहयोग पाने के लिए कम्यूनिस्ट लेवल के स्थान पर कोई और नाम रखना। (२) जब सांभे मोर्चे बनाने के कार्यक्रम पर चल रही हो तो उसके अधिक से अधिक अनुयायी बनाना। अथवा (३) पार्टी के अवैध हो जाने की स्थिति में कानून से बचने के लिए और नाम रखना।

५. कम्यूनिस्ट कौन हैं और अन्य लोगों से किस प्रकार भिन्न होते हैं ?

कम्यूनिस्टों का कोई भी व्यवसाय हो सकता है। वे विद्यार्थी, श्रघ्यापक, मजदूर संगठन के सदस्य अथवा सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। अपने साथियों से इसलिए भिन्न होते हैं कि उनका राजनीतिक दृष्टिकोण मास्को-पेपिंग "पार्टी लाइन" के अनुकूल होता है। मास्को-पेपिंग लाइन का अन्तिम आशय यही है कि स्वतन्त्र देशों का विनाश कर दिया जाए।

यह सम्भव है कि कोई कम्यूनिस्ट अपने व्यवहार तथा आचरण से अपने कम्यूनिस्ट होने की स्पष्ट घोषणा न करे। प्राय: वह छिप कर ही काम करता है या यदि खुल्लम-खुल्ला काम कर रहा है, तो वह यह कहता है कि वह जनहित में कार्यप्रस्त है, परन्तु इसके साथ ही, अधिकार हासिल करने की मुहिम में कम्यूनिस्टों की सहायता भी करता रहता है। पार्टी के संगठन तथा नीति पर स्थानीय कम्यूनिस्ट कभी खुलकर आलोचना नहीं करता। वह आमतौर पर मास्को-पेपिंग या उनके एजेण्टों की हिदायतों पर अमल करने के लिए हर समय तत्पर रहता है और सुव्यवस्थित सामाजिक, आधिक तथा राजनीतिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

यह तो सम्भव है कि पार्टी की झांतरिक तब्दीलियाँ (जैसे उथल-पुथल जो स्टालिन के वैभव को खत्म करने के बाद हुई) मास्को लाइन के प्रति पूर्ण निष्ठा पर प्रभाव डाले, परन्तु मार्क्सवाद, लेनिनवाद के मूल सिद्धांतों का खण्डन न तो नए भैंशं^{रां}सरतें^{प्रहे}भीरिभाषी विष्ठा भीर्थं एसिमि सरते हैं। उस्हें भिणाराष्ट्रवादी कम्यूनिज्म" का स्वतन्त्र मार्ग अपना रखा है।

फिर भी १९४६ में हंगरी में रूस के सशस्त्र हस्तक्षेप के कारण लौह आव-रण से वाहर बहुत-सी कम्यूनिस्ट पार्टियों में मतभेद तथा परित्याग की भावना उत्पन्न हो गई।

६. चीनी ! सोवियत गुट से वाहर कम्यूनिस्ट पार्टी का गठन कैसे होता है ?

कम्यूनिज्म को अमली प्रोग्राम के तौर पर पेश करने वाले लोग वे होते हैं जो हालात से संतुष्ट,न हों और सरकार का तख्ता उलट कर उसे बदलना चाहें। किसी न किसी समय वह कम्यूनिस्ट प्रचार से या कम्यूनिस्ट पार्टी के मेम्बरों से प्रभावित होते हैं और उनकी सहायता से कम्यूनिस्ट आन्दोलन में और भी खुव जाते हैं। आन्दोलन को प्रारम्भ करने वाले अधिकतर लोग मास्को, पेकिंग या किसी अन्य कम्यूनिस्ट केन्द्र में भेजे जाते हैं ताकि कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों तथा. ऋान्ति की विधियों में निपुणता प्राप्त कर सकें।

ऐसे ग्रादर्शवादी भी कम्यूनिज्म के मायाजाल में फंस जाते हैं जो ईमान-दारी से किसी वेहतर समाजी व्यवस्था की तलाश में हों। वह कम्यूनिज्म की वास्तविक वृत्ति से ग्रनुभूत नहीं होते। परन्तु ऐसे कम्यूनिस्ट जो पार्टी ग्रनुशा-सन का पालन नहीं करते, स्थानीय पार्टी के जन्मदाता नहीं वन सकते।

कभी-कभी पार्टी का गठन मास्को या पेकिंग के एजेन्ट भी करते हैं। उन्हें इसी विशेष उद्देश्य के लिए ही भेजा जाता है। उदाहरण के लिए मध्य अम-रीका के देश गोयण्टेमाला में कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना विदेशी कम्यूनिस्टों ने की थी।

पूर्वी यूरोप में भी जिन लोगों ने वहाँ की वैध सरकारों का विध्वंस किया है, उनमें से ग्रधिक वह थे जो काफी समय तक रूस में रह चुके थे; बहुत से तो रूसी नागरिक भी थे।

७. कम्यूनिल्म तथा सोशलिल्म में क्या ग्रन्तर है ?

ग्राधुनिक सोशिलज्म किसी हद तक मार्क्स तथा एंजल्ज के सिद्धान्तों पर ग्राधारित था। परन्तु घीरे-धीरे यह पुराने नियम छोड़ दिये गए। जुलाई १६५६ में सोशिलस्ट इन्टरनैशनल की एक मीटिंग हैम्बर्ग (जर्मनी) में हुई। इसमें रूढ़िवादी मार्विसज्म से नाता तोड़ने की घोषणा की गई ग्रौर निर्णय किया गया कि कम्यूनिस्ट पार्टियों के साथ मिलकर काम न किया जाए। सोशिलस्टों से राजनीतिक शिष्टं सार्क के जिसने अग्रहम आपस्को से किए। बहु सक ब्रुह्मफल रहे। सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप के विरुद्ध हैं। सोशलिस्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे वैध तरीके ग्रपनाते हैं। वे स्वतन्त्र चुनाव के समर्थंक हैं। एक हद तक निजी व्यवसाय की इजाजत देते हैं, परन्तु वह यह ग्रवस्य चाहते हैं कि देश के प्राकृतिक तथा मूल साधन राज्य के ग्रधिपत्य में हों। लोकसेवा संस्थानों तथा उत्पादन साधनों पर राज्य का ही नियन्त्रण रहे।

कम्यूनिस्ट जहां कहीं अधिकारारूढ़ हैं वहां केवल एक ही (अर्थात उनकी अपनी पार्टी) संस्था को जीवित रहने की इजाजत है, या उन पार्टियों को जीवित रहने दिया जाता है जो पूर्ण रूप से उनके नियन्त्रण में रहें। चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने का अधिकार भी ऐसी पार्टियों को ही दिया गया है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित कर दी जाती है। इन सबको कम्यू-निस्ट पार्टी स्वयं ही चुनती है। यदि उसे किसी अन्य पार्टी ने चुना हो तो कम्यू-निस्ट पार्टी उसका समर्थन करती है। कम्यूनिस्ट वल पूर्वक अधिकारारूढ़ रहने में विश्वास रखते हैं। सोशलिस्टों का दृष्टिकोण इस विषय में उनसे भिन्न है।

द. कम्यूनिचम तथा गरातन्त्रवाद में विशेष मतभेद क्या हैं ?

कम्यूनिज्म में सरकार व्यक्ति को केवल राज्य के लिए काम करने वाला एक श्रमिक समफती है। उसकी हैसियत सरकारी मशीन के पुर्जे से ग्रधिक नहीं होती। सच्चे गणतन्त्र में स्टेट ग्रपने नागरिकों की भलाई के लिए प्रयत्न-शील रहती है। उसके ग्रन्तगंत शासन मशीनरी निश्चित ग्रवधि के पश्चात स्वतन्त्र चुनाव के जरिए बदलती रहती है। परन्तु कम्यूनिस्ट स्टेट में सरकार ग्रपने ग्रापको स्थायी रूप से सत्तारूढ़ रखने के लिए तदबीरें करती रहती है। कभी-कभी किसी नेता की मृत्यु के कारण या ग्रधिकार के संग्राम स्वरूप ग्रधि-कारी बदल जाते हैं।

सोवियत संविधान अपने नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारित तो करता है, परन्तु उनका प्रयोग सरकार की इच्छानुसार सीमित किया जा सकता है या विल्कुल खत्म किया जा सकता है। गणतन्त्रीय सरकार, इब्राहिम लिंकन के शब्दों में "ऐसी सरकार है जो जनता की हो, जनता के जरिए हो तथा जनता के लिए हो।"

कम्यूनिस्टों का विश्वास है कि मार्क्स और एंजल्ज की हिदायतों पर अमल करते हुए यदि मजदूर वर्ग या सर्वहारा को सत्तारूढ़ करना है तो सब गैर- कम्यूनिस्टिं औरकारिं की करिया कर्मा प्राप्ति पाइँगां । इसि स्ट्रिंस मि कि कि एत कम्यूनिस्टों की नजर में सब साधन उचित हैं। लेनिन ने लिखा था, "यह ग्रति ग्रावश्यक है कि प्रत्येक कम्यूनिस्ट पार्टी ग्रन्य राजनीतिक संस्थाओं की भांति साधारण संस्था नहीं होती। बल्कि वह मौजूदा सरकार के विरुद्ध संगठित पड़-यन्त्र होती है।"

६. वया ग्राधुनिक कम्यूनिज्म ने ग्रपने उद्देश्य बदल दिए हैं ?

फरवरी, १९५६ में सोवित यूनियन की कम्यूनिस्ट पार्टी (सी० पी० एस० यू०) की वीसवीं कांग्रेस हुई। इसमें निर्णय किया गया कि कम्यूनिस्ट अपनी नीतियों में समयानुसार परिवर्तन करें परन्तु उनका अन्तिम उद्देश्य वही रहे जो पहले से निर्धारित है। पार्टी नेता निकिता खू इचेव ने नए सी० पी० एस० यू० की ''कार्य प्रणाली'' की व्याख्या की। इसके अन्तर्गत ''पूंजीवादी'' देशों के अमिकों की वड़ी संख्या स्वयं ही कम्यूनिजम को स्वीकार कर लेगी। इसलिए हिंसात्मक कार्यविधियों और गृह संग्राम को प्रचण्ड करना आवश्यक नहीं है।

खू इचेव ने एलान किया कि "सोशलिज्म (कम्यूनिज्म) की मंजिल सुस्था-पित संसदीय बहुसंख्या द्वारा भी हासिल की जा सकती है, जिसके समर्थन तथा सहायता के लिए सर्वेहारा की महान ऋन्तिकारी संस्था मौजूद हो।"

इस प्रकार कुछ समय के लिए हिंसा पर भरोसा रखने की वजाए इस वात पर वल दिया गया कि कम्यूनिस्ट प्रत्येक स्थान पर सांके राजनीतिक सार्वज-निक मोर्ची का समर्थन करें।

जून १६६० में प्रधान ग्राइजन हावर के प्रस्तावित दौरे से पूर्व टोिकयो में जापानी कम्यूनिस्टों तथा बामपक्षी पार्टियों ने बड़े पैमाने पर दंगे कराए। इससे कम्यूनिज्म के इस मूल सिद्धान्त की ग्रिमिब्यक्ति हुई कि बातें शान्ति की करो परन्तु लोगों को हिंसात्मक कार्यवाइयों के लिए उत्तेजित करते रहो।

कम्यूनिस्ट सरकारों ने संसार भर में राजनीतिक गांठ-सांठ करने के लिए अपने सदस्य छोड़ रखे हैं और पड्यंत्रकारियों तथा जासूसों की टोलियां नियुक्त कर रखी हैं।

१३ जून, १६६० को ग्रमरीका के स्टेट विभाग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया था कि "एक विश्वसनीय ग्रनुमान के ग्रनुसार कम्यूनिस्ट गुट तथा स्वतंत्र संसार में चीनी सोवियत गुट के देशों के जासूसी तथा सुरक्षा के २७ संस्थानों में लगभग ३ लाख निपुण ग्रधिकारी काम कर रहे हैं।

स्टेट विश्वातानि अप्रात्मीत कि प्रिक्षेता हैं। त्यहान स्वीति विश्वाति कि स्वाति विश्वाति कुछ वर्षों में स्वतंत्र संसार के ११ देशों में १३० सोवियत जासूस पकड़े गए हैं। इनमें से १३ समरीका में पकड़े गए। रिपोर्ट में दर्ज है कि "जासूसी तथा स्रदेध कार्य-विधियों के कारण ४७ सोवियत कर्मचारी स्वतंत्र संसार तथा संयुक्त राष्ट्रमंडल से बाहर निकाले जा चुके हैं।"

१०. क्या कम्यूनिस्ट चीन में कम्यूनिलम का कोई विभिन्न रूप है ?

कम्यूनिस्ट चीन में कम्यूनिष्म का विकास चीनी-सोवियत गुट के अन्य देशों से कुछ विभिन्न ही रहा है। चीन ने लेनिन के इस फारमूले पर अमल नहीं किया कि "क्रांतिकारी नेतृत्व" शहरी सर्वहारा को सौंपा जाए। इसने "सोश-लिष्म" (कम्यूनिष्म) के निर्माण के लिए किसान जनता को बुनियाद बनाया।

पेपिंग सरकार ने भूमि सुधार दो स्टेजों में करने के बाद १६५ में तीसरा और बहुत ही कठोर प्रोग्राम अपनाया। यह कम्यून सिस्टम था। पहली स्टेज में जमींदारों से भूमि छीन कर छोटे-छोटे क्षेत्रों के रूप में भूमिहीन किसानों तथा मुज़ारों में तक़सीम कर दी। दूसरी स्टेज में छोटे-छोटे टुकड़ों को एकत्रित करके "सामूहिक फार्म" या मजदूरों के कोग्रापरेटिव बना दिए गये। यह सब सोवियत नमूने पर बनाए गये थे। इस प्रोग्राम के अन्तंगत सामूहिक खेतों की मिल्कियत में किसानों का भी हिस्सा था। इन्हें खेती बाड़ी के श्रीजार और निजी जरूरत की चीजें रखने की ग्राज़ा थी। साधारण गांव की चिर प्रचलित व्यवस्था में कोई मूल परिवर्तन भी नहीं किया गया।

१६५५ में पेपिंग सरकार ने एक नये दौर का प्रारम्भ किया। एलान हुआ कि "उन्नित की ग्रोर लम्बी छलांग" के लिए आन्दोलन आरम्भ किया जायेगा ग्रौर तथाकथित कम्यून स्थापित किए जाएंगे। चुनाचे भूमि की व्यक्तिगत मिल्कियत को खत्म कर दिया गया। गांव के गांव थोड़े ही समय में उठा दिए गये ग्रौर उनके स्थान पर बैरिक किस्म की इमारतें बना दी गई जिनमें सैकड़ों परिवार एक ही स्थान पर रहने लगे। निजी ग्रावश्यकता की वस्तुएं जनता की मिल्कियत घोषित कर दी गई भूमि के टुकड़ों तथा ग्रादिमियों को इकट्ठा करके कम्यून बनाए गए। श्रव इन पर कम्यून के ग्रिवकारियों की कड़ी निगरानी रहती है, जिन्हें चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी नियंत्रित करती है। (चौथा तथा दसवां ग्रध्याय देखिए)।

मास्को के सोवियत नेताओं ने कम्यून सिस्टम को अपनाने के लिए कुछ अधिक जोश नहीं दिखाया है, ताहम वह पेपिंग के इस अधिकार को मानते हैं कि वह "सोशलिज्म" तक पहुँचने के लिए स्वयं ही अपनी राह निश्चित करे।

दूसरा ग्रध्याय कम्यूनिस्ट शासन-प्रणाली

१. सोवियत यूनियन में कितने ब्रादमी कम्यूनिस्ट हैं ?

सोवियत यूनियन की इक्कीस करोड़ की ब्रावादी में अस्सी लाख से भी कम (लगभग चार प्रतिशत) कम्यूनिस्ट पार्टी (सी० पी० एस० यू) के सदस्य हैं। चौदह ग्रौर छव्वीस वर्ष के बीच की ब्रायु के कोई एक करोड़ अस्सी लाख युवक ऐसे हैं जो युवक कम्यूनिस्ट लीग (कोमसोमोल) के सदस्य हैं। यह संस्था सोवियत युवकों को कम्यूनिस्म की सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षा देती है। शेप करोड़ों सोवियत नागरिक कम्यूनिस्म को इसलिए स्वीकार करने पर विवश हैं क्योंकि किसी ग्रीर सिस्टम का उन्हें पता ही नहीं ग्रौर उन्हें सिखाया गया है कि कम्यूनिस्म के मूल सिद्धान्त खोज तथा परख से ऊपर हैं।

कम्यूनिस्ट पार्टी ग्रीर कोमसोमोल के सदस्यों में से बहुत से इन संस्थाग्रों में इसलिए शामिल होते हैं कि ऊंची पदिवर्या प्राप्त कर सकें, या राजनीतिक मैदान में ग्रपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें। नवस्थापित कम्यूनिस्ट देशों में तो ग्रवसरवादी लोग इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए कि वहां की पार्टी को "संशोधन" की मुहिम चला कर .ग्रपने सदस्यों की संख्या घटानी पड़ी। पिट्ठू कम्यूनिस्ट देशों में जनता की ग्रत्थिक बहुसंख्या गैर कम्यूनिस्ट है।

 क्या सोवियत रूस में कम्यूनिस्टों को सोशलिज्म इत्यादि के विषय पर राजनीतिक विचार प्रगट करने की अनुमति है ?

रूस का दण्ड विधान कम्यूनिज्म के अतिरिक्त किसी और राजनीतिक सिद्धान्त के प्रचार को जुमें मानता है। इस दण्ड विधान के अन्तर्गत इस प्रकार का आरोप लगने पर "क्रान्ति विरोधी अथवा राज्य विरोधी" कार्यवाहियों के आधार पर मुकद्मा चलाया जा चुका है। और दण्ड भी दिए गए हैं। १६३७-३८ रक्तयुक्त "सफाई के मुकदमों" के शिकार और बाद के कुछ दूसरे लोग इसी सूचि में शामिल थे। मास्को को टबर्ज का का ज़िस्का के कि का प्रकार की विश्व की है ग्रीर उन्हें स्टालिन का 'कारनामा' ठहराया है। १६३० के दशक में जिन राजनी-तिक कैदियों को दण्ड दिए गए थे उन्हें ग्रंग मुक्त कर दिया गया है। कुछ कैदियों के लिए इतनी सजा भुगतने के पश्चात् ''पुनस्थीपन तथा पुनर्वास'' की तदवीरें की गई हैं। परन्तु वर्तमान ग्रधिकारियों ने भी यह प्रत्यक्ष रूप में जता दिया है कि रूस में केवल कम्यूनिरूम ही का प्रचार किया जा सकता है ग्रीर किसी सिद्धान्त को सहन नहीं किया जाएगा। पिट्ठ देशों में भी किसी हद तक निन्दत राजनीतिक नेताग्रों का ''पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन'' किया गया है।

३. क्या यह ठीक है कि कम्यूनिस्ट शासन में अजदूरों का राज होता है ?

नहीं। रूस में जनता के ग्रसली शासक मजदूर नहीं, सोवियत यूनियन की कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य होते हैं। ग्रल्प सख्या में होते हुए भी उनके ग्रधिकार ग्रसीमित होते हैं। यही ग्रुप नीति का निर्णय करता है, फैसले तथा हिदायतें देता है। यही स्वयं कम्यूनिस्ट पार्टी का नेतृत्व करता है। इसके निर्णय ही पार्टी के निर्णय होते हैं। पार्टी का प्रोग्राम विधान सभाग्रों ग्रीर प्रशासकीय नौकरशाही तक पहुँचाया जाता है जो प्रत्येक सरकारी स्तर पर उसे कार्यान्वित करती हैं।

स्टालिन ने १६२६ में कहा था "सर्वेहारा (श्रिमिक) वर्ग की डिक्टेटरिशप अपने आप नहीं चलती, इसे पार्टी की ताकतें इसके (पार्टी के) निर्देशन में चलाती हैं।" उन्होंने यह भी कहा "कोई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा इन्तजामी समस्या ऐसी नहीं है जिसे स्थानीय सोवियत या कोई और अवामी संस्थापन पार्टी के निर्देश के विना हल कर सकें।" सोवियत यूनियन की कम्यूनिस्ट पार्टी इस नियम पर बहुत सख्ती से अमल करती है।

अन्य कम्यूनिस्ट देशों में भी कम्यूनिस्ट पार्टियों का काम करने का तरीका यही है। परन्तु पिट्ठू देशों में एक वात और वढ़ जाती है कि देशी पार्टियों का नेतृत्व भी सी॰ पी॰ एस॰ यू॰ करती है।

तमाम कम्यूनिस्ट देशों में काम का सारा वोक श्रमिक वर्ग के कंधों पर पड़ता है। राज्य की ग्रोर से निश्चित काम उन्हें कम्यूनिस्ट पार्टी की नौकर-शाही की निगराना में तथा उसके निर्देशानुसार पूरा करना पड़ता है। प्रारम्भ में कम्यूनिस्टों ने कल्पना की थी कि "सर्वहारा ऋन्ति" के पश्चात् सब वर्ग खत्म हो जाएंगे ग्रीर वर्गहीन समाज वन जाएगा। परन्तु वास्तविक रूप में तमाम कम्यूनिस्ट देशों में, चाहे उनके संविधान में कुछ भी लिखा हो, बहुत सख्त वर्गीय भेद मौजूद हैं। ये नए भेद कभी काम तथा सेवाग्रों की किस्म पर ग्राधारित होते हैं ग्रीर कभी किसी व्यक्ति की सैनिक व्यवस्था या नौकर-शाही में पदवी से उत्पन्न होते हैं।

सोवियत समाजी व्यवस्था में उच्च कम्यूनिस्ट ग्रधिकारी, शासक, उच्च सैनिक ग्रफसर इत्यादि सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। यह ग्रुप नौकर शाही तथा सैनिक व्यवस्था में मध्यम स्तर के लोगों से विल्कुल भिन्न होता है। फैक्ट्री मैनेजर, सामूहिक फार्मों के ग्रध्यक्ष, व्यवसायी जैसे बकील, डाक्टर, प्रोफैसर, वैज्ञानिक, प्रमुख कलाकार, सरकारी व्यापारिक-संस्थापनों के डायरेक्टर, सबके सब साधारण मजदूरों तथा किसानों से बहुत ऊंचा समाजी रुतबा पाते हैं।

ग्रामदनी, शिक्षा तथा ग्रन्य सुविधाओं में कमी-वेशी से इस वर्गीय भेद का पता चलता है। सोवियत ग्रावादी का केवल दस प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जिसे विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं।

५. कम्यूनिस्ट देशों में शासन विधि क्या है ?

कम्युनिस्ट पार्टी सब ग्रधिकार ग्रपने हाथ में रखती है। वहीं सरकार की नीतियां निर्धारित करती है, वहीं इन पर ग्रमल कराती है। पार्टी पर केन्द्रीय समिति का नियंत्रण होता है। परन्तु वास्तविक रूप कुछ भी हो, तमाम कम्युनिस्ट देशों के संविधान (जो सोवियत विधान के नमूने पर बनाए गए हैं) एक वैध प्रशासन की रूपरेखा ग्रवस्य पेश करते हैं।

उदाहरण के लिए, १६३६ के सोवियत संविधान में एक सुप्रीम सोवियत या दो विधानसभाएँ बनाई गई हैं। एक सभा में सोवियत जनता के सदस्य बैठते हैं ग्रौर दूसरी में सोवियत गणतन्त्रों को सदस्यता दी जाती है।

संविधान के अन्तर्गत चुनाव यद्यपि प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान के आधार पर होते हैं, परन्तु मतदाताओं को उम्मीदवारों का निर्वाचन पार्टी द्वारा दी गई सूची में से ही करना होता है। यदि किसी, मतदाता को मतभेद प्रकट करना हो तो उसे एक विशेष वूथ पर जाकर प्रत्यक्ष रूप में नापसन्दीदा उम्मीदवाराम्ब्राध्यक्षमाञ्चमञ्चाञ्चाञ्चान्हैं uhक्बाद्धिराहै व्यक्कात्करीमवाञ्चलको से खाली नहीं। इसलिए "गुप्त मतदान" का वास्तविक ग्रस्तित्व कोई नहीं है।

सुप्रीम सोवियत को अधिक अधिकार नहीं दिये गए हैं, वह तो केवल सम-थंन तथा पुष्टि करता का रवर स्टैंप है। इसके अधिवेशन आम तौर पर पांच दिन के लिए होते है। आंतरिक अधिकारी वर्ग ने जो वातें पूर्व निश्चित कर रखी हों इन अधिवेशनों में उन पर पुष्टि की मुहर लगवा ली जाती है। मत-भेद प्रकट करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। किसी प्रकार का विरोध सहन नहीं किया जाता हालांकि मेम्बरों को वहस करने का अधिकार दिया गया है।

सुप्रीम सोवियत वयालीस मेम्बर चुनती है जो प्रीजिडयम कहलाते हैं, जिन दिनों सुप्रीम सोवियत के अधिवेशन नहीं होते उन दिनों प्रीजिडयम ही को अधिकार होता है कि आदेश जारी करे, कानूनों की व्याख्या करे, सुप्रीम सोवियत का अधिवेशन बुलाए, या उसे तोड़ दे, कर्मचारी नियुक्त करे या उन्हें वरसास्त कर दे, प्रीजिडयम का अध्यक्ष नाम को रूस का राष्ट्रपति होता है परन्तु उसकी हैसीयत रूसी प्रधान मन्त्री तथा कम्यूनिस्ट पार्टी के मन्त्री से कहीं कम होती है।

रूस में मन्त्री मण्डल उच्चतम विधायक तथा प्रशासकीय संस्था है। इसका आदेश कातून का दर्जा रखता है, खुरुचेव मन्त्रीमण्डल के ग्रध्यक्ष हैं।

१६४० तक रूस में १३ यूनियन गणराज्य शामिल थे। तीन वाल्टिक गणतन्त्र लातिवया लिथुआनिया तथा एस्ट्रोनिया जो पहले स्वतन्त्र देश थे, इसी वर्ष में वलपूर्वक रूस में शामिल कर लिए गए। यूनियन गणतन्त्र का प्रशासन ढांचा सोवियत यूनियन से मिलता-जुलता है परन्तु यह गणतंत्र हर मामले में सोवियत यूनियन के अधीन होते हैं हालांकि दिखावे के लिए उन्हें अब पहले से अधिक आंतरिक स्वाधीनता दे दी गई है।

सुप्रीम सोवियत के जुलाई, १९५६ के ग्रधिवेशन में कमेलो फिनिश सोवि-यत सोशिलस्ट गणतंत्र ने अनुरोध किया था कि उसका दर्जा घटा कर उसे रूसी गणतंत्र के अन्दर स्वायत्त गणराज्य का दर्जा दे दिया जाये। इससे यूनि-यन गणतंत्रों की संख्या केवल पन्द्रह रह गई।

१६४४ में सोवियत संविधान में जो संशोधन किए गए, उनके अनुसार "प्रत्येक यूनियन गणतंत्र को अधिकार है कि वह विदेशी सरकारों से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्ध स्थापित करे, सन्धियां करे, दूत मेजे और बुलाए" और यह भी कि "प्रत्येक यूनियन अपनी अलग सेना रख सकती हैं।" परन्तु यह संशो-

धन के बिला प्राप्ति तेपा वाहलो रूस को सरकारें संयुक्त राष्ट्र मण्डल की सदस्य वन गई।

सुप्रीम सोवियत, प्रीजिडयम और मन्त्री मण्डल की स्रोर से दिए गए स्रादेश यूनियन गणतंत्रों को पहुँचा दिए जाते हैं। फिर इन पर "स्रोबलास्ट" (प्रादेशिक) से लेकर "रईयो" (जिल) स्तर के प्रशासन के जरिए समल कराया जाता है।

६. कम्यूनिज्म में सरकारी कंट्रोल कैसे लागू किया जाता है ?

सोवियत यूनियन के सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य नागरिकों पर कंट्रोल रखने वाली सबसे बड़ी ताकत स्वयं कम्यूनिस्ट पार्टी है। इसकी प्रमुखता का प्रमुख्त संविधान का परिच्छेद १२६ है जिसमें लिखा है: "श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधियों तथा श्रमिकों में जो लोग सबसे कियाशील तथा राजनीतिक तौर पर जागरूक हैं वे सब सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी में एकत्रित हो गए हैं। पार्टी श्रमिक वर्ग का अग्र दल है। सोशलिस्ट पद्धति को मजबूत बनाने में, उसे बढ़ाने और फैलाने में, यह जनता का पथ प्रदर्शन करती है, श्रमिक जनता की सारी सरकार और गैरसरकारी संस्थाओं का यह प्रतिनिध दल है।"

यद्यपि संविधान में लिखा है कि कम्यूनिस्ट पार्टी श्रमिक जनता की तमाम संस्थाओं का अग्रदल है तो भी कुछ समय पहले तक यह हालत नहीं बतायी थी। उदाहरण के लिए १६२० में पार्टी के सदस्यों की नगरों में बहुत संख्या थी परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं-कहीं पार्टी सदस्य थे। अलबत्ता अब पार्टी के प्रतिनिधि प्रत्येक स्तर पर मौजूद हैं। कोई कारखाना, कोई सामूहिक फार्म इन से खाली नहीं है। इन्हीं पार्टी मेम्बरों को मिला कर वह संस्था बनती है जो तमाम योजनाओं तथा नीतियों पर अमल की प्रत्यक्ष निगरानी करती है।

सी० पी० एस० यू० की केन्द्रीय समिति में एक और छोटा-सा ग्रुप होता है। रूस में उसे प्रीजिडयम और कुछ अन्य देशों में पोलित-ज्यूरो कहते हैं। साधारण स्थित में प्रीजिडयम, केन्द्रीय समिति या पूरी पार्टी की ओर से निणंय करता है। कभी-कभी इसके निणंय केन्द्रीय समिति के पूरे अधिवेशन ने रह भी किए हैं। केन्द्रीय समिति के सौ से अधिक मेम्बर हैं।

केन्द्रीय समिति ने अपना प्रभुत्व आप ही स्थायी बना रखा है परन्तु पार्टी के अंतर्द्वन्द्व और अन्य कारणों से इसके मेम्बर बदलते रहते हैं। परन्तु केन्द्रीय समिति कायमुशंसङ्खी। है Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कम्यूनिष्म के अधीन कोई निश्चित गणतंत्रीय कार्य विधि तो होती नहीं, इसलिए पार्टी के अन्दर अधिकार के लिए युद्ध जारी रहता है। इस युद्ध में जो जीतता है, पार्टी का नेतृत्व उसी को प्राप्त होता है। १६३६-३८ में स्टालिन ने "शोधन" के जो निष्करण अभियान चलाए उनके फलस्वरूप सारी ताकत उनके हाथ में आ गई। स्टालिन की मृत्यु के परचात् खू, रुचेव ने धीरे-धीरे सी० पी० एस० यू० में अपना अधिकार जमा लिया। १६५७ में उन्होंने अपने पार्टी-प्रतिद्वन्द्वियों को "पार्टी-विरोधी समूह" सिद्ध करके उनका पार्टी से वहिष्कार करा दिया और पार्टी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इस टोली में पार्टी के भूतपूर्व प्रसिद्ध नेता मालेन्कोव मोलोटोव और कागनोविच शामिल थे। इन के अतिरिक्त भूतपूर्व विदेश मन्त्री शेपीलोव और भूतपूर्व प्रधान मन्त्री बुलगा-निन भी इसी टोली में थे।

निरीक्षण तथा नियंत्रण की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था राष्ट्र सुरक्षा समिति (के० जी० वी०) है। यह कमेटी मन्त्री-मण्डल के प्रति सीधी उत्तरदायी है। इसके कर्त्तंब्य हैं; विदेशों में मुखबिरी, सुरागरसानी तथा जासूसी करना ग्रीर देश के ग्रंदर गुप्त पुलिस का ग्रत्याचारी तहकीकाती प्रशासन बनाए रखना। के० जी० वी० के विशेष महत्व ने इसका दर्जा गृह मन्त्रालय से भी ऊंचा कर दिया ग्रीर १६६० में यह मन्त्रालय तोड़ दिया गया।

सोवियत समाज की प्रत्येक संस्था पर गुप्त पुलिस निगाह रखती है। शहरी संस्थान हों या कारखाने, यूनियन या गणराज्यों के दफ्तर हों या केन्द्रीय मन्त्रालय, कोई इसकी निगरानी से वाहर नहीं, के० जी० वी० का किसी को पकड़ लेना उसे अपराधी सिद्ध कर देने के तुल्य है। के० जी० वी० ने देश भर में मुखबरों का जाल विछा रखा है। पुलिस के अत्याचार और मनमानी धर-पकड़ अब इतनी आम नहीं परन्तु यह कार्य-क्रम किसी समय भी वड़े पैमाने पर आरम्भ किया जा सकता है।

निरीक्षण तथा नियंत्रण की कुछ ग्रौर विधियां भी हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा रूस भर की ग्रायिक व्यवस्था को कावू में रखा जाता है। राजकीय नियंत्रण के मंत्रालय के जिम्मे सरकारी जायदाद की देख-रेख करना, सरकारी खर्च पर नजर रखना तथा योजनाशों ग्रौर प्रोग्रामों की पूर्ति का हिसाव रखना है। इसके कर्मचारी राज्य की पूरी शासन व्यवस्था में फैले हुए हैं।

७. क्रम्यू निर्मार्क्त पुर्तारम् Samai Foundation Chennai and e Gangotri कार्या है ?

गुप्त पुलिस का प्रथम उद्देश्य यह है कि कम्यूनिस्ट पार्टी की नरकार की रक्षा करे और उसे कायम रखे। १६१८ के बाद ही से गुप्त पुलिस के अधिकार बढ़ते गए। सोवियत प्रशासन के लिए इसका महत्त्व भी बढ़ता गया। इसने प्रत्येक गांव तथा कारखाने में अपना आतंक फैला दिया। सरकार के तमाम दपतरों और मंत्रालयों में गुप्त पुलिस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सेना में इसके एजन्ट भरे पड़े हैं जिनका इन्तजाम सेना से पूर्णत्या पृथक् है।

कें जी वी का उच्च ग्रधिकारी पहले जनरल इवान सेरोव था जिसका वाल्टिक ग्रीर हंगरी की पुलिस के ग्रातंक तथा ग्रत्याचार से गहरा सम्बन्ध रहा है। १९५८ में इसका स्थान ग्रलक्सान्द्र शेलीपिन ने लिया जो कभी कोमसोमोल का ग्रम्यक्ष रहा था ग्रीर कम्यूनिस्ट नवयुवकों की तहरीक में उसका भाग महत्त्वपूर्ण था। (नवां ग्रम्याय देखिए)

भूतपूर्व गृहमंत्रालय (एम० वी० डी०) के कत्तं व्यों में कैंदलानों तथा दण्ड देने के अन्य केन्द्रों की व्यवस्था, नागरिक पुलिस विमाग की देखरेल तथा नागरिक सुरक्षा के कुछ भाग शामिल थे। वेगार के कैम्प (तीसरा अध्याय देखिए) बहुत समय तक एम० वी० डी० के अधीन एक उप-विभाग जी. यू. आई. टी० (भूतपूर्व जी० यू० एल० ए० जी०) के सुपूर्व रहे। जबरी वेगार के कुछ विभाग १९५३ में वित्त-मंत्रालयों के अधीन कर दिए गए। १९६० में एम० वी० डी० को तोड़ दिया गया। इसका काम यूनियन गणतन्त्रों को दे दिया गया।

 जिरफ्तारियों के लिए गुप्त पुलिस कौन-कौन से विशेष तरीके इस्तेमाल करती है ?

गिरफ्तारियों के सिलसिले में ऐसे ढंग अपनाए जाते हैं कि अभियुक्त भय-भीत हो जाए। पुलिस प्राय: रात के समय पूछगछ करती है। तहकीकात से पहले ही मान लिया जाता है कि अभियुक्त ने सचमुच ही अपराध किया है। इसलिए तहकीकाती अफसर की यही कोशिश होती है कि कैदी से "अपराध स्वीकार" कराले और उसे विवश करके 'अपराध में साथियों' का पता चलाले।

सोवियत नेताओं की ''उदार'' नीति के यनुसार सी० पी० एस० यू० ने राज्य पुलिस के अधिकार कुछ कम कर दिए हैं और न्यायिक विधियां भी कुछ नमें कर दी हैं परन्तु गुप्त पुलिस का ढांचा ग्रभी कायम है। पहले से अब पुलिस पिट्छ देशों में पुलिस के ग्रत्याचार के कई दर्जे हैं। हंगरी में स्थिति बहुत ही बुरी बताई जाती है। कम्यूनिस्ट चीन में पुलिस का नियंत्रण इतना कड़ा है कि रूस में स्तालिन के काल में भी ऐसा नथा। देश भर में गैर सरकारी मुखबरों का जाल विछा हुग्रा है जो पुलिस को हर प्रकार की सूचना देते हैं। यह जाल प्रत्येक कारखाने ग्रीर स्कूल में, प्रत्येक कम्यून ग्रीर नगर में मौजूद है।

 स्या कम्यूनिस्ट देशों में कम्यूनिस्टों की सरकार श्रनिश्चित समय तक श्रिकारारुढ़ रहती है ?

जव तक अधिकाराल्ड कम्यूनिस्ट पार्टी का सेना, गुप्त पुलिस तथा याता-यात के सावनों पर नियंत्रण रहता है और जनता उसकी भ्रावाज के म्रतिरिक्त कोई दूसरी भ्रावाज न सुन सके, उस समय तक यह निर्देयता से विरोधियों को कुचलती रहती है—भीर उसी समय तक मधिकार इसके हाथ में रहता है।

१०. कम्यूनिस्ट पार्टी का गुप्त पुलिस से क्या सम्बन्ध है ?

सोवियत यूनियन में कम्यूनिस्ट पार्टी की लीडरशिप ने कोशिश की है कि इस डिक्टेट्रशिप में गुप्त पुलिस को किसी समय भी इतना वल शाली नहीं बनने दें कि यह सीधी टक्कर लेने का साहस कर सके।

जुन्त पुलिस (के० जी० वी०) को केन्द्रीय समिति के ग्रधीन रखने के कई तरीके ग्रपनाए गए हैं। गुप्त पुलिस के मेम्बरों का पार्टी का सदस्य होना ग्रिनिवार्य है। पार्टी संस्थाग्रों के मंत्री के० जी० वी० में मौजूद रहते हैं। सी० पी० एस० यू० की केन्द्रीय समिति उन्हें ग्रपने कानों तथा ग्रांखों के तौर पर इस्तेमाल करती है। के० जी० वी० की निगरानी के लिए पार्टी कन्ट्रोल कमेटी के खास ग्रुप नियुक्त किए जाते हैं।

नव युवकों, खिलाड़ियों ग्रीर कलाकारों के ग्रुप, ग्रथवा सोवियत नागरिक जब विदेश यात्रा करते हैं तो के० जी० बी० के एजेन्ट उनके संग चलते हैं इन पर कड़ी निगरानी रखते हैं, विदेशियों के साथ उन्हें मेल मिलाप बढ़ाने नहीं देते। जैसे जुलाई, ग्रगस्त, १६५६ में वियाना में नवयुवकों का विश्व उत्सव हुग्रा। सोवियत गुट से ग्राने वाले सब शिष्ट मण्डल ग्रलग रखे गए ताकि गैर कम्यूनिस्ट देशों के प्रतिनिधियों के साथ उनका स्वतन्त्र मेल मिलाप सम्भव न हो।

११. क्या किन्यूनिस्ट देशों भें जनता को सरकारी कानूनों के विरुद्ध प्रतिवाद करने का ग्रविकार है ?

सरकारी कानूनों को लागू करने की विधियों के विरुद्ध तो जनता प्रतिवाद कर सकती है परन्तु मूल ग्रादेशों या नीति निर्णयों के विरुद्ध वह एक भी शब्द नहीं बोल सकती। विरोध प्रकट करने की कुछ राहें खुली हैं। उन्हें "ग्रात्म-ग्रालोचना" का नाम दिया गया है। कम्यूनिस्ट पार्टी इस तरीके को प्रोत्साहित करती है ताकि स्थानीय कर्मचारियों पर इसका दवाव बना रहे।

"ग्रात्म ग्रालोचना" की अनुमित इसिलए भी है कि इससे नागरिकों की शिकायतों ग्रौर निराशाओं को ग्रिभिव्यक्ति की राह मिल जाती है। पार्टी के उच्च नेता ग्रालोचना से बच जाते हैं ग्रौर निचले स्तर पर पार्टी के निर्यंक ग्रिभिकारी ही जनता के प्रकोप का शिकार बनते हैं।

१२. क्या कम्यूनिस्ट देशों में ग्राम, या किसी ग्रौर किस्म के चुनाव होते हैं ?

कम्यूनिस्ट देशों में स्थानीय प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्राय: चुनाव होते रहते हैं। मत देना प्रत्येक व्यक्ति के लिए ग्रानिवायं है। उम्मीदवारों की एक ही सूचि के ग्रधीन लड़े गए चुनाव के सरकारी परिणाम सदैव कम्यूनिस्ट पार्टी की विजय व्यक्त करते हैं। यह विजय ६७ प्रतिशत या इससे भी ग्रधिक वोटों से होती है।

हर चुनाव, चाहे वह ट्रेड यूनियन का हो, या आम चुनाव, कम्यूनिस्ट कोशिश करते हैं कि "सर्व सिमिति" से हो। इस प्रकार विरोध तथा प्रतिवाद की सब राहें बन्द हो जाती हैं।

कम्यूनिस्ट देशों में चुनाव इसलिए कराए जाते हैं कि लोग यह सममें कि सरकार की सब नीतियों को जनता का समर्थन प्राप्त है। यद्यपि वास्तव में उनका कोई दखल ही नहीं होता।

१३. क्या कम्यूनिस्ट प्रशासन के श्रधीन देशों में जनता कम्यूनिज्म को पसन्द करती है ?

कम्यूनिस्ट यह प्रचार करते हैं कि कम्यूनिष्म जहां सत्तारूढ़ है, वहाँ जनता इसे बहुत पसंद करती है। सोवियत यूनियन में ग्रव एक ऐसी पीढ़ी पैदा हो चुकी है जिसे किसी ग्रन्य शासन प्रणाली का न ग्रनुभव है ग्रौर न ज्ञान। उन्हें सिखाया पढ़ाया गया है कि कम्यूनिष्म के ग्रतिरिक्त शासन की ग्रन्य प्रणालियां बुरी तथा घृणा योग्य हैं। परन्तु क्रमुम्बिष्ठम् क्रिपुद्वस्ख्रेन्स्क्र-क्रिस्तिक्ष्यितिहरू हि क्षेत्र स्टिश् की बोल्शेविक क्रान्ति के उपरान्त करोड़ों व्यक्तियों ने कम्यूनिज्म के जबड़ों से भाग निकलने के प्रयत्न किए हैं। द्वितीय महायुद्ध के वाद ही से एक करोड़ से ऊपर व्यक्ति सोवियत गुट के देशों से भाग चुके हैं।

१४. क्या यूरोप के कम्यूनिस्टों के प्रधीन देशों में विद्रोह हुए हैं ?

१६१८ के वाद से रूस में कम्यूनिस्ट प्रशासन के विरुद्ध अनेकों विद्रोह हो चुके हैं। १६५३ में स्तालिन की मृत्यु के बाद पिछलग्य देशों में कम्यूनिरुम का विरोध इस हद तक बढ़ा कि राष्ट्रीय विद्रोह होने लगे।

१७ जून, १६५३ को वर्षिन के सोवियत क्षेत्र में जनता ने विद्रोह किया। इसके वाद पूर्वी जर्मनी और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों में हड़तालें और उपद्रव आम होने लगे।

एक और क्षोभकारी उपद्रव पोजनान (पोलेण्ड) में २८।३० जून, १९५६ को हुआ। यह उपद्रव वाहरी उत्तेजना के विना स्वयं ही फूट पड़ा। उपद्रव करने वाले मजदूरों का नारा था। "रोटी और आजादी।" यह उपद्रव शीघ्र ही सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। विद्रोही तूफ़ान की-सी तीव्र गित से आगे वढ़े और उन्होंने कम्यूनिस्ट पार्टी के मुख्य कार्यालय, नगरपालिका और केन्द्रीय जेल पर अपना फंडा फहरा दिया। परन्तु सोवियत कंट्रोल के अधीन पोल सेना के दो सशस्त्र डिवीजनों ने विद्रोह को घ्वंस कर दिया। सेना और पुलिस ने बहुत सी गिरफ्तारियां कीं। जिस पर भी विद्रोही होने का संदेह हुआ, उसे तुरन्त ही पकड़ लिया गया।

बुडापेस्ट, हंगरी का सशस्त्रं विद्रोह २३ ग्रक्टूबर, १६५६ को ग्रारम्भ हुगा। प्रचण्डता तथा मरने वालों की संख्या की दृष्टि से यह पूर्वी वर्लिन तथा पोजनान के विद्रोहों से बहुत ग्रागे था।

हंगरी के विद्रोह का प्रारम्भ नवयुवकों के प्रदर्शनों से हुआ। इन प्रदर्शनों की प्रचण्डता २२, अक्तूवर, को अपनी चरमसीमा पर पहुँच गई जबिक तीन विश्वविद्यालयों के सहस्रों विद्यार्थियों ने सड़कों तथा बाजारों में यह जोरदार प्रदर्शन किया कि हंगरी की सरकार मास्को की गुलामी को छोड़ दे। पश्चिमी गणतन्त्रों में नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें भी दिए जाएँ।

घीरे-घीरे मजदूर और अन्य नागरिक विद्रोह में शामिल हो गए शहर में सब काम ठप हो गया २४ अक्तूबर तक यह ज्वाला सारे देश में भड़क उठी। प्रत्येक दिला स्व by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri प्रत्येक दिला स्व किम्यूनिर्देश के ग्रंत्याचार की खत्म करने की ग्रावाज ग्राने लगीं। ३१ ग्रक्तूवर को मास्को से एलान हुग्रा कि रूस ग्रपनी ग्रिमधारी सेना को वापस बुलाने के "प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।" परन्तु तीन दिन पश्चात् पूर्व चेतावनी दिए विना ही सोवियत टैंक हंगरी में प्रविष्ट हो गए ग्रीर हंगरी की जनता के इस विद्रोह को निर्देयता से कुंचल दिया।

१४ वया कम्यूनिस्ट चीन में भी विद्रोह हुए हैं ?

चीन में कम्यूनिस्ट सरकार के विरुद्ध स्थानीय विद्रोह प्राय: होते ही रहे हैं।
परन्तु सबसे बड़ा तथा लम्बा विद्रोह १६५० में तिब्बत में शुरू हुआ। पेकिंग
सरकार ने तिब्बत के स्वतन्त्र कवाईली इलाकों में, ग्रजनवी चीनियों को बसाना
शुरू कर दिया था। इस पर सारे कवीले मड़क उठे ग्रीर ग्राठ साल तक वह
यत्रतत्र चीनियों के विरुद्ध छापा मार लड़ाई लड़ते रहे। मार्च, १६५६ में
तिब्बती कवीलों का विद्रोह बहुत जोर पकड़ गया जब तिब्बत के घामिक तथा
सांसारिक पेशवा दलाईलामा को ग्रादेश मिला कि वह ग्रकेले ही, ग्रपने
सेवकों तथा ग्रंग-रक्षकों के विना, कम्यूनिस्ट चीन के फौजी कमाण्डर के सामने
पेश हों।

चीनियों के इस अपमानजनक तथा अमंगलसूचक आदेश ने बौद्ध-भिक्षुओं को उत्तेजित कर दिया और उन्होंने चीन की आधिपत्य सेना के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह आरम्भ कर दिया।

१७ मार्च, १६५६ को दलाईलामा अपने कुछ अनुयायियों को साथ लेकर तिब्बत की राजधानी ल्हासा से निकल पड़े और एक मास की कठिन यात्रा के पश्चात् भारत पहुँच गए। इस समय तक विद्रोह सारे तिब्बत में फैल गया था। कई मास के रक्तपात के पश्चात् चीन की सशस्त्र सेना ने इस विद्रोह को ठंडा कर दिया। उन्होंने वौद्ध मठों को खण्डहर बना दिया और तिब्बती जनता पर नृशंस अत्याचार किए।

तीसरा प्रध्याय कम्यूनिज़म घौर मज़दूर

 क्या यह ठीक है कि कम्यूनिस्ट एक सर्वहारा राज्य बनाने का प्रयास करते हैं ?

कम्यूनिस्टों का दावा है कि उनका ग्रसली ग्रभिप्राय वर्गहीन समाज की स्थापना है। १८४८ में मार्क्स ग्रीर एंजल्ज ने कहा था:

"श्रमिक वर्ग की क्रान्ति की पहली मंजिल यह है कि सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य स्थापित किया जाए ताकि प्रजातंत्रवाद का संग्राम जीता जा सके" परन्तु स्टालिन ने १९३६ में घोषणा की "ग्रव (रूस) में कोई पूंजीपित वर्ग नहीं है जो श्रमिक वर्ग को लूट सके…। ऐसी स्थिति में क्या हमारा श्रमिक वर्ग सर्वहारा कहला सकता है ? व्यक्त है कि नहीं।"

तो भी कम्यूनिस्ट प्रचारक तथा प्रवक्ता आज भी कम्यूनिस्ट देशों के "सर्व-हारा अधिनायक तंत्र" का जिक्र करते हैं। वास्तव में ऐसी वार्ते करते समय उनके मस्तिष्क में कम्यूनिस्ट पार्टी की अधिनायकता होती है।

आज के कम्यूनिस्ट समाज में सुविधाएं (यदि मौजूद भी हैं) "सर्वहारा वर्ग" के लिए नहीं बित्क उच्च वर्ग के लिए हैं, जिसमें नौकरशाही और कम्यू-निस्ट अधिकारी शामिल हैं जो राज्य की शासन-व्यवस्था करते हैं और सरकार उनके नियंत्रण में होती है। या फिर इसमें उच्च स्तर के विद्वान् और फौजी अफसर आते हैं। वर्गीय विभाजन आज भी उतना ही कड़ा है जितना कि जार के युग में था।

२. कम्यूनिस्ट राज्य में कौन से ग्रुप सबसे ग्रधिक वेतन पाते हैं ?

उच्च सरकारी अधिकारी, बड़े फौजी अफसर, बड़े सरकारी व्यापारिक संस्थाओं के मैनेजर, रंगमंच और अन्य कलाओं में प्रतिष्ठित लोग, बड़े-बड़े वैज्ञानिक, अधिक वेतन पाते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। नौक्तुसाद्धीत् क्रीर्भाष्ट्रात्का में ज्याके स्टानिस्ता दिसों ही सुप्ता भी अच्छी खासी होती है। अधिमानित उद्योगों में काम करने वाले दक्ष अमिक भी अति-स्पर्धात्मक आधार पर अंशतः कार्य करके अच्छा बना पाते हैं।

सोवियत आवादी के बहुत वड़े भाग को अर्थात् साधारण श्रमिकों तथा कृपकों को बहुत कम वेतन मिलता है। कम्यूनिक्म के अन्तर्गत प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति को बहुत श्रम करना पड़ता है ताकि परिवार की आमदनी गुजर-वसर के लिए काफी हो सके।

३. क्या कम्यूनिस्ट देशों में जनसाधारए अपना व्यवसाय स्वयं चुन सकते हैं ? कम्यूनिस्ट देशों में जनता को चुनने का अधिकार हो नहीं है। सोवियत इस में व्यवसाय का प्रशिक्षण छोटी आयु में ही शुरू हो जाता है। बाद में तो

बहुत कम लोग व्यवसाय बदलते होंगे।

छूट केवल उसी समय मिलती है जब राज्यों को स्वयंसेवक की स्नावश्यकता हो। जैसे कुछ नगरों में हजारों युवक "स्वयं सेवक" मध्य एशिया के दूर के उजाड़क्षेत्रों में भेजे गये ताकि सरकारी भूमि पर काम कर सकें जिसको हल की नोक पहली बार छ रही थी।

एक नए सोवियत भ्रादेश के अनुसार मालिक को दो सप्ताह का नोटिस देकर कर्मचारी व्यवसाय वदल सकता है, परन्तु यदि वह किसी नए स्थान पर जाता है तो उसकी (ज्येष्टता) और एकत्रित अवकास खत्म हो जाते हैं। नए व्यवसाय में प्रथम छ: मास तक उसे डाक्टरी सुविधाएं नहीं मिलती। मजदूर को कुछ पता नहीं होता कि कब उसे वेगार के लिए जबरदस्ती भेज दिया जाएगा। मध्य एशिया और अन्य स्थानों पर लोगों को जबरदस्ती भेजा जा चुका है।

४. क्या सोवियत यूनियन में हड़तालें होती हैं ?

मजदूरों के हड़ताल करने पर कोई कानूनी प्रतिवन्ध नहीं है परन्तु कुछ दूसरे जैसे आर्थिक तोड़फोड़, अनुपस्थिति या कान्ति विरोधी कार्यविधियां आदि आरोप लगाकर उन्हें कठोर दण्ड दिए जाते हैं। व्यवहार में हड़तालें निषिद्ध हैं "क्योंकि उत्पादन के सब साधन मजदूरों के आधिपत्य से हैं, इसलिए वे स्वयं अपने विरुद्ध हड़ताल नहीं कर सकते।"

वैसे यह दलील ठीक नहीं । उत्पादन साधनों पर राज्य का प्रधिकार होता है । वही यह निर्णय करती है कि किसी प्रकार की हड़ताल ग्रीर विरोध सहन नहीं किया जीएगिन्प by सिक्ष विक्रियूर्ट उसारी शृशिति व्याप्त (विशेष व्यवशिष विवास नवस्वर, १९५६ में हंगरी में) हड़तालें हुई थीं।

५. कम्यूनिज्म किस प्रकार मजदूरों का शत्रु है ?

जब ग़ैर कम्यूनिस्ट देशों में मजदूर ग्रान्दोलन पर कम्यूनिस्ट कब्जा जमाना चाहते हैं, या मजदूर यूनियनों पर ग्रधिकार करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें इसकी रत्ती भर चिन्ता नहीं होती कि मजदूरों को कुछ ग्राधिक सुविधाएं मिलती हैं या नहीं। उनका पहला ग्रभिप्राय तो यह होता है कि मजदूर संघ इनके लिए राजनीतिक मुहरे वनें। एक बार ग्रधिकार इनके हाथ में ग्रा जाए तो फिर वे यूनियन के नेतृत्व को दबा कर ग्रपनी पार्टी का नियन्त्रण स्थापित करने में लग जाते हैं।

रूस में ट्रेड यूनियनें सरकार का ही एक भाग हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि मजदूरों में अनुशासन रहे ताकि उत्पादन वढ़ाने का आन्दोलन जारी रहे। सब यूनियनें कम्यूनिस्ट पार्टी की निगरानी में काम करती हैं।

अन्य कम्यूनिस्ट देशों में भी यही हाल है। वेतन तथा काम का समय निश्चित करने में कम्यूनिस्टों की चलाई हुई यूनियनों के सदस्यों की वहां कोई आवाज नहीं होती। काम की धर्ते और हालात के सम्बन्ध में वे कुछ नहीं कर सकते। यूनियन के अधिकारियों का निर्वाचन पार्टी के आदेश के अनुसार होता है।

ट्रेड यूनियनों की विश्व फैडरेशन, जो कम्यूनिस्टों के कब्जे में है, संसार भर की ट्रेड यूनियनों को अपने कावू में करने के लिए प्रयत्नशील रहती है ताकि उन्हें राजनीतिक स्वार्थों के लिए प्रयोग में ला सके।

६. कम्यूनिज्म के श्रधीन जब प्रत्येक व्यक्ति काम करने पर विवश है तो पारि-वारिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ?

यों तो सरकारी तौर पर "नए" सोवियत परिवार की एकता पर वड़ा जोर दिया जाता है। परन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं। पारिवारिक सम्बन्धों को खत्म करने के लिए वहुत से तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं। माताएं प्रायः काम करती हैं। इनके वच्चे दिन भर सरकारी शिशु-पालनालयों में रहते हैं। वच्चे छोटी आयु से माता-पिता के प्रभाव से वंचित हो जाते हैं। उनके मस्तिष्क में यह वात विटा दी जाती है कि स्टेट उनकी संरक्षक है। अभिप्राय यह होता है कि अनुशासन को सतर्कता से ग्रहण करने वाले कम्यूनिस्ट पैदा हों।

कम्यूषिएंदिकी अर्द्धिय विश्व हिला निकार स्था सामितिक वास्था शारीरिक शक्ति एक विशेष सांचे में दल जाए। उनका सारा जीवन पार्टी की सेवा में व्यतीत हो। उसकी व्यावसायिक निषुणता पार्टी और स्टेट के लाभ के लिए अपित हो (नवां तथा ग्यारहवां अव्याय देखिए)।

७. सोवियत ट्रेड यूनियर्ने अपने अधिकारों से किस प्रकार वंचित हुईं ?

१६१८ में द्विवर्णीय गृह-युद्ध धारम्म हुग्रा था। लेनिन ने युद्ध सम्बन्धी कुछ ग्रावेश जारी किए इनसे सोवियत यूनियन में जन-गठन के नाम पर वेगार का रिवाज प्रचलित हुग्रा। इन ग्रावेशों के ग्रन्तगंत हर व्यक्ति के लिए कार्य का धादशं कोटा निश्चित किया गया। हर पेशे ग्रीर प्रत्येक उद्योग में कार्य का स्तर निर्धारित किया गया। काम के अनुसार पारिश्रमिक का व्योरा तैयार किया गया। निर्धारित कार्य से ग्रधिक काम करने वालों के लिए 'बोनस' देने का निश्चय किया गया। "मजदूरों में ग्रनुशासन" भंग करने वालों को कठोर वण्ड देने की व्यवस्था की गई।

१६२० तक वोलशेविक सरकार ने ट्रेंड यूनियनों की स्वतंत्रता को काफी सीमित कर दिया। इसके पश्चात् दस वर्ष के भीतर ही स्टालिन ने रहे-सहे अधिकार भी उनसे छीन लिए। ट्रेंड यूनियनों के अधिकारी अब पार्टी की स्वीकृति से ही रखे जाने लगे या पार्टी के सदस्यों को ही ट्रेंड यूनियनों का अधिकारी बना दिया गया। कारखानों की कमेटियों में पार्टी के सरगमं सदस्यों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया। और राज्य सरकार स्वयं ही ट्रेंड यूनियन नीतियाँ निर्धारित करने लगी।

दूसरे महायुद्ध के दौरान में सुस्ती, काम से अनुपस्थित और इस प्रकार के छोटे-छोटे दोपों के लिए भी दण्ड दिए जाने लगे। युद्ध के पश्चात् इस संबंध में छूट दी जाने लगी। परन्तु अब भी मजदूरों में सख्त डिस्पिलिन रखा जाता है। १६५६ में तथाकथित कामरेड न्यायालय बनाए गए ताकि छोटे-छोटे अप-राध करने वालों पर तुरन्त ही मुकदमें चलाए जा सकों।

द्र. क्या स्टालिन के युग की श्रपेक्षा श्राज सोवियत ट्रेड यूनिय<mark>नों को श्रधिक</mark> श्रधिकार प्राप्त हैं ?

कुछ मामलों में सोवियत ट्रेड यूनियनों को पिछले कुछ दशकों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु यह बात पूर्णतया स्पष्ट है कि कम्यूनिस्ट पहले ग्रादेश के ग्रनुसार कारखाने की कमेटी को प्रवन्ध ग्रविकारी नियुक्त करने का हक दिया गया। जो मैनेजर ग्रपने कत्तंव्य-पालन में लापरवाही दिखाए वह उसके विरुद्ध कारवाई की मांग कर सकती है। उसे मजदूरों की छांटी पर विरोध प्रकट करने का ग्रविकार है। ग्रोवर टाइम तथा मजदूरों की भलाई की योजनाग्रों ग्रीर प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यों में उनसे विचार विमर्श किया जाता है।

उत्पादन कार्यवाहियों का अभिप्राय यह है कि सरकारी कारोबारी संस्थान उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करें, बल्कि इनसे भी आगे बढ़कर दिखाएँ।

मास्को का दावा है कि इस प्रकार के हुवमों से ग्रीचोिंगक प्रजातंत्रवाद को प्रोत्साहन मिला है। परन्तु इसके बावजूद कारखानों की कमेटियों पर पार्टी का नियंत्रण ढीला नहीं पड़ा। कारखानों की कमेटियों पर पार्टी का पूरा कंट्रोल है। उन्हें ग्रधिक ग्रधिकार देकर उत्पादन सम्बन्धी निर्देशों पर ग्रमल कराना स्टेट के लिए ग्रासान हो जाता है।

चालू सप्त वर्षीय योजना में मजदूरों का क्या कार्य है ?

सप्त वर्षीय योजना के अन्तर्गत (दसवां अध्याय देखिए) श्रम सम्बन्धी नियमों में कहा गया है कि---

- पांच करोड़ तीन लाख श्रमिकों की वर्तमान संख्या में एक करोड़ पंद्रह लाख श्रमिकों की वृद्धि की जाय ।
- २. उत्पादनों की लागतों में ११.५ प्रतिशत की कटौती की जाए। इसकें लिए स्वचालित मशीनें ग्रधिक संख्या में प्रयोग में लाई जायें ग्रौर प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़ाया जाए। ग्रनुमान था कि प्रत्येक श्रमिक ४५ से ५० प्रतिशत तक ग्रधिक उत्पादन दिखाएगा।
- १०. मजदूरों की उत्पादन योग्यता बढ़ाने के लिए सोवियत स्टेट की योजना क्या है ?

उत्पादन बढ़ाने के एिल सोवियत योजनाम्रों में स्वचालित मशीनों के प्रयोग पर तो ज़ोर दिया ही जाता है, इनके ग्रंतर्गत प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि के लिए भी प्रेष्ट्रास्ट्रकी क्रिक् क्रिके हैं amaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५६ के ग्रारम्भ में खूर्चिव ने इक्कीसवीं सी० पा० एस० यू० कांग्रेस में सप्त वर्षीय योजना की घोषणा की। इसके परचात् पार्टी ने "कम्यूनिस्ट मजदूर ग्रिगेड" स्थापित किए। ये उत्पादन संगठनों के ऐसे मजदूर ग्रुप थे जो अपने नियुक्त लक्ष्य को पूरा करने ग्रीर उनसे ग्रागे बढ़ने का प्रण लेते थे। परंतु उस वर्ष के प्रथम छः महीनों में ही इस बात का पता चल गया कि "मजदूर निगेड" का ग्रांदोलन भी नीजवान मजदूरों में इसी प्रकार ही ग्रसफल रहा जैसे स्टौखानीवाईट पद्धति (ग्रथवा तीन्न गित ग्रांदोलन) १६३० में रही थी।

जून, १९५९ में खुरचेव ने एक नए मज़दूर आंदोलन की नींव रखी। इसका आरम्भ इस प्रकार हुआ कि एक कौमसोमोल मजदूर युवित वैलेन्टीन गगानोवा ने स्वेच्छा से अपनी तबदीली एक ऐसे त्रिगेड में करा ली जो उत्पादन में पिछड़ गया था ताकि मज़दूर यूनिट का उत्पादन बढ़ाने में सहयोग दे।

सोवियत प्रौपेगण्डा साथनों द्वारा गगानोवा के इस कदम को बहुत उछाला गया। इसे "परिश्रम के सम्बन्ध में कम्यूनिस्ट दृष्टिकोण में नई प्रवृत्ति" का नाम दिया गया। १ जुलाई, १९५६ को प्रावदा में समाचार छपा था कि सी० पी० एस० यू० की ग्रोर से पार्टी, ट्रेड यूनियन ग्रौर कौमसोमोल की सब संस्थाओं को हिदायत दी जा रही है कि "देश-भक्ति के इस ग्रांदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लें"। गगानोवा को "सोशलिस्ट मजदूरों की हीरों" की उपाधि दी गई। परन्तु पिछले ग्रनुभवों के ग्राधार पर कहा जा सकता है कि गगानोविष्म का ग्रांदोलन भी खानोविष्म की राह पर जाएगा।

११. क्या सोवियत यूनियन में काम करने की सुविधाओं में वृद्धि हुई है ?

१९५३ में स्टालिन की मृत्यु के बाद से बहुत से सोवियत उद्योगों में काम के हालात कुछ सुधरे हैं। परन्तु ग्रभी तक वह पश्चिमी यूरोप श्रीर ग्रमरीका के कम से कम स्तर तक भी नहीं पहुँचे हैं।

वहाँ के ग्रौद्योगिक केन्द्र जिन विदेशियों ने देखे हैं, उनका कहना है कि वहाँ काम का वातावरण ग्राज भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ग्रौर खतरनाक है। दुर्घटनाग्रों से बचाव का सामान या तो है ही नहीं, या घटिया प्रकार का है। इंग्लैंड के खनिकों के एक मण्डल ने १६५७ में रूस में कोयले की खानों का दौरा किया था। उनकी रिपोर्ट के ग्रनुसार वहाँ रिहाईश का बन्दोबस्त ग्रच्छा नहीं है। खानों के ग्रन्दर कठिन कामों के लिए महिलाग्रों को भरती

Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri कर लिया जाता है। खानों में दुघटना से वचाव का सामान नहीं है। इंग्लैंड के खनिकों ने यह भी वताया कि रूसी खनिक महीने में जितने ज्यादा दिन काम करते हैं, उसका उदाहरण संसार भर में कहीं नहीं मिलता।

स्मरण रहे कि कोई कम्यूनिस्ट सरकार श्रीद्योगिक दुर्घटनाश्रों के श्रांकड़े प्रकाशित नहीं करती जबिक पिक्चमी सरकारें इस प्रकार के श्रांकड़े पावन्दी से प्रकाशित करती हैं।

अक्तूबर, १६५६ में सुप्रीम सोवियत ने इन प्रस्तावों पर विचार किया कि कारखानों और दफ्तरों में काम करने वालों का सप्ताह चालीस घंटे का हो और सरकार ने और सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम मजदूरी की दरों को लागू किया जाए। ये शर्तें वर्तमान हालात से अधिक उदार मालूम पड़ती हैं परन्तु खुश्चेव का यह वक्तव्य इनको कुण्ठित कर देता है कि मजदूरों की सामूहिक मजदूरी में वृद्धि नहीं की जाएगी।

श्रयंशास्त्र के स्विस विशेषज्ञ श्ररनैस्ट कुक्स ने कहा है कि "खूर्चेव का कहना है कि मजदूरों की मजदूरी घटाए विना काम का समय कम किया जाएगा परन्तु तथ्य यह है कि मजदूरों की वास्तविक श्राय में श्रवश्य ही कमी हो जाएगी।" इस सम्मति के सत्य होने का एक प्रमाण यह भी है कि निश्चित श्रंश से श्रिष्क काम करने पर बोनस देने की प्रथा खत्म की जा रही है।

१२. कम्यूनिस्ट बेगार का प्रयोग किस प्रकार करते हैं ?

.वेगार, श्रम कैम्पों के विन्दियों से ली जाती है। सब कम्यूनिस्ट देशों में यह रिवाज ग्राम है। रूस में जब बेगार लेने का रिवाज जोरों पर था (१६३६-४६) तो इन कैम्पों में रहने वालों की संख्या एक करोड़ से डेढ़ करोड़ तक थी।

कम्यूनिस्ट देशों में वेगार से कई एक राजनीतिक तथा आर्थिक लाभ उठाए जाते हैं। कम्यूनिस्ट परिभाषा में, जिन लोगों को (धनवान लोगों को जो पूंजीपित थे और दूसरों को मुलाजिम रखते थे) 'समाज दुश्मन' वर्ग कहा जाता है, उन्हें पूर्ण रूप में खत्म करने का ढंग यह भी है। चीनी सोवियत ब्लाक में जिन करोड़ों लोगों को जबरी वेगार का शिकार होना पड़ता है, उनमें वह मजदूर और किसान भी शामिल हैं जो किसी समय कम्यूनिज्म के विरोधी थे। इनके अतिरिक्त वेगार के कैंपों में आने वाले लोगों में कम्यूनिस्ट सरकार से मत-भेद रखने वाले व्यक्ति, सोशलिस्ट, कृषि व्यवसायी, संत, महात्मा और उनके अनुयामिक्कारका के आइर्जाकी दूशके कार्का क्षेत्र के जंगी मैदी वस्त्र कि पिट्ठ देशों से निकाले हुए व्यक्ति शामिल होते हैं।

सोवियत यूनियन में वेगार ग्राधिक व्यवस्था का महत्व पूर्ण ग्रंग वन चुकी है। प्राकृतिक साधनों पर ग्राधारित उद्योगों (जंगलात, खानों, मछली पकड़ने) में वेगार का प्रयोग सामान्य प्रथा है। रेल की पटरियां विछाने, सड़कें तथा जल मार्ग वनाने में, नहरों ग्रौर सिंचाई की परियोजनाग्रों के निर्माण में वेगार चिर समय से काम ग्राती रही है।

श्रवत्वर १६५६ में सोवियत सरकार ने ऐलान किया कि वेगार के कैम्प खत्म कर दिए जाएंगे। इनके स्थान पर "मजदूरों के सुधार" की कालोनियाँ और वंदीगृह बनेंगे, परन्तु यह श्रादेश प्रकाशित ही नहीं किया गया श्रीर इस बात की पुष्टि किसी प्रकार भी नहीं हो सकती कि इस श्रादेश के सब पहलुश्रों पर श्रमल किया गया है।

१६५७ के वाद से रूस की दिण्डत जनसंख्या में कमी का कारण यह है कि कुछ विन्दियों के मुकदमों के पुनर्निरीक्षण के पश्चात् उन्हें छोड़ दिया गया था। इसके अलावा युद्धवंदी अपने-अपने देशों को लौटा दिए गए थे। गुप्त पुलिस की गिरफ्तारियों में भी कमी था गई थी।

यद्यपि दिण्डित लोगों की कालोनियाँ पहले की तरह जगह-जगह फैली हुई नहीं मालूम होतीं फिर भी क़ैदलानों में वेगार करने वालों की संख्या कुछ बढ़ी ही है। इसके साथ नए क़ैदलानों के निर्माण का काम भी जारी है। वेगार की बहुत सारी कालोनियों में ग्रव हालात पहले से वेहतर बताए जाते हैं। कम्यूनिस्ट जान गए हैं कि हत्भाग्य, ग्रधभू ले तथा थके हुए बन्दी ग्राधिक दृष्टि-कोण से लाभदायक सिद्ध नहीं होते। (स्टालिन के दौर में क़ैदियों का १२ प्रतिशत प्रतिवर्ष मौत के मुंह में चला जाता था)।

कम्यूनिस्ट चीन की योजनाओं में बेगार का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने परहोता है, परन्तु वहाँ इस प्रकार के दिण्डत श्रमिकों और जबरी भरती से इन योज-नाओं पर लगाए गए मज़दूरों के दलों में अधिक अन्तर नहीं है। दोनों सामान्य रूप से अत्याचार की चक्की में पिसते हैं।

चौथा ग्रध्याय कम्यूनिज़म के ग्रन्तर्गत ज़मीन ग्रौर जायदाद की मिल्कियत

१. सोवियत रूस में जमीन किस की मिल्कियत हैं ?

सारी जमीन सोवियत राज्य की है। दूसरे कम्यूनिस्ट देश भी जमीन को राज्य की मिल्कियत बनाने में प्रयत्नशील हैं। परन्तु वहाँ जमीन की जब्ती का जबरदस्त विरोध हुआ है। जमीन की सामूहिक मिल्कियत और खेती वाड़ी, जिसके प्रोत्साहन के जिए सब कम्यूनिस्ट सरकारें प्रयास कर रही हैं, जमीन पर राज्य के आधिपत्य से बिल्कुल भिन्न है। फिर भी सामूहिक फार्म प्रायः स्टेट की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निगरानी में रहते हैं।

२. कम्यूनिस्ट सरकारं जमीन की मिल्कियत की समस्या को किस तरह निपटाती हैं ?

सोवियत यूनियन में वोलशेविक क्रान्ति के तुरन्त बाद सरकार ने सव बड़ी जागीरें जब्त कर लीं थों। इनमें बहुत-सी जमीन भूमिहीन किसानों में बांट दी गई।

१६२१ में लेनिन ने नई आर्थिक नीति (एन० इ० पी०) की घोषणा की।
यह नीति ग्रनाज की जबरी बसूली के विरुद्ध किसानों के विरोध और दुर्भिक्ष
के खतरे के कारण बनाई गई थी। ग्रव किसानों ग्रीर कारीगरों को अपनी
पैदाबार और रचनाग्रों को खुले बाजार में बेचने की श्रनुमित मिल गई।

लेनिन की मृत्यु के पश्चात् स्तालिन ने १६२६ से ज़मीन की सामूहिक मिल्कियत का कातून बनाया। कलक (खाते-पीते किसान) को खत्म करने की और मिल्कियत के अधिकार इससे छीन लेने का आंदोलन शुरू किया गया। इस सम्बन्ध में बड़ी सख्ती बरती गई। कृषि व्यवस्था बिगड़ गई। १६३१-३२ में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि लाखों किसान और ग्रामीण मौत का शिकार हो गए।

१९५० के बाद से सामूहिक फार्म धीरे-धीरे क्षेत्रफल में बड़े और संख्या में कम होते जा रहे हैं। इससे सी० पी० एस० यू० का नियंत्रण और भी मजबूत हो गया है। कम्यूनिस्टों का दावा है कि बड़ी इकाइयाँ आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक रहती हैं। परन्तु इस सामूहिकता से केवलमात्र आर्थिक लाभ ही नहीं, राजनीतिक लाभ भी तो मिलते हैं।

कम्यूनिस्ट नेताओं के वक्तव्य के अनुसार, सरकारी खेती की व्यवस्था ही, जिसमें किसान केवल मजदूर वन कर स्टेट के लिए काम करता है, सोवियत

भूमि तथा कृपि कार्यं कम की ग्रन्तिम मंजिल है।

पूर्वी यूरोप में बल्गारिया में सामूहिक कृषि की पद्धति काफी उन्तत हो चुकी है। पिट्टू देशों के सब किसान इस पद्धित के कट्टर विरोधी हैं। इस विरोध के बावजूद मास्को की योजना यह है कि १९६५ तक भूमि पूर्ण रूप से सामूहिक कृषि ब्यवस्था के अधीन आ जाए।

३. सामूहिक फार्भ का अभिप्राय क्या है ? क्या किसान को श्रपनी पैदावार वेचने

का ग्रधिकार है ?

सामूहिक फार्म में वे क्षेत्र लिए जाते हैं जिनके असली मालिकों से मिल्कि-यत का ग्रधिकार छीन लिया गया है। भूमि के अतिरिक्त इसमें किसानों के निजी निवासस्थान, खेतीवाड़ी का सामान और अन्य निजी सम्पित भी शामिल होतीं है।

सामूहिक फार्म के मुखिया को प्रधान कहते हैं जो निर्वाचित होता है। प्राय: उसके निर्वाचन की स्वीकृति स्थानीय कम्यूनिस्ट पार्टी या इसके सदस्य के

हाथ में होती है।

१९५८ के अर्घ तक सामूहिक फार्मों को अपने उत्पादन का निश्चित भाग सरकार द्वारा नियुक्त कीमतों पर देना पड़ता था। अब यह प्रथा छोड़ दी गई है। परन्तु सरकार अब भी इस बात पर जोर देतो है कि उत्पादन का निश्चित भाग उसे दिया जाए भूरि प्रतिप्र देशक किला, देशका सिकारी विकाशि (संप्त वर्षीय योजना) को पूरा करने के लिए पैदाबार में से अपना हिस्सा दे। सामूहिक फार्मों को दी जाने वाली कीमतें अब पहले से अधिक हैं परन्तु कीमतें निश्चित करने का काम अब भी सरकार ही करती है।

सामूहिक फार्म का सदस्य सामूहिक पैदावार का कोई हिस्सा स्वयं नहीं वेच सकता परन्तु उसे जमीन का छोटा-सा दुकड़ा रखने की अनुमति है। यह उसके परिवार के प्रयोग के लिए होता है। उसकी पैदावार खुले वाजार में वेच सकता है। सामूहिक खेतों के बहुत से सदस्य बड़े विलदान करके प्रयास करते हैं कि इस पैदावार को खुले वाजार में नकदी के बदले में वेच सकों और सख्त जरूरत की बहुमूल्य वस्तुएं (जूते, कपड़े और घरेलू वर्तन) खरीद लें।

असीन के मालिकों से कम्यूनिस्ट किस प्रकार छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं ?

वोलशेविक क्रान्ति के पश्चात्, बड़े-बड़े ज़मीदारों को उनकी जागीरों से निकाल दिया गया। कुछ बन्दी बना लिए गए, कुछ मारे गए और कुछ को साइदेरिया भेज दिया गया। दूसरे महायुद्ध के पश्चात् पूर्वी यूरोप के देशों में भी उनकी यही दुर्गति हुई परन्तु कुछ भूमिदार अपनी ज़मीन पर ही रहते रहे।

पूर्वी यूरोप में जब कम्यूनिस्टों ने शासन पर ग्रिषकार कर लिया तो भूमि सुधार के कानून लागू किये ग्रीर जमीन की निजी मिल्कियत निश्चित की। फालतू जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया ग्रीर उसे लगान पर खेती करने वाले किसानों ग्रीर भूमिहीन मजदूरों में 'वाँट दिया। परन्तु ये, टुकड़े इतने छोटे थे कि इन पर उनके परिवारों का गुजारा सम्भव न था। फिर कम्यूनिस्टों की निगरानी में "सांभी खेती" ग्रारम्भ की गई। ये नए छोटे काश्तकार जबरदस्ती इन खेतों में इकट्ठे कर दिए गए या फिर उन्हें नए सामूहिक फार्मों में शामिल होना पड़ा।

ग्रिंघकार प्राप्त करते ही कम्यूनिस्टों ने सभी कम्यूनिस्ट देशों में काश्त-कारों के लिए "मुफ्त जमीन" देने का वचन भुला दिया है। कम्यूनिज्म का वास्तविक ग्रिभिप्राय यही है कि सामूहिक खेती-वाड़ी की व्यवस्था स्थापित हो, वह राज्य के नियंत्रण में रहे ग्रीर उन पर काम करने वालों का दर्जा वही हो जो उन उद्योगों के मजदूरों का होता है जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। थ. क्या क्रम्यूनिज्ञमु के प्रनुवात प्रन्य प्रकार के hendral में ते सुरेज्ञद्व हैं या केवल सामूहिक फार्म ही रह गए हैं ?

तथाकथित सोशालिस्ट (कम्यूनिस्ट) क्षेत्र में कई प्रकार के खेत होते हैं। जैसे रूस में सामूहिक फार्म (कोल-खोज) ग्रौर स्टेट फार्म (सोव-खोज) हैं। स्टेट फार्मों का बंदोबस्त स्टेट के हाथ में होता है। खेतों में काम करने वालों को काम के हिसाब से उजरत मिलती है।

पूर्वी यूरोप में, कम्यूनिस्ट सरकारों के अधीन, स्टेट फार्म, सामूहिक फार्म या फिर साफे फार्म होते हैं जिन पर सरकार का अप्रत्यक्ष कंट्रोल रहता है। निजी क्षेत्र में व्यक्तिगत खेतीबाड़ी के कुछ चिह्न अभी बाकी हैं, परन्तु निजी खेतों के मालिकों को बहुत हानि उठानी पड़ती हैं। अधिक कर उनकी कमर तोड़ देते हैं। पिट्ठू देशों में सामूहिक खेती-वाड़ी का अनुपात १४ प्रतिशत (पोलैण्ड) से ६० प्रतिशत (बल्गारिया) तक है। सारे कम्यूनिस्ट संसार में जनता की ओर से सामूहिक खेती का सख्त बिरोध होता रहता है।

दिसम्बर १९५६ में पूर्वी जर्मनी की कम्यूनिस्ट पार्टी (एस० इ० डी०) की केन्द्रीय समिति ने खेती-बाड़ी के एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट सुनी। उसने कहा कि सामूहिक खेतों पर अधिक लूट मार और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां होती हैं। केवल जुलाई-अगस्त और शितम्बर में लूटमार की नौ सो से अधिक घटनाएं हुई थीं। साल के पहले नौ महीनों में चौदह लाख डालर का घाटारहा। ६. क्या भिन्न-भिन्न सामूहिक फार्मों की आय में अन्तर होता है?

रूस में भिन्न-भिन्न सामूहिक फार्मों की ग्राय में काफी अन्तर होता है। तथाकथित "लखपित" सामूहिक फार्म रूई जैसी उद्योगिक फसलें पैदा करते हैं। इनको सरकार की ग्रोर से सहायता भी मिलती है। दूसरे धनवान 'कोल-खोज' बहुत ही उपजाऊ भूमि में हैं। धनवान सामूहिक फार्मों के मेम्बरों की ग्रामदनी थोडी ग्राय वाले फार्मों के मेम्बरों से ग्रधिक होती है।

७. क्या यह ठीक है कि सोवियत किसानों के पास ट्रेक्टर होते हैं ?

कोई सोवियत किसान व्यक्तिगत रूप से ट्रेक्टर या खेती-बाड़ी के दूसरे सामान का मालिक नहीं होता। पहले सब ट्रेक्टर सरकार की मिल्कियत थे। इनकी देख-रेख, इनका चलाना, मशीन ट्रेक्टर स्टेशनों (एम० टी० एस०) के जिम्मे थी। ये स्टेशन सरकारी महकमे थे। सामूहिक फार्म ट्रेक्टर के प्रयोग के लिए फीस देते थे। मार्च, १९४८ में सरकारी आदेश के अनुसार सामूहिक खेतों को एम० टी० एस० से ट्रेक्टर खरीदने की अनुमति मिली। एम० टी० एस० मशीन सिविस स्टेनिनों कि का का में कारे जिले कि विस्ति साम सिक्त कि सुनि के सब स्थान ट्रेक्टर और दूसरी भारी मशीनें हैं। जो सामूहिक फार्म आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और स्वयं अपनी मशीनें खरीदने और चलाने की क्षमता नहीं रखते, उन्हें बड़े और समृद्ध फार्मों के साथ मिला दिया गया है।

सोवियत समाचार ऐजन्सी 'तास' के अनुसार वे जमीनें जो १६५० में ढाई लाख देतों में बँटी हुई थी, अब पचास हजार से भी कम सामूहिक फामों में

एकत्रित कर दी गई हैं।

एक साधारण सामूहिक फार्म से स्टेट फार्म का क्षेत्रफल कहीं ग्रधिक होता है। स्टेट फार्मों की संस्था लगभग छः हजार है।

द. जब कम्यूनिस्ट देशों में सारी पैदावार सरकार की मिल्कियत होती है तो सरकार इस पैदावार का क्या करती है ?

उपभोग्य वस्तुएं ग्रौर ग्रन्य सामान सरकारी दुकानों या सहकारी सोसाइ-दियों द्वारा वेची जाती हैं। कच्चा माल जैसे रूई ग्रौर सन सरकारी उद्योगिक निगमों इत्यादि को दे दिया जाता है। तैयार की हुई चीजें, ग्रनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थ ग्रौर कच्चा माल निर्यात व्यापार के सौदों में भी वेचा जाता है। कम्यूनिज्म के ग्रन्तगंत निर्यात तथा ग्रायात पर सरकार का एकाधिकार है।

क्या सोवियत रूस के नागरिक ग्रपने निवास-स्थान के मालिक हो सकते हैं ?

सोवियत संविधान के अनुच्छेद १० में लिखा है कि "नागरिकों को अधि-कार है कि उनके काम की उजरत, बचत के रुपये, रहने का मकान, सहायक बचतें, फर्नीचर, बर्तेन, निजी सुख तथा सुविधा की वस्तुएं, इनकी घरेलू मिल्कि-यत रहें। उन्हें पैतृक जायदाद का दायाधिकार और उक्त अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित है।"

इस प्रकार कानूनी तौर पर तो रूस में साधारण व्यक्ति के लिए मकान का मालिक होना सम्भव है। निजी मकान बनाने के लिए (विशेषरूप से मध्य-एशिया की 'नई भूमि' पर) सरकार कर्जे भी देती है। परन्तु मकान की जमीन मकान मालिक की मिल्कियत नहीं हो सकती। वैसे भी इस प्रकार की जाय-दाद प्राप्त करने में बहुत-सी कठिनाईयां हैं। सबसे बड़ी कठिनाई तो ग्राय और पूँजी की कमी है जिसके कारण निजी मकान बनाना ग्रसम्भव होता है।

ं रूस और इसके पिट्ठू देशों में जनता के लिए निवास-स्थान निर्माण की कई योजनाएं हैं परन्तु अभी तक सम्पूर्ण सोवियत ब्लाक में मकानों की जबर-

सोवियत सप्तवर्षीय योजना के अन्तर्गत १६६५ तक मकानों की संख्या में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित है। साढ़े चार करोड़ लोगों के लिए डेढ़ करोड़ मकान बनाने हैं। यह योजना एक परिवार में तीन व्यक्तियों के हिसाब से बनाई गई है। आजकल तो सांभे क्वार्टरों का रिवाज आम है। परन्तु नव-निर्मित निवास-स्थानों में प्रत्येक परिवार के लिए अलग-अलग मकान पर जोर दिया जायेगा। सांभे क्वार्टरों में दो या तीन परिवार रसोई, स्नान-गृह और अन्य घरेलू सुविधाओं में शरीक होते हैं। आजकल कम से-कम पाँच करोड़ व्यक्ति सांभे तौर पर रह रहे हैं।

वर्तमान योजना की पूर्ति से रिहाईश की समस्या काफी सुघर जाएगी, परन्तु यदि निवास-स्थान निर्माण के लक्ष्य पूरे भी कर लिए गए—जो नौकर-शाही अदक्षता के कारण बहुत किठन है, तो भी नागरिकों की बहुत बड़ी संख्या बदनुमा, घुटे-घुटे क्वार्टरों में ही रहती रहेगी। दिख्य बिस्तयों की सफाई और पुनर्निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है। भविष्य में भी इसकी कोई सम्भावना नहीं क्योंकि मकानों की कमी बहुत समय तक रहेगी। सरकार के निवास-स्थान निर्माण के फंड में साठ प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव अवस्य किया गया है। परन्तु जिन टूटे-फूटे मकानों में आज भी किराएदार भरे पड़े हैं, उनकी मरम्मत के लिए कोई योजना नहीं है। इसलिए वह घीरे-घीरे और खराब होते जाएंगे। १०. रूस के मुकाबिले में पिट्ठू देशों में मकानों की स्थित कै सी है?

चेकोस्लोवािकया को छोड़कर बाकी सब पिट्ठू देशों में मकानों की समस्या रूस से भी किंठन है। पिट्ठू देशों की "स्वतन्त्रता" के बाद से (जब युद्ध के परचात् पूर्वी यूरोप में मास्को की सहायता से सरकारें बनीं) बल्गारिया, हंगरी, रूमानिया और पोलैंड में शहरी रिहायशी स्थिति श्रीर भी खराव हो गई। चेकोस्लोवािकया में भी मकानों की कमी है यद्यपि वहां पर श्रधिक निवास-स्थान बनाने के लिए जनता की श्रोर से मांग होती ही रहती है।

पूर्वी जर्मनी में मकानों की हालत युद्ध-पूर्व हालत से भी बिगड़ गई है। यह हालत इस समय है जबकि छत्तीस लाख जर्मन पिश्चमी जर्मनी में शरण ले चुके हैं। दूसरे महायुद्ध से पूर्व पूर्वी जर्मनी की जितनी आबादी थी, आज उससे कहीं कम है परन्तु मकानों की समस्या अब और भी गम्भीर हो गई है।

रूस ग्रीर बल्गारिया के रिहाइशी नियमों के भ्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति को

कम-से-कम १ ि खाँगी है प्रियो पर विशे विशे कि एक कि सा बिह कि प्रत्येक देशों में से किसी में भी इस नियम का पालन नहीं किया जाता। वहां प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में ५४ वर्ग फीट या ५ वर्ग मीटर क्षेत्रफल ग्राता है। चेकोस्लो-वाकिया इस स्तर से कुछ ग्रागे वढ़ गया है। वहां प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में १२४ वर्ग फीट क्षेत्रफल ग्राता है।

हंगरी में प्रत्येक कमरे में लगभग २.५ व्यक्ति रहते हैं लगभग २० से २५ प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो दूसरों के साथ क्वार्टरों में रहते हैं।

कम्यूनिस्ट देशों में मकानों की आवश्यकता मरम्मत और देखभाल पर कोई व्यान नहीं दिया जाता। नए बने हुए मकान इतने बोदे हैं कि युद्ध के पश्चात् बनी हुई बहुत-सी इमारतें अभी से मरम्मत मांगती हैं।

२१. रूस में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग किस प्रकार रहता है ?

क्स में खुले और अच्छे मकान पहले विशेषाधिकार प्राप्त वर्म को ही मिलते हैं। उच्च अधिकारी और उच्च सैनिक अफसर ठाठ से रहते हैं। इनमें से बहुत से शहरी और ग्रामीण, दोनों प्रकार के निवास-स्थानों को अपने कब्जे में रखते हैं। कुछ ग्रामीण निवास-स्थान (जिन्हें 'दाचा' कहा जाता है) तो पूरे महल जैसे होते हैं। परन्तु चूंकि सोवियत यूनियन में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को भी मकानों की मिल्कियत का अधिकार नहीं, इसलिए इसे सदा यही खड़का नगा रहता है कि पता नहीं कब वह पार्टी की नजर से गिर जाएं और सब सुख-सुविधाओं से वंचित हो जाएं या पार्टी के भीतरी संघर्ष का शिकार बन जाएं।

१२. क्या कम्यूनिज्म के अन्तर्गत मजदूर को अधिकार है कि अपना कमाया हुआ रुपया स्वयं खर्च करे ?

निस्सन्देह, वह उस रुपये को जिस प्रकार चाहे खर्च कर सकता है, परन्तु कम्यूनिज्म के ग्राघीन ग्राम इस्तेमाल की वस्तुएं इतनी कम हैं ग्रीर उनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि साधारण व्यक्ति ग्रपने ग्रीर ग्रपने परिवार के लिए ग्रिति ग्रावश्यक वस्तुग्रों के ग्रितिरक्त कुछ ग्रीर खरीदने की क्षमता ही नहीं रखता।

रूस में खरीदार को सरकारी दुकानों से कोई भी वस्तु खरीदने पर ५० से १०० प्रतिशत तक 'उत्पादन ग्रथवा विक्री कर' देना पड़ता है। (दसवाँ श्राच्याय देखिए)। १३. केम्ब्रानिस्ट ध्यानिभ्यति कार्यानिस्ट ध्यानिस्ट ध्यानिस्ट ध्यानिस्ट क्यानिस्ट ध्यानिस्ट ध्य

वहाँ निज़ी गृह बहुत संख्या में तवाह हुए हैं। हजारों गांव विघ्वंस कर दिए गए। गिरे हुए मकानों से जो इमारती सामान मिला, उसे सांभी बैरकों के निर्माण में प्रयोग किया गया। कम्यून पद्धित के लागू होने से (पहला अध्याय देखिए) कृषि सम्बन्धी सामान और अनेकों घरेलू वस्तुओं की निजी मिल्कियत खत्म हो गई।

यद्यपि कम्यूनिस्ट चीन के पचास करोड़ किसानों में से अधिकतर कम्यूनों में रहने पर विवश कर दिए गए हैं, परन्तु रहन-सहन का यह ढंग अभी पूरी तरह लागू नहीं हो सका है। कम्यून आंदोलन के पहले चरण में खाने-पीने की खानदानी पर्दादारी को इस प्रकार खत्म किया गया कि बड़े-बड़े मोजना-लय बना दिए जहां सब लोग इकट्ठे बैठ कर भोजन करते थे, परन्तु जब लोगों ने इस पर रोष और विरोध प्रकट किया तो भोजनालय बन्द कर दिए गए। १९५६ की पत्रभड़ में इकट्ठे रहने का आंदोलन एक नए रूप में फिर बड़े जोश से चलाया गया। बहुत से भोजनालय फिर से खुल गए।

पांचवां ग्रध्याय कम्यूनिज़म में समता

१. कम्यूनिस्टों का दावा है कि कम्यूनिज्म के ग्रन्तर्गत सब एक समान हैं ग्रीर न कोई घनवान है ग्रीर न ही कोई निर्धन, क्या इस घोषणा में कुछ सच्चाई है ?

१९३६ के सोवियत संविधान के अनुसार सब नागरिक एक समान हैं, परन्तु वास्तविक रूप में न सोवियत रूस में ही ऐसा है और न किसी और कम्यूनिस्ट देश में।

सोवियत रूस में कई सामाजिक वर्गों में बहुत ग्रन्तर है। उदाहरण के लिए कम्यूनिस्ट समाज में ग्रधिकतम तथा न्यूनतम वेतन में उतना ही ग्रन्तर है जितना कि पूंजीवादी समाज में।

१६२० ग्रीर इसके पश्चात् सोवियत नेताग्रों ने 'समानता' के नियमों को कार्यान्वित करने का बहुत प्रयास किया। कर्मचारियों ग्रीर श्रमिकों को चाहे वे शिक्षित हों या ग्रशिक्षित, बरावर वेतन मिलने लगा। परन्तु उन्हें शीघ्र ही पता चल गया कि उजरत ग्रीर वेतन के इस नए ढांचे ने उत्पादन वढ़ाने की उमंग के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। १६३१ में स्तालिन ने "समान वेतन" के नियम को छोड़ दिया ग्रीर इसके स्थान पर उजरतों का एक नया नक्शा बनाया जिससे मजदूर निश्चित काम करता रहे ग्रीर उसे ग्रधिक काम करने के लिए प्रोत्साहन भी मिले।

१६३० के पश्चात् अधिकतम तथा न्यूनतम उजरत पाने वाले मजदूरों में ग्रीर उनकी नौकरशाही के भीतर वेतन का ग्रन्तर बराबर बढ़ता रहा है।

ग्रधिक ग्राय के ग्रतिरिक्त, कम्यूनिस्ट समाज में कुछ वर्गों को विशेष सुवि-धाएं भी प्राप्त हैं जो दूसरों को नहीं मिलतों। २. सोवियत रूस में मजदूरों के मुकाबिल में ग्राधकारीवर्ग की श्रामदनी कितनी है ?

. रूस में पाँच स्पष्ट वर्ग हैं। उच्चतम स्तर पर कुछ सी परिवार हैं जिनके हाथ में देश का शासन है। सरकार ग्रीर पार्टी के उच्च अधिकारी ग्रीर वड़े फौजी ग्रफसर पाँच लाख रूबल से ऊपर वार्षिक वेतन पाते हैं।

इनसे कम महत्व वाले ग्रधिकारी, बड़े-बड़े कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक ग्रन्य विद्वान, ग्रीर वड़े सरकारी उद्योगों के डायरेक्टर, जिनकी कुल संख्या पचास लाख है, भी लाखों रूबल का वार्षिक वेतन पाते हैं।

तीसरे वर्ग में पार्टी के न्यून स्तर के कार्यकर्ता, इंजीनियर, टैक्नीशियन, सामूहिक फार्मों और छोटे कारखानों के मैनेजर और कुछ अटेखाफोफ या ''तीव्र गित से काम करने वाले मजदूर'' आते हैं। इनकी वार्षिक आय बीस हजार रूबल होती है। ये तीनों ऊंचे वर्ग सोवियत यूनियन की बीस करोड़ आबादी का दसवाँ भाग हैं।

चौथा वर्ग साधारण मजदूरों और किसानों का है। ये यदि आठ हजार रूबल वार्षिक भी पा लें तो उनका सौभाग्य है। (इतनी आय से दो बड़ों और दो बच्चों के शहरी खानदानों का गुजारा नहीं हो सकता)। साधारण अर्ध-प्रशिक्षित मजदूर इससे आधी उजरत पाता है।

३. कम्यूनिस्ट देशों में नागरिकों को समतल पर कैसे लाया जाता है!?

कम्यूनिस्ट देशों में सबको एक स्तर पर लाने वाली केवल एक ही शक्ति है। कम्यूनिस्ट पार्टी स्वयं ही सुविधाएं और सुख प्रदान कर सकती है, वहीं उन्हें छीन भी सकती है।

४. क्या कम्यूनिस्ट देशों में भीख और दान मांगने का रिवाज है ?

कम्यूनिस्टों की दृष्टि में भीख श्रौर दान देना "पतनोन्मुख पूंजीवादी समाज" का चिन्ह है। इसलिए वे इसकी निन्दा करते हैं। फिर भी सोवियत नगरों में भिखमंगे नज़र श्राते हैं।

थ्र. क्या कम्यूनिस्ट देशों में लोकमत होता है ?

सरकारी सोवियत पत्रिका "बोल्शेविक" ने एक बार लिखा था "लोकमत की माँग है कि प्रत्येक सोवियत नागरिक सोशलिस्ट समाजी जीवन के नियमों का पालन करे—इन नियमों का भी जिनका कानून में जिक्र नहीं है।" Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कम्यूनिस्ट देशों में 'लोकमत' केवल कम्यूनिस्ट पाटों के ग्रादेश तथा निर्देश्यान के ग्रादेश तथा निर्देशन के ग्रादेश तथा निर्देशन के ग्रादेश तथा निर्देशन के ग्रादेश तथा निर्देशन के ग्रादेश तथा है। सरकारी ग्राधिकारी हो या जनसाधारण, सब पर पार्टी की निगरानी रहती है, परन्तु सोचने वाले लोग राय रखते हैं यद्यपि कारणवश वे उसे प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए सोवियत यूनियन ग्रीर पूर्वी यूरोप में लोकमत मौजूद ग्रवश्य है। लोकमत कुछ मामलों में कम्यूनिस्ट ग्राधिकारियों पर काफी दबाव डालता है ग्रीर वे इससे प्रभावित भी होते हैं।

पूर्वी यूरोप में जब से रूस ने प्रत्यक्ष ग्रथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से ग्रपनी अनुयायी सरकारें वहां की जनता पर लादी हैं, वहां के नेता मास्को की हां में हां मिलाते रहते हैं। लोकमत से वे सदा वेपरवाह रहे हैं। ग्रलवत्ता जब सोवियत नेताओं ने स्तालिन के दर्जे को कम किया तो वहां भी हालत कुछ बदली! लेखक, विद्यार्थी ग्रीर ग्रोद्योगिक मजदूर किसी हद तक ईमानदारी से ग्रपनी राय प्रकट करने लगे। परन्तु शीघ्र ही उन्हें मनाही कर दी गई कि सरकारी नीति की सीमाग्रों का उल्लंघन न करें।

ग्रवतूबर, १६५६ में पोलैण्ड ग्रौर हंगरी में जो उपद्रव हुए, उनके दौरान में ग्रौर इनसे पहले लोकमत का स्रोत एकाएक ही उबल पड़ा था।

पोलैण्ड में पिछले दिनों प्रेस श्रीर पोलिश कम्यूनिस्ट पार्टी के भीतर रूस के प्रति बहुत विरोध प्रकट किया गया जिससे पार्टी में काफी श्रफरा-तफरी मची। इसके साथ-साथ देश की श्राधिक दुर्दशा पर भी काफी ले-दे हुई।

पोलैंड की कम्यूनिस्ट पार्टी प्रयत्नशील रहती है कि मार्क्सवाद लेनिनवाद के पुराने मार्ग से जनता को हटने न दिया जाए परन्तु तमाम कोशिशों के उपरान्त भी पोलैंड में लोकमत और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति अधिक नियन्त्रण स्वीकार नहीं करते।

६. क्या सोवियत यूनियन में भिन्न-भिन्न जातियों को समान ग्रंधिकार प्राप्त हैं ?

सोवियत संविधान में लिखा है-

इन विशेष जमानतों के बावजूद १६२० के बाद से ही जनता की राष्ट्रीय उमंगों को दृढ़ता से कुचल दिया गया। वाल्गा के निचले क्षेत्रों में श्रीर मध्य एशिया में लाखों बौद्धों श्रीर मुसलमानों पर अत्याचार के पहाड़ तोड़े गए। इनके जीवन की परम्पराश्रों को मिटा दिया गया। वाल्टिक जातियों का मी यही हाल हुआ।

Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and e Garagotti दूसरी ग्रोर ग्रार० एफ० एस० ग्रार० के रूसी वासियों के उच्च स्तर को स्वयं मास्को ने स्वीकार किया है।

महान् रूस के इतिहास और संस्कृति को नमूने के तौर पर पेश किया जाता है। शेप चौदह प्रजातंत्रों की जनता को जो रूसी नहीं हैं, निमन्त्रण देते हैं कि इसी नमूने को ग्रपनाएं। सोवियत यूनियन के भीतर गैर रूसियों की राष्ट्रीय संस्कृति को योजनानुसार महान रूसी नमूने पर ढाला गया है।

यूनियन प्रजातंत्री में ग्रार० एफ० एस० ग्रार० क्षेत्रफल में सबसे बड़ी ग्रौर सबसे ग्रावादी वाला प्रजातंत्र है। मास्को इसकी राजधानी है। सोवि-

यत यूनियन की यह सबसे शक्तिशाली सरकार है।

कुछ यूनियन प्रजातंत्रों में कभी-कभी असंतोष की लहरें उठती हैं जिन्हें सी० पी० एस० यू० राष्ट्रवाद का नाम देती है। काज़क प्रजातंत्र में क़जाक अफसरों के स्थान पर जब केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारी नियुक्त किए तो

वहां बहुत गड़बड़ी हुई भी।

१६५३ के बाद कजाकिस्तान में सोवियत नागरिक, विशेपतया महान रूसी बहुत बड़ी संख्या में ग्राए। वंशीय मुकाविले ग्रीर संघर्ष ग्रारम्भ हुए। कजाक कम्यूनिस्ट पार्टी की पित्रका के सितम्बर १६५६ के ग्रंक में काजक राष्ट्रवाद के प्रदर्शन पर बड़ी ले-दे हुई। ग्रारोप लगाया गया कि स्थानीय कजाक रूसियों के प्रति शत्रुता दिखा रहे हैं। कजाक इतिहास को ग्रानावश्यक ही महान बना कर पेश कर रहे हैं ग्रीर ग्रायिक प्रादेशिकतावाद का प्रचार कर रहे हैं। (इस नीति का ग्रामप्राय यह है कि कजाकी उत्पादन कजाकिस्तान में ही रहें ग्रीर रूस के ग्रन्य प्रदेशों में न भेजा जाए)। कजाक ग्राधकारियों की यह शिकायत भी है कि उनके रहने के मकान काफी नहीं हैं। सरकारी दुकानों पर खाद्य-सामग्री ग्रीर कपड़ा कम मात्रा में मिलता है। १६६० में उच्च काजक ग्राधकारियों की बड़ी संख्या को तब्दील कर दिया गया था। इससे प्रकट है कि 'काजक राष्ट्रवाद' की समस्या ग्रंभी हल नहीं हुई है।

१६५६ में लेटेवियन कम्यूनिस्ट पार्टी को मुग्रत्तल कर दिया गया था । सी. पी. एस. यू. ने ग्रारोप लगाया था कि वह "स्थानीयतावाद" ग्रीर "बुर्जुंग्रा राष्ट्रवाद" से निमटने में ग्रसफल रही है। स्थानीय भावनाग्रों को दबाने का

यह एक भ्रोर उदाहरण है।

छठा ग्रध्याय

कम्यूनिज़म के अधीन न्यायालय तथा न्याय

१. क्या कम्यूनिस्ट देशों में कोई विधि-संग्रह है ?

विधि-संग्रह प्रत्येक कम्यूनिस्ट देश में मौजूद है। सोवियत यूनियन का विधि-संग्रह ग्रन्य कम्यूनिस्ट देशों के लिए नमूने का काम देता है। इन विधि-संग्रहों में इस बात की व्याख्या होती है कि कम्यूनिस्ट देशों में नागरिक की हैसियत क्या है, इसकी जिम्मेदारियाँ कौन-कौन-सी हैं। इनमें राज्य विरोधी कार्यविधियाँ करने वालों के लिए कौन-कौन-से दण्ड नियुक्त किए गए हैं।

कम्यूनिस्ट देशों में विधि-संग्रह का सबसे बड़ा काम राज्य के हानि लाभ की सुरक्षा करना है, नागरिक के ग्रधिकारों की निगरानी या रक्षा नहीं जैसा कि प्रजातांत्रिक देशों में होता है।

सोवियत रूस में कम्यूनिज्म के पहले कुछ वर्षों में कानूनी शिकंजे में सब से पहले "वर्ग शत्रु" फेंसे, अर्थात् वे लोग जो इस नए सिस्टम के विरुद्ध थे। साधारण अपराधी, चोर इत्यादि नम्र व्यवहार के पात्र समभे गए। दलील यह दी गई कि सोवियत समाज के "खालिस कम्यूनिज्म" की मंजिल तक पहुँचते-पहुँचते अपराघ स्वयं ही समाप्त हो जाएँगे। इसलिए अन्तरिम काल में कठोर दण्ड देने की आवश्यकता नहीं।

परन्तु ऐसा हुआ नहों। एक ग्रोर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, भूमि का सामूहिकीकरण किया जा रहा था, दूसरी ग्रोर अपराध बढ़ रहे थे। मजदूरों के अधिकार में कुछ भी नहों था। राज्य के पास सर्वस्व अधिकार थे। राज्य के लिए मजदूरों में न तो निष्ठा थी ग्रौर न ही सहानुभूति, न अपने कत्तंव्य का एहसास। इसके परिणामस्वरूप १६३० ग्रौर उसके पश्चात् सोवि-यत विधि-संग्रह में बहुत से परिवर्तन किए गए। कम्यूनिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण से इन परिवर्तनों का आश्रय यह था कि मजदूरों को ग्रधिक अनुशासित किया

जाए । १६ स्था में देते रिलिम् ने भीषं गिपका गंजपहील के अपिक्षा आफ यह अविक आवश्यक है कि हमारे कानून स्थावर हों।"

स्तालिन की इस घोषणा का ग्रिमिप्राय यह था कि शासक वर्ग को ग्रानु-शासन लागू करने के लिए कठोर दण्ड विधान की ग्रावश्यकता थी ताकि जनता पर उनकी पकड़ ग्रीर भी दृढ़ हो जाए। इस प्रकार के कानूनों का उदाहरण श्रमिक की नियमावली है। इसके नियम बहुत कठोर हैं। ग्रिमिप्राय यह है कि मजदूर संघटन के चुंगल में फंसकर विवश हो जाएं। सरकार के ग्राधिक प्रोग्रामों में, राजकीय योजना के किसी भाग में यदि कोई व्यक्ति बाधा डालता है ग्रथवा तोड़-फोड़ का प्रयत्न करता है, उसे कठोरतम दण्डों का पात्र समभा जाता है। ग्रव सोवियत दण्ड विधान का सिहावलोकन हो रहा है परन्तु यह काम ग्रभी पूरा नहीं हुग्रा।

२. सोवियत यूनियन में वैधानिक न्यायालयों का कौन-सा सिस्टम प्रचलित है ?

१६३६ के विधान के अनुसार रूस की सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। प्रत्येक प्रजातांत्रिक यूनियन की अपनी सुप्रीम कोर्ट है। इनके अतिरिक्त प्रादे-शिक न्यायालयों का पूरा जाल फैला हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने विशेषित न्यायालय भी नियुक्त कर रखे हैं जैसे रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन कोर्ट, मजदूरों के न्यायालय इत्यादि । ये न्यायालय विशेष मामलों

से सम्बन्धित मुकदमों के फैसले करते हैं।

स्थानीय न्यायालय, सार्वजिनक न्यायालय के नाम से पुकारे जाते हैं। इनके सदस्य तीन वर्ष की अविध के लिए जनमत से चुने जाते हैं। निर्वचिन से पूर्व स्थानीय कम्यूनिस्ट पार्टी प्रत्येक उम्मीदवार की जांच-पड़ताल करती है।

१६३७-३८ में स्तालिन ने प्रपने विरोधी नेताओं को निकाल बाहर करने के लिए "संशोधन का महान् ग्रांदोलन" चलाया था। रूस के न्यायालयों का भरम उन्हीं दिनों टूटा कि वह किस प्रकार पार्टी के ग्रान्तरिक द्वंद्व तथा राजनीतिक कूटनीति का मोहरा बनती हैं। ग्रांद्रे विशस्की उन दिनों सरकारी वकील थे। "पुराने बोलशेविकों" ग्रीर उनके साथियों पर जो नाममात्र मुकदमे चले उनमें ग्रदालती कायंवाही केवल खानापूरी के लिए होती थी। ग्रपराधियों के न्यायालय में उपस्थित होने से पहले ही उनके लिए स्तालिन की ग्रोर से दण्ड निश्चित कर दिये जाते थे।

स्तालिन की मृत्यु के पश्चात् एक बार फिर मुकदमों की हवा चली। इस बार निशाना ल्योरेन्टी वेरिया तथा उनके सहयोगी थे। इस प्रकार के आंत- Digitized by Arva Samaj Foundation Chennai and eGangotri रिक राजनीतिक मुकदमें सब कम्यूनिस्ट देशों में होते ही रहते हैं। कम्यूनिस्ट चीन में भी स्थिति इससे भिन्न नहीं।

पार्टी के भीतर के ऐसे मुकदमों में अपराधियों पर जो आरोप लगाये जाते हैं वे हैं, क्रान्ति विरोधी कार्यवाहियाँ और विदेशों के लिए जासूसी, "राज्य की आर्थिक स्थिति को भंग करने का प्रयास", "राज्य विरोधी तोड़-फोड़" इत्यादि। कम्यूनिस्ट पार्टी के पद-अधिकारी भी, जिन्होंने अपना जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया है, वे भी अपने आपको ऐसे आरोपों से सुरक्षित नहीं समस्ते। यह सर्विधिकारी पद्धित का एक अंश है, उदाहरण के लिए आजरवाईजान के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री और तीन उच्च अधिकारियों को मई १९५६ में "क्रान्ति विरोधी कार्यवाहियों" का आरोप लगा कर दण्ड दिया गया।

इ. कम्यूनिस्ट देशों में न्याय की व्यवस्था कैसे होती है ?

यदि पश्चिमी देशों के स्तर से परखा जाए तो रूस में किसी हद तक साधारण अपराधियों के साथ न्याय किया जाता है। इस सम्बन्ध में सोवियतः दण्ड-विधान अन्य देशों से भिन्न नहीं है।

परन्तु राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का जहाँ तक सम्बन्ध है सोवियत कातून और न्यायालय (जिनकी सहायता के लिए गुप्त पुलिस भी मौजूद है) की अपनी एक अलग ही श्रेणी है।

मार्च, १६५३ में स्तालिन की मृत्यु तक "सोशिलस्ट विधि" का नियम सर्वाधिकारी राज्य में विधि अनुसार न्याय के आदर्श के तौर पर बढ़-चढ़कर पेश किया जाता था परन्तु इसको कार्यान्वित कम ही किया जाता था। गुप्त पुलिस का किसी को पकड़ लेना उसे दोषी ठहरा देने के समान था। अन्याय की हद थी कि उसे अपील करने का अवसर भी नहीं मिलता था, जबरी श्रम के कैंप में कैंद से लेकर मौत तक का दण्ड दिया जा सकता था। अभियुक्तों पर अत्यान्वार और पुलिस द्वारा जुल्म आम होता। पुलिस आतंक फैलाने के लिए हर समय उत्सुक रहती थी।

फरवरी १६५६ में सी० पी० एस० यू० की वीसवीं कांग्रेस में खूंड्चेब का वह प्रसिद्ध भाषण हुआ जिसमें उन्होंने "व्यक्तित्व पूजा" को प्रचलित करने का आरोप लगाकर स्तालिन की निन्दा की। उन्होंने यह घोषणा भी की कि अन्य त्रुटियों के अतिरिक्त स्तालिन का एक दोष यह भी था कि उन्होंने पार्टी के मुख्य सदस्यों के विरुद्ध मुकदमों में "सोश्चलिस्ट न्याय्यता" का पालन नहीं किया । पछन्तुः स्ट्रुक्त्रेव्यन्ते व्यक्ति स्वाप्ति स्वा

खु रचेव के इन एलानों के प्रश्चात् सुप्रीम सोवियत ने विधि प्रोजेक्ट आयोग नियुक्त किया। उसे रूस में विधि तथा न्याय शासन के संशोधन का काम सींपा गया। दिसम्बर, १९५० में सुप्रीम सोवियत ने आयोग द्वारा निश्चित "मूल नियम" स्वीकार कर लिए। १९५९ में सोवियत यूनियन की अदालतें उनको कार्यान्वित करने लगीं, परन्तु इन पर अमल की हद प्रत्येक गणराज्य पर निर्भर थी।

नव दण्ड विधान का रूस से बाहर के जिन कानूनदानों ने अध्ययन किया है, वह उसमें कई त्रुटियां बताते हैं। रूस में ज्यूरी सिस्टम नहीं है। प्रायः कानून पढ़ा वकील ही अपराधी का कानूनी सलाहकार बन सकता है। परन्तु अदालत की आज्ञा से साधारण व्यक्ति भी कानूनी सलाहकार बन सकता है। किसी सोवियत नागरिक को अपराधी होने के शक पर ही बिना वारण्ट पकड़ा जा सकता है, मुकदमा चलाए बिना अथवा उसके विरुद्ध अपराधों की सूची दिए बिना ही उसे अनिश्चित काल के लिए कारावास में रखा जा सकता है, जब अपराधी बन्दी बना लिया गया होतो उसका बकील उससे मिल तो सकता है परन्तु मुकदमें से पहले की खोज में भाग नहीं ले सकता।

४. जन-न्यायालयों का क्या ग्रिभप्राय है ?

जन-न्यायालय जिला के सबसे छोटें न्यायालय होते हैं। इनके न्यायाधीशों को कानून और विधि का कोई ज्ञान नहीं होता। नशे में बदमस्ती के या पत्नी की मार-पीट के मुकदमें वही सुनते हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण तथा मुख्य कत्तंव्य यह देखना है कि सरकारी प्रोग्राम (जैसे वाधिक पैदावार का कोटा) स्थानीय स्तर पर पूरा होता रहे। इस प्रकार इनके ग्रधिकार में ऐसे मुकदमें आते हैं "काम से बचना", "ग़ैर-जिम्मेदारी", "ग्रनाज की चोरी" इत्यादि।

जन-न्यायालय ऐसे स्थानीय सरकारी कर्मचारियों पर भी मुकदमा चला सकते हैं जिन पर छल-कपट, सरकारी माल की चोरी, रुपया ऐंठने, रिकार्ड को भ्रष्ट करने और सरकारी संस्थानों के विरुद्ध अन्य आरोप हों। यदि जुमें किसी उच्च अधिकारी ने किया हो तो मुकदमा प्रान्तीय अथवा प्रादेशिक न्याया-लय के पास भेज दिया जाता है। या फिर यूनियन प्रजातन्त्र का सुप्रीम न्याया-धिकरण निर्णय करता है। थ. स्या सोवियत यूनियन के प्रातिरिक्त ग्रांन्य किम्यूनिरंट देशी भेजि

जन-न्यायालय हैं ? जन-न्यायालय लगभग सब कम्यूनिस्ट देशों में हैं। उत्तरी कोरिया ग्रौर

कम्यूनिस्ट चीन में भी हैं।

पूर्वी यूरोप में कम्यूनिस्टों के पदाल्ड होते ही यह न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे। उन्होंने केवल फासिस्टों ही पर मुकदमें नहीं चलाए बल्कि हजारों छोटे-बड़े जमींदारों, दुकानदारों तथा मध्यवर्ग के बहुत से व्यक्तियों को भी अत्याचार का निशाना बनाया और उन्हें भी कैंद से लेकर फांसी तक के दण्ड दिए गए।

पिट्ठू देशों में जन-न्यायालयों के "न्याय" का निशाना बनने वालों में सोशिलस्ट कृपक और वे नागरिक शामिल थे जिन्हें कम्यूनिज्म के विरोधी समक्षा जाता था। उदाहरण के लिए बल्गारिया में कम्यूनिस्टों के सत्ता प्राप्त कर लेने के पश्चात् ११,००० ग्रिभयुक्तों में "युद्ध ग्रपराधी" बहुत कम थे। बड़ी संख्या उन लोगों की थी जिन्हें कम्यूनिस्ट परिभाषा में वर्गशत्रु कहा जाता है।

कम्यूनिस्ट चीन में "जन-न्यायाधिकरणों के ग्रादेश से कम-से-कम पंद्रह् लाख व्यक्तियों को फांसी पर चढ़ाया गया ग्रीर कोई चार करोड़ ग्रपनी धन सम्पत्ति से मुक्त कर दिए गए। प्रारम्भ में "वर्ग संघर्ष" केवल वड़े भूमिदारों ग्रीर जागीरदारों तक ही सीमित था, परन्तु बाद में इसकी लपेट में वे किसान भी ग्रा गए जिनके पास भूमि ग्रधिक नहीं थी। तथाकथित जन-न्यायालयों ने "उन्हें" दूसरों के श्रम से ग्रनुचित लाभ उठाने वाले वर्ग में शामिल कर दिया हालांकि वे वेचारे स्वयं ही ग्रपने कुटुम्बियों की सहायता तथा सहयोग से खेती करते थे।

इ. साधारण ग्रपराघों के मुकदमों का निर्णय करने का ग्रधिकार किन ग्रदालतों को है ?

१६४६ के एक ब्रादेशानुसार नाममात्र सहयोगी ब्रदालतें स्थापित की गई। साघारण अपराघों के मुकदमे सुनने का काम इन्हें सींपा गया। जन न्यायालयों से इन ब्रदालतों का स्तर छोटा था। यह ब्रदालतें कारखानों और अन्य सरकारी संस्थानों, रिहाइशी मुहल्लों तथा ग्रामों में बैठती थीं।

इन ग्रदालतों में न्याय करने वाले व्यक्तियों को न तो कानून का ज्ञान होता था ग्रीर न ही उन्हें न्यायाधीश के कर्तव्य को पूरा करने की ट्रेनिंग मिली होती थी। ग्रवैध कार्यवाइयों की एक लम्बी सूची थी जिनके ग्रधीन पकड़े गये व्यक्ति इन अदालुतीं में पेक प्रिकेश किये कहिती हैं। में ति काम से अनुपित प्रयोग काम से अनुपित प्रयोग काम में अरुचि और "विफल काम"। अनुचित सामाजिक व्यवहार पर भी इन अदालतों में मुकदमा चलाया जाता था। जैसे गाली-गलीच, मार-पीट, सट्टा, काला व्यापार, नशे की वदमस्तियां इत्यादि आरोपों में पकड़े जाने पर मुकदमा इन्हीं अदालतों में पेश होता था।

ये ग्रदालतें डांट डपट, सी रूबल तक जुर्माना, पदावनित तथा पदच्युत तक दंड दे सकती हैं। ग्रभियोग बड़े हों तो मुकदमा जन-न्यायालयों में पेश कर दिया जाता है। "न्याय" के इस सिस्टम का प्रत्यक्ष रूप में ग्रनुचित प्रयोग होता था। ७. कम्यूनिस्ट दावा करते हैं कि सोवियत यूनियन में चोर ग्रोर डाकू नहीं हैं। क्या यह बात सत्य है?

दितीय महायुद्ध का जबसे अन्त हुआ है, इक्के दुक्के-चोरों, डाकुओं और संगठित अपराधी गुटों की चर्चा सोवियत समाचार पत्रों में प्रायः होती ही रहती हैं। सोवियत पत्र-पत्रिकाओं में ऐसे समाचार भी अधिक आ रहे हैं जिनमें सरकारी संस्थानों, उद्योगिक कारखानों के अब्टाचार तथा अपराधी कार्रवाइयों का वर्णन होता है।

करोड़ों रूबल का सरकारी माल प्रत्येक वर्ष चोरी होता है या अवैध कार्य-विधियों से वेच दिया जाता है। ये अपराध धन के लोम के कारण किये जाते हैं, जिसकी कम्यूनिस्ट निन्दा करते हैं। कुछ अवैध कार्रवाइयाँ इसलिए की जाती हैं कि अयोग्यता छिपी रहे, या उत्पादन लक्ष्य पूरा न होने की गल्ती पर पर्दा पड़ा रहे। अष्टाचारी लोग कारखाने और फार्म का रिकार्ड बदल देते हैं ताकि यह व्यक्त हो कि पदावारी कोटा पूरा हो गया है, जबिक वास्तव में पैदाबार निर्धारित लक्ष्यों से कम होती है।

नवयुवकों में अपराध वृत्ति (दंगा फसाद, उच्चकापन, मिंदरापान इत्यादि) इतनी तेजी से बढ़ी है कि १६५५ और १६५६ में रूस में "पाप के विरुद्ध" अभियान चलाना पड़ा। नवयुवक गुण्डों में अधिकतर सरकारी अधिकारियों की सन्तान थी।

प्- कम्यूनिस्ट देशों में कान्न भंग करने वालों पर कौन सा विभाग मुकदमा चलाता है ?

कानून भंग करने वालों पर मुकदमे चलाना न्याय-मंत्रालय की जिम्मेदारी है। १९५६ में यूनियन न्याय-मंत्रालय के कर्त्तव्य तथा ग्रधिकार एक फरमान द्वारा यूनियमि असे असे को क्यायामिकार विए जाने से भी उनकी आन्तरिक

स्वाधीनता में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई।

कम्यूनिस्ट जब किसी देश पर छा जाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले उनकी नजर न्यायमंत्री के पद पर पड़ती है। इस मंत्रालय पर अधिकार हो जाने से न्यायालयों पर इनका आधिपत्य हो जाता है। न्यायमंत्री कम्यूनिस्ट या इनका अनुयायी हो तो कम्यूनिस्ट पार्टी को अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने और उनको खत्म करने का अवसर मिल जाता है।

कम्यूनिस्टों के निकट दूसरा महत्वपूर्ण पद गृहमंत्री (ग्रथवा प्रतिरक्षा मन्त्री) का है जो राजनीतिक या गुप्त पुलिस का ग्रध्यक्ष होता है। कम्यूनिस्ट पार्टी के निर्देश के ग्रधीन वह न्यायमंत्री को पूरा-पूरा सहयोग देता है। ३. क्या पिट्ठ देशों के न्यायालयों में न्यायविधि में ग्रव कुछ परिवर्तन श्राए हैं?

पिट्ठू देशों में ग्रदालतों में न्यायविधि इतनी कठोर नहीं रही। परन्तु स्तालिनी तरीके ग्रमी तक प्रयोग होते हैं। सोवियत सेना ने जब हंगरी में जन-संग्राम की ज्वाला को ठण्डा किया तो मास्को के समर्थन के साथ कादर सरकार ने घोषणा की कि हंगरी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एम्रे नागी और उनके नजदीकी सहयोगी स्वतंत्रता से रह सकते हैं, उन्हें कोई हानि नहीं होने दी जायगी। २६ नवम्बर, १६५६ को जब नागी बुडापेस्ट के ग्रुगोस्लाव दूतावास की शरण में थे तो कादर ने बयान दिया—"हम वचन देते हैं कि एम्रे नागी और उनके मित्रों के विरुद्ध उनके गत ग्रपराधों के ग्राधार पर कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है...हम ग्रपने वचन पर स्थिर रहेंगे।"

इस प्रकार सञ्ज बाग दिखाकर नागी को उनके आश्रय स्थान से निकाल लिया गया। तुरन्त ही सोवियत एजेंट उन्हें ले उड़े। कई मास तक तो कादर सरकार ने उनका पता-निशान ही न बताया। फिर १७ जून, १६४८ को घोषणा की कि नागी, जनरल पाल मालेटर और दो हंगेरियन पत्रकारों को मृत्युदण्ड दिया गया है। न्याय की इस दुगैति पर संसार के कोने-कोने से रोष प्रकट किया गया। परन्तु खू इचेव ने इन सजाओं का समर्थन किया और कहा कि हंगरी के मृतपूर्व देशद्रोहियों पर अत्याचार विल्कुल उचित था।

सातवां अध्याय साम्यवाद का लौह श्रावरगा

१. लीह ग्रावरण ग्रीर वाँस पट से क्या ग्रामिप्राय है ?

लौह श्रावरण उन प्रतिवंधों का प्रतीक है जो यूरोप की साम्यवादी सर-कारों—विशेषतया सोवियत संघ—ने श्रपनी जनता पर लगा रखे थे। ये सरकारें श्रपनी जनता और वाहरी दुनिया के पारस्परिक सम्बन्धों पर—चाहे वह विचारों का श्रादान-प्रदान हो या लोगों का श्राना-जाना—नियंत्रण रखना चाहती थीं। वांस पट भी ऐसे ही वंधन थे जिनके द्वारा उत्तरी कोरिया और चीन की साम्यवादी सरकारों ने श्रपनी जनता को वाह्य संसार से श्रलग-थलग रखना चाहा। श्रव थे वंधन उतने कठोर नहीं रहे।

सोवियत जनता को अपने ही देश में बंदी बनाये रखने वाले इन बंधनों को स्तालिन ने "सोवियत सामाजिक व्यवस्था" का नाम दे रखा था। किन्तु इसे केवल सामाजिक व्यवस्था कहना उचित न होगा। पूर्णतया सुरक्षित सीमाएँ और बन्दरगाहों पर पूरा नियंत्रण तो एक श्रुक्कला की कड़ियाँ हैं जिसका उद्देश्य साम्यवादी व्यवस्था को किसी भी प्रतिकूल सम्भावना से अछूती रखना है। साम्यवादी सरकारें अपनी जनता को बाहरी दुनिया के बारे में केवल उतना ही पढ़ने, सुनने या जानने की इजाजत देती हैं जितना वे समभें।

१९५६ से रूस तथा पोलैंड में ये पावंदियाँ उतनी कठोर नहीं रहीं। विदेशी संवाददाताओं पर सेंसर पहले से ढीला हो गया है। विदेशी प्रकाशन भी ग्रधिक संख्या में प्राप्त होने लगे हैं।

२. सूचना स्वातंत्र्य के प्रतिबंध पर रूसी जनता की प्रतिक्रिया ?

सूचना प्रसार के सभी साधनों पर सोवियत सरकार का नियंत्रण होने के वावजूद भी यह स्पष्ट है कि सामूहिक रूप से वहाँ की जनता पार्टी प्रोपेगण्डा के प्रति उदासीन सी है।

१० जिस्स्य १० १० १० क्लेग्सी 50 पी विष्क्ष शिक्ष काल कि केन्द्र प्रिक्ष ति ने एक प्रस्ताव पास किया कि सोवियत जीवन में अभी तक अराजनैतिक दृष्टिकोण का वैयक्तिक रूप से प्रचार हुआ है राष्ट्रवाद और विश्वैकतावाद का विप फैला हुआ है। अतीत के अवशेष वाकी हैं। इनमें मेहनत और फर्ज से जी चुराना, सरकारी सम्पत्ति की चोरी, नौकरशाही, अष्टाचार, सट्टा, जी-हजूरीपन, वद-मस्ती, गुण्डागिरी तथा अन्य बुराइयां — जिनका सोवियत समाज में कोई स्थान नहीं — फैली हुई हैं। इन त्रृटियों को दूर करने के लिए सतत प्रयास की आव- स्थकता है। इसी प्रस्ताव में सी० पी० एस० यू० ने व्यवसायी प्रचारकों के नीरस और शुष्क भाषणों की भी कड़ी आलोचना की।

चालीस वरसों के निरन्तर प्रोपेगण्डा द्वारा भी सोवियत संघ नये समाज-वादी मानव की रचना करने में सफल नहीं हुग्रा। रूस में भी समाज-विरोधी व्यवहार ग्रौर ग्राचरण की कमी नहीं है।

जनसाधारण में अब साम्यवाद और सरकार के प्रति विरोध का स्थान अनासक्ति ने ले लिया है। सोवियत संघ में भ्रमण करने वाले कुछ यात्रियों का कथन है कि सोवियत नागरिक समाचार, सूचना और प्रसारण की सच्चाई को परखने का कष्ट तक नहीं करते।

ः क्या अन्य साम्यवादी देशों में भी लौह आवरण ऐसा ही है जैसा कि सोवियत सघ में ?

सोवियत संघ हो या कोई अन्य साम्यवादी देश—लक्ष्य सभी का एक है और वह ये कि साम्यवादी देशों के नागरिक स्वतन्त्र संसार से किसी प्रकार का सम्पर्क न रखने पाएँ किन्तु साम्यवाद के पिट्ठू देश पिरचमी यूरोप की सीमाओं के निकट हैं अतः वहाँ इन पावंदियों को पूर्णतया लागू करना सरल नहीं। पिश्चमी देशों से प्रसारित होने वाले प्रोग्रामों को ये बंदी लोग बड़ी उत्सुकता से सुनते हैं हालांकि ऐसा करना भारी अपराध माना जाता है और पकड़े जाने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था है। इन प्रोग्रामों को 'जाम' करने के लिए सोवियत सरकार काफी खर्च करती है। फरवरी, १६६० को सोवियत सरकार ने ब्रिटेन से रूसी भाषा में प्रसारण पर निषेध उठा लिया था। अम-रीकी प्रसारण सोवियत संघ में अभी तक निषद्ध हैं। ४. लीह स्राह्मरूक्त के शिक्षे पहिने किली जनसा को स्वतंत्र संस्टाले सम्पर्क क्यों नहीं रखने दिया जाता ?

लौह ग्रावरण की पावंदियों ग्रीर मनाहियों का एक सीधा-सा कारण यह है कि साम्यवादी ग्रधिकारी यह नहीं चाहते कि उनकी ग्राधीन जनता सच्चाई को पहचान ले क्योंकि सत्य का ग्रालोक होते ही उनकी मिथ्या प्रवचनाग्रों के मिट जाने की ग्राशंका है। एक कारण ग्रीर भी है ग्रीर उसका सम्बन्ध मार्क्संलिन के साम्यवादी दृष्टिकोण से है। जब लौह ग्रावरण से घिरे लोग कई साल तक केवल मार्क्सिजम-लेनिनिज्म का पाठ पढ़ते ग्रीर सुनते हैं तो एक समय वह भी ग्रा जाता है जब—साम्यवादियों के तक के ग्रनुसार—रूढ़ियाँ उनके सिद्धांत बन जाती हैं। सोवियत रूस के बारे में यह बात ज्यादा लागू होती है लेकिन जिन देशों पर कम्यूनिस्ट ग्राधिपत्य हुए ग्रधिक समय नहीं हुग्रा है उनके बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं।

प्र. क्या साम्यवादी देशों ग्रौर ग्रन्य देशों के वीच यात्रा की सुविधाएँ

उपलब्ध हैं ?

सोवियत सरकार काफी संख्या में व्यापारिक तथा सांस्कृतिक शिष्टमंडल वाहर भेजती और अपने देश में बुलाती रहती है। वैज्ञानिक और टैक्नीकल शिष्टमण्डल बुलाने और भेजने में मास्को अधिक उत्सुकता दिखाता है। उनकी सदैव यह इच्छा रहती है कि ऐसे क्षेत्रों में जिनमें वे पिछड़े हुए हैं दूसरे देशों से अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जाए। साम्यवादी देशों से खेल कूद की टीमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्राय: भाग लेती रहती हैं। रूस की ओपरा पार्टियाँ भी विदेशों में अपनी कला प्रदर्शन के लिए जाती रहती हैं। सरकार की ओर से भेजे हुए शिष्टमण्डलों के इलावा सोवियत नागरिकों को अपने देश से बाहर जाने का अवसर बहुत कम मिलता है। साम्यवादी देशों के नागरिक स्वतंत्र देशों में स्वेच्छा से वेरोक-टोक नहीं जासकते। साम्यवादी देशों की ओर से लगाई गई पाबंदियों के कारण स्वतन्त्र देशों के नागरिक भी आजादी से इन देशों में नहीं जा सकते किन्तु अब यह प्रतिबंध पहले से कम कर दिये गये हैं।

१९५८ से रूस सरकार विदेशी यात्रियों को सोवियत संघ में आने के लिए प्रोत्साहित करने लगी है। सोवियत ट्रैबल एजेंसी इन हजारों यात्रियों को ऐसे स्थल देखने की सुविधाएँ देती है जो प्रोपेगण्डा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं किन्तु देश के बहुत बड़े हिस्से की यात्रा करना अब भी सहज नहीं।

६. क्या स्वितिम्र देशी भी भी रहे साम्यीयादी देशी क्षी जनता की भी ज्यापनी रुचि के अनुसार विदेशी समाचारपत्र पढ़ने, रेडियो सुनने और टेलीवीजन देखने का अवसर मिलता है ?

साम्यवादी देशों के नागरिकों के सामने हर सूचना सेंसर और नियंत्रण से छन कर ग्राती है। रेडियो स्टेशन भी सरकारी प्रोपेगण्डा के साधन हैं तथा वही सूचनाएँ व समाचर प्रसारित करते हैं जो सरकार चाहे। समाचार ग्रीर सूचना प्राप्ति के विदेशी साधनों तक, स्वतंत्र रूप से उनकी पहुँच ही नहीं है। ७. क्या साम्यवादी देशों में समाचारपत्रों को स्वतंत्रता प्राप्त है?

नहीं ! प्रेस की ग्राजादी के सवाल का साम्यवादी जवाव लेनिन ने इन शब्दों में दिया था: "मुद्रण व प्रकाशन की सभी सामयिक तथा गैर सामयिक संस्थाग्रों पर कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति का नियंत्रण होना चाहिए चाहे उस समय पार्टी स्वयं वैधानिक हो या ग्रवैधानिक। प्रकाशनगृहों को कोई ऐसी नीति ग्रपनाने का ग्रधिकार नहीं होना चाहिए जो पार्टी के ग्रनुंकूल न हो।"

साम्यवादी देशों में प्रेस पर तो पार्टी का पूरा-पूरा नियन्त्रण है ही। लौह ग्रावरण के बाहर भी जो कम्यूनिस्ट पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, मास्को नीति की ही प्रतिब्विन हैं। साम्यवादी चीन ग्रीर कोरिया में तो प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल ही नहीं उठता। साम्यवादी देशों में इस कड़े नियन्त्रण का शिकार सिफं प्रेस ही नहीं, रेडियो ग्रीर टेलीवीजन भी हो चुके हैं।

द. क्या साम्यवाद में सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी सेंसरिशप की छाप है ? 'समाजवादी यथार्थवाद' के नाम पर तमाम सांस्कृतिक गतिविधियों पर

सेंसरिशप और पार्टी की कड़ी नजर रहती है। वड़े सोवियत इनसाईक्लो-पीडिया ने "समाजवादी यथाथंवाद" की परिभाषा इस प्रकार की है। "समाजवादी यथाथंवाद" जीवन को कला के रूप में प्रतिविम्बित करने का साधन है। क्रांति-कारी विकास का सही रूप प्रकट करना ही इसका उद्देश्य है। साहित्य की मांग यह है कि नई पीढ़ी ग्रर्थात् समाजवादी समाज के जन्मदाताओं की एक तस्वीर खींची जाए जिनमें साम्यवाद के लिए उनके ग्रथक संघर्ष का सही चित्र हो।

इस दृष्टिकोण के प्रमाणस्वरूप घटिया प्रकार की रचनाओं के ढेर लग गए। पार्टी, स्टेट और जीवन के साम्यवादी पहलू के प्रचार से अधिक इन रचनाओं का कोई मूल्य नहीं।

"स्मिल्जंबिद्दीश्येश्रीविद्यावंकिल्स्वित्तं अस्ति श्रेभाषं विकेल्प्रीक्ष्ण्यां नृत्यों पर पड़ा है। कला की दृष्टि से रूस में इनका स्तर बहुत ऊँचा है। सोवियत संगीत भी "समाजवादी यथार्थवाद" से ग्रछूता वच सका है। इसीलिए ग्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सोवियत संगीतज्ञ वरसों तक कड़ी ग्रालोचना के भागी रहे कि उनकी रचनाएं सामान्य जीवन का सही चित्रण करने में असफल रही हैं। १९५८ में पार्टी ने कुछ प्रसिद्ध संगीतज्ञों को "पुनः स्थापित" किया। इनमें शोस्टाकोविच, प्रोकोफीव ग्रौर खाचाटोरिया भी शामिल हैं ग्रीर ग्रव उन्हें डराया-धमकाया नहीं जाता।

कुछ गिने-चुने लेखक ऐसे भी थे जिन्होंने "समाजवादी यथार्थवाद" से दूर रहना चाहा । फलस्वरूप उनकी भोली में अधिक निरादर और फटकार पड़ी। १९५३ में स्तालिन की मृत्यु के पश्चात् कई लेखकों की क़लम ने पुराने निषेधों के बांध तोड़ कर एक नई, ग्राजाद ग्रीर रचनात्मक विचारधारा को जन्म दिया। इस सम्बन्ध में ग्रहरनवर्ग के नावल "वर्फ पिघलती है" ने पथ-प्रदर्शन किया। पार्टी ग्रधिकृत लेखक यूनियन ने इसका वहुत विरोध किया। इडिनस्टेव का उपन्यास "केवल रोटी ही से नहीं" ने भी प्रचलित धारा का खण्डन किया। पार्टी के रुढ़िवादी ग्रालोचकों ने इस पुस्तक को भी ग्राड़े हाथों लिया। कथा-साहित्य में सबसे ग्रधिक विवाद।स्पद पुस्तक कवि वोरिस पास्तरनक की "डाक्टर जिवागो" थी। यह १९५८ में इटली से प्रकाशित हुई। रूस में तो इसे शीघ्र ही जब्त कर लिया गया किन्तु अन्य देशों में यह पुस्तक बहुत अधिक संख्या में प्रकाशित हुई ग्रीर पढ़ी गई। ग्रक्तूबर १९५८ में पास्तरनक को साहित्य का नोविल पुरस्कार दिया गया। इस सम्मान पर सी० पी० एस० यू० ग्रीर लेखकों की यूनियन ने खूब रोष उगला।

१६५६ में सी० पी० एस० यू० ग्रौर पिट्ठू देशों की कम्यूनिस्ट पार्टियों ने प्रचलित प्रथाओं के विरुद्ध फूटती हुई खंडन की प्रवल लहरों को बहुत रोकना चाहा। कथा-साहित्य, ग्रालोचना, नाटक या साहित्य के सभी क्षेत्रों को पार्टी की ओर से निर्धारित सीमाओं में बाँधने की कोशिश की गई। अब नई घारा सिर्फ पोलैण्ड में ही जीवित रह पाई है। हंगरी तथा चैकोस्लोवािकया में उभ-रते हुए विद्रोही साहित्यिक ग्राँदोलन वेरहमी से कुचल दिए गए। साम्यवादी चीन और उत्तरी वीयतनाम में भी कुछ दिनों के लिए पार्टी लाइन के प्रतिकूल साहित्य की रचना की गई किन्तु इसे सहन नहीं किया गया स्रोर १६५६ में

नवचिन्तन के इन सुकुमार पुष्पों को निर्देयता से मसल दिया गया।

श्राठवां श्रध्याय कम्यूनिज़म चौर धर्म

१. क्या कम्यूनिस्ट देशों में धर्म का कोई श्रस्तित्व है ?

कम्यूनिस्ट सरकारें निरन्तर ऐसे प्रयोजन करती रहती हैं जिनसे जनता के धार्मिक विश्वास कमजोर पड़ जाएं और अन्त में दम तोड़ दें। परन्तु इनके ये प्रयास अभी पूरी तरह सफल नहीं हुए। कम्यूनिज्म के अधीन जनसाधारण की धार्मिक निष्ठा अभी तक बनी हुई है।

बौद्ध, इस्लाम और ईसाई घर्मों के अनुयायी कम्यूनिस्ट देशों में आज भी करोड़ों की संख्या में मौजूद हैं। परन्तु कलीसा अब इतनी शक्तिशाली और संगठित संस्था नहीं रहा। धार्मिक नेता—पादरी और कलीसा के अन्य कार्य-कर्ता—नास्तिक कम्यूनिस्ट सरकारों के हाथों कठोर से कठोर अत्याचार सहन करते रहते हैं।

१६१८ से लेकर अब तक हजारों पादरी, भिक्षु, मौलवी इत्यादि बेगार के कैम्पों में भेजे जा चुके हैं या मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। घर्म के आघार पर अत्याचार का सिलसिला अब रूस में खत्म हो चुका है परन्तु चीन में बहुत बढ़ गया है।

२. कम्यूनिस्ट धर्म को मिटाना क्यों चाहते हैं ?

कम्यूनिस्ट शासक इस नियम को नहीं मानते: "जो सीजर का हक है सीजर को, श्रीर जो ईश्वर का हक है ईश्वर को दो।" वे तो अन्धविश्वास श्रीर पूर्ण निष्ठा माँगते हैं जिसकी पात्र केवल कम्यूनिस्ट पार्टी श्रर्थात् कम्यूनिस्ट प्रणाली हो। घम चूंकि यह सिखाता है कि ईश्वरीय शक्ति अन्य सब शक्तियों से बड़ी है श्रीर उसका शासन सर्वोत्तम है, इसलिए कम्यूनिस्ट धम को सिरे से ही मिटा देने पर तत्पर हैं।

कम्यूनिस्ट की मजहब से दुश्मनी का एक कारण यह भी है कि प्रारम्भ में जब कम्यूनिस्टों ने शासन संभाला तो गिरजाघरों की जायदाद में उन्हें ग्रामदनी ३. जब कम्यूनिस्ट धर्म को खत्म करने पर तुले हुए हैं तो कम्यूनिष्म के प्रधीन जनता का धर्म ग्राखिर क्या है ?

कम्यूनिस्ट देशों के लोग ग्रभी तक एक सर्वोच्च शक्ति में विश्वास रखते हैं। कम्यूनिस्ट वहां की कुल ग्रावादी का ग्रांशिक भाग है। फिर जहाँ तक धर्मनिष्ठा का सम्बन्ध है, कम्यूनिस्टों में भी मतभेद हैं। उन्हों में एक छोटा-सा ग्रुप ऐसा है जो मार्क्सी-लेनिनी सिद्धान्तों पर ग्रटूट विश्वास रखता है उसका ईमान है कि इन पर ग्रमल से ही जनता की हालत सुधर सकती है।

कम्यूनिस्टों की वड़ी संख्या इस बात पर विश्वास रखती है कि पार्टी के प्रति, पूर्ण और अपार भक्ति ही से शक्ति और समृद्धि के आकाश तक पहुँचा जन

सकता है।

.. कम्यूनिस्ट किस धर्म को मानते हैं?

किसी को भी नहीं। धर्म की ग्राम परिभाषा यह है कि ईश्वर या देवता की भक्ति की जाए। कम्यूनिस्ट ग्रपने ग्रापको नास्तिक कहते हैं। वे ईश्वर के ग्रस्तित्व से ही मुनकर हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी के नेताग्रों ने पार्टी के मेम्बरों को यह काम सौंप रखा है कि घर्म के विरुद्ध संघर्ष जारी रखें।

प्र. क्या सोवियत रूस में गिरजा भीर मन्दिर हैं ? क्या वहां पूजापाठ किए

जाते है ?

भगवान् की वन्दना तथा पूजापाठ के लिए वहाँ गिरजा ग्रीर कलीसा, मिस्जिदें ग्रीर मिन्दर तो हैं परन्तु बोलकेविक क्रान्ति से पहले के मुकाबले में उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। बहुत से नए नगरों में जैसे मैगनी टोगो-रस्क ग्रीर स्टालिनस्क (जिनकी ग्राबादी दो लाख है) ग्रीर करागंडा, (ग्रावादी एक लाख बीस हजार) एक भी धर्म स्थान नहीं है।

शहरों में घामिक विधियों ग्रीर पूजा-पाठ को ग्रव कम्यूनिस्ट सहन कर लेते हैं। परन्तु ग्रामीण जनता को पूजा-पाठ के लिए बहुत-सी बाधाग्रों का सामना करना पड़ता है। जो लोग घामिक गतिविधियों में वढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं, गुप्त पुलिस उनपर नजर रखती है। भक्तजनों को कई प्रकार के भारोप (जैसें मिर्थ) फिक्किस मैलिनि या देश दीही का येव हिंदि का कर पकड़ लिया जाता है।

६. कम्यूनिस्ट सबसे अधिक घृएा किस धर्म से करते हैं ?

कम्यूनिस्ट सरकारें सभी धर्मों के अनुयायियों पर अत्याचार करती हैं। बाल्टिक प्रदेशों में और पूर्वी यूरोप के पिट्ठू देशों में धर्म-द्रोही आन्दोलनों का विशेष निशाना रोमन कैथोलिक, प्रौटेस्टेण्ट और ग्रीक आर्थोडावस चर्च रहे हैं। सध्य एशिया और कम्यूनिस्ट दूर पूर्व में धर्म के कारण अत्याचार सहने वालों में मुसलमान, बौद्ध और ईसाई शामिल हैं।

७. धार्मिक विचार रखने वाले लोगों से कम्यूनिस्ट कैसा व्यवहार करते हैं ?

जिन लोगों के धार्मिक विचार स्पष्ट हैं, उन्हें सरकार शक की निगाह से देखती है। यद्यपि यह भ्रावश्यक नहीं कि धार्मिक विचारों की घोषणा के फल-स्वरूप उन्हें गिरफ्तारी या ग्रत्याचार का सामना करना पड़े। अच्छे वेतन या महत्वपूर्ण पद ऐसे व्यक्तियों को, प्रायः नहीं दिए जाते।

कम्यूनिस्ट चीन में विदेशी धर्म-प्रचारकों पर घोर अत्याचार होते रहे हैं। अब पेकिंग सरकार धार्मिक सम्प्रदायों के स्थानीय सदस्यों के विरुद्ध आन्दोलन चला रही है। उन पर दोष यह बताया जाता है कि वह क्रांति विद्रोही कार्य-विधियों में भाग लेते हैं।

संसार भर में कम्यूनिस्ट पार्टियों के मेम्बरों को यह आदेश दिया गया है कि वे धर्म-विरोधी आन्दोलन में वढ़-चढ़ कर भाग लें। उन यूरोपीय देशों में जहां कम्यूनिस्ट शासन है, धर्म-विरोधी आन्दोलनों का इतना प्रभाव पड़ा है कि धर्म स्थानों का खुले तौर पर उपहास उड़ाया जाता है। धार्मिक विचार रखने वाले वालिग़ों को कभी-कभी अपमानित किया जाता है, उनके वच्चों के साथ अध्यापक और स्कूल के अन्य कम्यूनिस्ट अधिकारी अध्यों का-सा व्यवहार करते हैं।

१६३६ में सोवियत संविधान में पूजा-पाठ इत्यादि की आजादी और धर्म-विरोधी प्रचार के अधिकार स्वीकार किए गए हैं। परन्तु धार्मिक आजादी से सम्बन्धित अभिलेख की जो व्याख्या की गई है उसके अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता 'यूजा-पाठ' तक ही सीमित हो गई है। "उनको आवश्यक पूजा-पाठ की आजादी है, इससे अधिक धार्मिक सरगिंमयों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।" इस प्रकार धार्मिक संस्थाओं द्वारा जन-कल्याण और शिक्षा प्रचार तथा विस्तार के कार्यों का प्रश्न ही नहीं उठता। ज. स्य Digit विस्का । प्रश्याप्रसक्ते । अक्षा मह । आस्ति क्षेत्र के लिख्य का स्वति अपकार नियुक्त हैं ?

१६३६ में संविधान के लागू होने के बाद से रूस में आर्थोडाक्स चर्च के पादिरयों पर कानूनी प्रतिवन्ध नहीं है परन्तु कम्यूनिस्ट पार्टी धर्म के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष करती रहतो है ताकि नई पीढ़ी धर्म के प्रभाव से सुरक्षित रहे। १६४१ के बाद सोवियत यूनियन में सरकार की कलीसा पर कृपादृष्टि रही है। इसके बदले में कलीसा देश के भीतर और बाहर सरकार का समर्थन करता रहता है। परन्तु इस पर भी कम्यूनिस्ट सन्तुष्ट नहीं हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी के १६४४ के निर्देश के अनुसार सब धर्मों के विरुद्ध संघर्ष तेख कर दिया गया है।

आर्थोडाक्स चर्च के वर्तमान लोक समर्थन को भी पार्टी इसलिए सहन कर रही है क्योंकि उसे विश्वास है कि वृद्ध पीढ़ी, जिसमें घर्मनिष्ठा दृढ़ है, शीघ्र ही खत्म हो जाएगी और नई पीढ़ियां पूर्णरूप से भौतिकवादी होंगी।

पूर्वी यूरोप में हजारों पादरी वन्दी बनाए जा चुके हैं। बहुत से पादरी सरकार द्वारा "देशद्रोही कार्यवाहियों" के दोष में मौत के मुंह में पहुँच चुके हैं। १६५६ में पिट्ठू सरकारों ने कुछ राजनीतिक बन्दियों की रिहाई की घोषणा की थी, परन्तु बहुत से धार्मिक नेता अभी तक जेलों या अपने ही घरों में क़ैद थे।

पोलैंड ग्रीर हंगरी के उपद्रव के पश्चात् २८ ग्रक्तूवर को पोलिश पादरी कार्डीनल ग्रस्टीफान वजीफिस्की को कारावास से स्वतन्त्र किया गया। उन्होंने तीन वर्ष तक कारावास में ग्रत्याचार सहन किए। हंगरी में कार्डीनल जोक्फ मिंडजैण्टी को ग्राठ वर्ष की कैंद के पश्चात् घर जाना नसीव हुग्रा। ३ नवम्बर को जब सोवियत सेना ने बुडापेस्ट पर कब्जा किया तो कार्डीनल मैंडजैण्टी ने ग्रमरीकी दूतावास में शरण ली।

 क्या कम्यूनिस्ट सरकारें पादिरयों ग्रौर ग्रन्य कलीसाई ग्रधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करती हैं?

तमाम कम्यूनिस्ट सरकारें कलीसाई संस्थाओं, पादिरयों और उनके संघटनों पर कभी थोड़ा और कभी अधिक नियन्त्रण रखती हैं।

जैसे चेकोस्लोवािकया में मई, १९५० में भ्रादेश दिया गया जिसके भ्रनुसार सब प्रदेशों में धार्मिक जीवन तथा कलीसाई के मामलों की निगरानी लोक समितियों की कलीसा कमेटियों का उत्तरदाियत्व घोषित कर दी गई। ये कमे-टियाँ चेक कम्यूनिस्ट पार्टी का दुमछल्ला हैं। Digitized by Arva Samai Foundation Chennal की करिता हैं। घामिक ये कलीसाई विभाग कलीसाई जायदाद की निगरीनी करिता हैं। घामिक सभाओं और संस्थाओं पर इनका पूर्ण नियन्त्रण होता है। वित्त सम्बन्धी मामले भी इन्हीं के हाथ में होते हैं। पादियों और कलीसा के अन्य कर्मचारियों को वेतन इत्यादि भी यही देते हैं और उनकी उन्नित इत्यादि का निणय करते हैं।

जिन घामिक नेताओं को अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों का एहसास है वह वास्तव में कम्यूनिस्ट सरकारों का समर्थन नहीं करते। परन्तु कम्यूनिस्ट देशों में ऐसी धार्मिक कठपुतिलयां भी मौजूद हैं जो कम्यूनिस्टों की हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं और प्रत्येक रूप से उन्हें अपना सहयोग देती हैं।

जैसे रूस में ग्राथोंडावस चर्च के कुछ मुख्य पादरी ऐसे भी हैं जो सरकारी प्रचार करते हैं ग्रौर सोवियत यूनियन की विदेश नीतियों का पक्ष लेते हैं। पूर्वी यूरोप (विशेषतया हंगरी में) नाममात्र "शान्ति के पादरी" सरगर्म हैं। उनके ग्रपने चर्च ने उनका वहिष्कार कर दिया है। वह वड़ी लगन से "शांति ग्रांदो-लन" में काम करते हैं जो कम्यूनिस्टों का ही एक मोर्चा है। चर्च से निकाले गए कुछ कैथोलिक कम्यूनिस्ट चीन में भी हैं जो कम्यूनिस्ट पार्टी के पिश्ठू वने हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रन्दर ही ग्रन्दर कम्यूनिस्म के समर्थक हैं। सोवि-यत मध्य एशिया में कुछ पाखण्डी मुसलमान पादरी भी इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं।

१०. क्या धर्म के भ्रनुयायी माता-पिता को कम्यूनिज्म के भ्रधीन दण्ड दिया जाता है ?

यदि माता-पिता अपने वच्चों को घरों में धार्मिक शिक्षा दें तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं दी जाती परन्तु कम्यूनिस्ट सरकारें यह कोशिश अवश्य करती हैं कि वच्चे स्वयं ही अपने माता-पिता के प्रभाव पर काबू पा लें। सोवियत युवकों की सरकारी पित्रका "मोलोडोई कम्यूनिस्ट" में अक्तूबर १९५६ में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था "वच्चों का परिवार के धार्मिक प्रभाव से वचाव।" लेखक ने रूसी संविधान के अनुच्छेद १२४ का संकेत (जिसमें "मानिसक स्वतन्त्रता की जमानत" दी गई है) देकर लिखा: "सब नागरिकों को पूर्ण अधिकार है कि चाहें तो किसी धमें के अनुयायी रहें वरना धर्म-विरोधी प्रचार जारी रखें।"

इसके पश्चात् लेखक ने व्याख्या की : 'हमारे देश में मानसिक स्वतंत्रा का अर्थ ईश्वर भक्तों के लिए स्वतंत्रता के इलावा यह भी है कि नास्तिकों को भी वैज्ञानिक संया विका है कि यदि माता-पिता यह कोशिश करते हैं कि उनके वच्चे धर्म-विरोधी प्रचार से सुरक्षित रहें तो उनका यह काशिश करते हैं कि उनके वच्चे धर्म-विरोधी प्रचार से सुरक्षित रहें तो उनका यह काम वास्तव में "मान-सिक स्वतन्त्रता" के नियम का उल्लंघन है। इस सरकारी पत्रिका ने अन्त में लिखा है कि: "परिवार में वच्चों की समाज-विरोधीतथा धार्मिक शिक्षा के लिए माता-पिता को दण्ड मिलना चाहिए। माता-पिता की यह जिम्मेदारी केवल नैतिक ही नहीं विल्क यदि राज्य चाहे तो वैधानिक भी होनी चाहिए।"

इस सरकारी लेख में स्पष्ट शब्दों में जता दिया गया है कि यदि वर्तमान मंद धार्मिक चेतना जारी रही तो धर्म अनुयायी माता-पिता के विरुद्ध वैधानिक

कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा।

११. सोवियत रूस में पादरियों का सामाजिक स्तर क्या है ?

श्राथों डाक्स पादरी अपनी धार्मिक विधियों की पूर्ति के लिए यों भी कम्यू-निस्टों के मुहताज हैं क्योंकि स्थानीय सोवियत समिति यदि चाहे तो गिर्जे को खाली करा सकती है। पूजा-पाठ के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कम से कम बीस भक्त मिलकर एक धार्मिक संस्था बनाएँ और उसे स्था-नीय सोवियत में रिजस्टर्ड कराएँ। इसके पश्चात् ही सोवियत उन्हें गिर्जा के स्थापन की आज्ञा देगी। यह आज्ञा भी समय-समय पर फिर से लेनी पड़ती है। स्थानीय सोवियत ये आज्ञा पत्र फिर देने से इन्कार भी कर सकती है।

रूसी ग्रार्थोडाक्स चर्च के पादिरयों के ग्रितिरक्त दूसरे घर्म (जिनमें मुसल-मान, यहूदी ग्रीर वे ईसाई शामिल हैं जो ग्रार्थोडॉक्स नहीं हैं) के ग्राच्यात्मिक गुरु भी सोवियत यूनियन में धार्मिक संस्कार करते रहते हैं। परन्तु एक तो उनकी संख्या बहुत कम है, दूसरे उन्हें यह भी घ्यान रखना पड़ता है कि सोवि-यत यूनियन की नीतियों की जरा भी ग्रालोचना न होने पाये।

१२. क्या कम्यूनिस्ट धर्म को नशा समभते हैं ?

लेनिन ने कहा था कि मार्क्स का यह कथन कि "धर्म जनता के लिए

अपयून है धर्म के विषय में मानसीं दृष्टिकोण का आधार है।"

२२ सितम्बर, १६५५ को, जब फांस के कुछ महापुरुप मास्को के दौरे पर आए हुए थे, तो सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता निकिता खुड़चेव ने फांस की राष्ट्रीय विधान सभा के प्रधान को बताया: "कम्यूनिस्म ने धमं के प्रति अपना दृष्टिकोण नहीं बदला। हम कोशिश करते हैं कि धमं की अपयून का जादू भरा नशा उतर जाए।"

Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri १३. क्या कम्यूनिस्ट कलोसाओं और श्रन्य धर्म स्थानों की जीयदीद पर स्वयं कब्जा कर लेते हैं ?

रूस में सरकार ने कलीसाई जायदादों का प्रबंध अपने हाथ में ले रखा है। दूसरे कम्यूनिस्ट देशों में कलीसाई जायदाद नाममात्र की चर्च की मिल्कि-यत है परन्तु उसका प्रबंध सरकार द्वारा ही किया जाता है। कलीसाई जागीरें जब्त कर ली गई हैं। हाँ, कहीं-कहीं छोटे-छोटे टुकड़े पादियों की निजी आव-स्यकता के लिए छोड़ दिये गये हैं।

केवल एक सोवियत प्रजातंत्र में ही १६२१-२३ में ७२२ खानकाहें बंद कर दी गई थीं। इनका सारा सामान—धार्मिक पुस्तकें और ग्रन्य सामान सर-

कार ने जब्त कर लिया।

१४. बौद्धों के साथ कम्यूनिस्टों का व्यवहार कैसा रहा है ?

१६४३ में स्टालिन ने एक ग्रादेश द्वारा वालगा के कालमक क्षेत्र की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। इसके वौद्धवासियों की बड़ी संख्या को ग्रज्ञात प्रदेशों में भेज दिया गया।

कम्यूनिस्ट चीन में बौद्ध पुजारियों को विवश किया जाता है कि ग्रनपढ़, मूढ़ ग्रौर नास्तिक कम्यूनिस्ट प्रचारकों के भाषण सुनें। शहरों में रहने वाले बौद्ध पुजारी जीविका के तमाम साधनों से वंचित कर दिए गये हैं। वे हारकर थोड़ी उजरत के शारीरिक काम करने पर विवश हो गये हैं।

तिब्बत. में मठ तोड़ दिए गये हैं। ग्रव उन्होंने मठों ग्रौर भिक्षुग्रों को खत्म करने का ग्रांदोलन चला रखा है। (पहला ग्रध्याय देखिए)।

१४. धर्म के विनाश के लिए कम्यूनिस्ट क्या चालें चलते हैं ?

धमं पर ग्राक्रमण के लिए कम्यूनिस्ट नित नई वातें प्रयोग में लाते हैं। वह धार्मिक स्थानों को जब्त कर लेते हैं ग्रीर उनकी ग्राय के साधन बंद कर देते हैं। इस प्रकार घार्मिक संस्थाग्रों की ग्रायिक स्थित को विगाड़ देते हैं। प्रकाशन के साधनों पर ग्रीर कागज पर उनका पूरा कण्ट्रोल होता है। वह जब चाहें प्रकाशित साहित्य की विक्री रोक सकते हैं।

धार्मिक शिक्षा पर कम्यूनिस्ट दो ग्रोर से हमला करते हैं। एक ग्रोर उन्होंने प्राइवेट धार्मिक स्कूलों को बंद कर दिया है, दूसरी ग्रोर धार्मिक पाठ-शालाग्रों ग्रीर प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रबंध ग्रपने हाथ में ले लिया है। सरकारी

शिक्षा-प्रणाली तो धर्म विरोधी होती ही है।

धार्मिक निस्त्रीं की किय्यू मिस्ट एस स्कार किया कि स्ति के लों में भी ठूंसती हैं परन्तु धार्मिक विचारों के कारण नहीं। प्रायः उन पर जो धारोप लगाये जाते हैं, वे हैं—जासूसी, चोर वाजार का सट्टा, कलीसाई माल में हेर-फेर इत्यादि। ये भूठे धारोप इसलिए भी लगाये जाते हैं कि कलीसाई नेता धपने धनुयाइयों की नजरों में गिर जाएं। इन मुकदमों का एक धिमप्राय यह भी होता है कि स्वतंत्र संसार धोखे में धा जाए धौर यह न जान सके कि कम्यू-निस्टों का ग्रसली ग्रभिप्राय धर्म का विनाश है।

कम्यूनिस्ट युवकों की संस्थाओं और पार्टी के मेम्बरों को उकसाया जाता है कि वर्म के विरुद्ध सदा ही लड़ते रहें। "नास्तिक संस्थाएं" बहुत से कम्यू-निस्ट देशों में धर्म-विरोधी भ्रान्दोलन वड़े जोर-शोर से चलाती रहती हैं।

मई, १९५७ में सी० पी० एस० यू० ने मास्को में नास्तिकों की कांफ्रेंस की । इसमें कोई २५० धर्मविरोधी प्रचारक एकत्रित हुए । कांफ्रेंस के अन्त के परचात् "लड़ाके नास्तिकों की संस्था" जो १९४१ में तोड़ी जा चुकी थी, फिर मैदान में ग्रा गई।

१६५७ ही में स्टेट ने झोडीसा में नास्तिकों का घर वनाया। यह पहली संस्था थी यहाँ नास्तिकता के प्रशिक्षण का प्रवन्ध किया गया। १६५० में "नास्तिकता का विश्वविद्यालय" इश्कावाद तुर्कमानिस्तान में स्थापित किया गया। इसी प्रकार का एक और विद्यालय लेनिनग्राड में भी खोला गया। १६५६-६० में ऐसे और भी स्कूल स्थापित किए गए।

१६. क्या कम्यूनिस्ट ब्लाक से बाहर के देशों में कम्यूनिस्ट धर्म-विरोधी भावनाथ्रों को उत्तेजित करते हैं ?

धर्म को हानि पहुँचाने का कोई अवसर कम्यूनिस्ट नहीं छोड़ते । वे कभी प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण करते हैं, कभी छिप कर वार करते हैं। पिछड़े हुए देशों में उनका आन्दोलन अधिक शक्तिशाली होता है। उन स्थानीय स्कूलों में भी धर्मविरोध की अग्नि प्रचण्ड हो उठती है जहाँ अध्यापक कम्यूनिस्टों के समर्थक या सहचर हों।

भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी ने जब केरल प्रदेश में शासन संभाला तो कम्यूनिस्ट सरकार ने सबसे पहले शिक्षा विभाग की ग्रोर घ्यान दिया। उसने पाठ्यक्रम में ऐसी पुस्तकें शामिल कीं जो कम्यूनिचन की ग्रोर फुकाब पैदा करें। १६५६ के ग्रारम्म में एक शिक्षा विल पेश हुग्रा जिससे पूर्ण शिक्षा

प्रणाली पर किम्बूनिस्टेन का किम्बूनिस्टेन क्षेत्र क्षेत्र क्षिण काला शिवा किस किस प्रभाव से सुरक्षित न रह पाते । कम्यूनिस्टों का विचार ऐसी शिक्षा प्रणाली चालू करने का था जो केवल कम्यूनिस्म का पक्ष पात करती ताकि धार्मिक शिक्षा का धीरे-धीरे एक चिन्ह भी न रहता । इस शिक्षा विल के विरुद्ध ऐसा तूफान उठा कि ३१ जुलाई, १६५६ को केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को पदच्युत कर दिया । केरल सरकार की सर्वाधिकारी प्रवृत्ति इसी से स्पष्ट हो गई थी। वह स्कूलों की ग्राड़ लेकर ग्रपने विरोधियों को वलहीन बना कर उनका विनाश करना चाहती थी।

१७. कम्यूनिक्म से सुरक्षा के लिए धार्मिक नेता क्या कुछ कर सकते हैं ?

जब कम्यूनिस्ट चोरी छिपे या खुले तौर पर जनता को पथभ्रष्ट करें तो धार्मिक नेताओं का कर्त्तंच्य है कि चाहे वे किसी धर्म के भी अनुयायी हों, इकट्ठे हो जाएँ और जनता को कम्यूनिष्म के खतरों से परिचित करें। धर्म सार्वजिनक आवश्यकता है। कम्यूनिस्ट अत्याचार का इतिहास गवाही देता है कि धर्म के प्रति निष्ठा को मानव से पृथक् नहीं किया जा सकता। इसिलए शासन पर कम्यूनिस्टों का कब्ज़ा होने के बाद भी धार्मिक गुरु मानव की आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

धर्म कम्यूनिज्म के विस्तार के विरुद्ध प्रतिरक्षा का महान् और शक्तिशाली साधन है और इसके विस्तार को सफलतापूर्वक रोक सकता,है। इतिहास वताता है कि संगठित नास्तिकता कभी अधिक समय तक जीवित नहीं रही।

नवाँ श्रध्याय कम्यूनिज्म के त्राधीन शिद्या प्रणाली

१. सोवियत यूनियन में शिक्षा का वैधानिक ग्राधार क्या है ?

१६३६ के सोवियत संविधान में सब नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने के समान ग्रिधिकार दिए गए हैं। संविधान में लिखा है:

"रूस के सब नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का ग्रधिकार है। संविधान में इस ग्रधिकार के संरक्षक के लिए ये सुविधाएं दी गई हैं: ग्रनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, सात वर्ष तक मुफ़्त शिक्षा, महाविद्यालयों में योग्य विद्यार्थियों के लिए वजीक़े, प्रादेशिक भाषायें शिक्षा का माध्यम, कारखानों, स्टेट फामों में मजदूरों का व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा कृषि सम्बन्धी शिक्षा का मुफ़्त प्रवंध।

सोवियत रूस की कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपनी उन्तीसवीं कांफ्रैंस में आदेश दिया था कि सप्तवर्षीय पाठ्यक्रम के स्थान पर दस वर्षीय पाठ्यक्रम की नई योजना लागू होने से पहले ही नवम्बर, १९५६ में एक और योजना बन गई जिसमें सुभाव दिया गया था कि समूची शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन किया जाए और अनिवार्य शिक्षा की अवधि आठ वर्ष तक बढ़ा दी जाए।

२. इस में कितनी शिक्षा दी जाती है ?

विद्यार्थियों की बहुसंख्या के लिए सप्तवर्षीय पाठ्यक्रम ही काफी समका जाता है और इसके बाद विशेष व्यवसायिक शिक्षा आरम्म हो जाती है और यही कम्यूनिस्ट शिक्षा प्रणाली की अन्तिम मंजिल है। प्रत्येक विद्यार्थी की सेवाएं केवल राज्य के लिए हों और राज्य जिस तरह चाहे उनका प्रयोग करे।

विशेष व्यवसायिक शिक्षा के साथ-साथ कारखानों और सामूहिक फामों में पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता है या विद्यार्थियों को कारखानों से सम्बंधित स्कूलों में काम करना पड़ता है। इस शिक्षा प्रणाली का एक भाग रिहाईशी स्कूल भी हैं।

(पोलीटंकिनिक्स) बहुकलात्मक विद्यालयों में केवल विशेष शिक्षा ही दी

जाती है। Piquized by Arva Same Foundation Chem विद्यार्थिय कि कि विद्यार्थिय कि विद

ग्राठ वर्ष तक विद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् जिसमें माध्यमिक स्कूल के स्तर पर शिक्षा के साथ-साथ काम का प्रोग्राम भी शामिल है। ग्रधिकतर विद्यार्थी किसी वर्कशाप या सामूहिक फार्म में ग्रधं प्रवीण श्रमिक के तौर पर मुलाजिम हो जाते हैं। कुछ एक विद्यार्थियों को, जिनका पढ़ाई का रिकार्ड शानदार हो, उच्च विद्यालयों में दाखिल कर लिया जाता है। इसमें एक ही शतं है कि इनके ग्रावेदनपत्रों पर स्थानीय परीक्षाबोर्ड ने सिफारिश की हो,। परन्तु परीक्षा बोर्ड सिफारिश करते समय केवल शिक्षा रिकार्ड को ही नहीं देखता विद्यास भी ग्रावश्यक है कि प्रार्थी ग्रपने ग्रापको राजनीतिक तौर पर प्रौढ़ या विश्वास योग्य प्रमाणित कर चुका हो ग्रौर स्थानीय कोमसोमोल (कम्यूनिस्ट नवयुवकों की पार्टी), पार्टी के ग्रधिकारियों ग्रौर कारखाने के प्रवन्धकों ने इस वात की पुण्टि की हो।

रूस के विद्यार्थियों में से ५० से ६० प्रतिशत सातवें वर्ष के वाद विद्या प्राप्त नहीं करते। जिन लोगों को पढ़ाई की ग्रधिक लगन हो वे पत्राकार कोर्सेज ले सकते हैं या नाईट स्कूलों में दाखिल होकर ग्रागे पढ़ सकते हैं।

३. सोवियत स्कूलों में साइन्स कहां तक पढ़ाई जाती है ?

रूस में वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण पर बहुत जोर दिया जाता है। वहाँ की शिक्षा पढ़ित का यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। कुछ विद्यालयों में इसका उत्कृष्ट प्रवन्ध है। मास्को ग्रीर ग्रन्य नगरों में माध्यमिक पाठशालाएं तथा उच्च टैक्निकल विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सामान से पूरी तरह लैस होते हैं। इन स्कूलों का पाठ्यक्रम बहुत कठिन होता है। भारी उद्योगों, परमाणु शक्ति के प्रयोजनों ग्रीर युद्ध उपकरण सम्बन्धी पाठ्यक्रम में विशेषरूप से बहुत परिश्रम करना पड़ता है।

वैज्ञानिक शिक्षा का उच्चतम विद्यालय मास्को का फिजिक्स तथा टैक्नो-लोजी का इन्स्टीट्यूट है। इसमें केवल बहुत ही योग्य विद्यार्थियों को दाखिला मिलता है या फिर इसके द्वार उच्च सरकारी ग्रधिकारियों के वच्चों ग्रीर दूसरे विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के लिए खुले हैं। विज्ञानिक प्रमुख्य कुछ ती लेकिन के निष्म कि कि प्रीय की विद्यात जाता है जिनके अनुसार साइन्स 'भौतिकवाद' को बढ़ावा देती है और कुछ इसलिए कि वैज्ञानिक उन्नति राज्य की आर्थिक उन्नति के काम आए। कम्यूनिक्म में बैकानिक उन्नति को पूंजीवाद के विरुद्ध एक शस्त्र समक्ता जाता है। इसे धमें के विषय को नाश करने वाली औपिध माना जाता है। (आठवां अध्याय देखिए)। ४. आरक्ष अभिकों के स्कूल क्या हैं?

ग्रारक्ष श्रमिक स्कूल इसलिए स्थापित किये गये हैं कि मजदूरों को शिक्षाः वहीं पर दी जा सके जहाँ वे काम कर रहे हैं। इस प्रकार ग्रर्थ प्रवीण श्रमिकः मैंकेनिक ग्रीर टैक्नीशियन ग्रधिक-से-ग्रधिक संख्या में ग्रावश्यकतानुसार तैयार हो जाते हैं।

श्रमिक ग्रारक्ष पद्धति १९४० में स्तालिन के ग्रादेशानुसार ग्रारम्भ की गई थी। चौदह से सत्रह वर्ष तक की ग्रायु के युवक जवरी तौर पर इसके लिए भरती किए गए। स्तालिन के बाद स्थानीय प्रबंधकों से जबरी भरती का ग्रधि-कार तो छीन लिया गया परन्तु स्वेच्छानुसार भरती होती रही।

'प्रावदा' ने अपने २० अगस्त, १९५६ के अंक में लिखा था कि १९५५-६० के दौरान में श्रम आरक्ष स्कूलों में ३५ लाख विद्याधियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें उद्यौगिक, कृषि सम्बन्धी और अन्य क्षेत्रों में काम करने योग्य बनायेंगे। यह सिस्टम इसलिए आरम्भ किया गया है कि एक उत्पादक अर्थ व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर ट्रेड मजदूर आसानी से मिल सकें और इस प्रकार सप्त वर्षीय योजना में किसी समय भी मानव परिश्रम की कमी न रहे। (दसवां अध्याय देखिए) ५. सोवियत छात्रावासीय स्कूल क्या हैं और इनका अभिप्राय क्या है ?

फरवरी १९४६ में सी० पी० एस० यू० की बीसवीं कांग्रेस हुई। उसमें खू इचेव ने सुफाव दिया कि छात्रावासीय पाठशालाएं खोली जाएं। चुनाचे उस साल के पतफड़ में यह सिलसिला ध्रारम्भ हो गया। दिसम्बर १९५९ में इन स्कूलों में छात्रों की संख्या १,५०,००० थी परन्तु वर्तमान योजना के अनुसार इस संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। १९६५ के अन्त तक पच्चासी लाख छात्र इस सिस्टम के ध्राधीन ट्रेनिंग ले चुके होंगे। अनुमान है कि ध्रभी इन स्कूलों में ग्रीर बहुत बच्चे भेजे जाएंगे।

छात्रावासीय स्कूलों में दो-तीन वर्ष की आयु से ही आसंजित नर्सरियों में पढ़ाई शुरू हो जाती है और सत्तरह-ग्रठारह वर्ष की आयु तक जारी रहती है। विश्वां अपि भारत विसा कि लाग कि प्रमुखार मास्को के मुख्याच्यापक ने कहा कि 'भाता-पिता हमारे काम में बड़ी रुकावट पैदा करते हैं।''

छात्रावासीय स्कूला के बच्चे यूनिफार्म पहनते हैं। उन्हें सैनिक शिक्षा भी दी जाती है। पिच्चम के स्कूलों में बच्चों को सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। रूस में इनके स्थान पर मार्क्सवाद ग्रौर लेनिनवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। बच्चों को कट्टर कम्यूनिस्ट पार्टी ग्रौर कोमसोमोल भी ग्रपने तौर पर बच्चों के मस्तिष्क में ग्रपने नियम पक्के करने का यत्न करती हैं।

पहली कक्षा के छोटे-छोटे वच्चे प्रतिदिन साढ़े चार घंटे क्लास में गुजारते हैं। इसके वाद इन्हें तीन घंटे तक शारीरिक काम करना पड़ता है। दसवीं कक्षा तक पहुँचते-पहुँचते उनके लिए काम ग्रीर पढ़ाई का दिन कुल मिलाकर खारह घंटे का हो जाता है। जो लोग पढ़ाई का खर्च दे सकते हैं उन्हें परिवार की ग्राय का द से २५ प्रतिशत तक इस पर खर्च करना पड़ता है।

छात्रावासीय स्कूलों के सिस्टम के कई ग्रिभिप्राय हैं। यह सिस्टम इसलिए लागू किया गया है कि "माताएं वच्चों की देख-रेख से छुटकारा पा जाएं।" तािक कारखानों ग्रीर खेतों के काम के लिए भेजी जा सकें। वच्चा नर्सरी से लेकर उस समय तक स्कूल की निगरानी में रहता है जब तक वह उस व्यवसाय को ग्रहण न कर ले जिसके लिए उसे छात्रावासीय स्कूल ने तैयार किया है। छात्राग्रों को भी ऐसे ही डिस्पलिन का पाबंद वनाया जाता है। सोवियत छात्रों को हर घड़ी सैंद्धान्तिक शिक्षा देने का ग्रानिवार्य परिणाम यह निकलता है कि फिर उनके लिए स्वतन्त्र संसार से ग्राने वाले "ग्रपरिचित" विचार ग्रहण करने की क्षमता नहीं रहती।

६. सोवियत जिक्षा पद्धति का पुनर्गठन क्यों किया जा रहा है ?

सोवियत शिक्षा पद्धति के संशोधन के दो मुख्य कारण हैं। एक ग्राधिक है, दूसरा राजनीतिक। ग्राधिक कारण तो यह है कि सप्त वर्णीय योजना की पूर्ति के लिए ग्रावश्यक मानव श्रम मिलता रहे। (दसवां ग्रध्याय देखें)

राजनीतिक कारण १९५६ में पैदा हुग्रा। विदेशी यात्रियों को उन दिनों सोवियत नवयुवकों में मानसिक द्वन्द का ग्रामास हुग्रा था। इस द्वन्द को इस बात से ग्रीर भी उत्तेजना मिली कि सबसे वड़ा बुत गिर चुका था। भूतपूर्व डिक्टेटर स्तालिन का दर्जा कम करने का ग्रान्दोलन चल रहा था। फरवरी १६५६ किंभे भिर्मितीं सी४ किंग्ने सं १० व्यूकी भाग्ने से भाग्ने से स्विक्षिति करें ।

सोवियत मामलात के विशेषज्ञ एडवर्ड फ्रेन्कशा ने १६ फरवरी १६५७ के "हांगकांग स्टैन्डर्ड" में लिखा था: "ग्राज के नवयुवकों में वह मनुष्य द्वेषी भावना ग्रीर जड़ता नहीं रही जिसे मिथ्यावाद ग्रर्थात् स्तालिन प्रजा ने जन्म दिया था ग्रीर जिसके वारे में सब जानते हैं कि यह एक ग़लत राह है। ग्रब इसकी जगह निर्माणात्मक ग्राशावाद ने ले ली है। लोग सोचते हैं कि यदि स्तालिन जैसे व्यक्ति को मान-प्रतिष्ठा के मीनार से नीचे उतारा जा सकता है। तो फिर ग्रीर भी बहुत कुछ हो सकता है। ये युवक चुप-चाप किसी बात को नहीं मानते। हर बात पर तर्क करते हैं। वर्तमान नेताग्रों का प्रत्येक काम स्तालिन के बारे में खुइचेब के बक्तव्य की रोशनी में ही परखा जाता है।"

नई पीढ़ी की वेचैनी और उद्ण्डता से सी॰ पी॰ एस॰ यू॰ को बड़ी परे-शानी है। इसे डर है कि कहीं "वाहरी वूर्जुआई" प्रभाव पार्टी और स्टेट के सैद्धान्तिक ढांचे को तोड़-फोड़ न दे। इन मानसिक परेशानियों के अलावा नव-युवक के अपराघों की समस्या (छटां अध्याय देखिए) भी अधिक गम्भीर हो गई है। इसलिए काम और पढ़ाई के एकत्रित प्रोग्राम में "पार्टी डिसिप्लिन" और "सोशलिस्ट उत्पादन" पर जोर दिया गया है। तमाम विद्यार्थी श्रमिक स्यानीय पार्टी के अधिकारियों की निगरानी में रहते हैं। पार्टी को आशा है कि शिक्षा की यह पद्धति राजनीतिक वेचैनी को खत्म कर देगी।

जो विद्यार्थी बहुत लायक होते हैं, उनकी सिफारिश भी स्थानीय परीक्षा बोर्ड यों ही नहीं कर देता। पहले यह देखता है कि वह पार्टी का वफादार है या नहीं, राजनीतिक तौर पर उसके विश्वासपात्र होने के कोई प्रमाण मौजूद हैं या नहीं। इस सिफारिश के बिना न वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, न ही ग्रपनी मर्जी ग्रनुसार व्यवसाय चुन सकते हैं।

७. कम्यूनिच्म में भ्रायिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा को कैसे साथन बनाया जाता है ?

कम्यूनिज्म के अन्तर्गत शिक्षा का असली अभिप्राय स्टेट की सेवा है। इस-लिए नियमानुसार शिक्षा पद्धति निश्चित करते समय स्टेट के आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है। परन्तु यह काम इतना सहल नहीं। एक-दलीय शासनतंत्र तथा आयोजित समाज में भी जब विद्या को आर्थिक आवश्य- कताओं का भुंसिंदि विभिधा जीता है तो उसमें श्रीवश्य हो तो विद्यासिक होती हैं। रूस में विद्यार्थियों ग्रीर श्रीमकों के परस्पर सम्बन्धों में ग्रन्तर स्कूल सिस्टम में दूररस तबदीलियों का सबसे बड़ा ग्रार्थिक कारण है।

जन-शक्ति में इस कमी का एक कारण यह भी है कि दूसरे महायुद्ध में सोवियत यूनियन में जननगति बहुत कम रह गई है, जिससे युद्ध के बाद के कुछ वर्षों में स्कूलों में प्रवेश पाने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई है। उदा-हरण के लिए पहली चार कक्षाओं में पाठकों की संख्या जो १६४६-४६ में २,३७,३०,००० तक पहुँच गई थी। १६५३-५४ में घटकर केवल १,२३,००,००० रह गई।

१६५६-५७ में विद्यायियों की संख्या फिर वढ़ी ग्रीर १,५३, ५०,००० हो गई। जिन वच्चों ने १६४६ में ग्रपनी शिक्षा ग्रारम्भ की थी, वह १६५६ में कोई सोलह वर्ष की ग्रायु में नौकरी के लिए तैयार हो चुके थे। लेवर मार्किट के लिए जो सोलह वर्ष के नवयुवक मिले हैं, उनकी गिनती १६६२ में लगभग सबसे कम रहने की ग्राशा थी। ग्रर्थात् १६६५ में पूरे होने वाली सप्त वर्धीय योजना की ग्रवधि से कोई तीन वर्ष पहले (दसवां ग्रध्याय देखिए) खू इचेव तो इस वात का खण्डन करते रहे कि यह नया प्रोग्राम जन-शक्ति की कमी के कारण वताया गया है परन्तु हक़ीक़त यही है कि काम ग्रीर पढ़ाई की प्रयोजना, जो माध्यमिक स्तर से ग्रारम्भ होती है, केवल इसलिए वनाई गई है कि वांछित जवान श्रमिक मिलते रहे।

द. क्या सोवियत शिक्षा पद्धति में सामाजिक स्तर का कोई महत्व है ?

कुछ समय से सोवियत पत्र-पत्रिकाधों में शिकायतें द्या रही हैं कि विशेषा-धिकार प्राप्त वर्ग के वच्चे शारीरिक काम से जी चुराते हैं। वह अन्य घटिया कामों से भी वचते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक ग्रोर तो उच्च महाविद्यालयों में शिक्षित ग्रेज्युएटों की वड़ी संख्या मिलती है, दूसरी ग्रोर उद्योगों में ट्रेण्ड श्रमिक ग्रावश्यकता से कहीं कम भेजे जा सके हैं।

१६५७ में उच्च विद्यालयों के और ऊंचे टैक्निकल स्कूलों के ७,७४,००० ग्रेज्युएट थे, इसके मुकाबले में नव प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या ६,८६,००० थी। इस प्रकार शारीरिक काम न करने वालों की श्रधिक संख्या से एक प्रकार की वेकारी फैल गई है। जबिक उद्योगों में प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी है। "प्रावदा" ने २५ दिसम्बर, १६५७ के श्रंक में इस वात को स्वीकार किया था कि श्रव जरूरी हो गया है कि "माध्यमिक स्कूलों के ग्रेज्युएटों में से बहुत कम

को उच्च^{ात्राधार} टेक्सिक्स स्कूलि में दाखिल किया सर्पा व कुनिश्वि जिन लोगों को ग्रव प्रवेश मिलता है, वे उच्च विशेष वर्ग के होते हैं।

६. क्या रूस में शिक्षा मुफ्त है ?

रिहाईशी स्कूलों के अतिरिक्त पढ़ाई की फीस रूस में नहीं ली जाती।
मन्त्रि मण्डल के एक आदेश के अनुसार माध्यमिक स्कूलों, टैक्निकल विद्यालयों
और उच्च शिक्षा केन्द्रों में फीस बंद कर दी गई थी। परन्तु उच्च शिक्षा के केन्द्रों में पढ़ाई की फीस के अतिरिक्त भी काफी खर्च हो जाता है।

इस खर्च को पूरा करने में सहायता देने के लिए स्टेट वजीफे देती है। यह वजीफा २२० रूवल से ४५० रूवल मासिक तक होता है। मास्को स्पेशल इन-स्टीट्यूट फार फिजिक्स एण्ड टैक्नालोजी और स्कूल ग्राफ डिप्लोमेसी के छात्रों को ५०० रूवल प्रति मास मिलते हैं जविक मास्को विश्वविद्यालय के विद्या-थियों को २६० रूवल मासिक मिलते हैं।

स्पेशल इन्स्टीट्यूट और स्कूल आफ डिफ्लोमेसी में उच्च सोवियत अधि-कारियों के वच्चे ही प्रवेश पाते हैं। विद्यार्थियों का खर्च वजीफों से कम ही पूरा होता है इसलिए केवल खाते-पीते घरानों के बच्चे ही वहाँ पर प्रवेश पा सकते हैं। क्योंकि साधारण मजदूर के परिवार को तो जीवन व्यतीत करने के लिए तमाम कमाने वाले पुरुषों की आमदनी की जरूरत पड़ती है।

. १०. क्या ग्रध्यापकों से यह ग्राशा भी की जाती है कि वह सार्वजनिक कार्य-विधियों में भाग लिया करें ?

जनता और राज्य के लिए अध्यापक नाना प्रकार की सेवाएँ करने पर मज़बूर हैं। उनसे आशा की जाती है कि पाओनीयर संगठन (जो नौ वर्ष से चौदह वर्ष तक के वच्चों के लिए कम्यूनिस्ट संस्था में भाग लें और कौमसो-मोल (नवयुवक कम्यूनिस्ट लीग) की कार्यविधियों में शामिल हों जो चौदह से छब्बीस वर्ष तक के नवयुवकों की संस्था है।

ग्रामीण प्रदेशों में उनका कर्त्तव्य है कि सामूहिक खेतों के मेम्बरों को सरकार के ग्रादेश तथा नियम समकाएं, कम्यूनिस्ट पार्टी के बताए हुए विषयों पर भाषण दें ग्रीर उन तमाम ग्रांदोलनों में वढ़-चढ़ कर भाग लें जिनसे जनता पर कम्यूनिस्ट पार्टी की पकड़ दृढ़ हो। ग्रच्यापकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्त्तव्य यह है कि ग्रपने विद्यार्थियों को नया "सोवियत मानव" बनने के लिए तैयार करें। बचपन ही से उन्हें सिखायें कि कम्यूनिस्ट पार्टी ग्रीर स्टेट की सेवा ग्राव-

रयक है। पिटिंग्कि मेध्वीर निरम्तर निरम्तर निर्मारिनंश करित रहते हैं। जनक रूप से ग्रपना कार्य पूरा कर रहे हैं।

११. सोवियत रूस के ग्रध्यापक कम्यूनिस्ट उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं ?

स्तालिन ने १६३४ में एक लेखक को वताया था, "शिक्षा एक हथियार है। इसके प्रभाव की मात्रा इस हथियार को रखने वाले पर ग्रीर इससे घायल होने वाले पर ग्रीर इससे घायल होने वाले पर ग्रीधारित है।" ग्रध्यापकों से कहा जाता है कि क्लासक्म को कम्यूनिस्ट प्रोपेगण्डा का ग्रस्त्रागार बना दें। सरकारी शिक्षा सम्बन्धी पत्रिका "पैडागोगी" के कथनानुसार ग्रध्यापकों का कर्त्तंच्य है कि जनता के शत्रुओं के विरुद्ध बच्चों में घृणा उत्पन्न करें" ग्रथीत् उन सब लोगों से घृणा सिखाएँ जो देश में या देश से वाहर कम्यूनिस्म के विरोधी हैं। उन्हें मार्विसस्म लेनिनिस्म का प्रचारक ग्रीर कम्यूनिस्ट पार्टी की नीतियों का समर्थंक होना चाहिए।

१२. क्या सोवियत रूस में पढ़ाए जाने वाले सब विषयों में मार्क्सवाद, लेनिन-वाद शामिल कर दिया जाता है ?

कम्यूनिस्ट राजनीतक तथा सैद्धान्तिक विचारधारा कम से कम दसवीं कक्षा तक लगभग प्रत्येक विषय में धामिल है। उदाहरण के लिए पित्रका "पैडा-गोगी" लिखता है: "प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के प्रशिक्षण से विद्यार्थियों में तार्किक भौतिकवादी दृष्टिकोण सुदृढ़ होगा। केवल यही दृष्टिकोण वैज्ञानिक है और धामिक रूढ़ियों मूढ़-विश्वासों तथा भ्रमों का सफलतापूर्वक विरोध कर सकता है। भूगोल के ज्ञान से विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भौतिकवादी विश्व की रूपरेखा वनेगी। सोवियत इतिहासकार इतिहास को विशेषरूप से तोड़ते-मरोड़ते हैं और इसमें अपने लाभानुसार अदल-वदल करने में चतुर हैं। जैसे रूसी विद्यार्थी के निकट दूसरा महायुद्ध १६४१ में आरम्भ हुआ था, जब सोवियत यूनियन पर नाजी हमला हुआ था। १६३७ में नहीं जबिक पोलैंड पर आकम्मण हुआ था। पार्टी के लाभ के लिए कम्यूनिस्ट इतिहासकार अपने देश के इतिहास को आवश्यकता अनुसार बदलते रहते हैं। इस हस्तक्षेप से न रूस का इतिहास ही वच पाया है और न ही पिट्ठू देशों का। पिट्ठू देशों के इतिहास को या तो सोवियत इतिहासकारों ने नए सिरे से स्वयं लिखा है या उसी देश के इतिहासकारों ने सोवियत वित्रासकारों ने इसकी कांट-छांट की है।

जय से एसंशिक्षिक भे परसे निकिश करण वास्य सिन्यू का की किए जिन्दा तथा खण्डन किया गया है, सोवियत सामूहिक नेतृत्व के सामने एक जिटल समस्या ग्रा खड़ी हुई है। ग्रव इन हजारों पुस्तकों का पुनः निरीक्षण हो रहा है जिनमें इस डिक्टेटर की महानता तथा प्रतिष्ठा पर जोर दिया गया था। इस विराट ग्रान्दोलन का प्रभाव पाठ्यक्रम की पुस्तकों तथा संदर्भ ग्रंथों पर भी पड़ेगा जो सोवियत निर्देश के ग्रनुसार पिट्ठू देशों में प्रकाशित हुई हैं।

१३. सोवियत शिक्षा में सोवियत यूनियन श्रौर श्रन्य देशों का कैसा चित्रए किया गया है ?

सोवियत विद्यार्थी को वताया जाता है कि सोवियत सिस्टम सब सिस्टमों से अच्छा है, सोवियत यूनियन सबसे सम्पन्न तथा उन्नत देश है और इसके नेता बुद्धिमत्ता में अपना सानी नहीं रखते। दूसरे देशों में "पूंजीवाद" के अधीन रहने वाले लोग सामान्यतः मजलूम और गिरे हुए हैं और वह अपने पूंजीपित स्वार्थ-साधकों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार बैठे हैं और केवल संकेत की प्रतीक्षा में हैं।

कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा मन्त्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकों के विषय-वस्तु के सम्बन्ध में विद्यार्थी या उनके अध्यापक कोई प्रश्न नहीं उठा सकते।

१४. क्या सोवियत यूनियन में शिक्षा पद्धति केन्द्रित है ?

सोवियत शिक्षा पद्धित की व्यवस्था किसी केन्द्रीय एजेन्सी के हाथ में नहीं है परन्तु व्यवहारिक रूप में शिक्षा प्रणाली जैसे पाठ्यक्रम की पुस्तकें आदि सारे सोवियत संघ में एक समान हैं। सोवियत संघ के मन्त्रिमण्डल द्वारा किए गए निर्णयों के आधार पर यूनियन लोकराज्यों के शिक्षा मन्त्रालय अपनी शिक्षा पद्धित के विषय पर शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत आदेश देते हैं। तथापि सोवियत संघ के उच्च शिक्षा तथा संस्कृति के मंत्रालय और श्रमिक आरक्ष का मुख्य शासकीय विभाग केन्द्रीय निगरानी में प्रशिक्षण कार्य चला रहे हैं।

१५. युवक संस्थाएं सोवियत शिक्षा के संबंध में क्या करती हैं ?

युवक संस्थायों का स्कूलों के प्रशासन से गहरा सम्बन्ध रहता है। दोनों को मंजिल एक ही है। कम्यूनिस्ट विचारधारा को बच्चों के मस्तिष्क में जड़ित कर्ता प्रिक्ट्सिश्यिक पैदण करना, जिसे कम्यूनिश्टासमंभिक्ताओं राज्य में सबसे उत्तमभौणे मोना जाता है।

क्रियुवकी के लिए कौमसोमोल संगठन छोटी श्रायु के पाश्रोनीयरों के काम को श्राम बढ़ाने के लिए है परन्तु इसकी सदस्यता सीमित है और इसमें सैनिक प्रक्रिक्की तथा धर्मविरोधी प्रोपेगण्डे पर श्रधिक जोर दिया जाता है।

१६. क्या रूस में शिक्षा रूसी भाषा के म्रतिरिक्त किसी ग्रौर भाषा में भी दी जाती है ?

सोवियत संविधान की हिदायत है कि शिक्षा प्रादेशिक भाषा में दी जाए। ग्रार० एफ० एस० ग्रार० की भाषा रूसी है। ग्रन्य चौदह यूनियन प्रजातंत्रों में शिक्षा प्रादेशिक भाषाग्रों में दी जाती है। परन्तु सब सोवियत स्कूलों में रूसी भाषा का ज्ञान ग्रावश्यक है। प्रादेशिक भाषाग्रों का दर्जा कम करके रूसी भाषा को ग्राविक महत्व दिया गया है। प्रादेशिक केन्द्रों से शिकायतें ग्राती रहती हैं कि शिक्षा में "रूसी" (महान रूसी) भुकाव मुखरित रूप में पाया जाता है।

सोवियत शिक्षा के रूसी बनाए जाने का उदाहरण एक लेख से मिलता है जो २८ दिसम्बर, १९५२ के "क़ाजकस्तानस्काया प्रावदा" में छपा था। लेख में शिकायत की गई है: काजकस्तान के ऐतिहासिक विज्ञान में जबसे बूर्जुया थ्रौर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की कलई खुली है काजक इतिहास, साहित्य ग्रथवा प्रथं-व्यवस्था पर एक भी पुस्तक नहीं लिखी गई है। ग्राज भी इन विषयों पर पाठ्य पुस्तकों हमारे पास नहीं हैं।"

पिट्ठू देशों में भी राष्ट्रीय शिक्षा को इस प्रकार रूसी बनाया गया है। ग्राभिप्राय यह है कि अन्य जातियों अथवा प्रदेशों की कार्यविधियों पर महान रूस के कारनामों का बड़प्पन दिखाया जाए।

१७. कम्यूनिस्ट शिक्षा का ग्रमित्राय क्या है ?

सोवियत और वाकी कम्यूनिस्ट शिक्षा का प्रथम ग्रिभिप्राय तो यही है कि नवयुवकों को कम्यूनिस्ट (साइण्टेफिक शोसिलस्ट) समाज में उचित स्थान के लिए तैयार किया जाये। इसके लिए पहले तो उन्हें मार्किसज्म-लेनिनिज्म की शिक्षा दी जाती है। इसके पश्चात् उनका प्रशिक्षण इस ढंग से होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के प्रशासन में पहले से निश्चित स्थान ग्रथवा मुलाजि-मत के योग्य बनाया जाए।

इस शिक्षा प्रणाली में जो लोग कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रयोजनों की पूर्ति में

सवसे ऋग्रोग्राह्रेक्ते हैं, Arga ऋक्षेत्रक्षोग्राह्मस्ट्रेश्चें महें नहें हिला हिला हैं उन्हें इनाम दिये जाते हैं ।

कम्यूनिस्ट शिक्षा का एक अभिप्राय यह भी है कि कच्चे मस्तिष्क में यह कम्यूनिस्ट मिथ्या भर दी जाये कि सारे संसार में कम्यूनिष्म की विजय अनि-वार्य है। १९५६ में जब सोवियत ब्लाक के देशों में कम्यूनिष्म के विरुद्ध विद्यार्थियों के आंदोलन भयंकर हो गये तो इस प्रोपेगण्डे को वहुत धक्का लगा।

दसवां श्रध्याय कम्यूनिज़म के यन्तर्गत खाद्य वस्तुयों तथा माल का उत्पादन

१. कम्यूनिस्ट सरकार अपनी जनता को खाद्य पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं किस प्रकार जुटाती हैं ?

रूस और पूर्वी यूरोप में खाद्य वस्तुओं तथा अन्य माल का उत्पादन सर-कारी योजना के अनुसार होता है। इस योजना के अनुसार प्रत्येक उद्योग और कारखाने को हिदायत की जाती है कि माल की निश्चित मात्रा तैयार की जाये। अब तक ऐसे माल के उत्पादन पर जोर दिया गया है जिससे सोवियत यूनियन के भारी उद्योगों की उन्नित हो। वार्षिक उत्पादन का बहुत कम भाग रोजाना इस्तेमाल की चीजों जैसे कपड़े, घरेलू सामान इत्यादि के रूप में तैयार किया जाता है। आम इस्तेमाल की वस्तुएं कभी इतनी मात्रा में उत्पन्न नहीं होतीं कि मांग को पूरा कर सकें। यह ऐसी दूकानों में विकती हैं जिनकी व्यवस्था स्वयं सरकार के हाथ में होती है या जिन्हें ऐसे कोआपरेटिव चलाते हैं जो सर-कार के नियन्त्रण में होते हैं।

सरकारी योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्य निश्चित कर दिये जाते हैं। सामूहिक तथा स्टेटफामं इसी के अनुसार माल पैदा करते और पैदावार इकट्ठी करने वाली सरकारी संस्थाओं को दे देते हैं। नियम तो यह है कि फामं स्टेट की पैदावार का भाग देने के पश्चात् शेप माल चाहे अपने पास रख सकते हैं या खुले बाजार में वेच सकते हैं। परन्तु वास्तव में सरकार का हिस्सा दे देने के बाद आम किसान के पास इतना बचता ही नहीं कि इसके गुजारे से अधिक हो।

स्टेट जो कृषि-उत्पादन जमा कराती है, वह सरकारी दुकानों पर निश्चित क्रीमतों पर वेचा जाता है। उत्पादन योजनाभ्रों तथा विक्री तथा वितरण का ऐसा ही ढंग ग्रन्य कम्यूनिस्ट सरकारों ने भी ग्रहण कर रखा है।

२. प्रथम पंचनुर्वस्वित्योजनापृक्तेस्रोतसार्विः अर्धिः And Chennai and eGangotri

पहली पंचवर्षीय योजना स्तालिन ने शुरू कराई थी। १६२८ में जब स्तालिन ने निर्णय किया कि सोवियत यूनियन को श्रीद्योगिक देश बनाना है श्रीर इसे एक शक्तिशाली सैनिक राज्य का रूप देना है तो इस योजना की श्राधारिशला रखी गई। सोवियत सिस्टम ने यह नई करवट ली तो वहां का सर्वाधिकार केन्द्रित राज्य भी बदला और उसने दृढ़ता और ऋरता से राजनी-तिक विरोधियों को खत्म कर डाला और हर प्रकार की समाजी संस्थाओं को श्रपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए पूरी तरह नियंत्रित कर दिया।

स्तालिन के प्रोग्राम में यह भी शामिल था कि तमाम सामूहिक रूप से काम करें। मशीनों का ग्रथिक से ग्रथिक प्रयोग हो। परिणाम स्वरूप "कल्क" (खाते-पीते किसान) जो ग्रपनी जमीनों के सामूहीकरण के विरुद्ध थे, ग्रपना ग्रस्तित्व ही खो वैठे। कोई दस लाख 'कल्क' घराने ग्रपनी भूमि से वंचित कर दिये गये। इनमें से बहुत से स्तालिन के ग्रादेशानुसार वेगार के कैम्पों में नेज दिये गये।

३. सरकारी योजना को कैसे कार्यान्वित किया जाता है ?

राजकीय योजना संस्थापन (जिसे सोवियत यूनियन में गोस्पलान कहा जाता है) एक सम्पूर्ण तथा विस्तार पूर्ण प्रोग्राम बनाता है। इसके अन्तर्गत हर प्रकार की उपज तथा उत्पादन के लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं। उपज, उपभोज्य सामग्री ग्रीर भारी उद्योग (जिनमें युनियादी उद्योग भी सामिल हैं) जैसे कोयला, लोहा, इस्पात, तेल ग्रीर सैनिक सामान तथा अस्त्र, सस्त्र इत्यादि सब इसी में ग्रा जाते हैं)।

राजकीय योजना को, समय तथा-प्रदेशानुसार बाँट दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष के लिए पैदावार के निशाने निश्चित कर दिए जाते हैं। यूनियन प्रजातंत्रों में ग्रन्तग-मलग प्रदेशों तथा जिलों के लिए भी पैदावार के लक्ष्य नियत किए जाते हैं। इसके पदचात् स्थानीय रूप में नगरों, शहरों और गांवों, कार-खानों तथा सामूहिक फार्मों को उनके कोटे से सूचित कर दिया जाता है। तैयार माल या कृषि की उपज का निश्चित भाग उन्हें पूर्व सूचित तिथि तक सरकारी गोदामों में जमा कराना पड़ता है।

४. क्या सरकारी योजना के लक्ष्य पूरे हो जाते हैं ?

पूर्णरूप से यह लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते । कुछ क्षेत्रों में उपज निश्चित

. निशाने से विद्धारितिश है। भि श्विष्टि श्री ए खंबिभो ज्या बहतु स्रों। के खंबिश है। भारी उद्योग कम्यूनिस्ट सरकारों के लिए छोटे और हलके उद्योगों की उन्नित और फौजी सामान के उत्पादन का साधन हैं। कम्यूनिस्ट शासकों की दृष्टि में इनका महत्व दैनिक प्रयोग की वस्तुओं से कहीं अधिक है।

५. रूस में कितनी राजकीय योजनाएँ बन चुकी हैं ?

पहली पंचवर्षीय योजना १६२८ में शुरू की गई थी। छटी पंचवर्षीय योजना की घोषणा १६५६ में बीसवीं सी० पी० एस० यू० कांग्रेस में हुई परन्तु सितम्बर १६५७ में महसूस किया गया कि उद्यौगिक उन्नति निश्चित निशानों के अनुसार नहीं हुई। इसलिए छटी योजना को बीच में ही छोड़ दिया गया। इसके स्थान पर इवकीसवीं पार्टी कांग्रेस (२७ जनवरी से ५ फरवरी तक) में ख़ू उचेव ने उच्चाकांक्षी सप्त वर्षीय योजना की घोषणा की।

सप्त वर्षीय योजना में भौद्योगिक पैदावार में १६६५ तक ५० प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यह भी कहा गया है कि कृषि की उपज भी इतनी ही बढ़ाई जाएगी। ख़ुश्चेव ने दावा किया है कि यह योजना पूरी हो जाने के पश्चात् रूस में भी प्रतिव्यक्ति पैदावार भ्रमरीका के बरावर हो जाएगी।

श्राधिक समीक्षकों का श्रनुमान है कि रूस सामूहिक राष्ट्रीय पैदावार श्रम-रीका की कुल पैदावार का चालीस प्रतिशत है। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं है कि १६६५ तक या निकट भविष्य में दोनों देशों की पैदावार वरावर हो सकेगी।

पैदावार में वृद्धि के नए ग्रान्दोलन को सोवियत श्रमिकों के लिए रुचिकर बनाने के लिए ख़ू इचेव ने सम्पन्न भविष्य का ग्राश्वासन दिया है। २४ जनवरी १६६० को एक इन्टरव्यू में उन्होंने वताया था: "मेरा विचार है कि १६७४-८० के लगभग में हमें इतने भौतिक साधन पर्याप्त हो जाएंगे कि हमारी जनता का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। शर्त केवल यह है कि बीच में कोई जंग न हो।"

१६५३ की गर्मियों में भूतपूर्व प्रधानमंत्री मालिनकीव ने भी इसी प्रकार "सम्पन्न भविष्य" की शुभ सूचना सुनाई थी। पार्टी सेक्रेटरी खू उचेव ने उसे बहुत उछाला भी था। मालिनकीव बाद में "पार्टी दुश्मन ग्रुप" के समर्थक सिद्ध कर दिए गए और १६४७ में खू उचेव ने उन्हें ग्रधिकार से वंचित कर दिया। फिर भी वर्तमाम थोजमा क्रिका क

६. कारखानों के डायरेक्टर निर्धारित पैदावारी कोटे किस प्रकार पूरे करते हैं ?

कोटे पूरे करने में कारखानों के डायरेक्टरों को प्राय: बहुत कठिनाइयां पेश भ्राती हैं। कभी उनके कारखाने के लिए जितनी पैदावार का लक्ष्य रखा जाता है वह मशीनों की उत्पादन योग्यता से अधिक होता है, कभी उनके पास योजना के श्रनुसार काम चलाने के लिए मजदूर नहीं होते, कभी कच्चे माल की कमी रहती है।

इन किनाइयों पर काबू पाने के लिए कारखानों के डायरेक्टर बहुत-सी "युक्तियों" से काम लेते हैं जिनमें बहुत-सी विधि विरुद्ध होती हैं। जैसे कि वह अपना वही-खाता इस प्रकार से रखते हैं कि यह प्रतीत हो कि कोटा पूरा हो गया है, या पैदावार कोटे से भी अधिक बढ़ गई है। इस उद्देश्य के लिए वह घटिया माल को भी विद्या माल बता कर पैदावार में वृद्धि दिखा देते हैं। कभी वह तैयार हुए माल का मूल्य रूबल की वर्तमान कीमत के हिसाब से लगाते हैं, या कोई और घोखा देने वाला तरीका अपनाते हैं। कभी कच्चे माल पर होने वाले व्यय को कम करके दर्ज करते हैं ताकि कम-से-कम कागज़ पर लाभ अधिक नजर आए।

७. कम्यूनिस्ट योजनाग्रों का कारखानों के मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

प्रत्येक मजदूर पर, हर "व्रीगेड" पर निरन्तर दवाव डाला जाता है कि वह पैदावार बढ़ाता रहे। कम्यूनिज्म के श्रधीन मजदूर प्रायः काम के हिसाव से वेतन पाते हैं। इसलिए वह "सोशलिस्ट मुकाबले" में भाग लेने पर मजबूर हैं।

"मुकावले" का यह तरीका वास्तव में व्यक्तिगत रूप में प्रतिदिन जितना माल तैयार करने की आशा की जाती है, इस ढंग से इसमें और भी वृद्धि हो जाती है। इस श्रीसत को जो मजदूर पूरा नहीं कर सकता, वह साप्ताहिक उज-रत भी कम पाता है।

पैदावार बढ़ाने का एक दूसरा तरीका तेज काम करने वाले मजदूर जिन्हें "प्रगतिशील" या "प्रवर्तक" मजदूर भी कहा जाता है। उनका काम यह है कि कारखानों ग्रीर पैदावारी संस्थानों में काम का स्तर कायम करें। ये ट्रेण्ड मजदूर होते हैं। माल तेजी से तैयार करने की उन्हें ट्रेनिंग मिल चुकी होती

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and कि कि भूपिने हुनर की है। ये सोवियत समाज के उच्च वर्ग में गिन जाते हैं। उन्हें भूपिने हुनर की नुमाइश करने के लिए एक कारखाने से दूसरे कारखाने भेजा जाता है। उद्देश यह होता है कि वे दूसरे मजदूरों के लिए पथ-प्रदर्शन कर सकें। उनके काम को यह होता है कि वे दूसरे मजदूरों के लिए पथ-प्रदर्शन कर सकें। उनके काम को खौसत काम वता कर साधारण मजदूर से भी इतने ही काम की ग्राशा की जाए। स्पष्ट है कि इन विशेष "प्रगतिशील" मजदूरों के काम के स्तर पर साधारण मजदूर नहीं पहुँच सकते।

चीनी सोवियत ब्लाक के ग्रत्यधिक ग्रीद्योगिक संस्थानों में काम करने के हालात बहुत भयानक तथा खराव हैं। (तीसरा ग्रध्याय देखिए)।

द. क्या यह सच है कि कम्यूनिस्ट देशों में मजदूर ही कारखानों के मालिक होते हैं ?

कम्यूनिस्ट प्रचार करने वालों का दावा है कि उनके देशों में सब कारखाने मजदूरों की मिल्कियत होते हैं। परन्तु यह वात सत्य नहीं है। वहां के सब ग्रीद्योगिक संस्थानों ग्रीर ग्रन्य कारोबारी संस्थाग्रों की मालिक कम्यूनिस्ट स्टेट होती है। वहीं उन्हें चलाती है, वहीं इनकी व्यवस्था को देखती है। मजदूर तो वस व्यूरोक्रैटिक सरकार की विराट् मशीन के पैदावारी पुर्जे होते हैं। निर्णा-यक ग्रिधकार तो कम्यूनिस्ट पार्टी के हाथ में रहता है।

इन हालात में मजदूरों की ट्रेड यूनियनें भी वेकार होती हैं। कम्यूनिस्टों की चलाई हुई यूनियनें तो सरकार की सहकारी होती हैं। उनका सबसे बड़ा कत्तंव्य ही यही है कि उच्च ग्रधिकारियों के ग्रादेशों को मजदूरों तक पहुँचा दें ग्रीर मजदूरों में डिस्पिलिन कायम रखें, ग्रर्थात् उन्हें तेज़ी से काम करने पर उकसाती रहे।

 राजकीय योजना के ग्रधीन सामूहिक फार्मों के मेम्बरों के साथ कैसा व्यवहार होता है ?

सामूहिक फार्मों के मेम्बरों की दशा प्रायः ग्रच्छी नहीं होती। वे (पुरुष हों या स्त्री) प्रति दिन प्रातः से सायं तक फसल बोने या काटने में लगे रहते हैं। प्रायः उन्हें सप्ताह के सभी दिन काम करना पड़ता है। जब तक बीज बोने या फसल काटने का काम खत्म न हो वे जुटे रहते हैं। उजरत का मिलना ग्रानिहचत होता है और वह प्रायः कम होती है ग्रीर नकद या जिन्स के रूप में मिलती है।

प्रत्येक फार्म में मेम्बर के काम का हिसाब रखा जाता है। ये इकाइयां इसके

Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and e Gangotti परिश्रम की मात्रा और योग्यता को जाहिर करती हैं जो सामूहिक फार्म का मेम्बर करता है। ग्राय की तक़सीम, चाहे नक़द हो या जिन्स के रूप में, उपज पर निर्भर है। हर "कोलखोज़" का हिस्सा तमाम टैक्स, बकायाजात और बार्षिक चन्दे काटने के बाद निश्चित किया जाता है। इन कटौतियों के पश्चात् मेम्बरों को बहुत कम उजरत मिलती है। गुजर-बसर के लिए इसे ग्रपने छोटे बाग़ की पैदाबार का सहारा लेना पड़ता है।

सोवियत सरकार ने ढोंग तो यह रचा रखा है कि सामूहिक फार्मों की व्यवस्था प्रजातांत्रिक ढंग से होती है परन्तु हक़ीक़त कुछ और ही है। फार्म के सदस्य फ़ैसलों का केवल समर्थन कर सकते हैं जो फार्म के डायरेक्टरों अथवा मैनेजरों ने किए हों। सामूहिक फार्म का प्रधान वैधानिक तौर पर तो सदस्यों की आमसभा में "चुना जाता है", परन्तु वास्तव में यह सभा केवल उस उम्मी-दवार के निर्वाचन की पुष्टि करता है जिसे स्थानीय कम्यूनिस्ट ग्रुप ने या तो चुना हो, या उसका समर्थन किया हो।

सामूहिक फार्म का प्रधान नौकरशाही के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में से होता है। कम्यूनिस्ट पार्टी उसकी नियुक्ति तकनीकी योग्यता को देखकर नहीं करती, बल्कि यह देखती है कि पार्टी के दृष्टिकोण से वह किस हद तक विश्वस्तीय है। इसीलिए इसे प्रायः कृषि के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं होता। कभी-कभी वाहर से ग्राए हुए व्यक्ति को प्रधान बना दिया जाता है जिसे स्थानीय जल-वायु ग्रीर फसल इत्यादि के वारे में कोई ज्ञान नहीं होता। इसका प्रभाव प्रायः सामूहिक फार्मों में कम उत्पादन के रूप में प्रत्यक्ष होता है।

सामूहिक फार्म के प्रधान की ग्राय का हिसाब एक जटिल फारमूले से लगाया जाता है। भिन्न-भिन्न हालतों में यह ग्राय बदलती रहती है। यह ग्रौर फसल की किस्म फार्म के रकवे ग्रौर उसकी स्थिति पर निर्भर है। ग्रपनी राजनीतिक पोजीशन ग्रौर प्रभाव के कारण वह ठाठ से जीवन व्यतीत करता है। फार्म की उत्तम ग्रौर बढ़िया उपज पर उसका ग्रधिकार होता है।

मैनेजर अपने पद से लाभ उठाते हुए लूट-खसूट से भी नहीं चूकते। सोवि-यत समाचार पत्रों के अनुसार बहुत से प्रधानों पर इस कारण मुकदमे चलाए गए हैं कि उन्होंने फार्म की पैदावार काले बाजार में वेची थी अथवा अपने हिसाब में गड़बड़ किया था, या रिपोर्ट गलत तैयार की थीं और या सांके फंड में हेर-फेर किया था। १०. क्या सामूहिकः खेतीन्याको डसम्ब्रह्माकरान्ते व्हरसीतान्याने व्हर्णे जाती है ?

जब से ख़ु रचेव को ग्रधिकार प्राप्त हुग्रा है वह छृपि के लिए ऐसे लक्ष्यों का प्रचार करते रहते हैं जो सामूहिक खेती-बाड़ी की वर्तमान व्यवस्था को एकदम बदल कर रख दें। एक प्रस्ताव यह है कि खेती के नगर ग्रथवा "ऐग्रो-गोरोड्ज्" स्थापित किए जाएं। सब खेत मज़दूर कृषि योग्य भूमि के निकट ही रहें (परन्तु उस जमीन पर नहीं) जहाँ वे काम करते हैं। इस प्रकार सामूहिक खेती-बाड़ी के सामान की सामूहिक मिल्कियत की प्रथा खत्म हो जाएगी ग्रीर कृषि व्यवस्था इस प्रकार की हो जाएगी जिसमें किसान केवल उजरती मज़दूर बन जाएंगे।

सोशलिज्म से कम्यूनिज्म की ग्रोर बढ़ने की इस विधि के कारण भूमि से खेत मज़दूरों का सम्बन्ध टूट जाएगा।

सी० पी० एस० यू० के वक्ता यह भी कहते हैं कि निजी बाग़ के लिए छोटे क्षेत्र देने की प्रथा बन्द कर दी जाए। वह सामुदायिक जीवन का प्रोत्साहन कर रहे हैं। यद्यपि वे कम्यूनिस्ट चीन के कम्यून सिस्टम के विरुद्ध हैं।

११. क्या कृषि के समूहीकरण से कृषि उपज में बढ़ोतरी हुई है ?

भूमि की प्रति इकाइ के अनुसार हिसाब लगाया जाए तो खेती के समूही-करण से प्रति हैक्टेयर उपज में केवल कोई वृद्धि नहीं होती, विलक अधिकतर कम्यूनिस्ट देशों में तो सामूहिक कृषि उपज भी कुछ नहीं वढ़ी।

पैदाबार के मामले में पिहचमी यूरोप, ग्रमरीका तथा श्रन्य देशों के स्तर तक पहुँचने में सामूहिक खेती की श्रसफलता के कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि प्रति व्यक्ति पीछे उपज बढ़ाने के लिए खेतों पर काम करने वालों और सामूहिक फामों के सदस्यों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। दूसरा कारण कम्यूनिस्ट व्यूरोक्रैसी की श्रदक्षता है।

२५ दिसम्बर १६५६ को ख़ूक्षेव ने सी० पी० एस० यू० की केन्द्रीय कमेटी के सामने एक वक्तव्य में कहा कि कृषि उपज में कमी की जिम्मेदारी व्यूरो-क्रैटिक ग्रदक्षता तथा ग्रयोग्यता पर ग्राती है। उन्होंने बताया कि रूस में ऐसे नेता मौजूद हैं जो कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए कृषि उपज के लक्ष्य हुक़ीक़तों को सामने रख़े बिना ही नियुक्त किए गए हैं। खुरिकेश्व के शह कि कि हा कि एकि कि कार पड़ी है क्यों कि १८०० ट्रेक्टर ३२,००० कम्बाईन, २१,००० ट्रक और ११,००० फसल काटने की मशीनें नाकारा हो चुकी थीं।

खूरचेव ने इस बात को प्रकट किया कि खाने-पीने की वस्तुओं श्रीर अन्य चीजों की कमी की बहुत सी शिकायतें केन्द्रीय कमेटी को मिली हैं। सप्तवर्पीय योजना के ग्रधीन १६५६ तक कृषि उपज को प्रतिशत बढ़ना था परन्तु सी० पी० एस० यू० की सभा में जो श्रांकड़े पेश हुए उनसे प्रत्यक्ष था कि १६५८ के मुकाबले में कृषि उपज १० प्रतिशत गिर गई।

१९५९ में वलगारिया और पूर्वी जर्मनी में अन्त-संकट उत्पन्न हो गया था। पूरे उत्तरी यूरोप में उपभोज्य वस्तुओं की कभी रही और उनकी कीमतें चढ़ती रहीं।

पूर्वी जर्मनी के कम्यूनिस्ट ग्रध्यक्ष वाल्टर उलबृच ने यह वात स्वीकार की कि वहाँ मूल फसलों की प्रति हैक्टेयर उपज पश्चिमी जर्मनी से बहुत कम है। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव रखा कि खेतों के समूही-करण का काम तेज कर दिया जाए। यद्यपि पूर्वी जर्मनी के किसान सामूहिक खेती के कट्टर विरोधी हैं।

१६५६ में हंगरी की सरकार ने बहुत जोर डालकर सामूहिक फार्मों की संख्या में वृद्धि कर ही ली। उस वर्ष के अंत तक समस्त कृषि योग्य भूमि का ७० प्रतिशत भाग सामूहिक फार्मों में सम्मिलित कर लिया गया था। कोई ३,५०,००० व्यक्ति जबरदस्ती सामूहिक फार्मों में काम करने के लिए विवश कर दिए गए। परिणाम यह हुआ कि किसानों में बहुत हलचल और असंतोष पैदा हुआ और बहुत आर्थिक हानि हुई।

श्रुलाई १६६२ के समाचार पत्रों में एसोसीएटिड प्रेस का यह समाचार प्रकाशित हुग्रा :

> कजाकिस्तान में कृषि संकट फसल की कटाई रुकी पड़ी है

मास्को, प जुलाई ए० पी० ने समाचार दिया है कि सोवियत सरकार ने कल स्वीकार किया कि कज़ाकिस्तान के बड़े "नई खेती के प्रदेशों" में फसल की कटाई का काम गम्भीर संकट में है। सोवियत सरकार भ्रौर कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के हस्ताक्षरों से जारी किये गये एक वक्तव्य में कहा गया है कि कजाकिस्तान में कम्बाइन भ्रौर भ्रापरेटर तो कम हैं ही, यातायात की सुविधायें भी पर्याप्त नहीं हैं।

यह वक्तव्य पार्टी के समाचार पत्र "प्रावदा" के पूरे पहले पन्ने पर फैला हुआ है। इसमें कहा गया है कि केवल जेलीना के प्रदेश में ही ३४,००० कम्वाइन और २४,००० कटाई की मशीनें वेकार हो चुकी हैं। पोलोडर के क्षेत्र में केवल २० प्रतिशत कम्वाइन काम करने के योग्य हैं।

वक्तव्य में कहा गया है कि कजाकिस्तान की सरकार ने ७०,००० फसल काटने वालों के लिए ग्रपील की है।

सोवियत प्रेस में पिछले दिनों यह समाचार ग्राते रहे हैं कि मजदूर इन नई जमीनों पर रहने से इन्कार कर देते हैं क्योंकि वहाँ हालात कठिन ग्रीर ग्रसह्य हैं। नई जमीनों को कृषि योग्य बनानेकी यह योजना नये प्रयोजनों में से है।

ग्यारहवां ग्रध्याय कम्यूनिज़म के चन्तर्गत पारिवारिक जीवन स्त्रियां चौर वच्चे

१. क्या कम्यूनिस्ट देशों में स्त्रियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है ?

कुछ कम्यूनिस्ट देशों में स्त्रियों को भी उच्च पद मिले हुए हैं। रूस की शासन-व्यवस्था में केवल एक ही स्त्री उच्च पद पर नियुक्त है। अकाटैरीना फरजीवा सुप्रीम सोवियत की सदस्या हैं। मई, १९५० में उन्हें सांस्कृतिक मामलों की मन्त्रिणी वना दिया गया।

निर्वाचित स्थानों पर (जैसे सुप्रीम सोवियत) पुरुष सदस्यों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या श्रमिक वर्गों में उनकी तादाद के अनुपात से बहुत ही कम है। पिछलग्य देशों में भी छोटे पदों को महिलाएं पा सकती हैं परन्तु कम्यूनिस्ट पार्टी के उच्च अधिकारी केवल पुरुष ही वन सकते हैं।

गैर-कम्यूनिस्टों पर ग्रत्याचार करने में महिला कम्यूनिस्ट ग्रिविकारियों ने बहुत दक्षता दिखाई है। कम्यूनिस्ट पूर्वी जर्मनी में १९५३ की लोक क्रान्ति के बाद कठोरहृदयी कट्टर कम्यूनिस्ट महिला "रैड हिल्ड" वन्जामन को न्याय-मिन्त्रणी नियुक्त किया गया। उसने कम्यूनिस्ट सरकार के प्रमाणित तथा ग्रदृष्ट विरोधियों पर ऐसे-ऐसे ग्रत्याचार किए कि सारा देश कांप उठा। १९५६ में पार्टी के नेताग्रों ने उस पर कड़ी ग्रालोचना ग्रीर निन्दा की।

एनापोकर भी इतनी ही बंदनाम थीं। वह रूमानिया की विदेशमंत्रिणी थीं। गैर-कम्यूनिस्टों को हानि पहुँचाने पर इन्हें भी इनाम दिया गया था। बाद में वह पार्टी की नजर से गिर गईं और उसे ग्रधिकार से वंचित कर दिया गया। कम्यूनिस्टों ने जब शासन-प्रबन्ध अपने हाथ में लिया तो इस स्त्री ने ऐसा "लाल ग्रातंक" फैलाया जिसकी बराबरी कम्यूनिस्ट बल्गारिया में जोना द्रीगाट शैवा का वहशीपन ही कर सकता था।

२. स्त्रियों के संगठनों का कस्युनिस्ट देशों में क्या पार्ट होता है ?

कम्यूनिस्ट शासन में स्त्रियों के संगठन कम्यूनिस्ट पार्टी को बढ़ाने ग्रीर शक्तिशाली बनाने में बड़े काम ग्राते हैं। ग्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये संगठन कम्यू-निस्ट प्रोपेगण्डा फैलाते हैं, पार्टी की हिदायतों को कार्यान्वित करते हैं। इसकी योजनाग्रों की सफलता में सहायता देते हैं। गैर-कम्यूनिस्ट स्त्रियों की संस्थाओं को ऐसे प्रोग्रामों में खींच लाते हैं जो कम्यूनिस्ट उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हों।

स्त्रियों के ऐसे संगठन कम्यू निस्टों के प्रभाव में तो होते ही हैं परन्तु पार्टी की नीति के निर्णय में उनका कोई हाथ नहीं होता। (सोलहवाँ अध्याय देखिए)

३. सोवियत गृहिगाी की क्या हैसियत है ?

सोवियत गृहिणी की सामाजिक पोजीशन इस वात पर निर्भर है कि सोवि-यत समाज के नये वर्गीय शासन प्रवन्ध समाज में इसका स्थान क्या है। यदि वह किसी वड़े सरकारी ग्रधिकारी या उच्च फौजी ग्रफसर की पत्नी है तो हर प्रकार के सुख ग्रौर ग्राराम के द्वार उसके लिए खुले हैं। उसे बहुत सी वे समाजी सुविधाएं भी मिल जाती हैं जो "पूंजीवादी" समाज में किसी स्त्री को प्राप्त हैं। परन्तु तमाम समाजी सम्बन्धों में उसका स्थान ग्रपने पति के सामाजिक स्तर के ग्रधीन होता है। पिछले दिनों तक उच्च सोवियत ग्रधिकारियों की पत्नियां भी गुमनाम रही हैं।

सोवियत समाज के अन्य वर्गों में गृहिणी का काम दुहरा है। वह घर की देखरेख भी करती है और आजीविका भी कमाती है। और अधिक व्यान उसे आजीविका जुटाने पर ही देना पड़ता है। सोवियत स्त्रियों के लिए काम के हालात वही हैं जो पुरुषों के हैं। उद्योग और खेती-वाड़ी में उन्हें अधिकतर अदक्ष काम का बोभ उठाना पड़ता है।

जुलाई १९५६ में सुप्रीम सोवियत के ग्रधिवेशन को भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बुल्गानिन ने विश्वास दिलाया था कि स्त्रियों को बहुत भारी काम नहीं दिलाया जाएगा परन्तु मजदूरों की कमी ने स्त्रियों के हिस्से का भारी काम घीरे-घीरे ग्रीर भी बढ़ा दिया है।

सोवियत यूनियन में अनुत्पादक स्त्री उसे कहा जाता है जो राज्य की अर्थ-व्यवस्था के किसी क्षेत्र में भी मुलाजिम न हो। ऐसी स्त्री को समाजी तथा डाक्टरी संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होता। खाद्य-सामग्री के राशंन, मकान Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and e Gangoiri इत्यादि में उसका ग्रधिकार कम से कम रखा गया है। इसके मुकावल में सरकार की मुलाजिम ग्रभिनेत्रियां ग्रीर वह स्त्रियां जिन्होंने किसी कला में स्थाति प्राप्त की हो, ग्रच्छे वेतन पाती हैं ग्रीर उनकी ग्राय उच्च कर्मचारियों से कम नहीं होती।

सोवियत सरकार स्त्रियों के खेलों में भाग लेने को भी बढ़ावा देती है। ऐसी स्त्रियों को सरकार ग्रन्य कर्मचारियों की तरह वेतन देती है चाहे वह कम

ही हो।

४. कम्यूनिक्स के ग्रन्तर्गत श्रमजीदी स्त्रियों की क्या हालत है ?

ऐसे कम्यूनिस्ट संसार में पुरुप और स्त्री की समानता का राग गाया जाता है। परन्तु चीनी सोवियत ब्लाक में कहीं भी स्त्रियों को कोई सुविधा नहीं दी जाती। समानता के नियम के अनुसार स्त्रियों को इस्पात की मिलों, जंगलाती लकड़ी के कैम्पों,रेलों, सड़कों आदि सभी स्थानों पर मजदूरी करनी पड़ती है। निर्माण कार्यों में वे ऊंचाई पर सामान भरी परातें पहुँचाती है, सड़कों साफ करती हैं, लकड़ी चीरती है, भट्ठी फ्रोंकती हैं, मशीनों पर काम करती हैं, बढ़ई बनती हैं और इस प्रकार के बीसियों काम करती नजर आती हैं। परन्तु उनके निरीक्षक कुछ धन्धों को छोड़कर, प्रायः पुरुष ही होते हैं।

जो स्त्रियां प्रशिक्षण इत्यादि के काम में लगी हुई हैं, उनके काम को प्रोपे-गण्डा के लिए ग्रधिक महत्व दिया जाता है। रूस में चिकित्सा ग्रौर डाक्टरी के पेशों में स्त्रियों की संख्या काफी है। ग्रन्य पेशों में भी स्त्रियों को स्थान मिल जाता है। परन्तु पिट्ठू देशों में शिक्षा सम्बन्धी पेशों में स्त्रियों की संख्या कम

ही है।

कम्यूनिस्ट प्रवक्ता रूस ग्रीर पूर्वी यूरोप के कम्यूनिस्ट देशों में स्त्रियों की "वरावरी" का बहुत शोर मचाते हैं। परन्तु श्रमिक वर्ग की स्त्रियों को जहां कुछ ग्रधिकार मिल गए हैं, वहां उन्हें सरकार की ग्रोर से नियुक्त किए गए भारी कामों को करना पड़ता है। स्त्रियों की बड़ी भारी संख्या को घटिया ग्रीर कम पारिश्रमिक वाला काम दिया जाता है जहां उन्नति के ग्रवसर न होने के बरावर होते हैं।

चेकोस्लोवािकया की कम्यूनिस्ट पार्टी की निजी पत्रिका "रोड परावो" ने अपने ७ जनवरी, १९५७ के ग्रंक में इस दोष को स्वीकार किया है कि "बहुत से ट्रेड यूनियन ग्रधिकारी प्रायः विना किसी उचित कारण के स्त्रियों के काम

को भीर उम्बुबोटबवेष्प्रत्यस्थे को होन-सामक्ति हैं और ना अवहें विख्ये हुए से का काम साँपने से सकुचाते हैं।

चेकोस्लोबािकया में काम के हालात पूर्वी यूरोप के अन्य देशों से थोड़े बेहतर हैं परन्तु बहां भी स्त्रियां भूमि के नीचे युरेनियम की खानों में काम करती हैं, लोहे के कारखानों में मज़दूरी करती हैं। इस्पात की एक मिल में दो सौ महिलाओं ने शिकायत की कि उन्हें रात की शिफ्ट में केवल इसलिए काम करना पड़ता है कि उन मज़दूरों का स्थान ले सकें जिन्हें पार्टी के जलसों में जाना होता है। जब इस अन्याय के बिरुद्ध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन्हें तितर-वितर कर दिया।

१६५६ में पिट्ठू सरकारों ने भी रूस की देखा-देखी "श्रमदान" का स्रांदो-लन चलाया। सब पुरुप और महिलाएं इसकी लपेट में स्ना गए तथा स्कूलों के विद्यार्थी भी वच नहीं पाए। अपने काम के अतिरिक्त नर-नारी तथा वच्चे श्रमदान देते थे उसका उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था जैसे पूर्वी जर्मनी में स्कूल के बच्चों को सप्ताह में एक दिन विना किसी पारिश्रमिक के काम करना पड़ता था। उस दिन को "उत्पादन-दिवस" कहा जाता है।

५. काम करने वाली माताग्रों को सोवियत यूनियन में क्या सुविधाएं प्राप्त हैं ?

काम करने वाली माताओं ग्रौर गर्भवती स्त्रियों को प्रसूति ग्रवकाश मिलता है। १६४४ के कानून के ग्रनुसार यह ग्रवकाश ७७ दिन का होता है। ३५ दिन की छुट्टी वच्चे के जन्म लेने से पूर्व ग्रौर ४२ दिन वाद में दी जाती हैं। जो महिलाएं सामाजिक संरक्षण की सुविधाग्रों की ग्रधिकारी हैं उनको हस्पताल का खर्च वीमा कम्पनियां देती हैं। इन सुविधाग्रों के ग्रतिरिक्त बहुत-सी सोवि-यत माताग्रों को सरकार की ग्रोर से वच्चों के कपड़े ग्रौर कुछ नकद ग्रलाऊंस भी मिलता है।

यद्यपि सोवियत माताग्रों को यह सुविधाएं प्राप्त करने का कानूनी ग्रधि-कार है फिर भी इनका मिलना इतना आसान नहीं। सरकारी लाल फीते के कारण कारखाने के ग्रधिकारियों की वेख्खी की वजह से इन सुविधाग्रों के मिलने में देर भी हो जाती है। कारखाने के डायरेक्टर कोशिश करते हैं कि उनकी मजदूर संख्या कम न होने पाए। इससे काम करने वाली माताग्रों के लिए कानूनी संरक्षण व्यथं हो जाते हैं।

एक बात और भी है। कुछ बड़े-बड़े नगरों को छोड़ कर जहां काम करने

Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri वाली महिलाओं के लिए प्रसूति प्रवेध उपलब्ध है, छोट नगरी और ग्रामों में जिकत्सा की सुविधाएं ग्रीर वच्चों की देखरेख के प्रवंध या तो कम हैं या सिरे से हैं ही नहीं।

६. कम्यूनिस्ट देशों में माताश्रों के काम करते समय उनके छोटे बच्चों की देखरेख किस प्रकार होती है ?

अधिकांश कारखानों में नरसिरयां होती हैं। ये दो मास से तीन वर्ष के वच्चों की देखरेख करती हैं। तीन साल से सात साल के वच्चों के लिए किण्डर-गार्टन हैं। वहां वच्चों की देखरेख की फीस ली जाती है। वच्चे के पालन-पोषण पर जो खर्च आता है उसका एक तिहाई से एक चौथाई तक माता-पिता देते हैं, वाकी सरकार अथवा प्रवर्तक संस्थाओं के जिम्मे होता है।

वच्चों की देखरेख करने वाले केन्द्रों के सम्बन्ध में एक शिकायत आम है कि वहाँ अधिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं। नियुक्त संख्या से कहीं अधिक बच्चे भर्ती कर लिए जाते हैं। अकुशल लोगों के हाथों में उनका प्रबंध कभी ठीक नहीं होता। बड़े नगरों से वाहिर ये त्रुटियां और भी आम हो जाती हैं।

इन शिकायतों का नमूना एक सोवियत सैनिक की पत्नी का पत्र है जो उसने स्थानीय समाचार पित्रका को लिखा था। "मैं काम पर नहीं जा सकती क्योंकि घर में कोई भी नहीं है जिसके पास बच्चों को छोड़ सकूं। एक मास से मैं इन्हें नरसरी में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न कर रही हूँ परन्तु वहां से हर बार यही उत्तर मिलता है कि बस नरसरी नई शाखा खुलने की देर है कि मेरे बच्चों को दाखिल कर लिया जाएगा। परन्तु यह कोई नहीं बताता कि वह शुम दिन कब आएगा।" (लेनिनस्कोया जुआन्या में प्रकाशित एक पत्र से)

७. क्या यह सच है कि कम्यूनिस्ट सरकारें बच्चों को माता-पिता के प्रभाव से दूर कर देती हैं ?

मान्संवादी तथा लेनिनवादी शिक्षाप्रणाली, जो सब कम्युनिस्ट देशों में प्रचलित है बच्चों को माता-पिता के प्रभाव से दूर करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। कम्यूनिस्ट स्कूलों में प्रशिक्षण तथा कम्यूनिस्टों की चलाई हुई युवकों की संस्थाएं बच्चों पर नियन्त्रण रखने में सहायक सिद्ध होती हैं।

पारिवारिक सम्बन्ध नाममात्र रह जाने का एक कारण यह भी है कि कम आय के कारण माता और पिता दोनों काम करने के लिए विवश होते हैं। एक साधारण शिक्षित सोवियत कारीगर आठ सौ रुवल प्रतिमास या इससे भी श्रधिक कमीलिंग्हिले प्रिन्तुं भी अध्या स्विष्टि हो स्विष्टि हो कि कि एक हिन्ने कि कि तो उसे मकान के किराए अथवा खाने-पीने पर एक हजार कवल उठ जाता है। इसलिए पत्नी के काम किए विना गुजारा नहीं होता। यदि वह अशिक्षित है तो उसे अपने पति से केवल आधा वेतन मिलेगा।

काम का समय भी काफी लम्वा होता है। छयालीस घंटे का सप्ताह गिना जाता है परन्तु वास्तव में इससे भी वढ़ जाता है क्योंकि मज़दूरों के सिर पर काम का कोटा पूरा करने की तलवार लटकती रहती है। होता यह है कि वच्चे प्रातः से सायं छः बजे तक सरकारी संस्थाओं के निरीक्षण तथा निर्देशन में रहते हैं। स्कूल के वाद युवक संस्थाएं इत्यादि वच्चों के मस्तिष्क में कम्यूनिस्ट सिद्धान्त विठाती हैं। धर्म विरोधी प्रचार निरन्तर होता रहता है। बच्चे को सिखाया जाता है कि उनकी निष्ठा का प्रथम पात्र कम्यूनिस्ट प्रशासन हैं; घर नहीं।

द. सोवियत रूस में उत्पादन क्षेत्रों में महिलाग्नों के बलात् प्रवेश से पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्पादन क्षेत्र में श्रौर श्रम के श्रन्य कार्यों में महिलाश्रों के बलात् प्रवेश से सोवियत यूनियन में मजदूरों की कुल संख्या तो श्रवश्य वढ़ गई है परन्तु व्यक्ति श्रौर परिवार को इसका बहुत बड़ा मूल्य देना पड़ा है।

दिन भर सोवियत महिला जीविका कमाने के लिए कमर तोड़ काम करती है। कभी-कभी तो उसे वह कठिन काम भी करना पड़ता है जिससे महिलाओं को स्वतंत्र देशों में वर्जित किया गया है।

काम पर जाने से पहले सोवियत महिला को खाद्य सामग्री की दुकान पर लम्बी लाईन में खड़ा होना पड़ता है। यहाँ ग्राकर उसे प्राय: यह सूचना मिलती है कि बहुत से ग्रावश्यक खाद्य-पदार्थ खत्म हो गए हैं या मिल नहीं सकते। उसके लिए ग्रौर उसके पति के लिए वर्कशाप के जलसों में शिक्षा सम्बंधी लैक्चरों में या यूनियन ग्रौर कम्यूनिस्ट पार्टी के ग्रन्तगंत होने वाली कार्य-विधियों में शामिल होना ग्रनिवार्य है। इस प्रकार उन्हें कई-कई सप्ताह ग्रापस में मिल बैठने का ग्रवसर नहीं मिलता।

६. कम्यूनिज्म के अधीन माता-पिता का क्या रोल है ?

१ = अन्तूवर, १६५२ को कम्यूनिज्म के अधीन माता-पिता के रोल के विषय में एक भाषण प्रसारित किया गया था इससे पता चलता है कि सरकार

Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri की दृष्टि में माता-पिता का क्या उत्तरदायित्व हैं।

इस भाषण में वताया गया था : "कम्यूनिस्ट नैतिकता की म्रात्मा को सामने रखते हुए वच्चे के प्रशिक्षण में परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों ग्रीर माता-पिता का वड़ा भाग है। यदि माता-पिता सच्चे तथा भावुक देशमक्त हैं ग्रीर सामाजिक कार्यविधियों में भाग लेते रहते हैं, पंचवर्षीय योजनाग्रों को पूरा करने में ग्रपना कर्तव्य पालन करते हैं, दूसरों की उनके कामों में ग्रीर परिवार की देखभाल में सहायता करते हैं तो वच्चों का स्वयं ही उचित प्रशिक्षण होता रहता है।"

इस प्रकार माता-पिता का कर्तव्य यह है कि कम्यूनिस्ट पार्टी की कार्यविधियों को आगे वढ़ाएं। प्रारम्भ ही से वच्चे की देख-रेख तथा प्रशिक्षण पार्टी की इच्छानुसार करें। इस प्रकार वच्चों पर सरकार का नियंत्रण सुदृढ़ हो जाता है।

इसके ग्रतिरिक्त कम्यूनिस्ट यह प्रयत्न भी करते हैं (यद्यपि इसमें ग्रभी ग्रिंघिक सफलता नहीं हुई) कि विवाह सैद्धान्तिक ग्राधार पर हों। एक सरकारी कम्यूनिस्ट प्रकाशन का ग्रादेश है: "जीवन साथी चुनते समय एक कम्यूनिस्ट नवयुवक को यह देखना चाहिए कि दूसरे पक्ष के राजनीतिक विचार ठीक हों। इसके पश्चात् शिक्षा, स्वभाव, स्वास्थ्य ग्रीर रंग-रूप पर घ्यान देना चाहिए।" १०. सोवियत यूनियन में साधारण श्रमिकों के परिवार को किस प्रकार की डाक्टरी सहायता वी जाती है ?

सोवियत यूनियन में उच्च वर्ग के परिवारों को हर प्रकार की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त हैं। वह योग्य डाक्टरों से इलाज करा सकते हैं। इसके उलट साधारण श्रमिकों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं कम होती हैं। सामूहिक रूप से पूरे रूस में ७०० व्यक्तियों के लिए एक डाक्टर है। परन्तु नगरों में चूंकि डाक्टर ग्रधिक संख्या में होते हैं इसलिए कुछ ग्राम्य क्षेत्रों में दस हजार व्यक्तियों के लिए केवल एक डाक्टर है।

११. क्या सोवियत पंचवर्षीय योजनाश्रों से साधारए अमिकों की क्रयशक्ति में कोई बढ़ोतरी हुई है ?

सोवियत यूनियन में पंचवर्षीय योजनाओं से जनता की क्रयशक्ति नहीं बढ़ी है। पहली पंचवर्षीय योजना १९२८ में ग्रारम्भ हुई थी। जबसे १९६० तक साधारण श्रमिकों के वेतन में जितनी वृद्धि हुई है, रोज के इस्तेमाल की चीजों के मूल्य उससे ग्रधिक तेजी से बढ़े हैं। सात खुद्धार हुर कुर्यो कुर उन्न से कि साम्राह्म स्थान सम्बद्धा हुर को १६२८ के मुका-सप्ताह भर का राशन खरीदने के लिए सोवियत मजदूर को १६२८ के मुका-वले में ग्राज लगभग ४० प्रतिशत ग्रधिक काम करना पड़ता है।

अक्तूबर, १६५६ में सोवियत अर्थ-व्यवस्था में एक नई प्रथा आरम्भ की गई जिसके अनुसार उपभोज्य वस्तुओं की सीमित मात्रा किस्तों में खरीदने के सिस्टम को कानूनी मान लिया गया। १५, अक्तूबर को सी० पी० ए० यू० की विज्ञप्ति में कहा गया कि देर तक चलने वाली वस्तुओं का उत्पादन वढ़ाया जाए। इन्हीं दिनों मास्को के पत्र-पत्रिकाओं में यह समाचार छपे कि जुराबों, धागे, बुने हुए कपड़ों, हल्के-फुल्के जूतों, सुन्दर कपड़ों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी है और उनकी क्वालिटी घटिया है।

१२. क्या रूस में साधारण मजदूरों पर करों का ग्रधिक बोक्त है ?

सोवियत यूनियन में साधारण मजदूर पर प्रत्यक्ष कर तो ग्रधिक नहीं हैं परन्तु उसे ग्रीर बहुत-सी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए सरकारी बाण्ड खरीदना, यूनियन का चन्दा ग्रीर वकाया देना इत्यादि। इस प्रकार उसका वेतन बहुत ही कम रह जाता है। सबसे ग्रधिक बोभ तो विकी टैक्स का है। यह तमाम ग्रामदिनयों पर एक छिपा हुग्रा कर है। इसके कारण प्रत्येक वस्तु ७० प्रतिशत महंगी हो जाती है।

स्रोसत स्रोद्योगिक वेतन पर, जो कि ७००-८०० रूवल प्रति मास तक होता है, ४०० रूवल तक कर पांच प्रतिशत है। इससे ऊपर ७०० रूवल तक कर की दर १० प्रतिशत है।

२७ सितम्बर, १६५६ को खु, रचेव ने घोपणा की कि "निकट मविष्य में जनता पर से तमाम कर उठा लिए जाएँगे।" तथापि आयकर जो १६५६ में सरकारी आमदनी का ७.५ प्रतिशत था, सोवियत वजट में अधिक महत्व नहीं रखता। जैसे १६५६ में सोवियत जनता की ओर से आय-कर, विशेषकर तथा रिपब्लिक टैक्स के रूप में दिए जाने वाले कुल टैक्स से विकी तथा मुनाफा टैक्स सात गुना अधिक था।

श्राय-कर खत्म हो जाने से सोवियत नागरिकों की श्रामदनी कुछ वढ़ जाएगी परन्तु इसका कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि सोवियत परिवार को पहले से ४० से १०० प्रतिशत तक ग्रधिक विक्री टैक्स देना पड़ेगा। १३. क्यो सावियेत रूस भेगसबं विशासिंग का सामाधिक सुरका के सवीन लापा गया है ?

लगभग ग्राघे सोवियत श्रीमकों, जिनमें ३ करोड़ तीस लाख खेत मजदूर भी घामिल हैं, पर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू नहीं होती, इण्टरनेशनल लेवर रिव्यू की रिपोर्ट के ग्रनुसार सोवियत श्रीमक को नौकरी के पहले छः मास में चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती ग्रीर उसे डाक्टरी इलाज के लिए पूरा खर्च उसी समय दिया जाता है जब वह एक ही स्थान पर दस साल तक काम करता रहें।

सामाजिक सुरक्षा के अधीन श्रमिकों को सात वर्ष की आयु पा लेने पर पेंशन का अधिकार मिल जाता है यदि उन्होंने २५ वर्ष तक निरन्तर काम किया हो। महिलाओं को ५५ वर्ष की आयु में पेंशन मिल सकती है यदि उनके निरन्तर काम की अवधि २० वर्ष हो। यह सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सोवियत सरकार के साथ में ऐसा हथियार है जिससे वह श्रमिकों को एक ही जगह पर आयु भर एक ही काम करने पर विवश कर सकती है।

सुप्रीम सोवियत के १२ जुलाई, १६५६ के अधिवेशन में भूतपूर्व प्रधान-मंत्री निकोलाई बुलगानिन ने एक नई पेंशन योजना घोषित की जो उनके अपने शब्दों में "पहली पेंशन योजना से बहुत बेहतर थी।" नए पेंशन कानून के अनुसार प्रत्येक सोवियत नागरिक को जिसने २० से २५ वर्ष तक काम किया हो; कम से कम ३०० रूवल तथा अधिक से अधिक १२०० रूवल पेंशन पाने का अधिकार मिल गया।

सोवियत संघ में मजदूरों पर ग्रान्तरिक पासपोर्ट तथा "काम के हिसाब-किताब की पुस्तक" के सिस्टम द्वारा कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। प्रत्येक मजदूर के पास उसकी "वर्क बुक" का होना ग्रनिवार्य है। इसमें उसकी नौकरी का पूरा रिकार्ड होता है।

१४. क्या मजदूरों को म्रारामघरों इत्यादि में मुफ्त ठहरने की सुविधा है ?

साधारण मजदूरों को ऐसी सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए इनका मूल्य देना पड़ता है परन्तु "तीव गित से काम" करने वाले मजदूरों तथा कम्यूनिस्ट पार्टी के ग्रधिकारियों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। यद्यपि ग्रारामधरों या स्वास्थ्यीय स्थानों में रहने का खर्च ग्रधिक नहीं है परन्तु उसमें सफर का खर्च भी मिला दिया जाए तो यह साधारण मजदूर की पहुँच से बाहर हो जाते हैं ग्रीर उसका अस्ति असे अब बेल आकार सकता and eGangotri

इन स्थानों में जाने के योग्य सोवियत मजदूरों में से केवल एक प्रतिशत को प्रति वर्ष वहां मुफ्त रहने की इजाजत मिलती है। इन स्थानों पर ग्रामतौर पर कम्यूनिस्ट पार्टी के ग्रधिकारी, शासक तथा ग्रन्य विशेषाधिकार पाने वाले व्यक्ति ही मौज मनाते हैं।

१५. क्या कम्यूनिस्ट देशों में बच्चों को ग्रपने माता-पिता पर जासूसी करना सिखाया जाता है ?

कम्यूनिस्ट देशों में बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह कम्यूनिस्ट पार्टी के निर्देशानुसार चलने में अपने माता-पिता तथा अध्यापकों की असफलता की रिपोर्ट करें। मास्को में क्रास्नोप्रैस्नसक वाल उद्यान में पिटलक मोरोजोफ का एक बुत लगा है जिसने वारह वर्ष की आयु में, पाओनीयर सदस्य होने के नाते अपने पिता की अधिकारियों से शिकायत की थी कि उसने अनाज इकट्ठा करने वाले अधिकारियों से कुछ अनाज छिपा लिया है। मोरोजोफ के पिता को दस वर्ष के लिये जवरी श्रम के कैंप में भेज दिया गया। पाओनीयर तथा कोमसोमोल के सदस्यों को "महान् पिटलक" की उपासना करने के लिए सरकारी तौर पर प्रोत्साहित किया जाता है।

१६. क्या सोवियत संघ में नवयुवा ग्रपराधी हैं ?

१६ ग्रक्तूवर, १९५६ को रेडियो मांस्को ने दावा किया कि सोवियत संघ में नवयुवापराघ की समस्या ग्रव खत्म हो गई है। परन्तु इस दावे का खंडन मास्को प्रेस में विगड़े हुए नवयुवकों की सरगिंमयों के वारे में छपने वाले समा-चारों से होता है। स्वतन्त्र देशों में उद्ण्ड नवयुवकों की ग्रनैतिक सरगिंमयों को ही नवयुवापराधियों के ग्रस्तित्व का प्रमाण समका जाता है।

१६५६ से पार्टी तथा सरकार नवयुवकों के दुराचार तथा कुकमों की रोक-थाम की ग्रोर ग्रधिक घ्यान देने लगी है। इस सम्बन्ध में १६५६ में जारी किए

गए दो प्रोग्रामों से अनुमान होता है कि स्थिति काफी गम्भीर है।

तथाकथित "जनता के जत्थे" (पीपल्ज स्क्वंड) जो १६५६ में कुछ गिने चुने नगरों में बनाए गए थे, ग्रव हर स्थान पर बना दिये गये हैं। इन जत्थों में ग्रीद्योगिक मजदूर, सामूहिक फार्मों के किसान तथा ग्रन्य राजंकीय संस्थानों के कर्मचारी शामिल होते हैं ग्रौर उनका काम यह होता है कि कुकर्मी नव-युवकों का सुधार वहीं पर किया जाए जहाँ वह काम करते हैं।

जत्ये आदि व्यांक्य क्षांत्र विश्वस्ता प्यार्थि व्याप्त को स्मित को से मन वरों को वनाया जाता है और उन्हें अनुशासन विरोधी कार्रवाइयों तथा दुराचारों की रोक-थाम का अधिकार होता है। उन्हें यह अस्तियार भी है कि सामान्य कातून का तोड़ने वालों की रिपोर्ट "सहयोगी अदालतों" (का ओड़ली कोर्टस को करें)। (छठा अध्याय देखिए)

नागरिकों के यह जत्थे शहरी पुलिस या मिलिश्या से अलग होते हैं, इस-लिए इनके विरुद्ध शिकायतें आई हैं कि इन्होंने अपने अधिकारों का उल्लंघन करके लोगों के निजी मामलात में भी हस्तक्षेप किया है।

क्स में युवावस्था की समस्या का प्रमाण इस घोषणा से भी मिलता है जो सोवियत सरकार ने अक्तूबर, १६५६ को की । इस घोषणा में नवस्थापित नव-युवक आयोगों के विषय में व्यवहार विधि का उल्लेख किया गया था । इन आयोगों को जिला, नगर तथा प्रादेशिक कम्यूनिस्ट पार्टियों ने स्थापित किया है । इनके जिम्मे दुहरा काम था : कुकर्मी नवयुवकों को कातून मंग करने से रोकना तथा कातून तोड़ने की सूरत में दण्ड देना और इन नवयुवकों के माता-पिता के विरुद्ध कातूनी चाराजोई करना । अवयस्क बच्चों के दुराचार के लिए उनके बुजर्गों को जिम्मेदार ठहराया जाता है ।

ग्यारह वर्ष की आयु से ऊपर के अवयस्क वालकों को सामाजिक दृष्टि से खतरनाक काम करने या सामान्य कानून का वार-वार उल्लंघन करने के लिए अपराध में तीन साल तक शैक्षिक वस्तियों में भेज दिया जाता है।

१७. कम्यूनिलम को पारिवारिक जीवन के लिए खतरा क्यों समक्ता जाता है?

मार्क्सी-लैनिनी सिद्धान्तों के अनुसार परिवार को "स्टेट मशीन का आज्ञा-कारी तथा अनुशासित" कम्यूनिस्ट पैदा करने वाला भाग समक्ता जाता है।

सोवियत राज्य या इसकी विभिन्न संस्थाओं के अधिकारी या स्थानीय कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता जब चाहें तब सोवियत परिवार का निरीक्षण तथा निगरानी करने के हकदार हैं। बच्चों को अधिक समय तक माता-पिता की निगरानी तथा देखभाल से दूर रखा जाता है। माता-पिता भी अपने काम के हालात तथा रहन-सहन की स्थिति के कारण प्रायः अपने बच्चों से अलग ही रहते हैं?

बारहवां ग्रध्याय कम्यूनिज़म में व्यापार

१. क्या सोवियत यूनियन में व्यापार इसी प्रकार होता है जैसे ग्रन्य देशों में ?

सोवियत देश का विदेशी व्यापार स्वतन्त्र देशों से कई प्रकार से भिन्न है। रूस में व्यापार का सबसे ग्रधिक उत्कृष्ट पहलू यह है कि इस पर सरकार का पूर्ण ग्रधिकार है।

स्वतन्त्र देशों में व्यापार प्रायः पराइवेट व्यक्तियों तथा कम्पनियों के हाथ में रहता है। वही मांग स्रीर सप्लाई का हिसाब लगाकर निर्णय करते हैं कि कितने माल का निर्यात किया जाएगा स्रीर किन देशों को किया जाएगा।

सोवियत यूनियन और अन्य कम्यूनिस्ट देशों में विदेशी तथा देश के भीतर व्यापार पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण होता है। वह सब माल की मालिक है। इसे बाजार में वेचती है। सोवियत यूनियन में निर्यात तथा आयात दोनों विदेशी व्यापार के मंत्रालय के अधिकार में हैं। वास्तविक ट्रेड एजन्सियाँ (Trade Agencies) और ट्रस्ट (Trusts) व्यापार के व्यवहारिक पहलुओं को देखते हैं और उनका आधार अन्य सरकारों अथवा निजी संस्थानों से की गई व्यापार सन्वियों पर होता है।

ऐसी बहुत-सी सन्धियां प्रायः राजनीतिक तथा प्रोपेगण्डा के लाभ के लिए की जाती हैं।

२. सोवियत व्यापार को प्रभावित करने वाली मुख्य वातें क्या हैं ?

सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी द्वारा निर्घारित पालिसियों और उनके अनुसार निश्चित राजनीतिक लक्ष्यों का सोवियत विदेशी व्यापार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सोवियत यूनियन की औद्योगिक तथा सैनिक आव-श्यकताओं को निश्चित करना और उनमें ताल-मेल पैदा करना सी० पी० एस० यू० का उत्तरदायित्व है और उक्त आवश्यकताओं को सामने रखकर ही आयात का प्रोग्राम बनाया जाता है। सोवियत निर्यात भी राजकीय योजना के अधीन निर्यात के सिर्ं उदिनीदिते भाषिणी की भाषी श्री शिक्षा वर्ष हि शाधारित है।

सोवियत निर्यात की मात्रा निश्चित करने में इस वात को भी दखल है कि सोवियत सरकार की देश में पैदा न होने वाली वांखित सामग्री के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की ग्रावश्यकता है। सोवियत निर्यात ग्रीर ग्रायात व्यापार का मुख्य भाग उन देशों से होता है जिनसे सोवियत यूनियन बहुत गहरे सम्बन्ध पैदा करने या बनाए रखने की इच्छुक होती है।

३. मार्क्सवाद-लेनिनवाद ने सोवियत विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव डाला है ?

मास्को की व्यापार नीति पर मार्क्सवादी तथा लेनिनवादी विचारधारा का प्रायः गहरा प्रभाव पड़ा है। कम्यूनिस्ट नीतियों में परिवर्तन के साथ-साथ सोवियत विदेशी व्यापार के रुख भी वदलते रहे हैं।

उदाहरण के लिए जब तक भ्रप्रैल, १६५२ की मास्को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक कांफ्रेंस (एम० आइ०ई०सी०) नहीं हुई थी, रूस के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि वह पूर्व तथा पिक्चम के बीच व्यापार आर्थिक लाभ की दृष्टि से अर्थात् संबं-धित देशों के परस्पर लाभ के लिए कर रहा है। कांफ्रेंस के-दौरान में भी रूस का व्यवहार ऐसा ही रहा।

परन्तु १९५२ में स्तालिन का एक लेख सरकारी पत्रिका "वोलशिवक" में प्रकाशित हुग्रा। इससे रूस की विदेशी व्यापार नीतियों में निर्णायक परिवर्तन हुए। स्तालिन ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद के ग्राघार पर यह दलील दी कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में साम्राजी ग्रन्तिवरोध "पूंजीपित देशों" के मीतर व्यापारिक युद्ध तथा भगड़ों को जन्म देंगे। इसलिए कम्यूनिस्ट ब्लाक को परस्पर स्वावलम्बी व्यापार का विकास करना चाहिए। सैद्धान्तिक पृथक्ता और "दो समान ग्रक्षवृत्त ग्रन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों" के दृष्टिकोण ने सोवियत व्यापार पर भारी प्रभाव डाला। उनकी कल्पना में एक मण्डी लौह ग्रावरण के पीछे थी ग्रीर दूसरी बाहर। परिणाम यह हुग्रा कि स्वतन्त्र देशों में सोवियत सरकार का व्यापार-वाणिज्य मंदा पढ़ गया।

मार्च, १६५३ में स्तालिन की मृत्यु हुई। दो मास के भीतर ही नई सरकार ने, प्रधानमंत्री जार्जी मेलिनकोव के नेतृत्व में "व्यापारिक आक्रमण" आरम्भ कर दिया। मास्को आर्थिक कांफ्रेंस के पश्चात् व्यापार सम्बन्धी यह सबसे वड़ा अभियान था। एक वर्ष वीत जाने के पश्चात् मेलिनकोव ने घोषणा की कि सोवियत सरकार सब पूंजीवादी देशों के साथ, जिनमें अमरीका भी शामिल

है, सोविस्ता सहित्रका हो प्राधिताप्रण-हार्थिक सकावले की समर्थक है।

इसके बाद से विदेशी व्यापार के सम्वन्ध में सोवियत प्रापेगण्डा तथा सरगर्मियां इतनी वढ़ चुकी हैं कि "श्वान्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व" के समर्थन में मास्को
की ग्रोर से जितना प्रापेगण्डा होता है उतना ही प्रचार विदेशी व्यापार के बारे
में किया जाता है। वैसे भी पूर्व ग्रीर पश्चिम के बीच व्यापार का विकास
"सहग्रस्तित्व" की नीति का महत्वपूर्ण ग्रंश है। मास्को की ग्रोर से घोपणा तो
बार-बार की जाती है कि वह विदेशी व्यापार बढ़ाने की इच्छुक है, परन्तु सोवियत सरकार ऐसे उत्तरदायित्व ग्रभी तक निभा नहीं सकी है जो व्यापारिक
संधियों के ग्रन्तगंत उस पर लागू होते हैं, सोवियत व्लाक दैनिक ग्रावश्यकता
की वस्तुग्रों की ग्रपेक्षा सैनिक सामान खरीदना चाहता है। ग्रर्थ नवस्वर, १९५५
में हुई जेनेवा कांफ्रेंस में तो सोवियत विदेशमन्त्री मोलोटोव ने यह बात बहुत
स्पष्टता से कही थी।

कम्यूनिस्ट देशों के विदेशी व्यापार का ग्रधिकांश चीनी-सोवियत व्लाक के भीतर ही सीमित रहता है। इस सारे कारोवार पर केन्द्रीय शासकों का निय-न्त्रण रहता है।

४. कम्यूनिस्ट देशों के निदेशी-व्यापार का फैलाव कितना है ?

कम्यूनिस्ट ब्लाक के व्यापार का ठीक अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि मुद्रा विनिमय का साधन ब्लाक की मुद्राएं नहीं हैं। कम्यूनिस्टों की सरकारी मुद्रा विनिमय से ब्लाक के व्यापार का मुद्रा (जैसे डालर) में हिसाव लगाया जाता है तो सामूहिक व्यापार असल से कहीं अधिक दिखाई देता है।

"सोशिलस्ट देशों की मण्डी ग्रौर पूंजीवादी मण्डी" के वीच में व्यापार में कोई विशेष ग्रदला-बदली नहीं हुई। १९५२ में इन दो मण्डियों के वीच व्यापार स्थिर रहा। इस वर्ष में इन दो मण्डियों के वीच व्यापार विश्व भर के वाणिज्य का २.२ प्रतिशत था १९५६ में इसमें कुछ वृद्धि हुई ग्रौर यह २.६ प्रतिशत हो गया। कम्यूनिस्टों की ग्रोर से प्रस्तुत मुद्रा-विनियम के ग्रांकड़ों के ग्रनुसार १९५० के वाद के दशक में कम्यूनिस्ट कैम्प का विश्व व्यापार में भाग काफी बढ़ा। १९५२ में यह ६.२ प्रतिशत था तथा १९५६ में १३.७ प्रतिशत हो गया। परन्तु यथायिक ग्रनुमान के ग्रनुसार १९५६ में कम्यूनिस्ट देशों का व्यापार १० प्रतिशत के लगभग था। १९५६ में ब्लाक का कुल व्यापार का ७६ प्रतिशत शत भाग ब्लाक के मीतर ही जिनस के रूप में हुग्रा।

कम्यूनिस्ट यूँजी से भिरति वाले स्माचितिक प्रीनुसार विकेड देशी से ब्लाक के व्यापार का १६५२ में कुल मूल्य १,२२,००,००,००० डालर था १६५८ में यह बढ़कर २,५८,०००,००० डालर हो गया। इस वृद्धि के वावजूद यह रकम उस व्यापार का एक तुच्छ ग्रंश है जो पिछड़े देशों ग्रीर ग्रैर कम्यूनिस्ट देशों के बीच होता है।

५. इस से किन वस्तुओं का निर्यात होता है ?

रूस में प्राकृतिक साधन बहुत ज्यादा हैं, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि खनिज पदार्थों के अतिरिक्त इसे ऐसी ही अन्य वस्तुओं के निर्यात के प्रति अपना वचन निभाने में कठिनाई होती है। मास्को ने ऐसी बहुत-सी व्यापार सन्धियां कर रखी हैं जिनके अन्तर्गत इसे औद्योगिक वस्तुएं निर्यात करनी पड़ती है।

रूस की पौराणिक निर्यात वस्तुएं, अनाज और लकड़ी आज भी सोवियत यूनियन में कम पैदा होती हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी के मन्त्री निकिता ख़ुइचेव ने रूस में अनाज तथा लकड़ी की अल्प उपज पर कटु शब्द कहे हैं। अन्य कच्चा माल जैसे अशोधित तेल और कोयला रूस की औद्योगिक तथा सैनिक संस्था-पनों की खपत के लिए ही पूरा होता है।

१६५४ के बाद सोवियत सरकार ने स्वतन्त्र देशों से व्यापारिक संधियां तो बहुत की हैं परन्तु विनिमय सूची में लिखित वस्तुग्रों के देने में प्रायः ग्रसमर्थ रही है या ग्रनिच्छुक रही है।

१६३८-१६५८ में सोवियत निर्यात न्यापार में बहुत से परिवर्तन हुए हैं।
मशीनें और औजार, धातुएं और धातुओं से बना सामान, जो १६३८ में सोवियत निर्यात का केवल ६.६ प्रतिशत था, १६५८ में ३५ प्रतिशत हो गया।
कच्ची तथा शोधित धातुओं का निर्यात इस अविध में दुगना हो गया। जबिक आम प्रयोग की वस्तुओं का निर्यात पहले से आधा रह गया। कपड़े और रूई इत्यादि के निर्यात में कुछ वृद्धि हुई अर्थात् यह ४.२ से बढ़कर ६.८ प्रतिशत हो गया। कुल निर्यात में ईंधन, जिसमें बड़ा भाग अशोधित तेल का था, ८.८ प्रतिशत से बढ़कर १५.२ प्रतिशत हो गया। इसके मुकाबले में अनाज का निर्यात २१.३ प्रतिशत से गिर कर ८.३ प्रतिशत रह गया।

ग्रशोधित तेल का निर्यात १६५७ में ५६ लाख टन था, १६४८ में यह एकदम बढ़कर ६० लाख टन हो गया। मशीनों के निर्यात में बड़ा भाग ट्रकों तथा कारों का रहा। १६५८ में २६,७०० ट्रक बाहर मेजे गये, जबिक १६५७ में इनकी संख्या क्षे १९७० ६ अभि। ा० ८० ६ सिक्ति कि इस्कि किए गए उनमें से २०,५६५ ट्रक कम्यूनिस्ट चीन को दिए गए। पेपिंग श्री छोगिक मशीनरी का भी बड़ा ग्राहक रहा है।

चीन भीर रूस के वीच व्यापार में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि ट्रैक्टरों में हुई है। १६५८ में पेपिंग ने २,६२५ ट्रैक्टर खरीदे जबिक १६५७ में केवल ६८ टैक्टर लिए थे।

स्वतन्त्र देशों के २७ देशों से रूस के व्यापार में १९५७ की निस्वत १९५५ में ३ ७ प्रतिशत वृद्धि हुई। परन्तु १९५६ में इस व्यापार का मूल्य रूवलों में फिर भी कुछ ग्रधिक नहीं था ग्रर्थात् १ ग्ररव रूवल (सरकारी विनिमय दर के ग्रनुसार २ ग्ररव २५ करोड़ डालर था)।

लेटिन ग्रमरीका, मध्य पूर्व तथा दूर पूर्व के देशों ने जो रूस से ग्रायात करते हैं, शिकायत की है कि रूस ने माल भेजने में तो दिलम्ब किया ही है, परन्तु माल भी नियमित स्तर, जो कि व्यापार सन्धियों में दर्ज था, के ग्रनुसार नहीं किया।

६. मास्को ग्रपने पिट्ठू देशों के व्यापार पर किस प्रकार प्रभाव डालता है ?

पूर्वी यूरोप के देशों का विदेशी तथा परस्पर व्यापार मास्को द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार होता है, या फिर यह व्यापार पिट्ठू देशों के उन संस्थानों के नियन्त्रण में रहता है जो मास्को के अधीन होते हैं।

१६४७-४६ में पूर्वी यूरोप पर कम्यूनिस्टों का ग्रधिकार क़ायम हुग्रा था। तभी से पिट्ट देशों की राष्ट्रीय ग्रर्थ-व्यवस्था तथा व्यापर में ऐसे परिवर्तन ग्राए हैं जो रूस के कारोवारी प्रोग्राम के ग्रनुकूल हैं ग्रौर जिनसे सोवियत ग्रर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है।

पहले पूरे पूर्वी यूरोप में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का मूल तत्व कृषि था। अब सोवियत नीति के कारण बड़े उद्योगों का विकास किया जा रहा है तािक सोवि-यत यूनियन के उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी हों और उनके विकास में सहा-यता मिले। इससे उन देशों के कृषि-विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, पहले पिट्ठ देश पश्चिमी यूरोप को अनाज तथा अन्य कृषि उपज निर्यात किया करते थे, अब उनके पास निर्यात के लिये कुछ बचता ही नहीं। कुछ देश तो कृषि पदार्थों के अभाव के प्रदेश बन गये हैं। Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and e Gangoto उदाहरण के लिय, दूसरे महायुद्ध से पूर्व हंगरी यूरोप की "रूई की डिलया" कहलाता था, ग्रव वह ग्रनाज का विल्कुल निर्यात नहीं करता। रूमानिया तथा पोलैंड भी श्रन्न में ग्रात्म-निर्भर नहीं रहे।

पूर्वी यूरोप में खेती-वाड़ी के समूहीकरण से कम्यूनिएम के अन्तर्गत किसानों को वलपूर्वक संगठित करने के कारण कृषि उपज का अभाव हो गया है। पश्चिम को निर्यात अब बन्द हो गया है। स्वयं कम्यूनिस्ट देशों का परस्पर व्यापार भी बहुत घट चुका है। १९५३ के बाद में पश्चिमी देशों से व्यापार में तो वृद्धि हुई है परन्तु पिट्झ देशों का पश्चिम से व्यापार नाममात्र ही रह गया है।

मई, १९५६ में सब यूरोपी कम्यूनिस्ट सरकारों के सदस्यों की एक कान्फ्रेंस पूर्वी बिलन में हुई। यह अधिवेशन आठ दिन तक रहा। इसमें रूस की ओर से कम्यूनिस्ट गुट के आर्थिक संगठन की योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना के अनुसार गुट के प्रत्येक देश को कुछ वस्तुओं की उपज की थोर विशेष रूप से ध्यान देना है। इस प्रस्ताव का अभिप्राय वास्तव में यह था कि पिट्झ देशों की पंचवर्षीय योजनाओं को रूस की योजना के अनुकूल बनाया जाए और उसके संग जोड़ दिया जाये।

सोवियत गुट के घाधिक संगठन के लिए मास्को कान्फ्रेंस में प्रस्तुत योजना को परस्पर द्याधिक सहयोग की समिति जिसे ''सैमा" तथा ''कौमीकोन'' के नाम से भी पुकारा जाता है, कार्यान्वित करती है। १६५८-५६ में कौमीकोन की जो बैठकें हुई, उनमें जोर दिया गया कि चीनी-सोवियत गुट के सब सदस्यों के बीच ग्राधिक तथा सैनिक सहयोग हो भौर कम उन्नत देशों को तेजी से व्यापारिक सहायता देने का काम ग्रारम्भ किया जाए।

इस प्रोग्राम के अन्तर्गत मध्य पूर्व अफीका और एशिया को पिट्ठ देशों के निर्यात में १६५७ के मुकाबले में डालर के मूल्य के अनुसार २० प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिट्ठ देशों में निर्यात करने वाले विशेष वर्णन योग्य देश चेकोस्लो-वाकिया, पूर्वी जर्मनी तथा रूमानिया हैं।

कम्यूनिस्ट सरकारें देश के अन्दर अपने माल के प्रचार तथा विज्ञापन की झोर वहुत थोड़ा घ्यान देती हैं, परन्तु विदेशी व्यापार से संबंधित प्रकाशन बहुत सुन्दर और सचित्र होते हैं। उनमें ऐसे माल की विज्ञप्तियाँ होती हैं जो या तो देश के अंदर मिलता ही नहीं या उसके मूल्य ऋयशक्ति से वाहर होते हैं। ७. क्या पूर्व भी ए पश्चिम भे सी मितं व्याणार पश्चिम को को को के लेखा लुसार प्रतिबन्धों का परिस्ताम है ?

ब्रिटिश साप्ताहिक "दि आवजरवर" ने १८ अप्रैल, १६५४ को लिखा था।
"इस व्यापार के सीमित होने का कारण पिश्चम की ओर से लगाए
गए प्रतिबंध नहीं हैं। इसका वास्तिवक कारण यह है कि सोवियत आधिक
व्यवस्था ग्रधिकतर आत्म-निर्भर है। निर्यात के लिए निश्चित प्रवार्थों की मात्रा
बहुत कम होती है। सब आवश्यकताएं ही पूरी करने पर बल देने के फलस्वरूप
विदेशों से व्यापार घट जाता है। ग्रनाज का निर्यात केवल उसी समय बढ़ सकता
है जबकि देश में पशुओं की संख्या में वृद्धि के ग्रान्दोलन को त्याग दिया जाए।
लकड़ी का निर्यात (जो युद्ध से पूर्व की निस्वत केवल दस प्रतिशत रह गई है)।
बढ़ाया जाएगा तो स्वयं देश के ग्रन्दर लकड़ी का ग्रभाव हो जायेगा)।

पूरे सोवियत गुट में गत कुछ वर्षों में ऐसी ग्राधिक क्रान्तियां ग्राई हैं जिनसे मशीनी माल की मांग बहुत बढ़ गई है ग्रीर उनका मूल्य चुकाने के लिए पौरा- णिक निर्यात वस्तुग्रों की योग्यता बहुत कम हो गई है।

द. सोवियत विदेशी व्यापार का राजनीतिक श्रिभप्रायों के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जाता है ?

व्यापार को "कम्यूनिज्म का शस्त्र" किस प्रकार वनाया जाता है, इसका एक उदाहरण ईरान के मामले में मिलता है। वहां सोवियत यूनियन ने व्यापार

के हेतु ईरान की कम्यूनिस्ट संस्था को ग्राधिक सहायता दी।

एक उदाहरण और भी है। दिसम्बर १६४८ में जब रूस द्वारा नियन्त्रित "कोमिनफार्म" से यूगोस्लाविया की कम्यूनिस्ट पार्टी के बहिष्कार को कुछ मास ही हुए थे कि मास्को से घोषणा की गई कि यूगोस्लाविया के साथ रूस का क्यापार १६४६ में गत वर्ष के व्यापार का केवल घाठवां भाग रह जाएगा। पिट्टू देशों ने तत्काल ही रूसी घोषणा का पालन किया। परन्तु उन सबके सांसे प्रयत्न विफल रहे और ग्रायिक प्रतिरोध से टीटो की सरकार को हटाकर मास्कों की ग्रनुयायी नई सरकार को पदारूढ़ करने की नीति ग्रसफल रही।

१९५८ में दोनों देशों के बीच फिर सीमित मात्रा में व्यापार होने लगा है। मास्को ने यूगोस्लाविया को एक भारी रूवल ऋण भी दिया। परन्तु १९५८ में जब रूस ग्रीर यूगोस्लाविया के सम्बन्ध पुनः भंग हुए तो मास्को ने यूगोस्ला-

विया को दिया जाने वाला कर्जा रोक दिया।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri %. कम्यूनिस्ट सरकार व्यापार को ग्राधिक हथियार के रूप में कैसे प्रयोग करती है ?

सोवियत सरकार ग्रीर पिट्ठ देशों ने इन दिनों विदेशों से व्यापार वृद्धि का जो ग्रान्दोलन चला रखा है वह वास्तव में मास्को की इस नीति का ही भाग है कि कुछ देशों में ग्रार्थिक लगाम उनके हाथ में ग्रा जाए, कुछ देशों में महत्वपूर्ण ग्राधिक तथा राजनीतिक सुविधाएँ मिल जाएँ। कम्यूनिस्ट गुट तथा गैर कम्यूनिस्ट देशों के बीच जो व्यापार सन्धियां होती हैं उनमें वह गैर-कम्यू-निस्ट देशों को बहुत ग्राकर्णक तथा प्रलोभक शर्त पेश करते हैं जैसे कम व्याज पर ऋण, लम्बी ग्रवधि के कर्जे इत्यादि।

सोवियत यूनियन तथा अन्य कम्यूनिस्ट सरकारें ये सब कुछ इसलिए करती हैं कि व्यापारिक सौदों से उनका अभिप्राय तत्काल लाभ उठाना नहीं है। बिल्क उनकी इच्छा यह होती है कि गैर-कम्यूनिस्ट देशों में उनका आर्थिक अवेश हो सके और जो देश औद्योगिक रूप में पिछड़े हुए हैं उन पर इच्छानु-सार अपनी सत्ता कायम की जाए।

व्यापार को किसी देशं में आर्थिक-प्रवेश का साधन वह किस प्रकार बनाना चाहते हैं उसका उदाहरण अफगानिस्तान का मामला है। इस देश में कम्यू-निस्ट गुट का आर्थिक तथा राजनीतिक जाल फैलाने के लिए सोवियत सरकार ने कई कटु नीतियों का प्रयोग १९५१ में आरम्भ किया था। इस षड्यंत्र का आरम्भ "इस एकान्तप्रिय" राज्य में गैसोलीन के जखीरों का सिलसिला स्थापित करने के लिए औद्योगिक विशेषज्ञ भेज कर किया।

इसके उपरान्त सोवियत सरकार ने अफगानिस्तान में कई एक कारखाने स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी है। यह सहायता ऋण के रूप में दी गई जिसका भुगतान अफगान माल देकर किया जाएगा। मास्को की आर्थिक सहायता तथा व्यापार की नीतियों के कारण अफगानिस्तान सोवियत आर्थिक बंधनों में बुरी प्रकार जकड़ा गया है और कम्यूनिस्टों के राजनीतिक जोड़-तोड़ में फंस गया है।

अनुमान है कि ५००-६०० सोवियत नागरिक अफगानिस्तान में मौजूद हैं। उनमें राज मजदूर भी हैं श्रीर टैक्नीशियन भी, उनमें से बहुत से प्रायः अफगानी भाषा में वातचीत करते हैं। कुछ सोवियत टैक्नीकल "सलाहकार" कम्यूनिस्ट प्रोपेगण्डा प्रकाशन बांटते हुए भी पाए गए हैं। एक बार ऐसा भी हुआ कि एक नई वन रही विल्डिन में किस्यूनिस्ट निश्वेश्वमार दिश्वाश्योर वाद में उन्हें मिटाना पड़ा।

इस काल में गैर-कम्यूनिस्ट देशों से अफगानिस्तान का व्यापार कम हो गया। व्यापार तथा वस्तुविनिमय की सन्धियों के अंतर्गत अफगानिस्तान का ४० प्रतिशत तक निर्यात केवल रूस को ही रह गया। सोवियत यूनियन से आयात बढ़ रहा है, परन्तु रूस से आने वाले माल का घटिया स्तर प्रमाणित हुआ है।

एक बार यदि कोई गैर-कम्यूनिस्ट देश रूस के आर्थिक नियन्त्रण में आ जाये तो उसे अपने आपको सोवियत ब्लैकमेल के समिपित करना पड़ता है। रूस उसे किसी समय भी डरा-धमका सकता है कि उसने यदि कम्यूनिस्टों के राजनीतिक लक्ष्य पूरे न किये तो उसके साथ तमाम व्यापार सम्बन्ध तत्काल ही तोड़ लिए जाएंगे। एक ऐसे देश के लिए जो स्वतन्त्र देशों से पहले ही व्यापारिक सम्बन्ध लगभग तोड़ चुका हो, यह धमकी भीषण संकट की द्योतक हो सकती है।

१०. कम्यूनिस्ट व्यापारिक धावे का क्या श्रर्थ है ?

कम्यूनिस्ट गुट के व्यापारिक ग्रभियानों से, जिन्हें "शान्तिपूर्ण मुकावले" का नाम दिया जाता है, प्रोपेगण्डा, राजनीतिक तथा ग्राथिक लाभ उठाये जाते हैं। १६५५ से निकट पूर्व, मध्य पूर्व ग्रीर दूर पूर्व में चीनी सोवियत गुट के व्यापारिक ग्रभियान दिन प्रति दिन जोर पकड़ रहे हैं।

नवम्बर, १९५७ में संसार भर से आए हुए कम्यूनिस्ट पार्टियों के नेता भिविष्य के कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए मास्को में एकत्रित हुए। उनकी कांफ्रेंस के वाद से कम्यूनिस्टों के व्यापारिक अभियानों का निशाना विशेषरूप से लेटिन अमरीका और अफ्रीका के नए देश वने हैं। १९५९ में इन देशों से सोवियत व्यापार की मात्रा तो अधिक नहीं थी परन्तु इससे कम्यूनिस्टों के राजनीतिक उद्देश्यों के बारे में अवश्य ही पता चल गया।

कम्यूनिज्म के "व्यापारिक तथा सहायता देने के" आन्दोलनों और इसके राजनीतिक उद्देशों में कितना गहरा सम्बन्ध है इसका एक और उदाहरण देखिये—नवम्बर और दिसम्बर, १९५५ में सोवियत प्रधानमन्त्री बुलगानिन तथा कम्यूनिस्ट पार्टी के सेकेंटरी खु, इचेव ने भारत तथा वर्मा का दौरा किया। उन्होंने इन देशों को व्यापार सम्बन्धी बड़े-बड़े आश्वासन दिये और उनमें प्रोपे-गण्डे और पश्चिमी प्रजातन्त्र देशों के लिये कटु शब्दों का खूब मिश्रण किया। इस प्रेमिर जैव पेपिंग के श्रीविकारी श्रीपने प्रचार तथा प्रसारण, संस्थान जापानी सरकार के विष्द्ध भूठे तथा मिथ्या का तूफान तोल रहे थे। कम्यूनिस्टों के इस प्रोपेगण्डा श्रीभयान के मुख्य उद्देश्य दो थे। टोकियो पर दवाव डाल कर पेपिंग सरकार को स्वीकार करने पर विवश करना। जापान से सैनिक सामग्री के ऋय पर वल देकर यह प्रयत्न करना कि स्वतन्त्र देशों द्वारा चीन का युद्ध उपयोगी सामान वेचने पर प्रतिवन्धों को निष्फल वना दिया जाये।"

११. राजनीतिक उद्देश्यों के स्रतिरिक्त कम्यूनिस्ट व्यापारिक स्रश्रियान के विशेष आर्थिक कारण क्या हैं ?

चूंकि कम्यूनिज्म में विदेशी व्यापार में निजी लाभ का कोई दख्ल नहीं होता, इसलिये कम्यूनिस्ट देशों के सरकारी इजारादार संस्थानों को "लाभ" उसी रूप में होता है कि निर्यात तथा ग्रायात की ग्रावश्यकता चालू सरकारी योजना में भली-भांति निर्धारित हों (दसवां ग्रध्याय देखिए)।

विदेशों के साथ व्यापार सन्धियां सोवियत गुट की अर्थ-व्यवस्था की दो परस्पर विरोधी परन्तु सामान्यरूप से मूल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। पहली आवश्यकता तो यह है कि सोवियत गुट को मूल कच्चा माल चाहिए ताकि औद्योगिक विंकास होता रहे। दूसरे सारे गुट की परन्तु विशेषतया रूस की यह प्रवल इच्छा है कि उसकी सीमित टैक्नीकल दक्षता में वृद्धि हो जो आजकल सैनिक सामान, मीजाईल और भारी उद्योगों में केन्द्रित है और नए क्षेत्रों में (जैसे रसायन, प्लास्टिक्स तथा कृत्रिम रेशे इत्यादि) औद्योगिक उन्नति से लाभ उठाने का अवसर हाथ आ जाए।

सोवियत गुट में रूस सबसे प्रभुताशाली देश है और अपनी मुख्य पोजी-शन के कारण वह अपने पिट्ठू देशों के लिए मूल वस्तुओं का स्रोत है। इन देशों के लिए रूस दलाली का काम करता है। चुनाचे १९५६ में रूस ने १,४०,००० टन से अधिक कच्चे रवड़ का आयात किया और इसका लगभग १७ प्रतिशत भाग चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जमंनी और पोलैण्ड को पुनः निर्यात कर दिया। इसी वर्ष में सोवियत अशोधित तेल के निर्यात का दो तिहाई भाग कम्यूनिस्ट चीन तथा पूर्वी यूरोप को भेजा गया। इसके अतिरिक्त सोवियत हई के नियति स्विष्ट प्रितिस्ति अपिक्षिण अपिक्षिण स्विष्ट स्विष्ट

सोवियत गुट में तमाम निर्यात तथा आयात किए जाने वाले माल का विनिमय मूल्य मास्को ही निश्चित करता है। इसलिए सोवियत व्यापारिक इजारादार नियमित रूप से माल कम दाम पर खरीद कर वही वस्तुएँ अधिक मूल्य पर वेचते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पिट्ठू देशों के नागरिकों को मास्को से व्यापार संबन्ध रखने का दण्ड आवश्यक वस्तुओं के अभाव तथा वहमूल्य के रूप में देना पड़ता है।

मशीनों, फार्मूलों तथा ग्राविष्कारों के जो निर्यात कर्ता पश्चिम में हैं, उन्हें रूस से सदा भय रहता है कि वह केवल एक वार ही ग्राडर देंगे। ग्रीर इसके पश्चात् स्वयं ही वैसी वस्तुएँ बना कर मण्डियों में मुकाबला शुरू कर देंगे क्योंकि रूस ग्रन्य देशों के 'पेटेन्ट' के ग्रधिकारों को स्वीकार नहीं करता।

तरहवां श्रध्यायं कम्यूनिज़म का विस्तार

१. १६३६ में सोवियत विस्तारवादी नीति प्रारम्भ होने के बाद कितने व्यक्ति कम्यूनिस्ट ग्राधिपत्य में लाए जा चुके हैं ?

१६३६ के बाद से ७० करोड़ व्यक्ति वलपूर्वक कम्यूनिस्ट ग्राधिपत्य में लाए जा चुके हैं। इनमें पूर्वी यूरोप के पिट्ठू देशों की जनता, चीन के उपमहाद्वीप के नागरिक, उत्तरी कोरिया, उत्तरी वीयमनाम तथा तिब्बत के लोग भी
शामिल हैं। इस संख्या में रूस के २०.५० करोड़ व्यक्ति मिला कर कम्यूनिस्ट
सरकारों द्वारा शासित लोगों की संख्या नव्वे करोड़ ग्रर्थात् विश्व जनसंख्या का
एक तिहाई है। ग्राज जितनी ग्राबादी चीनी सोवियत कम्यूनिस्म के शासनाधीन है। इसका ग्राधिक्य द्वितीय महायुद्ध के अन्त से लेकर १९५० तक ग्रर्थात्
केवल पांच वर्ष में कम्यूनिस्म का शिकार हुई।

एक ग्रोर कम्यूनिस्ट गुट के कैम्प में करोड़ों व्यक्तियों को बलपूर्वक भरती किया जा रहा या तो दूसरी ग्रोर नव-स्वतन्त्रता प्राप्त देशों की ६५ करोड़ जनता थी जिसने स्वतन्त्र देशों की बिरादरी में शामिल होने को श्रेयस्कर समका। इनमें से ग्रधिकतर दूर पूर्व ग्रीर ग्रफीका के रहने वाले थे। पश्चिमी देशों ने इन नए प्रजातन्त्रों को सहायता दी है ग्रीर उनको प्रोत्साहित किया है।

२. इ.म्यूनिस्ट विस्तार का क्या क्रम रहा है ?

१६३६ की स्टालिन-हिटलर सिन्ध से सोवियत यूनियन को पूर्वी पोलैण्ड पर कब्जा करने और उसको राज्य में मिला लेने का अधिकार मिल गया। इस अभियान के तुरन्त बाद ही रूस ने वाल्टिक के प्रजातन्त्र राज्यों, लिथुआ-निया, लेटेविया तथा एस्टोनिया को भी अनुबद्ध कर लिया। इसके उपरान्त रूस ने रूमानिया को भी अपना एक बड़ा इलाका देने पर विवश कर दिया। फिनलैण्ड ने अपने बलवान पड़ोसी से युद्ध में पराजित होने के बाद दक्षिण में सामरिक महत्व के इलाके रूस को दे दिए और दूर उत्तर में कारेलिया का एक जिला भी छोड़ दिया जिन्हें रूस ने अपने राज्य में शामिल कर लिया। Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangoki ऐसी वितिय महायुद्ध ग्रमी जारी था कि क्रमिलन ने छल ग्रीर कंपेंट की ऐसी चालें चलीं जिनके फलस्वरूप ग्रल्पसंस्यक कम्यूनिस्ट पार्टियां पूर्वी यूरोप के सीमावर्ती राज्यों की शासक वन गई। १६४७ ग्रीर १६५० के बीच पोलैण्ड, चेकोस्लोवािकया, हंगरी, रूमािनया, वल्गारिया ग्रीर ग्रल्वािनया में कठपुतली सरकारें स्थापित हो गई। विलिन का सोवियत क्षेत्र ग्रीर पूर्वी जर्मनी (जिस पर रूसका कब्जा है) भी मास्को के ग्रविकार में ग्रा गए। १६४६ में ग्रुगो-स्लाविया पर मार्शल टीटो के नेतृत्व में कम्यूनिस्टों की सरकार वन गई।

उधर उत्तरी कोरिया पर कब्जा करने वाली रूसी सेना ने वहाँ पर कठ-पुतली सरकार बना दी। चीनी कम्यूनिस्ट सोवियत सैन्य सहायता से १६४६-१६५० में पूरे चीनी उपमहाद्वीप पर ग्रपना ग्राधिपत्य जमाने में सफल हो गए। उत्तरी बीयतनाम की सहायता चीन ने की ग्रीर परिणामस्वरूप वहां भी कम्यू-निस्ट सरकार स्थापित हो गई।

१६३६ के बाद से एक करोड़ चालीस लाख वर्ग मील इलाका कम्यूनिस्टों के माधिपत्य में माया है। यह सारा इलाका कुछ तो सशस्त्र बल से ग्रीर कुछ षड्यन्त्र, तोड़-फोड़ तथा ग्रातंक फैला कर हथियाया गया है। १६५६ में पेपिंग की विस्तारवादी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष हो गई। इसने तिन्वत की ग्रांतरिक स्वाधीनता छीन ली। भारत के सीमावर्ती इलाकों पर ग्रपना ग्रधिकार जताना मारम कर दिया ग्रीर दक्षिण-पूर्वी एशिया के लिए चिरस्थायी खतरा वन गया।

३. क्या किसी देश ने कम्यूनिस्ट शासन प्रणाली को स्वेच्छा से ग्रहण किया है?

लोकमत के आधार पर आज तक सोवियत यूनियन सहित किसी भी देश ने कम्यूनिस्ट शासन को स्वीकार नहीं किया। वास्तव में जब कभी जनता को स्वेच्छा से सरकार चुनने का अवसर मिला है उसने कम्यूनिएम को ठुकराया है। प्रथम महायुद्ध के उपरान्त हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया में ग्रामचुनाव में यही हुआ।

कम्यूनिस्टों को कहीं-कहीं स्थानीय विजय ग्रवश्य हुइ है। मिसाल के तौर पर गोएटेमाला में एक "क्रांतिमयी स्थिति" में कम्यूनिस्टों ने वड़ी गड़बड़ की। (पन्द्रहवां ग्रध्याय देखिए)। इसके उपरान्त सरकार में कम्यूनिस्टों का प्रभाव बढ़ गया। परन्तु जून, १६५४ में एण्टी कम्यूनिस्ट (कम्यूनिस्ट विरोधी) दल ने ग्रकस्मात् घावा बोलकर सरकार पर कब्जा कर लिया। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri भारत में केरल प्रदेश में कम्यूनिस्ट पार्टी ने १९५७ के आमचुनाव में ३५ प्रतिशत से भी अधिक मत प्राप्त किए और स्वतन्त्र विधायकों के सहयोग से प्रदेश में सरकार वनाने में सफल हो गए। परन्तु जब कम्यूनिस्ट सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था को अधिकार में लेने का प्रयास किया तो उसका असली रूप सामने आ गया। १६५६ की वसन्त ऋतु तक इसकी सर्वाधिकारी वृत्ति प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात हो चुकी थी। सारे प्रदेश में शासन-व्यवस्था विगड़ गई। ३१ जुलाई को केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश सरकार को पद-मुक्त कर दिया। फरवरी १६६० के विशेष चुनाव में कम्यूनिस्ट केरल विधान सभा में पहले की अपेक्षा केवल आधे सदस्य ही सफल करा सके। (आठवां अध्याय देखिए) ४. पूर्वी यूरोप के देश, पिट्ठ देश क्यों कहलाते हैं?

पूर्वी यूरोप के जो देश कम्यूनिस्टों के ग्रधीन हैं उन्हें पिट्ठू देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सोवियत संघ की ग्रर्थ-व्यवस्था, राजनीति तथा सैनिक व्यवस्था से सम्बद्ध हैं।

यह कठपुतली सरकारें नाम को लोकतन्त्र कहलाती हैं परन्तु वे किसी प्रकार भी गणतंत्र राज्य कहलाने के पात्र नहीं वयों कि वहां की जनता का सरकार के निर्वाचन में कोई दख्ल नहीं और नहीं वह सरकारी नीतियों के निर्धारण पर प्रभाव डाल सकती है।

इन कठ पुतली सरकारों की राष्ट्र तथा परराष्ट्र नीतियों का निर्देशन मास्कों से होता है। राष्ट्र के कम्यूनिस्ट नेता मास्को 'लाईन' पर चलते हैं।

पोलैण्ड में १९५६ में पार्टी के झान्तरिक संघर्ष के फलस्वरूप एक नई कम्यूनिस्ट सरकार स्थापित हुई जिसने समाजवाद (कम्यूनिष्मं) के "नव, स्वतंत्र पथ" पर चलने की शपथ ली परन्तु १९५९ तक यह सरकार मास्को लाईन के निकट झा गई। फिर भी झन्य कम्यूनिस्ट देशों की अपेक्षा पोलिस्तानी जनता को झाज भी अधिक स्वतन्त्र्य प्राप्त है।

४. क्या युगोस्लाविया भी रूस का पिट्ठ देश है?

युगोस्लाविया रूस का पिट्ठू देश नहीं है। १६४७ में युगोस्लाव कम्यूनिस्ट पार्टी कोमिनफार्म की सदस्य थी। परन्तु एक वर्ष के पश्चात् ही इसका बहिष्कार कर दिया गया। इसके कारण नीति के मतभेद थे। विशेष कारण यह था कि टीटो स्तालिन के भ्रादेश तथा निर्देशानुसार चलने को राजी नहीं थे। तबसे युगोस्लाव सरकार भ्रपनी राष्ट्र तथा परराष्ट्र नीतियों का स्वतंत्रता से निर्धारण करती है। ६. पूर्वी खूबोफ्रन्में ख्रासप्रसंख्यकः क्रान्स्यूनिक्यः आसासक्षणः क्रान्यने से किस प्रकार सफल हुए ?

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् फैले विष्लव में पश्चिमी गणतंत्र राज्य तेजी से सैन्य वियोजन में लगे हुए थे ताकि लाखों नवयुवक सैनिकों को शान्तिपूर्ण व्यव-सायों में लगाया जाए श्रीर उनकी सरकारें श्रपनी शक्ति युद्ध में हुए विष्वंस तथा विनाश के स्थान पर पुनर्निमणि में लगा सकें।

परन्तु सोवियत संघ ने अपनी सेनाओं को मुक्त नहीं किया विलं पूरे पूर्वी यूरोप में उन्हें फैला दिया। कहीं वह अधिपत्य सेना के रूप में उपस्थित थी, कहीं सीमाओं पर नियुक्त थी और स्वतंत्र राज्यों के लिए खतरा वनी हुई थी।

लाल सेना वास्तव में एक और सोवियत "सेना", की सशस्त्र सहायता कर रही थी। इस दूसरी "सेना" में कम्यूनिस्ट एजेन्ट, गुप्त पुलिस के सिपाही, आतंकवादी, कम्यूनिस्ट षड्यंत्र के स्थानीय अनुयायी जो उन्हीं देशों के वासी थे, सब शामिल थे। धीरे-धीरे इस सेना ने सब विरोधियों को कुचल डाला। (सोलहवां अध्याय देखिए)

७. क्या पश्चिमी गरातन्त्र राज्य पूर्वी यूरोप के गैर कम्यूनिस्टों की रक्षा करने योग्य नहीं थे ?

पित्रचमी सरकारें उन महत्वपूर्ण सिन्धयों पर भरोसा किए बैठी रहीं जिन पर सोवियत प्रधानमंत्री स्तालिन ने याल्टा तथा पोस्टडम में हस्ताक्षर किए थे और इनके अनुसार नाजियों के भूतपूर्व अधिकृत देशों की स्वाधीनता और प्रादेशिक तथा राजनीतिक अखण्डता की जमानत दी गई थी। जमेंनों द्वारा परास्त जनता को स्तालिन ने वार-बार आश्वासन दिलाया था कि रूस में उनकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगा।

१६४२ के एक "आज का आदेश" में प्रधानमंत्री 'स्तालिन ने कहा था: "हमारा यह युद्धोहेश्य न है और न हो ही सकता है कि हम अपनी ओर सहा-यता के लिए देख रहे स्लावों तथा यूरोप की अन्य दास बनाई गई जनता पर अपनी इच्छा तथा अपना शासन लागू करें। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हिट-लर के अत्याचार से मुक्ति प्राप्त करने के संघर्ष में उनकी सहायता करें और उसके पश्चीत् उन्हें स्वेच्छा से सरकार के निर्वाचन की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए।"

पश्चिमी देशों ने स्वतंत्र निर्वाचन के संबंध में रूस द्वारा याल्टा तथा

पोस्टडम Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पोस्टडम सन्धियों के उल्लंधन का वार-वार विरोध किया परन्तु रूस ने सदैव यही उत्तर दिया कि पश्चिमी देशों ने यदि कोई हस्तक्षेप किया तो इसे "राष्ट्रीय प्रभुसत्ता" पर श्रतिक्रमण समभा जाएगा। साथ-ही-साथ क्रेमलिन स्वयं सिक्रय रूप से इन देशों की वैध सरकारों का तख्ता उलटने के लिए पड्यंत्रों में लगा रहा।

जदाहरण के लिए, १६४५ में फरवरी के अन्त में सोवियत विदेशी मामलों के उपकमिसार स्वर्गीय आदी विशिस्की ने स्तालिन के निर्देश के अनुसार रूमा-निया के नरेश माईकल से मांग की कि प्रधानमंत्री के पद पर रूस के पिट्ठू पेट्रो गरोजा को नियुक्त किया जाए। नरेश को यह मांग स्वीकार करने पर विवश कर दिया गया और आगामी वर्ष के अन्त तक गरोजा ने कम्यूनिस्ट प्रतिरक्षा सैनिक दुकड़ियों की सहायता से नरेश को राज त्याग के लिए विवश कर दिया।

द. कम्यूनिस्टों ने पूर्वी यूरोप में राज सत्ता प्राप्त करने के लिए किन-किन पर्दों का दुरुपयोग किया ?

कम्यूनिस्टों ने अपना सारा जोर इस बात पर लगाया कि प्रमुख पदों पर अपने सबस्य या अनुयायी नियुक्त कर दिए जाएं। गृह मंत्रालय जो गुप्त पुलिस को भी कंट्रोल करता है, न्याय मंत्रालय जो न्यायालयों को अपने अधिकार में रखता है, और सूचना तथा प्रसार मंत्रालय जिसके द्वारा प्रेस, रेडियो इत्यादि पर नियंत्रण रखा जाता है, उनकी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। कम्यूनिस्टों ने पहले इन पर अधिकार किया। जब्त की हुई भूमि के पुनवितरण के लिए कृषि मंत्रालय को भी अपने कब्जे में लेना कम्यूनिस्टों के लिए आवश्यक था।

मंत्रालयों और भिन्त-भिन्त विभागों के ग्रतिरिक्त ट्रेड यूनियनिषम भी कम्यू-निस्टों के लिए कुछ कम महत्व नहीं रखता। पहले वह मजदूर संगठनों में किसी-न-किसी तरह घुसकर ग्रपने पांव जमाते थे और उनको पूरी तरह ग्रपने नियंत्रण में ले लेते थे। इसके उपरान्त वे इन्हें राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग में लाते हैं।

६. कम्यूनिस्टों ने चुनाव को अपने लिए अधिकार-प्राप्ति का साधन कैसे बनाया ?

द्वितीय महायुद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के केवल दो देशों में चुनाव किसी हद तक स्वतन्त्र वातावरण में हुए हैं। हंगरी में मई. १६४५ के चुनाव में कम्यू-निस्टों ने कुल सतों में केवल १७ प्रतिशत मत प्राप्त किए। चेकोस्लोवांकिया में मई, १६४६ इन्हें भारत्मा हों निम्मू निस्कास दिन्स निम्मू निस्न से विभागों में कम्यूनिस्ट पहले ही पहुँच चुके थे। विरोधी पार्टियों को उन्होंने पड्यंत्र और छल-कपट से दवा रखा था।

फरवरी, १६४८ में कम्यूनिस्टों ने अकस्मात् आक्रमण द्वारा चेकोस्लोबा-किया की सरकार का तख्ता उलट दिया। इससे भलीभाँति स्पष्ट हो गया कि मतदाताओं पर इनका प्रभाव क्षीण पड़ गया और मतदान द्वारा उन्हें अपनी सफलता का विश्वास नहीं रहा था।

पूर्वी यूरोप में और भी जितने चुनाव हुए उनमें कम्यूनिस्टों ने छल-कपट और हिंसा से अधिक काम लिया। उनके इशारे पर विरोधी दलों के सदस्यों पर अनुचित आरोप लगाए गए, उन पर मुकदमे चलाए गए, वह गिरपतार हुए और कारावास में डाल दिए गए। सशस्त्र गुण्डों ने गैर-कम्यूनिस्टों के जलसों में हड़बोंग मचाई और तितिर-वितिर कर दिया। विरोधी दलों के मुख्य कार्या-लयों पर हमले किए, उन्हें लूट लिया गया या उनकी पूर्ण तालावन्दी कर दी गई।

कठपुतली कम्यूनिस्ट शासकों ने नित नए हीले बना कर नागरिकों की बड़ी संस्था से मताधिकार छीन लिया । विरोधी पार्टियां अवैध घोषित कर दीगई, बोट की पिंच्यों में गड़बड़ और वेईमानी की और चुनाव परिणामों में इच्छा-नुसार परिवर्तन कर दिए।

१०. पिट्ठू देशों में जनता को राष्ट्र-प्रेम की भावनाएँ प्रकट करने की आज्ञा कहाँ तक है ?

सोवियत नीतियों से राष्ट्रवाद का जब भी टकराव हुआ है पिट्ठू देशों की कठपुतली सरकारों ने इस पवित्र परन्तु "अनिश्चित" भावना को कुचल दिया। इन देशों में यदि किसी कम्यूनिस्ट नेता ने मास्को के हितों पर अपने देशों के हितों को श्रेष्ठ माना तो उसका पद घटा दिया गया या पयश्रष्टता का आरोप लगा कर मुकदमा चला कर टिकाने लगा दिया।

सोवियत यूनियन की कम्यूनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस में जबसे स्तालिन-वाद के विरुद्ध ग्रीभयान ग्रारम्भ हुग्रा है, ग्रीर विशेषतया जबसे पार्टी सेक्रेटरी निकिता खूड्चेव ने स्वयं भूतपूर्व डिक्टेटर की निन्दा की है, पिट्ठू देशों में मास्को के वर्तमान नेताग्रों की ग्रालोचना कभी कभार सुनने में ग्रा जाती है। १६५१६ की भीष्म ऋतुम्ब्रिक भारतिचिनि कुछ बंदी देवी सी थी परन्तु पत-भड़ के आने तक आलोचना पब्लिक तीर पर और कठोरता से की जाने लगी।

पोलैण्ड तथा हंगरी की कम्यूनिस्ट पार्टियों में रूस विरोधी भावनाएं प्रवल हो गईं। पोलैण्ड में पार्टी के नेतृत्व में तुरन्त ही परिवर्तन किए जाने से उफ़ान दक गया। परन्तु हंगरी में रूस तथा कम्यूनिक्म के विरुद्ध जनता के रोष तथा कोध ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया। परन्तु रूस के आतंक तथा हिंसा ने राष्ट्रवाद का यह दीप अधिक समय तक जलने न दिया।

११. सोवियत उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है ?

कठपुतली कम्यूनिस्ट देशों पर मास्को के आधिक दबाव तथा आधिपत्य को ही सोवियत उपनिवेशवाद का नाम दिया गया है। इस परिभाषा में वह इलाक़े भी शामिल हैं जो सोवियत गुट से बाहर होने पर भी किसी न किसी प्रकार रूस के आधिक राजनीतिक तथा सैन्य नियंत्रण में हैं।

वोलगेविक कान्ति के वाद ही से सोवियत सीमाओं से बाहर दूर, पूर्व में

रूस राजनीतिक तथा सैन्य दवाव डालता रहा है।

कम्यूनिस्ट सरकार दावा तो यह करती है कि इसने एशिया के प्रति जारों की साम्राज्यवादी नी ति का परित्याग कर दिया है परंतु वास्तव में रूस ग्रब भी उन नीतियों में, कोई परिवर्तन किए बिना ही उन पर चल रहा है। चीन में कम्यू-निस्ट क्रांति की सफलता के बाद भी रूस ने विस्तारवाद की नीति नहीं छोड़ी।

चीनी वाहरी मंगोलिया में रूस द्वारा हस्तक्षेप तथा प्रवेश १६२० में ही आरम्भ हो गया था। १६२४ में सोवियत सहयोग से मास्को द्वारा ट्रेंड मंगोल कम्यूनिस्टों ने "मंगोल लोक गणतन्त्र" का स्थापन किया। १६४५ तक रूस वाहिरी मंगोलिया पर चीन का नाममात्र अधिराज्य स्वीकार करता रहा परन्तु उसी वर्ष लोकमत का स्वांग भर कर मंगोलिया को पूर्णतया स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। यह "गणतंत्र" अब रूस का अर्घ उपनिवेश है। बाहरी मंगोलिया की इस स्थित को स्वयं चीनी कम्यूनिस्ट सरकार को भी १६५२ में स्वीकार करना पड़ा।

बाहरी मंगोलिया का समीपवर्ती टन्तूटवा, भी चिरसमय तक चीन का ही भाग था। परन्तु १६२० में वह भी सोवियत हस्तक्षेप का निशाना बना। १६४४ में रूस ने इसको पूरी तरह सोवियत संघ में शामिल करके अखण्ड भाग बना दिया। इसे टोवियन आत्मशासित राज्य का नाम दिया। इसे कठपुतली राज्य का दर्जा भी नहीं दिया गया। चीन का जिल्ह्यांगु प्रदेश अभि सुरू में सोवियत विस्तार क्रम में यंकित था परन्तु १९५४ के य्रन्तिम चरण में रूस वहां पर ग्रपने याथिक स्वार्थ चीन के हित में छोड़ने पर राजी हो गया था।

१६४० और १६४५ के बीच में रूस ने तीन बालटिक रियासतों को अपने राज्य में मिला लिया और रूमानिया, पूर्वी पोलैण्ड, पूर्वी चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी प्रशिया और फिनलैण्ड के कुछ भाग भी अपने आधिपत्य में ले लिए। युद्ध से पूर्व इन इलाकों की जनसंख्या दो करोड़ चालीस लाख से भी अधिक थी।

इसके ग्रांतिरिक्त १९४६ और १९४८ के बीच में सोवियत यूनियन ने पूर्वी जमंनी ग्रीर पूर्वी यूरोप के पांच देशों का दर्जा घटा कर उन्हें राजनीतिक तथा ग्रांथिक रूप में ग्रपने ग्राधीन बना लिया। इस पूरे इलाके की कुल जनसंख्या कोई नौ करोड़ तीस लाख थी।

१२. रूस की कम्यूनिस्ट पार्टी का अन्य देशों की कम्यूनिस्ट पार्टियों से क्या

सम्बन्ध है ?

युगोस्लाव कम्यूनिस्ट पार्टी को छोड़कर संसार की सब कम्यूनिस्ट पार्टियां क्सी कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार चलती हैं। (चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी कुछ मामलों में सी० पी० एस० यू० की अनुयायी नहीं है)।

१६४७ और १६४५ के दौरान में सी० पी० एस० यू० विश्व आन्दोलन की अगुआयी कोमिनफामं द्वारा करती थी। इस संगठन में रूस, फांस, इटली

भीर पांच पिट्ठू देशों के प्रतिनिधि थे।

ग्रप्रैल १६५६ में कोमिनफार्म को तोड़ दिया गया। परन्तु बोलशेविक क्रान्ति की चालीसवीं वर्षगांठ के ग्रवसर पर १६५७ में कम्यूनिस्ट नेताग्रों का ग्रिविवेशन मास्को में हुग्रा ग्रौर उसमें सी० पी० एस० यू० ग्रौर ग्रन्य कम्यूनिस्ट पार्टियों के परस्पर सम्बन्ध नए ढंग से निश्चित किए।

इस प्रधिवेशन के उपरान्त "वारह पार्टी कार्यक्रम" घोषित किया गया। इसमें कम्यूनिजम के विश्व उद्देश्यों का वर्णन था और एक "शान्ति ज्ञापन पत्र" भी शामिल था जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिजम में सी० पी० एस० यू० के पथ-प्रदर्थन की सराहना की गई थी। ज्ञापन-पत्र पर ६५ पार्टी नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। १६५७ के अधिवेशन के उपरान्त सी० पी० एस० यू० और इसकी अनुयायी पार्टियों ने "संशोधनवाद" अथवा स्वतन्त्र साम्यवाद की पद्धित की निन्दा की और उसे कम्यूनिस्ट आन्दोलन के लिए "घोर खतरा" घोषित किया।

१३. राजमीक्षिकः संस्थात्रमें कैः क्रितिशिक्तः की सम्बद्धेमः से संस्थात्रों को कम्यू-निस्ट स्वतंत्र देशों में मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के प्रचार का साधन बनाते हैं?

अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए कम्यूनिस्ट बहुत-सी अग्र संस्थाएं बनातें हैं ताकि कम्यूनिज्म की विचारधारा का प्रचार किया जा सके। इसके अतिरिक्त वह सुधार वादी आ्रान्दोलनों में भी घुस जाते हैं और उन्हें अपने राजनीतिक विया सैद्धान्तिक हितों के लिए प्रयोग करते हैं।

"लेननिष्म की आधार शिला" में स्टालिन ने लिखा था। 'पूंजीवादी प्रशा-सन के अधीन क्रान्तिकारी कार्यरीति में सुधारवादी आन्दोलनों में शामिल हो कर प्रशासन को खण्डित करना और क्रान्ति को सुदृढ़ बनाना भी शामिल है।"

१४. क्या कम्यूनिस्ट अपनी बात से या घारएा से कभी पीछे हटते हैं ?

"सी० पी० एस० यू० का संक्षित इतिहास" में लिखा है—"अक्तूबर की क्रान्ति की अविध में लेनिन ने पार्टी को सिखाया कि यदि स्थिति अनुकूल हो तो साहस के साथ अभय होकर आगे बढ़ा जाए। बैस्ट-लिटोविस्क शान्ति के दिनों में (जबिक सोवियत संघ ने जमंनी को बहुत-सी सुविधाएं दीं।) लेनिन ने शिक्षा दी थी कि जब शत्रु शक्तिशाली हो तो किस प्रकार कमानुसार पीछे हटना चाहिए और इसके पश्चात् नए हमले के लिए पूर्ण शक्ति से तैयारी की जाए।"

इस प्रकार, यदि दवाव इतना ग्रधिक हो कि कम्यूनिस्ट न तो इस पर विजयी हो सकें ग्रौर न ही प्रतिरक्षा के समर्थ हों तो वह कुछ समय के लिए पीछे हटजाते हैं। परन्तु उनका पश्चगमन कपटपूर्ण होता है। इस ग्रविध को वह नए हमले की तैयारी के लिए प्रयोग करते हैं।"

१५. क्या सब कम्यूनिस्ट समाज सिद्धान्तों पर विश्वास रखते हैं ?

सोवियत यूनियन, पूर्वी यूरोप और दूर पूर्व के सभी कम्यूनिस्ट देश मार्क्स-वाद-लेनिनवाद के श्राम सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं, परन्तु कम्यूनिस्ट चीन में कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों में कुछ संशोधन हुआ है। वहां इन्हें कम्यूनिस्ट चीन के नेता माग्रोत्से तुंग के नाम पर "माग्रोवाद" का नाम दिया गया है।

माम्रोबाद, मानर्सवाद-लेनिनवाद का कुछ परिवर्तित रूप है। इसमें उन विशेष समस्याम्रों को भी दृष्टिगोचर रखा गया है जिनका सामना पेपिंग सर-कार को करना पड़ता है मौर यूरोप की समस्याम्रों से भिन्न हैं। किसी हद तक यह भेद इसलिए मिनवार्य थे क्यों कि चीन ग्रौद्योगिक तौर पर पिछड़ा हुग्रा देश है ि श्रीस्ट बहुत प्रश्निक कि सिद्धान्त के ग्रनुसार "श्रमिक वर्ग की क्रांति का पथ-प्रदर्शन" ग्रौद्योगिक श्रमिक वर्ग ही को करना था। कम्यूनिस्ट चीन में किसानों की स्थित को तथा किसानों की समस्याग्रों को ग्रधिक महत्व दिया जाता है।

चीन में अधिकार तथा प्रभाव का केन्द्र, प्रथा अनुसार कुटुम्व ही रहा है। इसके पश्चात् गाँव की वारी आती है। इसलिए चीनी कम्यूनिस्टों ने पहले कुटुम्व पर ही वार किया है और कोशिश की है कि परिवार के संगठन का विच्छेद हो जाए। १६५६ में उन्होंने कम्यून सिस्टम चालू कर दिया था। इसके अन्तर्गत पचास करोड़ व्यक्ति चींटियों की भाँति समाजी जीवन व्यतीत करने पर विवश हैं (दूसरा अध्याय देखिए)।

१६. कम्यूनिस्ट प्रशासन के अधीन देशों में विद्रोह कहाँ तक हुए हैं ?

१६२० के वाद के दशक के प्राथमिक चरण को छोड़कर रूस में कोई संगठित विद्रोह नहीं हुआ है। १६२१ में एक भयंकर उपद्रव हुआ था। पेट्रोग्राड से
वाहर करोनस्टाफ में नौसेना का एक दुर्ग था। वहां के सैनिकों ने लेनिन को
सत्तारूढ़ होने में सहायता दी थी। १, मार्च, १६२१ को उन्होंने मांग की कि
"गुप्त मतदान द्वारा दोवारा चुनाव कराया जाए।" इसके अतिरिक्त उन्होंने
भाषण, मुद्रण तथा श्रमिक संगठन के स्वातंत्र्य की मांग भी की थी। उन्होंने
इस बात की भी अभियाचना की थी कि सशस्त्र सेना में राजनीतिक किमसार
न रखा जाए। करोनस्टाट के विद्रोह को गुप्त पुलिस तथा सोवियत सेना के
६०,००० सिपाहियों ने निर्दयता से कुचल दिया। विद्रोही नौसैनिकों और उनके
परिवारों को कत्ल कर दिया गया। सख्त मुकाबले के उपरान्त १७, मार्च को
करोनस्टाफ ने हिथयार डाल दिए।

१६२६ से १६३२ तक खेतों के जबरी समूहीकरण का युग था, स्थानीय किसानों तथा ग्रामवासियों ने इस ग्रान्दोलन को रोकना चाहा। विरोधियों के लाखों परिवारों को खत्म कर दिया गया या जबरी श्रम के कैम्पों में भेज दिया गया।

पूर्वी यूरोप में पहली बार उपद्रव १७ जून, १९५३ को पूर्वी बॉलन में जनता के बलवे के रूप में हुआ जो कि तुरन्त ही पूर्वी जर्मनी के अनेकों औद्यौ-गिक केन्द्रों में फैल गया। फिर २८ से ३० जून, १९५६ को पोजान, पोलैंड में तीनि स्मिन दिन्न किस्किन एक्षां ि इस्मिनी किस्रोही का प्रारम्भ का प्रारम्भ का प्रदर्शनों से हुमा ग्रीर फिर ग्रकस्मात् ही वड़े पैमाने पर जनता की ग्रीर से दंगे फसाद होने लगे।

हंगरी में स्वतन्त्रता संग्राम २०-२२ ग्रक्तूवर को विद्यार्थियों के बान्तिपूर्ण 'प्रदर्शन से प्रारम्भ हुग्रा ग्रीर कुछ दिनों में ही विद्रोह की ज्वाला बुडापेस्ट से निकल कर सारे देश में फैल गई। लड़ाई के दौरान में हजारों हंगेरियन ग्रीर कुछ सोवियत सैनिक घायल तथा हताहत हुए। ३ नवम्बर को सोवियत सैनिकों ने वड़ी कूरता तथा वहशीपन से इस विद्रोह को दवा दिया। सोवियत सेना सारे देश में फैल गई ग्रीर इसे ग्रपने ग्राधिकार में ले लिया।

१६५६ की वसन्त ऋतु के अन्त में चीनी कम्यूनिस्ट सरकार के विरुद्ध तिब्बत में विद्रोह हुआ। बहुत दिनों तक गोरिला युद्ध का सिलसिला जारी रहा। १६५६ तक यह उपद्रव बढ़ते-बढ़ते सारे देश में फैल गया। (दूसरा अध्याय देखिए)।

१७. सोवियत केन्द्रीय सरकार का मध्य-एशिया की गैर-रूसी जनता से क्या

सम्बन्ध है ?

इरान, ग्रफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत के उत्तर में मध्य-एशिया का चालीस लाख वर्गमील क्षेत्र रूसी ग्रधिराज्य में है। इनमें सोवियत गणतन्त्र सम्मिलित हैं जिनकी कुल जनसंख्या लगभग एक करोड़ सत्तर लाख है।

सोवियत यूनियन में जो "गणतंत्र" सिम्मिलत हैं, उन्हें संविधान के अन्तर्गत वहुत से अधिकार प्राप्त हैं। अधिकारों की सूची लम्बी है और उपरिष्ट रूप में प्रभावशाली भी। इन अधिकारों में गणतंत्रों को सोवियत यूनियन से अलग होने का अधिकार भी शामिल है। परन्तु वास्तविक रूप में इन अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक स्थान पर रूसी लोगों को और रूसी भाषा को श्रेष्ठ समक्ता जाता है। स्थानीय तौर पर यदि कहीं राष्ट्रवादी भावना उजागर प्रतीत होती हो अथवा इस्लाम के अनुयायी बढ़ने लगें तो उन्हें रूढ़िवाद का नाम देकर कुचल दिया जाता है। इस युग के असली उपनिवेश का यही कारनामा है।

१८. कम्यूनिस्ट चीन में राष्ट्रीय ग्रल्पसंख्यक जातियों के साय कैसा

व्यवहार होता है ?

कम्यूनिस्ट चीन में कोई साठ ग्रल्प संख्यक जातियां हैं जिनकी कुल जन-संख्या साढ़े तीन करोड़ से भी ग्रधिक है। यह सब (चीन वंश) हान की प्रजा हैं। ऐतिद्वासिक्ष्व महत्त्र प्रख्ते बाकी सत्त्व "सहस्य आह्यसंख्यक आहियों" में मंगोल मुस्लमान तथा तिब्बती शामिल हैं और इनकी जनसंख्या एक करोड़ है। इन अल्प संख्यक जातियों ने अपनी आंखों के सामने अपनी सांस्कृतिक विरासत का विच्वंस होते देखा है।

१६४६ में चीन के ग्रवामी गणतंत्र के "ग्रधिकार पत्र" के ग्रन्तर्गत सांभा प्रोग्राम ग्रुक हुग्रा जिसके ग्रधीन ग्रत्प संख्यक जातियों की स्वतंत्रता ग्रौर स्वायत्त शासन को सीमित कर दिया गया। यद्यपि दिखावे के लिए पेपिंग सरकार ने ग्रत्प संख्यक जातियों के लिए स्वायत्त शासित प्रदेश स्थापित कर रखे हैं जिन्हें सैद्धान्तिक रूप में ग्रान्तरिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है, परन्तु इन शासन इकाइयों पर भी हान या उनके कठपुतली व्यक्तियों का ही नियंत्रण है।

स्वायत्त शासन को भंग करने का क्रूर उदाहरण तिब्बत में मिला जहां पर प्रादेशिक स्वतंत्रता को १९५६ में खत्म कर दिया गया और हान ग्राक्रमणकारियों ने पेपिंग की सेना के सहयोग से तिब्बतियों पर बहुत अत्याचार किए हैं। (देखिए अध्याय नम्वर २) १६५६-१६६० में तिब्बतियों और अन्य राष्ट्रीय अल्पसंस्यक जातियों के लाखों व्यक्तियों का पुनर्वास बहुत बड़े पैमाने पर किया गया।

चौदहवां ग्रध्याय शान्तिपूर्णा सहग्रस्तित्व ग्रोर सैन्यवाद

१. कम्यूनिस्टों की परिभाषा में ज्ञान्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व का क्या ग्रर्थ है ?

कम्यूनिस्ट सिद्धान्त का ग्राधार इस विश्वास पर है कि "पूँजीवाद" ग्रीर "समाजवाद" के बीच संघर्ष ग्रटल है। मार्क्स ग्रीर लेनिन तो खुले तौर पर क्रान्तिकारी थे ग्रीर नादघ्वनि से कहते थे कि "पूंजीवादी प्रशासन पद्धति" को खत्म कर देना चाहिए, परन्तु स्तालिन ग्रीर उसके ग्रनुवर्तियों का भी यही विचार था कि सोवियत स्टेट का ग्रिधिपत्य ही "समाजवाद" की विजय है। इस सिद्धान्त को "शान्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व" तथा "शान्तिपूर्ण मुकाबले" के फार्मूलों ने कुछ समय से घुंबलके में घकेल दिया है।

१६१६ में लेनिन ने घोषणा की कि "कल्पना भी नहीं की जा सकती कि सोवियत गणतंत्र के संग साम्राज्यीय रियासतें भी बहुत समय तक उपस्थित रहेंगी। ग्रन्त में इनमें से किसी एक को विजयी होना है और जो विजय पाएगी उसी का ग्रस्तित्व रहेगा। इससे पूर्व सोवियत गणतन्त्र और पूंजीवादी राज्यों के बीच भयानक टक्कर होती रहेगी।" वर्तमान सोवियत नेता सरकारी तौर पर इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते।

१६३१ में शुरू होने वाली म्राक्रमात्मक कार्रवाइयों के एक दीर्घ क्रम के परचात् स्तालिन ने अपने प्रवक्ता जार्जी मालिनकोव द्वारा संसार को विश्वास दिलाया कि सोवियत यूनियन "पूंजीवाद से शान्तिपूर्ण मुकाबले" के म्रतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। सोवियत यूनियन का कोई ऐसा विचार नहीं कि जीवन के प्रति मना सिद्धान्त ग्रथवा म्रपनी म्राधिक पद्धति किसी पर बलपूर्वक ठोंसे।"

फरवरी, १६५६ में सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस में पार्टी सेक्नेटरी निकिता खूड्चेव ने भी ऐसी ही भावना प्रकट की थी। "यह सोचना हास्यस्पद है कि क्रान्ति भादेश के भ्रनुसार तैयार की जा सकती है।" परन्तु पूर्वी यूरोप में १९४४-४८ की क्रान्तियां "भादेशानुसार ही लाई गई थीं। यादेश कोतुन्ताहोत अपस्क्रों अधीर बन्नसकेत एआएम स्रीडन विद्रहरू से edangotri

इसलिए ग्राज सोवियत "सामूहिक नेतृत्व" यदि "शान्तिपूर्ण मुकावले" पर बल डाल रही है ग्रीर इसके साथ ही संसार के बहुत से क्षेत्रों में कम्यूनिस्टों की तोड़-फोड़ की कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो इसे भी कम्यूनिस्टों की कूटनीति ही समभना चाहिए, जिसे ग्रावश्यकतानुसार किसी समय भी वदला जा सकता है। २. क्या सोवियत युनियन की "शान्ति ग्रायोजना" कोई ताजा ग्राविष्कार है?

बोलशेविक क्रान्ति के उपरान्त ही से सोवियत नेता (कम्यूनिस्ट ढंग के) "शान्ति" का ढोल पीटते रहे हैं। इसके साथ मास्को की लालसा का प्रदर्शन भी होता रहा है। इसने छोटे-छोटे पड़ोसियों को हड़प करके अपने राज्य का विस्तार किया है। इसके लिए इसने इच्छा तथा आवश्यकता अनुसार सैन्य शक्ति, पड्यन्त्र तथा तोड़-फोड़ सभी का प्रयोग किया है।

३. कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों में "शान्ति" का क्या महत्व है ?

१६१६ में लेनिन ने लिखा था: "यदि शान्ति ग्रायोजना जनता को क्रांति की ग्रावस्यकता तथा महत्व नहीं जताती, क्रान्ति में जनता के संघर्ष को सह-योग देने ग्रीर संघर्ष को सुदृढ़ वनाने के लिए उत्साहित नहीं करती, तो वह जनता के लिए घोखा है।

१६२८ में कम्यूनिस्ट इंटरनैशनल की विश्व कांग्रेस में "शान्ति" के प्रति सोवियत नीति की व्यास्या इस प्रकार की गई।

"रूस की विश्व शान्ति का उद्देश्य रूस के शासक वर्ग ग्रर्थात् सर्वहारा वर्ग के हितों की रक्षा करना ग्रीर सर्वहारा वर्ग की डिक्टेट्रशिप के सारे सम-थंकों को ग्रपने अंडे तले इकट्ठा करना है।"

"साम्राज्यवादी देशों के परस्पर भगड़ों से लाभ उठाने के लिए यह नीति अत्यधिक उपयोगी है।"

"इस नीति का उद्देश्य यह है कि विश्व क्रान्ति की रक्षा करे और सोश-लिएम (अर्थात् कम्यूनिएम) के निर्माण के संघर्ष को रुकावटों से सुरक्षित रखे — क्रयोंकि सोशलिएम के विजयी होने के फलस्वरूप संसार में एक नई क्रान्ति पैदा होगी। इस नीति का लक्ष्य है कि साम्राज्यवाद से सशस्त्र टक्कर जितनी देर तक सम्मव हो, रोके रखे।"

इससे व्यक्त है कि सोवियत सरकार की "शान्ति की नीति" इसलिए निर्धा-रित की गई है कि गैर-कम्यूनिस्ट देशों से टक्कर न हो ग्रीर इस ग्रविध में Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कम्यूनिस्टों को मिश्रित होकर अपनी तोड़-फोड़ की कार्रवाइयाँ जारी रखने का अवसर मिलता रहे। वे अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिष्म की विजय के लिए प्रयत्नशील रहें और संसार भर के देश कम्यूनिष्म को अपनाने पर विवश हो जाएं। "शांतिपूर्ण सहग्रस्तत्व" की नीति रूस को इस आंतरिक अथवास्थानीय संग्राम में हस्तक्षेप करने से नहीं रोकती जो कम्यूनिस्ट ताकतों तथा उनके समर्थकों ने आरम्भ कर रखा हो और जो मास्को के हित में हो। ४. स्टाकहाम की तथाकथित शान्ति अपील क्या थी?

मार्च, १६५० में मास्को की प्रेरणा पर स्टाकहाम में विश्व शान्ति कांग्रेस हुई। "स्टाकहाम ग्रंपील" इस कांग्रेस ने प्रस्तुत की थी। ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रोपे-गण्डे के लिए रूस के सबसे बड़े सूत्र कामिन फार्म ने इस ग्रंपील को विश्व मर में वितरण के लिए एक विस्तारपूर्वक योजना बनाई। सारी दुनिया में इस ग्रंपील का चर्चा कराया गया। इस कार्य में सहयोग देने वालों में कम्यूनिस्टों तथा उनके समर्थकों के ग्रंतिरिक्त वे लोग भी शामिल थे जो ग्रंपने स्वभाव के कारण इस ग्राकर्षक जाल में फंस गए थे।

करोड़ों लोगों ने इस संक्षिप्त अपील से घोखा खाया। क्योंकि वे समसे कि यह अपील युद्ध निषेच की मांग करती है हालांकि इसमें केवल परमागु हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई थी। इसमें साधारण हथियारों अथवा युद्ध तथा आक्रमण के अन्य रूपों का जिक्र तक न किया गया था। इसका वास्तविक उद्देश्य दूर पूर्व में आयोजित रूसी आक्रमण की तैयारियों पर पर्टा डालना था।

यह अपील अन्तिम क्षण तक देश-विदेश में गूंजती रही। फिर अकस्मात ही इसका भेद खुल गया। उत्तरी कोरिया ने अपने दक्षिण में शान्तमयी तथा दुर्बल पड़ोसी, दक्षिणी कोरियाई गणतंत्र पर धावा वोल दिया। इस आक्रमण का आयोजन क्रेमलिन में ही हुआ था और रूस ने इस हमले में उत्तरी कोरिया को हर प्रकार की सहायता दी थी।

प्र. कम्यूनिस्टों द्वारा ग्रायोजित "शान्ति ग्रान्दोलन" को गतिरूढ़ रखने के लिए सोवियत सरकार ने ग्रौर किन-किन साधनों का प्रयोग किया है ?

मास्को के आधुनिक "शान्ति आन्दोलन" का श्रीगणेश अगस्त, १६४८ में हुआ था। उसदिन कोमिन फार्म को स्थापित हुए एक वर्ष ही हुआ था। मास्को ने "शान्ति" का पहला आन्दोलन शान्ति के बनाये रखने के लिए 'शांति के लिए हिन्द्वा दियों हो दिवा कि हो से स्वार्ध के लिए हिन्दी के स्वार्ध के लिए कई संस्थाएँ बनाई जा चुकी हैं।

(कोमिन फार्म अथवा कम्यूनिस्ट सूचना ब्यूरो अप्रैल, १९५६ में तोड़ दिया गया)

आजकल कम्यूनिस्ट प्रकाशन ग्रीर प्रसारण के प्रत्येक साधन तथा जनता को प्रमावित करने की प्रत्येक विधि ग्रपने शान्ति के वहरूप पर संसार भर का विश्वास जमाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वे जनसाधारण को विश्वास दिलाने का प्रयत्न करते हैं कि कम्यूनिस्ट शान्ति प्रेमी हैं जविक पूंजीवाद के ग्रनुयायी "जंगवाज" हैं ग्रीर ग्राक्रमण कार्रवाइयों को प्रोत्साहन देते हैं। कम्यूनिस्टों के ग्रधीन तमाम समाचारपत्रों, पत्रिकाग्रों, रेडियो स्टेशनों ग्रीर मंचों से मास्को के "शान्ति प्रेम" के गीत गाये जाते हैं। मास्को द्वारा ग्रायोजित विश्व कान्फ्रेंस मी ऐसे ही प्रस्तावों पर वहस करती है ग्रीर उन्हें स्वीकार करती रहती है जिनमें सोवियत "शान्ति प्रियता" का ढोल पीटा गया हो।

इस प्रकार एक ओर तो कम्यूनिस्टों द्वारा "शान्ति यान्दोलन चलाये जाते हैं और दूसरी य्रोर संसार के भिन्न-भिन्न भागों में षड्यन्त्र तथा उपद्रव रचे जाते हैं।

६. क्या कम्यूनिस्टों ने त्रपने कान्ति के कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई स्थायी संस्था भी बना रखी है।

यप्रैल १६४६ में कम्यूनिस्टों के चलाए गए शान्ति आन्दोलन के समर्थकों ने पैरिस में विश्व शान्ति काँसिल स्थापित की। इस पर कम्यूनिस्टों का पूर्ण नियन्त्रण पहले की तरह अब भी है। प्रतिवर्ष यह काँसिल 'विश्व शांति कांग्रेस' का आयोजन करती है। यह कांग्रेस सोवियत प्रापेगण्डा ही का साधन है। नवम्बर, १६४६ में कोमिनफोर्म की सरकारी पत्रिका "स्थायी शान्ति के लिए, अवामी प्रजातंत्र के हित में" (जिसका प्रकाशन अप्रैल, १६५६ में बन्द कर विया गया) में कम्यूनिस्ट पार्टी के सब सदस्यों को हिदायत की गई कि मास्को द्वारा चलाए गये "विश्वशान्ति आन्दोलन" को बढ़ावा दें और इसका सम्भवतः गैर कम्यूनिस्टों को समर्थक वनाए।

इस ग्रान्दोलन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी संस्थाओं का ग्राश्रय लिया गया जैसे "श्रमिक संघ नारियों तथा नवयुवकों की संस्थाएँ, परस्पर सहयोग के संस्थापन, स्वंस्कृतिकः किलाञ्चम्बंधीं विकारिकातिकः स्थापन, स्वंस्कृतिकः स्वापन, विज्ञानिक, लेखक, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, प्रजातन्त्रीय नेता जो शान्ति के समर्थक ग्रीर युद्ध के विरोधी हों।

इस ग्रान्दोलन के पीछे कम्यूनिस्टों की यह ग्राकांक्षा छिपी हुई थी कि विद्वानों के संघ, ट्रड यूनियन कार्यकर्ता लोकप्रिय सिद्धान्त "शान्ति" के हित में एकत्रित हो जाएँ जिसकी प्रियता सार्वजनिक है, परन्तु जिसे मास्को ने पहले भी ग्रपने लाभ के लिए प्रयोग किया था ग्रौर भविष्य में भी करना चाहता है। ७. कौन-कौन सी विशेष संस्थाएँ कम्यूनिस्टों के "शान्ति ग्रान्दोलनों" को चलाती हैं?

सोवियत संघ की "शान्ति" के लिए आन्दोलन चलाने वाली संस्थाएँ ये हैं—नारियों की विश्व गणतन्त्रीय परिषद्, ट्रेड यूनियनों की विश्व फैडरेशन, वैज्ञानिकों की विश्व फैडरेशन और गणतन्त्रीय नवयुवकों की विश्व फैडरेशन। इन सब संस्थाओं पर कम्यूनिस्टों का कब्जा है।

सोवियत वांड "शांति" के प्रापेगण्डा के लिए कुछ श्रीर संस्थाएँ भी प्रयत्न-शील रहती हैं। विद्यार्थियों की विश्व यूनियन। गणतन्त्रीय कानूनदानों की विश्व एसोसिएशन श्रीर पत्रकारों की विश्व संस्था। भिन्न-भिन्न स्थानों पर इन संस्थाग्रों की शाखाग्रों की संख्या इतनी ग्रिधिक है कि उन्हें गिनाना ग्रसम्भव है। (सोलहवां ग्रध्याय भी देखिए)।

प्रमन कमेटियां (शान्ति समितियां) क्या हैं और उनका ग्रिभप्रायं क्या है ?

विश्व शान्ति कौन्सिल मास्को के इशारे पर चलती है। इसने स्थानीय "ग्रमन कमेटियों" का जाल विछा रखा है जिनमें कम्यूनिस्टों ग्रीर उनके सम-श्रमन कमेटियों" का जाल विछा रखा है जिनमें कम्यूनिस्टों ग्रीर उनके सम-श्रंकों के ग्रतिरिक्त कुछ ऐसे गैर-कम्यूनिस्ट भी शामिल हो गये हैं जो इनके वास्तविक उद्देश्यों से ग्रपरिचित हैं।

कुछ देशों में "ग्रमन कमेटियां" राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती हैं। इनके मुख्य कर्तव्य ये हैं: (१) शहरों जिलों तथा कारखानों में, जहां भी सम्भव हो, ग्रमन कमेटियां स्थापित करना। (२) कम्यूनिस्ट पार्टी के मेम्बरों की हिदायत पर ऐसे गैर-कम्यूनिस्टों को फुसलाना जिन्हें विश्व-शान्ति से लगाव हो ग्रौर (३) शान्ति के प्रापेगण्डे की ग्राड़ में सोवियत की परराष्ट्र नीति के उद्देश्यों को पूरा करना या स्थानीय कम्यूनिस्ट पार्टी को मजबूत बनाना।

ह. "पूर्ण निर्म्स्त्रीक्षरीए" के किक्किकि में सीविधने अस्तां व क्षय है जिने क्या इसमें कोई विशेष गुरा भी है ?

सितम्बर, १९५९ में "पूर्ण निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव राष्ट्र संघ की वृहत् सभा में प्रधान मंत्री खू इचेव ने स्वयं रखा यह उनके ग्रमरीकी दौरे का चरम चरण था। उन्होंने कहा: हमारे प्रस्ताव का सारतत्त्व यह है कि चार वर्ष के ग्रन्दर-ग्रन्दर सब देश पूर्ण निरस्त्री करण की नीति को ग्रहण कर लें। इसके उपरान्त जंग छेड़ने का कोई साधन किसी के पास न रहे।"

१६३२ के जेनेवा विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन में सोवियत विदेश मंत्री लिटवीनोफ ने जो सुक्षाव रखा था, खू इचेव का प्रस्ताव उससे काफी मिलता-जुलता है। परन्तु उस सम्मेलन के सात वर्ष बाद ही हालत यह थी कि एक क्षोर स्टालिन के प्रवक्ता रूस की 'शान्तिपूर्ण'' नीति के गुण गा रहे थे ग्रौर दूसरी ग्रोर पूर्वी यूरोप में रूस ने ऐसी ग्राक्रमणात्मक कार्रवाइयां शुरू कर रखी थीं जिनका उदाहरण ग्राष्ट्रिक काल में कहीं नहीं मिलता। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् सी. पी एस. यू. ने विश्व कम्यूनिस्ट संस्थान स्थापित किए जो ग्राज भी दोमुखी नीति ग्रपनाए हुए हैं। एक ग्रोर तो वह सोवियत प्रोपेगण्डे के नारों को दोहराते हैं: "भयानक वमों पर प्रतिबंध लगाग्रो" इत्यादि ग्रौर दूसरी ग्रोर जब कोरिया, हंगरी ग्रौर तिब्बत में चीनी सोवियत गुट की ग्रोर से सशस्त्र शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वह चुप रहते हैं। इसलिए खू इचेव का यह प्रस्ताव खाली प्रापेगण्डा से ग्रधिक महत्व नहीं रखता, जिसे देश के ग्रन्दर ग्रौर बाहर जनता को छल देने के लिए फैलाया जाता है। उनकी कोशिश यह है कि किसी-न-किसी तरह मास्को को "शान्ति कैम्प" का वना कर पेश किया जाए। १० शान्ति के नाम पर ग्राक्रमएगात्मक कार्रवाइयों को कम्यूनिस्ट किस प्रकार

उचित सिद्ध करते हैं ?

मास्को की वास्तविक धाकांक्षाधों पर पर्दा डालने के लिए रूस जो प्रयत्न करता है उसे उचित सिद्ध करने के लिए सोवियत प्रोपेगण्डा शब्दों की रचना से खूब काम लेता है।

उदाहरण के लिए, पूर्वी पोलैंण्ड पर लाल सेना के ग्राक्रमण से एक दिन पूर्व १६ सितम्बर, १६३६ को सोवियत समाचार पत्रों में इस प्रकार के समा-चार प्रकाशित हुए:

संसार भर के देशों को मोलोटोव का ग्राश्वाशन: रूस युद्ध में (द्वितीय महायुद्ध) तटस्थ रहेगा: सोवियितिं गिर्मिकिमिं तिस्ति प्रिमित्तिं निक्षिण स्मित्रिं सित्रिं सि

सोवियत दृष्टिकोण के अनुसार किसी भगड़े का "शान्तिपूर्ण निपटारा उसे कहा जाता है कि या तो महत्वपूर्ण समस्याओं पर गैर कम्यूनिस्ट सरकार मास्को का आधिपत्य स्वीकार करने अथवा हिंसा, दमन तथा तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों से कम्यूनिज्म अधिकारारूढ़ हो जाए।

११. क्या सोवियत सरकार ने दूसरे देशों से की गई युद्ध न करने की संघियों का उल्लंघन किया है ?

जी हाँ — कई वार ! १६२७ में ईरान तथा सोवियत सरकार ने तटस्थता की संधि पर हस्ताक्षर किए। निर्णय हुया कि कोई भी देश एक दूसरे के यांत-रिक मामलों में दखल नहीं देगा। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के अन्त के बाद मास्को ने उन सोवियत सैनिक दस्तों को वापस बुलाने से इन्कार कर दिया जो युद्धकाल में ईरान भेजे गए थे। संयुक्त राष्ट्र का दवाव पड़ने पर ही कहीं १६४७ में यह दस्ते ईरान से निकाले गए।

१६२६ में सोवियत सरकार ने पोलैंड, एस्टोनिया, लटेविया और रूमानिया के साथ जंग न करने की संधियाँ कीं। फिर मास्को ने एस्टोनिया तथा
लटेविया के साथ व्यक्तिगत रूप से भी सिन्धयां कीं और लिथवानिया से मैत्रीसंधि की। इसके बाद पूर्वी पोलैंड पर सोवियत सैनिक दस्तों ने कब्जा कर
लिया और १६३६ में इस इलाके को सोवियत यूनियन ने अपने राज्य में मिला
लिया। एस्टोनिया, लटेविया, और लथवानिया पर भी लाल सेनाएं चढ़ दौड़ीं,
और १६४० में उनको भी राज्य का ग्रंग बना दिया गया। रूमानिया की
वैधानिक सरकार को सोवियत सैन्य शक्ति तथा पड्यन्त्र ने खत्म कर दिया
१६३३ में सोवियत सरकार ने फिनलैंड के साथ युद्ध न करने की सिन्ध पर
इस्ताक्षर किए। १६३६ में बिना सूचना दिए अकस्मात् ही सोवियत सेनाओं
ने फिनलैंड पर घावा बोल दिया।

१६३७ में मास्को ने राष्ट्रवादी चीन की सरकार से जंग न करने की संघि की । अगस्त, १६४५ में इसी सरकार को चीन की वैध सरकार मानकर मैत्री सिन्ध की बिला किए किए के किए के हिंदि कि प्रतिकार कि प्रदेश मन्यूरिया के उद्योगों को लूट लिया, चीनी कम्यूनिस्टों को हथियार दिए और उन्हें राष्ट्र-वादी सरकार का तस्ता उलट देने के लिए प्रत्येक सहायता दी। रूस ने चीनी कम्यूनिस्टों को अधिक सैनिक सहायता देकर इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह चीनी मेन लैंड पर काविज हो गया।

१२ फरवरी, १६४५ को स्तालिन ने ग्रपने पश्चिमी मित्र देशों के साथ याल्टा सिन्ध पर हस्ताक्षर किए। फिर २, ग्रगस्त को उन्होंने पोस्टडम संधि की। इन सिन्धयों में उन्होंने विश्वास दिलाया कि पूर्वी यूरोप में सरकारें गण-तान्त्रिक विधियों के ग्रनुसार स्थापित की जायेंगी।

इन सिन्धयों पर हस्ताक्षर हुए अधिक समय नहीं हुआ था कि रूसियों ने, और पिट्ठू देशों में उनके सहायकों ने, उनकी अवहेलना शुरू कर दी। १२. संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत यूनियन का क्या व्यवहार रहा है?

१६४५ में जब सानफरांसिसको की ग्रंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो ४६ ग्रन्य देशों के साथ सोवियत सरकार ने भी संकल्प किया कि ग्रंतर्राष्ट्रीय भगड़ों के शान्तिपूर्ण निपटारे के लिए वह सदा ही प्रयत्नशील रहेगा। परन्तु रूस ने ग्रपने इस संकल्प का कभी पालन नहीं किया। राष्ट्र संघ में रूस ने प्रायः रोड़े ग्रटकाने तथा ग्रड़चनें पैदा करने का व्यवहार ग्रपनाए रखा है। सोवियत गुट के प्रतिनिधि सदैव विफल प्रयत्न करते रहते हैं कि ऐसे प्रस्ताव स्वीकार कराए जाएं जिनमें स्वतन्त्र देशों की निन्दा की गई हो। १६५६ में सोवियत प्रतिनिधियों ने सुरक्षा परिषद में ग्रस्सी बार वीटो का प्रयोग किया।

ग्रगस्त, १६४५ में सोवियत सेना टुकड़ियों ने उत्तरी कोरिया पर कब्ज़ा किया। सोवियत प्रशासकों ने उत्तरी कोरिया के लिए सेना भर्ती की, उन्हें युद्धकला सिखलाई, हथियार दिए ग्रौर २५ जून, १६५० को उनसे कोरिया के गणतन्त्र पर ग्राक्रमण कराया। संयुक्त राष्ट्र मण्डल ने उत्तरी कोरिया को ग्राक्रमणकारी घोषित किया परन्तु सोवियत यूनियन के प्रतिनिधि ने न केवल ग्राक्रमण का समर्थन किया विलक बाद में चीन के सशस्त्र हस्तक्षेप को भी उचित सिद्ध किया। दिसम्बर १६५६ में रूस ने तथा हंगरी की कठपुतली सरकार ने राष्ट्र मण्डल के एक प्रस्ताव को कार्योन्वित करने से इन्कार कर दिया। इस प्रस्ताव में राष्ट्र मण्डल के प्रेक्षक हंगरी में भेजने की ग्रनुमित दी गई थी।

१३. युद्ध के विषय पर मार्क्सी-लीननी दृष्टिकीए क्या हूं and eGangotri

लेनिन ने १९१८ में कहा था: यदि सर्वहारा वर्ग अपने देश के पूंजीपित वर्ग को परास्त करने के पश्चात् युद्ध करे और यदि उस युद्ध का उद्देश्य यह हो कि कम्यूनिज्म सफल तथा शक्तिशाली वने तो ऐसा युद्ध उचित है, "पुण्य" है।

इस दृष्टिकोण के समर्थन में "वृहत् सोवियत सर्वभौमकोष" (Encyclopaedia) के दूसरे संस्करण में युद्ध के विषय पर एक लेख है जिसमें "गण-तान्त्रिक (कम्यूनिस्ट) ग्रान्दोलन के विरुद्ध साम्राजी पूंजीपति वर्ग" की ग्रोर से छेड़ी गई "ग्रन्यायपूर्ण तथा प्रतिक्रियावादी लड़ाइयों" का कम्यूनिस्ट सरकारों द्वारा "न्याय संगत स्वाधीनता दिलाने वाले" युद्धों का अन्तर वताया गया है।

इस दृष्टिकोण के अनुसार यह निर्णय करने के अधिकारी केवल कम्यूनिस्ट हैं कि कौन-सी लड़ाई "अन्यायपूर्ण और प्रतिक्रियावादी" है और कौन-सी "न्याय-संगत तथा आजादी दिलाने वाली ।" इस तर्क के अनुसार जब रूस ने एक छोटे से राज्य फिनलैंड पर हमला किया तो उसे "न्यायपूर्ण" लड़ाई कहा गया। कौरिया गणतन्त्र पर उत्तरी कोरिया की सरकार का आक्रमण भी उनकी दृष्टि में न्याय संगत था।"

१४. क्या कम्यूनिस्ट शिक्षा पद्धति भी सैन्य वृत्ति पैदा करती है ?

रूस तथा समस्त अन्य कम्यूनिस्ट देशों की शिक्षा पद्धतियों में सैन्य वृत्ति आच्छादित है और शिक्षा अधिकारी इसी वृत्ति को प्रवल बनाने के उद्देश्य को सामने रखकर ही पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। प्राथमिक स्तर से गुजरने के उपरान्त कोमसोमोल (Young Communist League) युद्धकला के प्रशिक्षण तथा ट्रेनिंग पर अधिक बल देती है (नवां अध्याय देखिए)। कीड़ा क्षेत्र भी इस वृत्ति से सुरक्षित नहीं है। १९५३ में सोवियत सेना तथा नौ सेना की वर्ष गांठ मनाई गई। इस अवसर पर "सोवियत" ने थल, नौ तथा वायु सेना की सहायक समिति के उद्देश्यों की व्याख्या की।

"हमारी नवीन पीढ़ी इस बात की इच्छुक है कि वह युद्धकला तथा विज्ञान में कुशल हो। वह खेल-कूद के उन विशेष पहलुओं में बहुत दिलचस्पी लेती है जो युद्ध में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं—जैसे निशाने बाजी, पैराशूट का इस्तेमाल, मोटर तथा मोटर साइकल चलाना, जल क्रीड़ाएं, विमानों तथा जल यानों के तुमुत्ते बताना पूर्वत्यादि। । । । । । पर्वाप्त के तुमुत्ते विवास पीढ़ी सोवियत समाज की ग्रात्मा वन सकेगी । । ।

कोमसोमोल की सरकारी पित्रका "कोमसोमोलस्काया" ने अपने २७ फरवरी १६५३ के ग्रंक में नवीन पीढ़ी को ग्रादेश दिया कि हर कोमसोमोल सदस्य को डी० ग्रो० एस० ए० एफ० का भी मेम्बर बनाना चाहिए। कोमसोमोल के मेम्बरों पर यह जिम्मेवारी ग्राती है कि देश भर के नवयुवकों के प्रमुख अपने ग्रापको युद्ध कुशलता का मिसाली नमूना बना कर पेश करें।

कोमसोमोल हर प्रकार की सैनिक सामग्री से लैस रहती है। हर तरह की सैनिक गतिविधियों के लिए सदैव प्रबन्ध रहता है। थल सेना के हथियार, विमान, छोटे जहाज, इसके पास रहते हैं। परन्तु इनकी व्यवस्था सैनिक वजट के ग्रन्तर्गत नहीं होती, विल्क इनके खर्च सरकारी व्यापारी संस्थापना तथा नागरिक संस्थाग्रों के हिसाब में डाले जाते हैं।

१५. क्या लाल सेना का नियन्त्रण सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी के हाथ में है ?

लाल सेना पर सी० पी० एस० यू० नियंत्रण की व्यवस्था बहुत जटिल है।
यह सिस्टम वर्षों तक भिन्न-भिन्न युद्ध सेवाग्रों तथा जिम्मेदारियों, जो सर्वहारा
वर्गे के राज्य के लिए ग्रावश्यक समभी गई थीं, के ग्रघ्ययन के पश्चात् निश्चित
किया गया।

१६२० के बाद के दशक में इस बात पर पूर्ण बल दिया गया था कि सोवियत सेनाएं एक ग्रोर नागरिक ग्रावादी को काबू में रखने का विश्वसनीय सामन हों ग्रौर दूसरी कम्यूनिष्म की "मातृ-मूमि" की सुरक्षा का कार्य संभाल सकें।

इसी दौरान में कम्यूनिस्ट पार्टी ने राजनीतिक किमसारों का सिस्टम कायम किया (१६४४ में यह तोड़ दिया गया था)। इसके ग्रन्तगंत लाल सेना में प्रत्येक स्तर पर पार्टी के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। उनके ग्रधिकार सैनिक ग्रफसरों के बराबर ग्रथवा उनसे भी ग्रधिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्हें फिर से नियुक्त कर दिया गया। इस बार उन्हें राजनीतिक सलाहकार का नाम दिया गया। 'स्तालिनग्रांड के हीरों' मार्शल जुस्नोव के मामले से व्यक्त है कि सेना पर पार्टी का नियंत्रण कितना कड़ा है। स्तालिन को युद्ध काल के बहुत से जरनैलों पर भरोसा नहीं था। उन्होंने जुस्नोव को भी एक मामूली से पद पर नियुक्त कर दिया। स्तालिन की मृत्यु के पश्चात् जुस्नोव को पुनः प्रतिष्ठित

किया गया शिक्षा क्रिक्ट अन्ते अनुस्था मिनि क्षा क्षा पर सिना क्षा किया तो जुलीव भी सफाई की महिम का शिकार हो गया। उन पर लाल सेना पर पार्टी का नियं- त्रण कमजोर करने का ग्रारोप लगाया गया।

१६. क्या लाल सेना में गुप्त पुलिस भी काम करती है ?

के॰ जी॰ वी॰ (गुप्त पुलिस) ने लाल सेना पर निगरानी रखने के लिए विशेष व्यवस्था बना रखी है।

के० जी० वी० के विशेष दस्ते लाल सेना में ग्रसन्तोष के लक्षणों की तलाश्य में रहते हैं। इस निगरानी से सेना के उच्चतम ग्रधिकारी भी नहीं वचे रहते। प्रत्येक सैनिक के चरित्र का लेख प्रमाण रखा जाता है ग्रीर उसकी वैयक्तिक फाइल का विस्तार से निरीक्षण किया जाता है कि इसने भूतकाल में कभी सोवियत विरोधी कार्यविधियों तथा सोशलिज्म विरोधी ग्रान्दोलनों में भाग तो नहीं लिया। के० जी० बी० ग्रपने गुप्तचरों को सैनिकों तथा उनके ग्रधिकारियों पर मुखवरी का प्रोत्साहन करती है ग्रीर इस प्रकार सैनिक तथा ग्रधिकारी सामान्य रूप में राज्य विरोधी कार्यविधियों के ग्रारोप दण्ड दिए जाने के खतरे से सदा दो-चार रहते हैं।

१७. लाल सेना में वर्गीय भेदभाव कहाँ तक मौजूद हैं ?

शाही काल की रूसी सेना की तरह लाल सेना में भी साधारण सैनिकों तथा अफसरों के वीच वर्गीय भेद-भाव मौजूद हैं।

पद तथा ग्रलंकरण का प्रदर्शन, ऊंचा वेतन तथा ग्रानन्दपूर्ण जीवन उच्च सैनिक ग्रधिकारियों के विशेपाधिकार हैं।

फीजी अफसर का वेतन सामान्यतः उच्च व्युरोक्षेट के वरावर होता है। सेना में को आप्रेटिव स्टोरों का एक विशेष सिलसिला कायम है जिसे "वोइन-टोर्ग" कहते हैं। इन दुकानों से फौजी अफसर तथा उनके परिवार विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तथा कपड़े और अन्य सामग्री—हासिल कर सकते हैं जो साघारण सैनिकों तथा शहरी आवादी को नहीं मिलती। सुविधापूर्ण मकान भी अफसरों को सबसे पहले दिए जाते हैं।

१८. लाल सेना के बहुत से घ्रफसर रूस से भाग क्यों ग्राए हैं ?

लाल सेना से भगौड़े अफसर कम्यूनिज्म से अपने सम्बन्ध विच्छेद का बड़ा कारण यह बताते हैं कि गुप्त पुलिस की निरन्तर निगरानी से उन्हें हर समय ग्ररिक्षत होसे।क्षिक्षिक्षावसारव्यक्षेत्रावहति।श्रीवहता समात्रहतात्रावस्य Gangotri

यों तो सोवियत फौजी ग्रफसर प्रतिष्ठित तथा विशेषाधिकार वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं परन्तु के बी बी हारा उन पर निगरानी उन्हें हर समय याद दिलाती रहती है कि स्वाभाविक रूप में मुंह से निकला हुग्रा कोई शब्द या गुप्तचर की कोई ग्रप्रमाणित सूचना किसी समय भी उनका सैनिक जीवन से वहिष्कार या जीवन के ग्रन्त का कारण वन सकती है।

१६. क्या पिट्ठू देशों में भी बड़ी-बड़ी सेनाएँ हैं ?

पूर्वी यूरोप के सब देशों ने वड़ी-वड़ी सेनाएं रख छोड़ी हैं जो प्रायः लाल-सेना के प्रभावाधीन होती हैं और बहुधा उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती हैं। पिट्ठू देशों की सेनाएं सोवियत शस्त्रों से लैस होती हैं या फिर उन्हें वही सामान दिया जाता है जो पूर्वी यूरोप में सोवियत सैनिक कोटि के अनुसार तैयार किया गया हो। १६५४-१६५६ में पिट्ठू देशों की सेनाओं में सीमित कमी की घोषिणा की गई थी।

२०. क्या कम्यूनिस्ट चीन ने भी सोवियत रूस की भाँति ग्राक्रमगात्मक वृत्ति व्यक्त की है ?

१९५० के वाद ही से पीपिंग सरकार ने ग्राक्रमणात्मक कार्यविधियों तथा विस्तारात्मक कार्रवाइयों को ग्रपना नियम बना रखा है।

इसी वर्ष में कम्यूनिस्ट चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसका अपने राज्य में प्रदेश के रूप में विलय कर लिया है। तिब्बती लोगों के साथ भी वह यही कूर व्यवहार कर रहे हैं जो चीनी मेन लेण्ड में लोगों के साथ किया जाता है।

सितम्बर, १९५० में चीनी कम्यूनिस्ट सैनिक वड़ी संख्या में उत्तरी कोरिया में प्रविष्ट हुए । वे अपने आपको स्वयंसेवक कहते थे । उन्होंने राष्ट्र संघ की उन सेनाओं से जंग छेड़ दी जो कोरियाई गणतन्त्र की प्रादेशिक अखण्डता तथा स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए वहां गई थीं । इस हस्तक्षेप के कारण राष्ट्र संघ ने चीन को भी आक्रमणकारी घोषित किया।

२१. कम्यूनिस्ट सञस्त्र सेनाग्रों की आधुनिक सांख्यिक ताकत क्या है ?

सोवियत सशस्त्र सेना की कुल संख्या का ठीक अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि सशस्त्र सेना के अतिरिक्त कोमसोमोल जैसी अर्घ सैनिक संख्याओं में भी बड़े पैमाने पर भर्ती होती है। खु उचेव ने अपनी १४ फरवरी, १६६० के पिट्ठू देशों की सेनाओं में एक अनुमान के अनुसार दस लाख सिपाही हैं। कम्यूनिस्ट चीन के बारे में विश्वास किया जाता है कि वहां २६,००,००० व्यवसायी सैनिक हैं और कोई साठ लाख व्यक्ति सशस्त्र अगामी सेना) में हैं। अवरोक्त को युद्ध-कुशल नहीं समक्षा जाता।

२२. राष्ट्रीय क्रान्तियों को कम्यूनिस्ट किस प्रकार श्रयने उद्दश्यों के लिए इस्ते-माल करते हैं ?

१६५५ के बाद से (विशेष रूप से १६५७ में ग्रीर इसके उपरान्त) ग्रंत-र्राष्ट्रीय कम्यूनिएम की नीति, मास्को के निर्देशानुसार यह रही है कि कट्टर राष्ट्रवादी पार्टियों तथा ग्रान्दोलनों की सहायता की जाये ताकि कम्यूनिएम को उनमें घुसने तथा ग्रधिकृत करने में सफलता मिल सके।

१६५५ में सोवियत गुट से युद्ध सामग्री बड़े पैमाने पर मध्य पूर्व को भेजी जाने लगी। यह इस क्षेत्र में सोवियत राजनीति के हस्तक्षेप का संकेत था। कम्यूनिस्टों ने हथियारों की सप्लाई के साथ-साथ व्यापार तथा आर्थिक सहायता की पेशकदा भी की। ताहम इन कार्यविधियों के राजनीतिक प्रभाव उपे-क्षणीय रहे क्योंकि निकट पूर्व तथा मध्य पूर्व में कम्यूनिस्ट पार्टियों का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है।

परन्तु जब जुलाई/ग्रगस्त, १६५ में ब्रिगेडियर कासिम ने इराक़ में सैनिक विप्लव के पश्चात् सरकार कायम कर ली तो कम्यूनिस्टों को यहाँ पर उच्छे-दक कार्य विधियाँ करने का ग्रवसर मिला। इराक़ की कम्यूनिस्ट पार्टी इतनी शक्तिशाली नहीं है परन्तु इस उपद्रव से पार्टी ने पूर्ण लाभ उठाया और किसानों तथा ग्रीद्योगिक श्रमिकों को संगठित करना शुरू कर दिया (इस क्रान्ति से पूर्व मजदूर संगठन नाम मात्र ही था)। कम्यूनिस्टों ने सोचा था कि ये नई संस्थाएं उनके ग्रधिकार में रहेंगी। ग्रीर वह जिस प्रकार चाहेंगे इन्हें इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कोशिश की कि पूर्वी यूरोप की "कार्रवाई समितियों के नमूने पर इराक़

में भी एक "अवामी सेना" बनाई जाए। (जब पूर्वी यूरोप पर कम्यूनिस्टों का Digitized by Arya Samaj Foundation Cheonal and eGangotri क्यां करा यह प्रशिक्षित "कार्रवाई समितियाँ शासन व्यवस्था को संभालने के लिए तुरन्त ही मैदान में आ गई थीं और उन्होंने प्रशासन का प्रत्येक विभाग अपने हाथ में ले लिया था)। कम्यूनिस्ट इस बात के लिए भी प्रयत्नशील रहे कि क्रान्तिकारी सरकार में प्रत्येक स्तर पर उनका रसूख कायम रहे। प्रत्येक विभाग में उनकी आवाज प्रवल हो और सशस्त्र सेना में उनके विश्वस्त व्यक्ति नियुक्त हों। परन्तु जब कम्यूनिस्ट पड्यंत्र तथा चालें अभिव्यक्त होने लगीं तो कम्यूनिस्टों ने स्थायी तौर पर यह सिलसिला बंद कर दिया। चालों तथा घातों के मामले में स्वयं कम्यूनिस्ट पार्टी में फूट पड़ने लगी। और १६६० तक प्रत्येक बात अनिश्चित थी। कोई नहीं कह सकता था कि आगामी दिन क्या रंग दिखाएगा।

जनवरी, १६५६ में फीडल कास्ट्रो और उनके साथियों ने क्यूबा में क्रान्ति करके अपनी सरकार स्थापित कर ली। क्यूबन कम्यूनिस्टों को स्वर्ण अवसर हाथ लगा। उन्हें एक नया मार्ग दीखा। उन्होंने पूरा जोर दिया कि क्रान्ति की घारा वे निश्चित करें, कास्ट्रो सरकार की नीतियाँ उनकी इच्छानुसार बने। इसमें वे सफल भी हुए। सोवियत घात नीतिज्ञ तो अक्टूबर, १६५८ से ही इशारों ही इशारों में समभा रहे थे कि कम्यूनिस्टों की नई मंजिल क्यूबा है। उनकी दृष्टि विशेष रूप से क्यूबा के मजदूर संघठन पर थी। कम्यूनिस्टों के निकट क्यूबा बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा था। उन्हें आशा थी कि वहां से लेटिन अमरीका में उनका प्रभाव बढ़ेगा। षड्यंत्र फैलाने में सहायता मिलेगी। परन्तु १६५९ अभी समाप्त भी न हुआ था कि लेटिन अमरीका के विषय में सोवियत घातों का सर्वस्व संसार को पता चल गया। इसलिए वहां पर कम्यूनिस्ट भेदन की गित को रोक दिया गया। ताहम कम्यूनिस्टों ने अभी तक साहस नहीं छोड़ा है। लेटिन अमरीका और अफीका के देश, मध्यपूर्व और दूर पूर्व आज भी कम्यूनिस्टों के विष्वसक पड्यंत्र कार्य-क्रम में प्रथम स्थान पर हैं।

१६५६ में सोवियत गुट के कष्टपूर्ण षड्यन्त्रों में सीमित रूप में चीन भी भाग लेता रहा। वह लेटिन अमरीका और अन्य देशों में अपना प्रापेगण्डा अभियान अलग चलाता रहा और इस प्रकार सोवियत ब्लाक की विष्वंसक कार्य विधियों को सिक्तय बनाने में सहयोग देता रहा।

पंद्रहवां अध्याय कम्यूनिज़म चौर स्वतन्त्र संसार

२. कम्यूनिस्टों की गैर-कम्यूनिस्ट देशों पर श्रपना नियन्त्रए स्थापित करने की कौन-कौन सी विधियां हैं ?

कम्यूनिस्टों ने गैर-कम्यूनिस्ट देशों को निम्नलिखित चार विधियों में से किसी एक के द्वारा या इनके सिम्मश्रण से अपने नियन्त्रण में लिया है और इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं।

- (१) ऐतिहासिक तौर पर, २ सैन्य-समाजी क्रांतियों द्वारा कम्यूनिस्ट श्रिष-कारारूढ़ हुए। बोलशेविक पार्टी ने रूस में श्रक्तूबर, १६१७ की क्रान्ति को सफल बनाया और सैन्य बल से श्रन्तिम रूप में श्रपना श्राविपत्य स्थापित कर लिया। कम्यूनिस्ट चीन के विषय में भी यह बात सत्य है। (सोवियत नेता श्रव इस विधि को श्रिषक महत्व नहीं देते)।
- (२) दूसरी विधि ग्रंकित देश की सीमाग्रों पर सैन्यशक्ति का प्रदर्शन तथा दवाव डालना है। मास्को ने पूर्वी यूरोप में राजनियक दवाव डालने ग्रौर ग्रांत-रिक गड़बड़ फैलाने की विधि से काम लिया है।
- (३) तीसरे तरीके में जोकि दूसरे से बहुत मिलता-जुलता है, पड्यन्त्र, अन्तःसरण, राज्योच्छेदन इत्यादि शामिल हैं जिनसे गैर-कम्यूनिस्ट सरकार का तस्ता उलट दिया जाता है। इस विधि का अत्युत्तम उदाहरण चेकोस्लोवाकिया पर कम्यूनिस्टों का कब्जा है। बीसवीं पार्टी कांग्रेस में सोवियत नेताओं ने यह प्रस्ताव रखा था कि कम्यूनिस्ट वैधानिक तरीकों से भी सत्तारूढ़ हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने हिंसा का विशेषरूप से, जहां कम्यूनिस्टों के सरकार पर कब्जा का विरोध हो, परित्याग नहीं किया है। यह बात उल्लेखनीय है कि कम्यूनिस्टों ने किसी भी देश में वैधानिक किया विधि से सफलता प्राप्त नहीं की।
- (४) किसी वैधानिक सरकार का तख्ता उलटने का, अथवा इस कार्य के लिए प्रयत्नशील होने का चौथा तरीका यह है कि कम्यूनिस्टों द्वारा स्थापित

"स्वाधीन हा कुला के स्वाधीन हैं कि सी दूसरे ग्रंप को इस्तेमाल किया जाए। ऐसे ग्रंप प्रायः श्रंकित राज्य से बाहर स्थापित किए जाते हैं। यह ग्रंप देश से बाहर एक "स्वतन्त्र सरकार" की स्थापना घोषित करके सारे देश पर अपने श्रधिकार का दावा करता है। पोलैण्ड में यही ग्रुक्त प्रयोग की गई थी। वहां पहले लिबलिन में सोवियत निर्देशन के श्रधीन "राष्ट्रीय स्वाधीनता कमेटी" वनाई गई जिसमें कस में बहुत देर से रहने वाले पोलिस्तानी कम्यूनिस्टों को धामिल किया गया। धीरे-धीरे पोलैंड पर कम्यूनिस्टों को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया।

किसी स्वतन्त्र देश के भीतर या उसकी सीमा के निकट ही कम्यूनिस्ट
"तटगत मोर्चे" की कार्य रीति दूर पूर्व के देशों में सफलता से आजमाई गई है।
वाद में यही मोर्चा कम्यूनिस्ट सरकार के फैलने और आगे बढ़ने के लिए अड्डा
वन जाता है। लाओस को ले लीजिए। वहां कम्यूनिस्ट पायेट लाऊ सरकार
ने उत्तरी लाओस के १३,००० वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया और इस
प्रकार जुलाई, १९५४ की जेनेवा युद्ध-स्थगन सन्धि का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन
किया।

वाद में लाग्रोस की सरकार ग्रीर पाथेट लाऊ कम्यूनिस्टों में एक सन्धि हुई जिसके ग्रन्तगंत दोनों पक्षों के सशस्त्र सेनाग्रों के एकीकरण का निश्चय किया गया। परन्तु यह निश्चय कार्यान्वित न हो सका। कुछ पाथेट लाऊ सैनिक एकीकरण के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने इसकी राह में वाधाएं डालीं ग्रीर उत्तरी लाग्रोस के ग्रपने ग्रहों में चले गए ग्रीर शुरू-शुरू में इक्का-दुक्का हमले करते रहे। घीरे-घीरे स्थित बिगड़ने लगी। १६५६ की ग्रीष्म ऋतु तक कम्यूनिस्ट गुरेला युद्ध इस इलाक़े में दूर-दूर तक फैल गया था। उत्तरी वियतनाम इस युद्ध में शस्त्र चलाने तथा युद्ध नीति में कुशल सैनिक देकर उन्हें पूर्ण सहयोग दे रहा था।

जब स्थित संकटपूर्ण हो गई तो लाग्नोस की सरकार ने संयुक्त राष्ट्रमंडल को सूचित किया कि उत्तरी वियतनाम ने इस पर श्राक्रमण की धमकी दी है तथा इसकी भावी श्राक्रमण से रक्षा की जाए। सितम्बर में संयुक्त राष्ट्रमंडल ने मौका पर जाकर जांच-पड़ताल के लिए एक श्रायोग भेजा। उसने स्थिति की छानबीन के उपरान्त रिपोर्ट पेश की कि यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में श्राक्रमणकारी तैयारियां नहीं हो रही हैं, परन्तु उत्तरी वियतनाम की कम्यूनिस्ट सरकार ने

पाथेट लार्डि कि पाथेट लाऊ के गुरेला सैनिकों को उत्तरी वियतनाम में द्रेनिंग दी गई है।

२. क्रस्यूनिस्ट किन विचारों का विशेष रूप से प्रचार करते हैं और उनके प्रोपेगण्डा के लिए धन कहां से म्राता है ?

कम्यूनिस्ट प्रचार-व्यवस्था बहुत विस्तृत होती है। रूस तथा कम्यूनिस्ट चीन की सरकारों इसके लिए विशाल हृदय से धन देती हैं। जिन देशों में कम्यू-निस्ट पार्टियाँ स्थापित हो चुकी हैं वहां पार्टी भी इस काम के लिए धन एक-त्रित करती है।

कम्यूनिस्ट नेता प्रापेगण्डे को वही महत्व देते है जो वह कम्यूनिस्क के विस्तार के अन्य साधनों को प्रवान करते हैं। इनके लिए यह भी उतना ही महत्वपूणं है जितना सैन्य-शक्ति, कूटनीति तथा विघ्वंस की कार्रवाइयां। यह कम्यूनिस्म-लेनिनस्म का मूल तत्त्व है और मूल सिद्धांत के रूप में जनता को सक्साता है कि तमाम गैर-कम्यूनिस्ट सरकारों तथा सुस्थित समाजी संस्थानों का विनाश कर दो। परन्तु आधुनिक कम्यूनिस्ट प्रापेगण्डा लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने और उन्हें कम्यूनिस्म का समर्थंक बनाने के लिए अब पुरानी परिभाषाओं जैसे सर्वहारा वर्गं की ऋांति (प्रोलतारी ऋान्ति) तथा "सर्वहारा वर्गं की पूणं सत्ता" इत्यादि नारों का आश्रय नहीं लेता।

इसके स्थान पर पिछड़े हुए तथा उपनिवेश देशों में कम्यूनिस्ट प्रचारक तथा प्रवक्ता स्वाधीनता, राष्ट्रवाद, "भूमि पर किसान के आधिपत्य" श्रीर अन्य लोकप्रिय नारे लगाते हैं श्रीर अपने प्रचार में संसार भर में आधुनिक काल के सबसे बड़े, श्रत्याचारी सोवियत उपनिवेशवाद का जिक्र तक नहीं करते।

उद्योगों में उन्नत देशों में कम्यूनिस्ट मजदूरों को भड़काते हैं ग्रौर भगड़े फैलाते हैं। इनका श्राशय मजदूरों की भलाई नहीं होता बिल्क निजी लाभ, जिसमें राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना तथा कम्यूनिस्ट पार्टी के ग्रधिक समर्थक बनाना होता है। वह मजदूरों को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का भांसा देते हैं। जिसमें "उत्पादन के तमाम साधनों पर उनका अपना कब्जा होगा" हालांकि कम्यूनिस्ट देशों में उद्योगों के ग्रसली मालिक मजदूर नहीं स्टेट होती है जो कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा बनाई हुई योजनाओं तथा इच्छानुसार उन्हें चलाती है।

३. नवयुवकों को कम्यूनिल्म की थ्रोर श्राकाषित करने के लिए कम्यूनिस्ट Digitized by Avya Samai Foundation Chennai and eGangotri प्रचारक किन विधियों से काम लेते हैं?

१६४७ के उपरान्त नवयुवकों के विश्व मेले कई बार वड़ी धूमधाम से मनाए जा चुके हैं। गणतन्त्रवादी युवकों की विश्व संस्था (वर्लंड फैंडरेशन आफ डेमोक्नैटिक यूथ—डब्लयू० एफ० डी० वाई०) तथा छात्रों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ (इन्ट्रनेशनल यूनियन आफ स्टूडेंटस—आई० यु० एस०) ने वड़े पैमाने पर नवयुवकों के कई विश्व मेलों का प्रयोजन किया है। ढिंढोरा तो यही पीटा जाता है कि इन उत्सवों का राजनीति से दूर का भी सम्बन्ध नहीं परन्तु वास्तव में यह मेले प्रापेगण्डा की विराट् प्रदर्शनियां वनकर रह जाते हैं। अनुभवी कम्यूनिस्ट रूस के निर्देशन अनुसार इनका प्रवंध करते हैं।

नव युवकों का छठा विश्व उत्सव १६५७ मास्को में हुम्रा था। लगभग ३४,००० नवयुवकों ने इनमें भाग लिया था। "शान्ति तथा मित्रता" के लिए नवयुवकों तथा छात्रों का सातवां मेला वियाना में २४ जुलाई से ४ ग्रगस्त, १६५६ तक हुम्रा। यह पहला भ्रवसर था जबिक ऐसा उत्सव लौह भ्रावरण से बाहर किसी देश में मनाया गया। इन उत्सवों का वास्तविक रूप यहीं अभिन्यक्त हुम्रा जबिक इस उत्सव में कम्यूनिस्ट हुल्लड़वाज जत्थों ने घक्केशाही से नवयुवकों को कम्यूनिस्ट बनाने की कोशिश की।

४. क्या सोवियत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रमण्डल के प्रति ग्रयने वचनों को पूरा किया है ?

संयुक्त राष्ट्रमंडल के चार्टर पर रूस ने भी हस्ताक्षर किए थे। चार्टर में लिखित है: हम संयुक्त राष्ट्रों के लोग... "अन्य बातों के अतिरिक्त इस बात का प्रण लेते हैं कि "मानव के मूल अधिकारों तथा उसकी प्रतिष्ठा तथा श्रेष्ठता और सब छोटे-बड़े देशों के, चाहे वह छोटे हों या बड़े, नर-नारियों के समान अधिकारों में दृढ़ विश्वास रखने पर सहमत हैं। इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के किसी अनुच्छेद पर भी सोवियत यूनियन ने स्थिरता तथा ईमानदारी से अमल नहीं किया।

इसके अतिरिक्त सोवियत संघ द्वारा किए गए आक्रमणों, अन्य देशों को बलपूर्ण अपने राज्य में शामिल करने और अन्तर्राष्ट्रीय सिन्धयों के विच्छेद की कार्रवाइयों के सम्मुख यह बात सिद्ध है कि सोवियत संघ ने संयुक्तराष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं का भी पालन नहीं किया है। राष्ट्रमण्डल चार्टर में लिखित दूसरों के प्रति उदारती दिस्त निया शास्ति सं ग्रेन्छ । पड़िता कि सिर्ह रहने से सम्बद्ध नियमों का खण्डन किया है। संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है कि कम्यूनिजम का कार्यक्रम सशस्त्र शक्ति, आक्रमण, पुलिस आतंक तथा कम्यूनिस्टों द्वारा प्रेरित हिंसात्मक तथा विनाश पूर्ण कार्रवाइयों पर निर्भर है।

५॰ "संयुक्त कोरिया" तथा "संयुक्त जर्मनी के विषय में कम्यूनिस्टों द्वारा प्रस्तुत

सुफाव पश्चिमी देशों के प्रस्तावों से किस प्रकार भिन्न हैं ?

कोरिया तथा जर्मनी के एकीकरण के लिए पश्चिमी राष्ट्रों के सुकावों तथा कम्युनिस्टों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में मूल भेद चुनाव का तरीका है।

दोनों ही देशों के विषय में सोवियत सुभाव बहुत हद तक समान हैं। कम्यूनिस्ट कहते हैं कि पहले एक अन्तःकाल विधान सभा बनाई जाए जिसमें दोनों भागों से बराबर सदस्य लिए जाएं। परन्तु उनके सुभाव को कार्यान्वित करने का अर्थ यह होगा कि इन कृत्रिम विधान सभाओं पर कम्यूनिस्ट छा जाएंगे। क्योंकि उत्तरी कोरिया की जन संख्या दक्षिणी कोरिया से एक तिहाई से भी कम है। इस तरह पूर्वी जर्मनी तथा बलिन के रूसी क्षेत्र की आवादी बोन की गणतंत्र सरकार अर्थात गैर कम्यूनिस्ट जर्मनी की जनसंख्या के एक तिहाई से कुछ ही अधिक है।

दोनों परिस्थितियों में कम्यूनिस्ट इलाकों के प्रतिनिधि (जो नामजद कठ-पुतिलयां होंगे) एक समान ही मत देंगे। इसके लिए उन्हें मास्को से (कोरिया के संबंध में सम्भवतः पीपिंग से) निर्देश मिला करेंगे। गणतंत्रीय प्रतिनिधियों में

किसी प्रकार के मतभेद का लाभ कम्यूनिस्टों को ही होगा।

फिर एक बात और भी है। उत्तरी कोरिया तथा पूर्वी जमंनी की सरकारें जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हैं। इसके बावजूद कम्यूनिस्ट सुकावों के अनुसार यह अन्तःकाल विधान सभाएं चुनाव सम्बंधी तमाम समस्याओं तथा वर्तों का निर्णय करेंगी। यह वही निश्चित करेंगे कि मतदाताओं की योग्यता का स्तर क्या होना चाहिए। मास्को अथवा पीपिंग ने ऐसी कोई प्रयोजना प्रस्तुत नहीं कि जिसके अन्तर्गत कम्यूनिस्ट अधिकृत इलाकों में वास्तविक रूप में स्वतंत्र चनाव हो सकें।

दूसरी थ्रोर, पश्चिमी राष्ट्रों के निकट दोनों देशों के एकीकरण का मूल ग्राधार वहाँ पर स्वतंत्र चुनाव हैं जिनकी निगरानी के लिए उचित व्यवस्था हो ताकि मतदाता दवाव, त्रास थ्रौर ग्रातंक से सुरक्षित रहें, गुप्त मतदान का

नियम न टूटे और चुनाव परिणाम बिल्कुल ठीक हों।

६. पश्चिमी र्वातन की समस्या का कम्यूनिस्ट उक्ति "शान्तिपूर्ण सहश्रस्तित्व" Digitized by Ayya Samaj Foundation Chennai and eGangotri से क्या सम्बन्ध हैं!

नवम्बर, १६५८ में ख़ुश्चेव ने पश्चिमी बर्लिन के दर्जे में एक बड़ी तव-दीली की मांग की । इससे संसार भर में एक संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस उदाहरण से भी सोवियत कूटनीति एक बार फिर परिव्यक्त होती है कि एक ग्रोर तो कम्यूनिस्ट राष्ट्रों की शान्तिपूर्ण प्रवृत्ति तथा सद्व्यवहार के गुण गाए जाते हैं ग्रौर दूसरी ग्रोर यही राष्ट्र सशक्त ग्राचार ग्रपनाए हुए हैं।

पश्चिमी वर्लिन के लिए खु इचेव का फार्म्ला एक ब्रादेशात्मक तथा एक-पक्षीय मांग थी कि पश्चिमी वर्लिन से तमाम ग्रधिकारी सेनाग्रों को निकाल लिया जाए ताकि वह एक "स्वतंत्र नगर" वन जाए। इस धमकी का वैकिल्पक रूप यह था कि (बाद में इस धमकी में से समय निर्धारण की शर्त निकाल दी गई थी) । मास्को तथा कम्यूनिस्ट पूर्वी जर्मनी के वीच व्यक्तिगत रूप से संधि होगी जिसके अनुसार पश्चिमी बॉलन से आने-जाने पर नियंत्रण पूर्वी जर्मनी का हो जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था में जो खतरे निहित हैं। वह स्पष्ट हैं। पश्चिमी जर्मनी चारों ग्रोर सर्वाधिकारी पुलिस राष्ट्रों से घिरा हुग्रा है। इसकी सशस्त्र सेनाग्रों का दवाव इस पर बना रहेगा तो वह स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में कायम नहीं रह सकेगा। ख़ुरचेव ने तो यह भी पहले ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि इस ग्रायोजना के ग्रघीन "स्वतंत्र" पश्चिमी वर्लिन को कम्यूनिस्ट नीतियों पर वेरोक टोक आलोचना करने की आज्ञा नहीं होगी। न ही यह उन लोगों को भ्राश्रय देगा जो पूर्वी जर्मनी में भ्रत्याचार तथा जबरी संगठन से भाग कर इधर आते हैं। इन परिस्थितियों में पश्चिमी बॉलन को "स्वतन्त्र नगर" का नाम देना पारिभाषिक शब्दों को प्रापेगण्डे का साधन वनाने का एक ग्रीर उदाहरण है।

कम्यूनिस्ट दृष्टिकोण के अनुसार पिश्चमी बीलन अपनी सम्पन्न तथा उन्नत अर्थ व्यवस्था और वहाँ के उद्योगी उद्यमी नागिरकों सिहत पूंजीवाद का प्रतीक हैं जिसे दवा देना अथवा खत्म कर देना ही उचित है। इसके बाद ही "शांति पूर्ण सहअस्तित्व" संभव है। पिश्चमी बीलन की स्वतन्त्रता के विनाश को मार्क्सिलेनिनी फार्मूले के अनुकूल प्रमाणित किया जा सकता है जिसके अनुसार इस संसार में दो मुख्य समकालीन पद्धतियाँ हैं—पूंजीवाद तथा साम्यवाद। दोनों प्रकृतिस्थ एक दूसरे के विरोधी हैं और अन्त में कम्यूनिस्ट सिद्धान्त का विजयी होना अनिवायं है।

७. स्वतः श्रिः संस्तर्भे भें े श्रामिका संमृद्धिः के लिए पिडिश्वमी बेदाई कि स्वान्त्रया प्रयत्न किये हैं ?

हितीय महायुद्ध के उपरान्त पिंचमी यूरोपीय देशों ने आर्थिक स्थिरता तथा राष्ट्रीय संरक्षण के लिए ग्रनेकों उपाय किए। यूरोपीय सरकारों के एक युप ने ग्राधिक सहयोग यूरोपीय संगठन (ग्रो० इ० इ०सी०) यूरोपीय सुगतान यूनियन (इ० पी० यू०), कोयेले तथा इस्पात की विरादरी स्थापित कीं। यूरोपीय कांसिल की स्थापना भी की गई जिसके जिम्मे केवल परामशं देने का काम था।

१६४८ में मार्शल प्लान, (ग्रमरीका का यूरोपीय पुनर्निर्माण प्रोग्राम में जिस का मुख्य उद्देश्य युद्ध के परचात् परिचमी राष्ट्रों में ग्रायिक स्थिरता पैदा करना था, शामिल होने का निमन्त्रण प्रत्येक देश को दिया गया। रूस ने इस प्रोग्राम में शामिल होने तथा सहयोग देने से इन्कार कर दिया ग्रीर अपने पिट्टू देशों को भी इस प्रोग्राम से लाभ उठाने से रोक दिया। इस प्रोग्राम में शामिल देशों की कम्यूनिस्ट पार्टियों के मेम्बरों को ग्रादेश मिला कि प्रत्येक सम्भव तरीके से प्लान का हड़तालों तथा तोड़-फोड़ की ग्रन्य कारवाइयों से ग्रन्तव्वंस करें। परन्तु उनके तमाम प्रयत्न विफल सिद्ध हुए ग्रीर यूरोप का ग्रायिक पुनर्निर्माण जारी रहा।

एशिया, ग्रफीका ग्रीर लैटिन ग्रमरीका के देशों को भी ग्रमरीका के 'प्वाइन्ट फोर'' प्रोग्राम के ग्रधीन तकनीकी सहायता दी जा रही है। "ग्राथिक सहयोग प्रशासन" (इ॰ सी॰ ए॰) की ग्रोर से ग्रारम्भित इस प्रोग्राम को

(फारेन् आप्रेशन्ज एजेन्सी) (F.O.A.) चला रही है।

ग्रमरीका की ग्रोर से विदेशों को सहायता प्रायः ग्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी (I.C.A.) द्वारा दी जाती है। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त ग्रमरीका ने कुल मिला कर ग्रस्सी देशों को ग्रसैनिक सहायता दी है। जून, १६५६ तक इस सहायता पर ग्रमरीका ४६५ ग्ररब डालर खर्च कर चुका था।

१६५० में श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो में ग्रायोजित ब्रिटिश राष्ट्रमंडल ग्रिधिवेशन ने कोलम्बो योजना की ग्राधार शिला रखी। इसके ग्रन्तगंत दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की ग्राधिक उन्नति के लिये छः वर्ष की ग्रविध में ५० करोड़ से ग्रधिक व्यय का निश्चय किया गया।

शुरू में कोलम्बो योजना में केवल सातं देश शामिल थे। बढ़ते-बढ़ते १९५४ में सदस्यों की संख्या सोलह हो गई। सहायता देने वाले राष्ट्रों के नाम

हैं, ब्रिटेन, कनाडा, ग्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रमरीका तथा जापान । सहायता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों में भारत, पाकिस्तान, वर्मा, हिन्देशिया, (इन्डोनेशिया) श्रीलंका, लाग्नोस, कम्बोज (कम्बोडिया), वियतनाम, तथा थाईलैंड हैं। (बाईलैंड सहायता देता भी है)।

स्वतन्त्र संसार की आर्थिक समृद्धि के लिये नवीन मार्ग तथा उन्नित के अंतर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development) ने भी बहुत सहायता दी है। यह वैंक राष्ट्र संघ की विशेष्ठित संस्था है। इसे जून, १६४६ में स्थापित किया गया था। तत्काल यह ५४ देशों को ५० करोड़ डालर के ऋण दे चुका है। यह ऋण इसलिए दिये गये थे कि द्वितीय महायुद्ध में हुये विनाश के कुप्रभावों को खत्म किया जा सके और नवनिर्माण का काम तीव्रता से हो सके। बाद में यह ऋण स्वतन्त्र संसार के बहुत से भागों में विद्युत-उत्पादन, कृषि तथा उद्योग की उन्नित के लिये भी दिये गये। इस वैंक के ६० मेम्बर देशों में नं तो सोवियत यूनियन शामिल है, न इसके पिट्ठू देश।

राष्ट्रीय संघ की एक और विशेषित संस्था कृषि तथा खाद्य संगठन (F.A.O.), जो स्वतन्त्र संसार को, विशेष रूप से पिछड़े हुए देशों को, जहाँ खाद्य सामग्री का ग्रभाव है, सहायता देती है। इस संगठन में सोवियत गुट का केवल एक ही देश, पोलैंड शामिल है। मानव की सेवा तथा हित के लिए राष्ट्र संघ की एक और संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) है जिसका सारा खर्च स्वतन्त्र संसार देता है।

इसके अतिरक्त राष्ट्र संघ पिछड़े हुये देशों के लिए तकनीकी सहायता का एक प्रोग्राम चलाता है। इस प्रोग्राम के लिए अधिकतर आर्थिक व्यवस्था पिश्चिमी देश ही करते हैं। पिछले दिनों तक सोवियत यूनियन इस प्रोग्राम में भाग नहीं लेता था। परन्तु कुछ समय से इसने भी एक छोटी-सी रक्तम देकर अपना योग देने की इच्छा प्रकट की है।

प्रत्माखु शक्ति शान्ति के हित में" की योजना क्या है ?

द दिसम्बर, १६५३ को भ्रमरीको राष्ट्रपति भ्राइजन हावर ने राष्ट्रसंघ की वृहत् सभा में भाषण देते हुए एक भ्रष्ट्रता और प्रभावशाली प्रस्ताव पेश किया। उनका भाषण भ्राष्ट्रितक परमाणु हथियारों के विनाशक प्रभावों के प्रकाश में दिया गया था। राष्ट्रपति ने कहा:

ग्रमरीक्षां की इस नास का का का कि बि विषय प्रयोग न किया जाए तो तवाही की यह महान् शक्ति एक ऐसा पारितोपक बन सकती है जिससे संसार भर को लाभ है इसलिये में यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि जो देश परमाणु शक्ति के ग्रनुसंधान में ग्रमसर हैं उन्हें चाहिये कि ग्रपने हितों का संरक्षण करते हुये जहाँ तक हो सके ग्रपने यूरोपियन तथा ग्रन्य विस्फोटक पदार्थों के मण्डार का एक भाग परमाणु शक्ति की ग्रंतर्राष्ट्रीय संस्था को देना ग्रारम्भ कर दें ग्रीर भविष्य में भी देते रहें। इस प्रकार एक सामा ग्रन्तर्राष्ट्रीय जलीरा बन जाएगा। ऐसी संस्था ता मुख्य कर्त्तव्य होगा कि ऐसे तरीक़े निकाले जिनके विस्फोटक पदार्थों को शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये नियत कर दिया जाये। उस समय यह सम्भव हो सकेगा जब कि योग देने वाले देश ग्रपनी शक्ति का एक ग्रंश मानव की ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति के लिए खर्च करेंगे न कि भय तथा ग्रातंक फैलाने में।

आठ राष्ट्र—श्रमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, फांस, श्रास्ट्रेलिया, वैलिजयम, पुर्त-गाल तथा दक्षिण श्रफीका के प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति संस्था के चार्टर सदस्य बने श्रीर उन्होंने इस संगठन के स्थापन के लिए अक्तूबर, १९५५ में राष्ट्र संघ को परिनियम प्रविधान पेश किया।

१९५६ के गुरू में नई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के स्थापन के आघार कर्म के लिए बारह राष्ट्रों की प्रारम्भिक बैठकें हुईं। अन्त में २६, अक्तूबर, १९५६ को सत्तर राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति एजेन्सी (International Atomic Energy Agency) में परिनियम प्रविधान पर हस्ताक्षर कर दिए।

द नवम्बर, १६५६ को बुसेल्ज में अमरीका तथा यूरोपीय अणुकक्ति समु-दाय (European Atomic Energy community EURATOM) के छ: मेम्बर देशों में अणुक्ति के असैनिक प्रयोग में सहयोग देने के विषय में एक समभौता हुआ। इस समभौते का लक्ष्य है कि आने वाले पांच या सात वर्षों में समुदाय के राष्ट्र आणविक् शक्ति से दस लाख किलोवाट विजली तैयार करने लगेंगे। इसके लिए अमरीका में बनाये गये रिएक्टर काम में लाए जाएंगे। यह समभौता केवल अणुक्ति की महान् उन्नति का ही द्योतक नहीं है बल्कि घीरे- घीरे यूरोप क्रिल्मा सिंगु होगुट हु क्रेंगुट हु क्रेंग

१. निरस्त्रीकरण के सोवियत तथा पश्चिमी राष्ट्रों के प्रस्तावों में क्या प्रन्तर है ?

१६४७ के बाद से राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण आयोग के सोवियत प्रति-निधियों ने निरस्त्रीकरण के लिए पश्चिम की ओर से प्रस्तुत सुभाओं को कभी स्वीकार नहीं किया। पश्चिमी देशों के आग्रह पर सार्थंक निरीक्षण के लिये रूस ने जो प्रस्ताव रखे उनमें भी निरीक्षण की उचित गारंटी नहीं दी गई। १६५६ भी बीत गया परन्तु रूस ने गतिरोध बनाये रखा।

निरस्त्रीकरण के विषय में अमरीकी सरकार की पोजीशन इस पत्र से अत्यक्ष होती है जो १७ नवम्बर, १९५६ को अमरीकी राष्ट्रपति आइजन हावर ने अमरीकी सैनेटर हवटं हमफे को लिखा था। राष्ट्रपति आइजन हावर ने अन्य वातों के अतिरिक्त यह भी लिखा:

"गत छः वर्ष में अमरीका की यह विशेष कोशिश रही है कि हिथयारों पर नियंत्रण के लिये और हिथयारों की दौड़ खत्म करने के लिए प्रभावी तरीके तलाश किये जाएँ। इस जुस्तजू में उन्हें सफलता होगी तो सब देश अपने आप को सुरक्षित समर्भेंगे और आणविक युद्ध का खतरा टल जायेगा। पिछले दिनों (नवम्बर, १६५६ में) अमरीका और वृहत् समां के अन्य सदस्यों द्वारा पेश किये हुये राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में पूर्णतया साधारण निरस्त्रीकरण का जो लक्ष्य निश्चित किया गया है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने यह नीति अपना रखी है कि हथियारों की पूरी समस्या के जिन भागों पर समभौता हो सकता है, उन पर संसार भर के राष्ट्रों की स्वीकृति प्राप्त की जाए।"

११ फरवरी, १६६० को अमरीकी राष्ट्रपति ने सुकाव दिया कि अन्तरिक्ष में आणिवक टैस्टों पर प्रतिबन्ध लगाया जाए ताकि तेजोदिगरि पात के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता निवारण की जा सके। परन्तु सोवियत सरकार ने इस अमरीकी प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया।

सोलहवां मध्याय कम्यूनिज़म का मुकावला कैसे किया जाए?

 साधारण व्यक्ति कम्यूनिज्म विरोधी संघर्ष में किस प्रकार सहायता दे सकता है ?

इस प्रश्न का कोई एक ही उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि कम्यूनिज्य का खतरा बहुमुखी है। अपने उद्देशों की प्राप्त के लिए वह कभी तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों को अपनाता है और कभी अधिकार युक्त पदों पर कब्जा करके उन्हें साधन बनाता है, कभी शक्ति को प्रयोग करता है तो कभी इन तीनों विधियों को इकट्ठे इस्तेमाल करके कार्य सिद्ध करने की कोशिश करता है। अपनी षड्यंत्रकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने और प्रायः उनको छिपाने के लिये कम्यूनिस्ट रेडियो, समाचा-पत्रों और भाषणों द्वारा निरन्तर प्रापेगण्डा करते रहते हैं। उनका प्रभावपूर्ण प्रापेगण्डा अधिकतर महाजी संस्थाएँ ही करती हैं। देखने में यह ग्रुप भोले-भाले और हानि शून्य नजर आते हैं परन्तु इनकी बाग-डोर कम्यूनिस्टों के हाथ में होती है।

स्थानीय रूप में जहाँ-कहों भी कम्यूनिल्म की आशंका हो, वहाँ स्वाधीनता की सुरक्षा के लिए तुरन्त ही इसका प्रतिरोध करना चाहिए। इस खतरे को दूर करने के लिए एक हथियार अति आवश्यक है: वह है सत्य का ज्ञान। इसलिये जो लोग इस खतरे की रोक-थाम के लिये मैदान में आयें उन्हें पहले इसे पूरी तरह समभना चाहिये। उन्हें इस बात का बोध होना चाहिये कि कम्यूनिस्ट अपने अनिच्छुक तथा अज्ञानी आखेट पर कौन-सी विधियां तथा चालें प्रयोग में लाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें कम्यूनिल्म के विरोधियों को इस खतरे का सामना करने के लिये दृढ़ता से संगठित किया जाए।

२. कम्यूनिस्टों की 'महाज़ी' संस्था क्या होती है ?

कम्यूनिस्ट महाजी संस्था ऐसा संगठन होता है जिसे कम्यूनिस्ट पार्टी हिदायतें देती है नियन्त्रित करती है तथा अपने स्वार्थ के लिये इस्तेमाल करती है। कम्यूम्बिस्ट्र-छह्त्रकों/किश्वपूर्विनियं प्रसानियं साथावसहयोगि देखे को लिये इसे संगठित किया जाता है। प्रायः इसका नाम कुछ और ही होता है और यह प्रत्यक्ष रूप में कम्यूनिस्ट पार्टी से विभिन्न दीख पड़ती है। यह प्रायः कम्यूनिष्म से असम्बन्धित लोकप्रिय उद्देश्यों का समर्थन करती हैं। इसके अतिरिक्त कम्यूनिस्ट बहुधा प्रतिष्ठित नागरिकों के नाम अपनी महाजी संस्था के प्रवत्तंकों अथवा उसके मुख्य सदस्यों के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि वह भोले-भाले लोगों को अपनी संस्था की और आकष्यित कर सकें।

३. मुख्य अन्तर्राब्द्रीय कम्यूनिस्ट महाजी संस्थाएं कौन-कौन-सी हैं श्रीर वे क्या काम करती हैं ?

१६४५ में जब द्वितीय महायुद्ध का अन्त हुआ और संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापित किया गया, तो सोवियत यूनियन के तत्त्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट महाजी संगठनों के स्थापनक्रम का प्रथम चरण प्रारम्भ हुआ। १६५४ तक ऐसे तेरह संगठन वन चुके थे। इन संस्थाओं के संगठन का उद्देश्य यह था कि इनके हेतु कम्यूनिस्ट प्रापेगण्डा फैलाया जाए। चीनी-सोवियत गुट की विदेशनीतियों के समर्थक बनाए जाएं और ऐसे व्यक्तियों को जो कम्यूनिस्टों से आशं-कित न हों और उनके वास्तविक उद्देश्यों का वोधन रखते हों, उन्हें कम्यूनिस्टों को सहयोग देने पर सहमत कराया जाए।

१६४५ में स्थापित तीन कम्यूनिस्ट महाज यह थें : ट्रेड यूनियनों की विश्व-फैड्रेशन, (World Federation of Trade Unions) लोकतंत्रीय नवयुवकों की विश्व फैड्रेशन (World Federation Democratic Yauth) नारियों की विश्व लोकतंत्रीय फैड्रेशन (Womens International Democratic Federation)।

म्रागामी वर्ष में पांच महाज श्रीर वने । विद्यार्थियों की विश्व यूनियन (International Students Union) ग्रघ्यापकों के संगठन की विश्व फुँड्रेशन (World Federation of Teachers Unions), लोकतंत्रीय कानूनदानों की विश्व एसोसिएशन (International Association of Democratic Lawyers), पत्रकारों की ग्रन्तर्राष्ट्रीय ग्रारगेनाईजेशन (International Organisation of Journalists) तथा प्रसारण की ग्रन्तर्राष्ट्रीय ग्रारगेनाईजेशन (International Broadcasting Organisation) १६४६ में कम्यूनिस्ट प्रापेगण्डे की सबसे शक्तिशाली संस्था विश्व शान्ति कौन्सल स्थापित हुई (World Peace Council) (सोलहवां ग्रघ्याय देखिए)।

इत ग्रेंग्संरिष्ट्रीय महाजी सिंग्रेनिंगनिंगि रिष्ट्रीय स्थानिय सिंग्याएं सम्बद्ध होती हैं। इनमें से अधिकतर तो इतने छोटे होते हैं कि इनका कोई महत्व ही नहीं होता। इन महाजों का दावा है कि इनके करोड़ों सदस्य हैं, परन्तु सत्य यह है कि इस संख्या के ५० प्रतिशत सदस्य चीनी-सोवियत गुट के बासी हैं, जहां श्रौद्योगिक श्रमिकों तथा व्यवसायिकों के लिए स्टेट द्वारा बनाई हुई यूनि-यनों के सदस्य बनना अनिवायं है।

प्रत्येक महाज का प्रवन्ध कम्यूनिस्टों तथा उनके सहगामियों के अधिकाराकढ़ गुट के हाथ में होता है। किसी भी महाज के चुनाव लोकतंत्रीय प्रणाली
अनुसार नहीं होते। इन संस्थाओं की तमाम कार्रवाइयों और प्रस्तावों का
अधिकाराक्द वर्ग पहले ही से निर्णय कर लेता है। यह मास्को लाइन के अनुकूल होते हैं। हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप के पश्चात् पश्चिमी यूरोप तथा अन्य
देशों की महाजी संस्थाओं के सदस्य अपनी मान-प्रतिष्ठा खो बैंटे हैं। कुछ
स्थानों पर तो प्रवन्धक कमेटियों के अन्दर हंगरी की समस्या पर बहुत विवाद
हुआ। तिब्बती जनता पर चीनी कम्यूनिस्टों ने जो अत्याचार किए हैं, उनकी
निन्दा किसी महाज ने नहीं की है।

४. कम्यूनिस्ट महाजी संस्थाय्रों से कैसे निवटा जाए ?

पहले तो कम्यूनिस्ट "महाजी" संस्थाओं को भलीभांति पहिचान लेना चाहिए, इस प्रकार कि शंका की कोई संभावना न रहे। इसके उपरान्त घोषित कर देना चाहिए कि यह संस्थाएं कम्यूनिस्टों की पिट्ठू हैं और इनका उद्देश्य उन्हीं लोगों पर विदेशी नियंत्रण स्थापित करना है जिनको यह सहायता की अपीलें करती हैं। आमतौर पर इन संस्थाओं के रहस्योद्घाटन से ऐसे व्यक्ति अपनी सदस्यता त्याग देते हैं जो नासमभी से इन महाजों के मेम्बर बन जाते हैं। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे महाज को चन्दा इत्यादि देना भी बंद कर देते हैं। सदस्यों के बिना ये संस्थाएं निर्यंक हो जाती हैं।

प्. मजदूर यूनियन के सदस्य कम्यूनिस्टों की यूनियन को स्वार्थ के लिए इस्ते-माल करने से कैसे रोक सकते हैं ?

कम्यूनिस्ट (जिनकी पार्टी सदस्यता गुप्त रखी जाती है) छल तथा कपट से यूनियन की बैठकों को इतना लम्बा कर देते हैं कि बहुत से मेम्बर घर चले जाएं। इसके उपरान्त कम्यूनिस्ट ग्रुप ग्रपने मनोनीत प्रस्ताव स्वीकार करा लेता है। बैठक के रिकार्ड में लिख दिया जाता है कि सब मेम्बरों ने बैठक में प्रस्तुत ग्रागोजन्तिक (स्पार्शना किया) है जावकि ताला साह होता है कि जिल का समर्थंन केवल कम्यूनिस्ट ही करते हैं। इन छलपूर्ण विधियों के प्रतिरोध के लिए यह ग्रानिवार्य है कि तमाम सदस्य बैठक के अन्त तक बैठें अथवा उस समय बैठक स्थितित करने की मांग कर दें जब उन्हें विश्वास हो जाए कि कम्यूनिस्ट जान-बूक्कर बैठक को लम्बा कर रहे हैं। कम्यूनिस्टों की यह चाल ग्रीर भी ज्यादा खतरनाक है जबिक वह यूनियन के महत्वपूर्ण पदों पर अधिपत्य करके यूनियन को स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। अन्य संस्थाओं की भांति मजदूर संघ के सदस्य भी साधारणतः अपनी-अपनी रूचियों अनुसार विभिन्न गुटों में बट जाते हैं। कम्यूनिस्ट सदस्य ऐसी स्थितियों का लाभ उठाते हुए गुटों के बीच फूट डालते हैं ग्रीर गुट के नेताओं में वैर-भाव को उजागर करते हैं। उचित समय पर (ग्रामतौर पर चुनाव के अवसर पर) कम्यूनिस्ट किसी एक गुट को अपनी शर्तों पर संगठित सदस्यों की सहायता पेश करते हैं। उनकी शर्ते ग्रामतौर पर यूनियन कौन्सिल में अपना स्थान निश्चित करने के विषय में होती हैं।

कम्यूनिस्टों के प्रन्तिम लक्ष्य हैं : यूनियन की केन्द्रीय ग्रथवा कार्य संचालक सिमिति में काम चलाने योग्य बहुसंख्या, यूनियन के प्रधान ग्रथवा मंत्री के पद पर ग्रधिकार, कोषपाल के पद की प्राप्ति क्योंकि इससे यूनियन को ग्राधिक रूप में नियंत्रित करने का अवसर मिलता है, ट्रेड यूनियन के प्रकाशनों पर सम्पादकीय नियंत्रण ग्रथवा वर्कशापों में कारिन्दों की ग्रासामियों पर कब्जा तािक श्रमिक के साथ उनका गहरा सम्पक्तं बना रहे। कम्यूनिस्टों की इन चालों की रोकथाम केवल सचेत तथा तथ्य ज्ञाता यूनियन मेम्बर ग्रीर उनके नेता ही कर सकते हैं।

६. राज्य सत्तारूढ़ होने की कम्यूनिस्ट विधि का उचित उदाहरए कौन-सा देश प्रस्तुत करता है ? ऐसी परिस्थित को कैसे रोका जा सकता है ?

चेकोस्लोवाकिया का मामला एक ऐसा ही उदाहरण है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व यह देश अपने उदार प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। कम्यूनिस्टों को चुनाव में कभी दस प्रतिशत से अधिक मतदान प्राप्त नहीं हुए थे। परन्तु १६४५ में उन्होंने जनता को यह कह कर फुसलाया कि युद्ध के दौरान में उनके देश को सोवियत नेताओं ने संयुक्त किया है और प्रोत्साहन दिया है। इस आधार पर कम्यूनिस्टों ने देश के मन्त्रिमण्डल की २३ सीटों में से द की माँग की और वह उन्हें दे दी गईं। इसके अतिरिक्त कम्यूनिस्टों के दो सहगामी जो निरन्तर उनके

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri एजेन्ट वन रहे, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा मंत्री वन गए। संक्षेप में कम्यूनिस्टों ने पुलिस, सेना तथा देश के प्रापेगण्डा साधनों को प्रपने नियंश्रण में ले लिया। कम्यूनिस्टों को यह सुविधाएं वेन्स सरकार ने मई, १९४६ के चुनाव के बाद दी, जिसमें कम्यूनिस्टों ने ३६ प्रतिशत वोट प्राप्त किए।

नई सरकार ने कम्यूनिस्टों के दबाव के कारण तीन राजनीतिक पार्टियां जिनमें शक्तिशाली एग्नेरियन पार्टी भी शामिल थी, तोड़ दीं और श्रन्य पांच पार्टियां, जिनमें कम्यूनिस्ट पार्टी भी शामिल थी, का श्रस्तित्व बनाए रखने की श्रनुमित दे दी। पराधिकृत पार्टियां तब राष्ट्रीय फंट में मिलकर काम करने पर सहमत हो गई। यह व्यवस्था गैर-कम्यूनिस्ट पार्टियों के लिए घातक सिद्ध हुई।

फरवरी, १६४८ में, जब कम्यूनिस्ट वेन्स सरकार का तस्ता जलटने के लिए अन्तिम प्रहार की तैयारियों में लगे हुए थे, केन्द्रीय मजदूर यूनियन पर उनका नियन्त्रण था। इसलिए सार्वजिनक हड़ताल तथा प्रदर्शन कराने में उन्हें कोई किठनाई नहों थी। गृह-मंत्रालय तथा पुलिस पर अधिकार होने के कारण यह कम्यूनिस्ट विरोधी विद्यार्थियों के प्रदर्शनों को कुचल सकते थे। प्रधान वेन्स जो कम्यूनिस्टों के योग देने में कोई बुराई नहीं समभते थे, एक नई सरकार बनाने पर विवश कर दिए गए, नए मंत्रिमण्डल में इतने कम्यूनिस्ट घुस आए कि समूचे प्रशासन पर उनका कब्जा हो गया। वेन्स ने निराश तथा अधीर होकर त्यागपत्र दे दिया। कम्यूनिस्टों ने अधिकारारूढ़ होते ही एक नया संविधान लागू कर दिया जिसके द्वारा बहुत से मूल अधिकार जनता से छीन लिए गए।

इस प्रकार की स्थितियों को रोकने के लिए अनिवार्य है कि गैर-कम्यूनिस्ट पहले तथाकथित "राष्ट्रीय फंट" की तकनीक को समर्भे, दूसरे इनमें भाग लेने से साफ इन्कार कर दें। कम्यूनिस्टों के साथ मिलकर सरकार बनाने का अर्थ गैर-कम्यूनिस्टों के लिए आत्महत्या के समान है।

दिसावे में तो तथाकथित "राष्ट्रीय फंट" का ग्रिभिष्राय समान लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय एकता होता है परन्तु वास्तव में इस चाल का सारांश यह होता है कि तमाम राजनीतिक शक्तियों की मर्जी को कम्यूनिज्म के उद्देश्यों के प्रधीनस्थ किया जाए। नवम्बर, १६५७ के बाद से मास्को ने कई देशों में विशेष-रूप से पिछड़े हुए देशों में "संयुक्त फंट" ग्रर्थात् कम्यूनिस्ट तथा कट्टर राष्ट्रवादी

पार्टियों की john क्षेत्र कार्ते हो हिस्स कार्य कि कि स्वार्क की स्वार्य की स

७. क्या कम्यूनिस्ट विरोधी मिली-जुली सरकार सफल हो सकती है ?

ग्रवश्य ही, भारत में केरल प्रदेश इस सफलता का चिन्ह है। सत्ताइस मास तक वहाँ कम्यूनिस्ट पार्टी का शासन रहा। इसके बाद जुलाई, १९५९ में केन्द्रीय सरकार ने उसे पदयुक्त कर दिया। १९५७ के चुनाव में कम्यूनिस्टों को केरल की जनता के कुल ३५ प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। विधानसभा की १२६ सीटों में से ६० उन्होंने प्राप्त की थीं। कम्यूनिस्टों की सफलता का बड़ा कारण उनका संगठन है। गैर-कम्यूनिस्ट पार्टियां बहुत-सी समस्याग्रों पर पर-स्पर बंटी हुई थीं।

मगर जब फरवरी, १६६० में चुनाव हुम्रा तो कम्यूनिस्ट विरोधी तीन बड़ी पार्टियाँ—कांग्रेस, प्रजा सोशिलिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग—इकट्ठी हो गईं और उन्होंने संयुक्त प्रजातंत्रीय फंट बना लिया। यद्यपि इस बार कम्यू-निस्टों को ४३ प्रतिशत वोट मिले परन्तु केरल विधानसभा में उनकी सीटें ६० से घट कर २६ तक रह गईं कम्यूनिस्ट विरोधी कोलीशन ने ८४ सीटें प्राप्त कीं।

भारतीय समाचार पत्रों में इस चुनाव पर टिप्पणियों में यही कहा गया कि कम्यूनिस्टों को इतनी वड़ी हार कम्यूनिस्ट विरोधी दलों की एकता तथा दृढ़ संकल्प के कारण हुई।

द. यदि कम्यूनिस्ट थ्रोर उनके सहगामी गुप्त रूप से काम कर रहे हों तो उनकी कैसे पहिचान की जाए ?

जब पार्टी के नेताओं ने कम्यूनिस्टों को हिदायत दे रखी हो कि पार्टी से अपने सम्बन्ध को प्रत्यक्ष न होने दें तो उनकी पहिचान काफी कठिन हो जाती है परन्तु असम्भव नहीं होती। कम्यूनिस्ट मनोवृति रखने वाले व्यक्ति की एक विशेष पहिचान है। गैर-कम्यूनिस्ट देश में रहने वाले कम्यूनिस्ट सामान्यतः अपनी सरकार तथा अपने देश की स्थिति पर वेषड़क आलोचना करता रहता है। परन्तु सोवियत यूनियन या इसकी राष्ट्र तथा परराष्ट्र नीतियां उसकी आलोचना का निशाना कभी नहीं बन पाती। इसी तरह सहगामी भी (वह लोग जो कम्यूनिस्प के समर्थंक हैं यद्यपि वह वास्तविक रूप में कम्यूनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित नहीं होते) "मास्को लाइन" पर प्रायः आलोचना नहीं करते।

जब से नए सोवियत नेतृत्व द्वारा स्तालिन की निन्दा तथा भत्सेना के पश्चात्

पार्टी के अनुबार भी किन्नु आकोचना का क्रमण मुख्य हो जया है। कुछ हो एइस परिवर्तन से और कुछ टीटोजिम (जो सी० पी० एस० यू० से कम्यूनिस्टीक की स्वतंत्रता का प्रतीक है) से सहगामियों की पहिचान और भी कठिन हो जाती है।

सोवियत सामूहिक नेतृत्व ने जब से स्तालिन की अधोगित की है, संसार भर के कम्यूनिस्टों ने कम्यूनिस्ट सिस्टम की तमाम त्रुटियों की जड़ "अ्यूक्तित्व-वाद" को करार दिया है, स्वयं कम्यूनिस्ट सिस्टम को नहीं।

2. क्या पूछताछ से कम्यूनिस्ट अथवा कम्यूनिस्टों के समर्थक का पता चल

सकता है ?
जिस व्यक्ति पर कम्यूनिस्ट होने की शंका हो, उसकी सही शनास्त के लिए
प्रश्नोत्तर का तरीका अधिक उपयोगी नहीं।

नीचे से ऊपर तक कम्यूनिस्ट पार्टी के सब सदस्य मार्क्सी तकं शास्त्र की मौखिक कलावाजियों में निपुण होते हैं। "ग्राशक्त" कम्यूनिस्ट ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में संकोच करेंगे जिनसे उसकी पहिचान सहल हो जाए। वस टालने के लिए वह तुरन्त ही ग्रसम्बद्ध विषयों पर वार्तालाप छेड़ देगा।

१०. क्या कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य रह कर कोई नागरिक अपने देश का

वफादार हो सकता है ?

कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य की वफादारी प्रथमतः अपनी पार्टी के प्रति होती है। अपने जन्म-स्थान तथा देश से नहीं। इसका अर्थ यह है कि कम्यू-निस्ट पार्टी का सदस्य जो पार्टी के अनुशासन के पालन के लिए विवश है अपने देशोहित के विरुद्ध काम करने पर हर समय तत्पर रहता है। यदि उसे आदेश मिले तो वह अपनी मातृभूमि को घोखा देने से और देश द्रोहियों को लाभ पहुँचाने में भी संकोच नहीं करेगा।

यह ठीक है कि सब कम्यूनिस्ट जासूसी में व्यस्त नहीं रहते फिर भी इस मामले में कोई भी कम्यूनिस्ट, जो पार्टी के नियमों तथा आदेशों का पालनकर्ता है, भावी जासूस हो सकता है। ग्रीर आदेश मिलने पर किसी समय जासूसी सरगमियां शुरू कर सकता है। चूंकि कम्यूनिस्ट मास्को से (या कुछ इलाकों में पीपिंग से) हिदायतें लेते हैं इसलिए वे वास्तव में विदेशी एजेन्ट हैं। कुछ देशों

के विधि संग्रहों में इनका वर्णन इन्हीं शब्दों में किया गया है।

बहुत से देशों में कम्यूनिस्ट पार्टी अवैध घोषित कर दी गई है। इसलिए नहीं कि यह एक राजनीतिक संगठन है ३ व्हिक इसलिए कि विधि अनुसार स्थापित सरकार के अस्तित्व के लिए निरन्तर खतरा बनी रहती है। ११. क्या कम्यनिस्ट प्रन्तर्राज्य नीति भी उसी कार्यरीति पर चलती है जो Diaifized by Ana Sama Foundation Chennal and eGangotri राजनीतिक मदीन में प्रपनाई जाती हैं

अन्तर्राष्ट्रीय नीति के मैदान में मास्को ने प्रत्येक अवसर पर कोशिश की है कि पिरचमी लोक तन्त्रीय देशों के बीच एकता तथा सहयोग को भंग कर दिया जाए तथा उनके परस्पर मतभेद से लाभ उठाया जाए।

प्रत्येक क्षेत्र में—राजनीतिक हो या ग्रार्थिक, समाजी हो या ग्रन्तर्राष्ट्रीय— कम्यूनिस्टों की विभाजनात्मक नीति के प्रतिरोध के लिए यह ग्रनिवार्य है कि गैर कम्यूनिस्ट व्यक्ति तथा संस्थाएँ कम्यूनिस्टों की छलपूर्ण विधियों को भली भांति समक्ष लें ग्रौर ग्रपने सांके हितों की रक्षा के लिए एक हो कर रहें।

१२. श्रध्यापक कम्यूनिचम के प्रतिरोध में किस हद तक उपयोगी हो सकता है ?

जिन लोगों ने शिक्षण का व्यवसाय ग्रहण किया है उनका विशेष रूप से यह कर्त्तंव्य है कि अपने छात्रों को कम्यूनिस्ट प्रभाव से बचाए रखें क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिज्म अपने विकास के लिए नई पीढ़ि को अपनी भ्रोर आक-र्षित करने पर बहुत जोर देता है।

फिलपाइन के दौत्यकर्मी तथा राजनीतिज्ञ कार्लीस पी० रोमोलो ने अपनी पुस्तक "एशिया में घर्म युद्ध" में लिखा है।

"कम्यूनिस्टों की संसार भर में यही गुप्त विधि रही है। नवयुवकों को फांसो जो भावी नेता हैं, नई पीढ़ी के प्राण हैं ''कम्यूनिष्म का उद्देश्य श्रव भी यही है। संसार भर के नवयुवकों पर उनकी निगाह और मन में उनको कम्यूनिस्ट बनाने की लालसा है। श्रीर जहाँ कहीं सम्भव हो बच्चों को कम्यूनिष्म का उपदेश देने का प्रयत्न करते हैं।"

कम्यूनिषम के विरोधी (जिन में सैनिक तथा नागरिक दोनों शामिल हैं) रूस से चीन धौर कोरिया तक कम्यूनिषम से लड़ने के "दोप" में बहुत दुःख सहन कर चुके हैं। उन्होंने जीवन बिलदान किए हैं। करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्षय तथा अभाव में जीवन व्यतीत किए हैं परन्तु कम्यूनिषम के आगे सुके नहीं। इनके उदाहरण से प्रत्येक साधारण व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलन चाहिये कि इस राह में जो बिलदान तथा त्याग भी आवश्यक हो, पेश करे और कम्यूनिषम के उपल्पव को बचाए रखें।

कम्यू जिन्न दक्ते खन्न है। क्षेत्र क्



संयुक्त राज्य श्रमरीका

(U. S. A.)

के राष्ट्रपति

का यूनियन की दशा के विषय पर भाषण

से उद्धृत श्रंश

जो उन्होंने

७ जनवरी, १६६० को

सीनेट तथा हाउस भ्रांव रिप्रिजेन्टेटिवज के संयुक्त श्रधिवेषन में दिया

हम उस साभी मंजिल के ग्रिमिलाषी हैं जहाँ हमारे ग्रपने नागरिकों के लिए उज्ज्वल ग्रवसर हों, समूचे संसार के लिए न्याय तथा शान्ति हो।

हमें ग्रौर हमारे मित्रों को एक ऐसे सिद्धान्त का सामना करना है जिसने गत चालीस वर्ष से ग्रपनी पद्धित से भिन्न शासन प्रणालियों पर विजय पाने के लिये उपद्रव उठा रखा है।

हमें इस बात का पूरा एहसास है कि हम साम्राज्यवादी कम्यूनिएम के सिद्धान्तों को चाहे कितना ही अस्वीकार करें यह आज एक महान उपक्रम बर चुका है। इसके नेता अपनी जनता को मजवूर करते हैं कि वह अपनी काम करने की आजादी, आत्मा की स्वाधीनता तथा निजी उमंगों और अभिलाषाओं का बिलदान दे दें और इसके बदले में भिवष्य के अदृश्य तथा मायामय लागों को स्वीकार करलें। कम्यूनिस्ट गत पन्द्रह वर्षों में प्राप्त की गई आधिक सफवनताओं की सूची प्रस्तुत कर सकते हैं जो उनके तटस्य राष्ट्रों के साथ किए गए चमकीले नकली वादों को और पुरानी परिभाषाओं का अर्थ वह नहीं रहा जो हम जानते आए हैं। पुलिस राज्यों को अवामी गणतंत्र कहा जाता है। स्वतंत्र लोगों पर सशस्त्र विजय को "स्वाधीनता दिलाए जाने का" नाम दिया जाता है।

इन चिक्तें नरिं के किरण संची निष्ठां, धर्म तथा तथ्य का संचारण कठिन हो गया है।

हमें अपने शान्तिपूर्ण उद्देश्यों का, श्रेष्ठतर संसार के निर्माण सम्बन्धी अपनी श्राकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। इसके लिए हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो मन को प्रबुद्ध करे, श्रौर उसे सत्य को अष्ट करने तथा पूर्व निश्चत विकोक्ति का साधन नहीं बनना चाहिए।

उनकी ग्रोर से मुकावला बहुत सस्त है, यह हम स्वीकार करते हैं।
परन्तु ग्रपनी मान्यताग्रों के कम में हम स्वतंत्रता को प्रथम स्थान देते हैं।
हमारा राष्ट्रीय ग्रस्तित्व, हमारी राष्ट्रीय उन्नित इस मूल सिद्धान्त पर निर्मर है। इसी सिद्धान्त ने हमें स्वतंत्र संसार का नेतृत्व प्रदान किया है। यह सबसे बड़ा इनाम है जो किसी देश को मिल सकता है। कम्यूनिएम यह इनाम कभी महीं दिला सकता। स्वतंत्रता का वातावरण रहते हुए ग्रमरीका ने जो ग्राधिक उन्नित की है उसका प्रमाण हमारी ग्रपनी समृद्धि तथा सम्पन्नता ही नहीं वरण् वह खरवों डालर भी हैं जो हमने स्वतंत्र देशों के नव-निर्माण के लिए दिए हैं तािक वह दितीय महायुद्ध के दौरान हुए विष्वंस तथा विनाश को दूर कर सकें। ग्रौर खरवों डालर भी इसी बात के साक्षी हैं जो हमने उन देशों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए दिए जिनकी ग्राजादी को बाहर से खतरा पैदा हो गया था। इतिहास के जिस नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसकी सम-स्याग्रों को सुलक्षाने की योग्यता तथा साहस हम में ग्रवश्य ही है।

हमें अपनी योग्यता तथा बुद्धिमता के साथ तथा अनथक ढंग से अपने

नुकसान से विमुख होकर, काम लेना चाहिए।

हमारे नक्षत्र में जो दरार पड़ गई है वह गहरी तथा चौड़ी है। इसके अतिरिक्त हम शब्दों के ठीक अर्थों को भंग कर देने वाले तूफान में एह रहे हैं जिसमें शब्दों के अर्थ बदल गए हैं।



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



कम्युनिजम के सम्बन्ध में प्रश्नु विद्यार्थी . व्यापारी , धार्मिता, किसान , मजदूर तथा दूसरे लोग साधारणतया पूढ हैं इस पुस्तक में उन के ठोस उचित उत्तर दिये गये हैं:

- **कम्युलिस की स्परेरत**े
- कम्युनिस्ट शासन-प्रणाली 🗥 🛠
- कम्युनिज्य और मज़दूर
- कम्यूनिस्म के अन्तर्गत ज्ञमीन तथा जायदाद की मिरिकयत
- कम्यूनिङ्म में समता
- कम्युनिङ्म के अधीन न्यायालय तथा न्याय
- साम्यवाद का लीह आवरण
- कम्यूनिज्म और धर्म
- कम्यूनिज्म के अधीन शिक्षा-प्रणाली
- कम्यूनिज्ञ के अधीन स्तृष्ट् त्स्तुओं तथा मात का उत्पादन
- कम्यूनिज्म के अधीन पारिवारिक जीवन दिन्न में और बच्चे
- कम्युनिज्म में व्यापार
- कम्युनिरम का विस्तारे
- शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सै-यबाद
- कम्युनिज्म और स्वतन्त्र संसार
- कम्युनिस्म का मुंक़ाबिला कैसे किया जाए
 अमरीका के राष्ट्रपतिका युनियन की दशा के विषय पर आवण